

**भारतीय रिजर्व बैंक की 1961 से मौद्रिक एवं साख
नीति की समीक्षा-कृषि क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में**
**A Review of Monetary and Credit Policy of RBI With
Special Reference to The Agricultural Sector Since 1961)**



इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डि० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

द्वारा
राकेश पाण्डेय

निर्देशक
डा० बी० के० त्रिपाठी
उपाचार्य

अर्थशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1993

विषय सूची

प्रावकथन

अध्याय - 1 -	प्रस्तावना, शोध अध्ययन का स्वरूप, औचित्य एवं प्रमुख बातें	1 - 26
1 1	अध्ययन का उद्देश्य	15
1 2	शोध अध्ययन की परिसंकल्पना	15
1 3	शोध - अध्ययन विधि	16
1 4	उपलब्ध साहित्य की समीक्षा	17
1 5	शोध अध्ययन का अध्याय क्रम	21
अध्याय - 2 -	मौद्रिक एवं साख नीति के सिद्धान्त	27 - 70
2 1	मौद्रिक सिद्धान्त तथा मौद्रिक नीति	27
2 2	मौद्रिक एवं साख नीति की अवधारणा	32
2 3	मौद्रिक नीति के उद्देश्य	38
2 4	मौद्रिक नीति के अवरोध	47
2 5	मौद्रिक नीति के उपकरण	51
2 6	सस्ती मुद्रा नीति	58
2 7	घाटे की वित्त व्यवस्था और मौद्रिक नीति	61
2 8	रेडक्लिफ कमिटी की रिपोर्ट	64
2 9	मौद्रिक नीति का कार्य क्षेत्र एवं गैर-कार्य क्षेत्र	66
अध्याय - 3 -	मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्त, रिजर्व बैंक विश्लेषण, मौद्रिक नीति हेतु नीतिपरक बातें	71 - 103
3 1	मुद्रा पूर्ति विश्लेषण - बैंकिंग सर्वसमिका	73
3 2	मुद्रा या साख गुणक का सिद्धान्त	75
3 3	मुद्रा पूर्ति का उच्च अर्ध (एच) सिद्धान्त	78
3 4	भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा-जोखा मुद्रा पूर्ति विश्लेषण	85
3 5	साख की पूर्ति तथा इसका निर्धारण	89

अध्याय - 4 -	भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एव साख नीति - पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत	104 - 167
4 1	प्रथम एव द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मौद्रिक एव साख नीति	105
4 2	तृतीय पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एव साख नीति	109
4 3	वार्षिक योजनाओं में मौद्रिक एव साख नीति	114
4 4	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एव साख नीति	118
4 5	पचम पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एव साख नीति	124
4 6	छठी पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एव साख नीति	131
4 7	सातवीं पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एव साख नीति	138
4 8	मौद्रिक एव साख नीति में नवीनतम् परितर्वन एव विकास	152
अध्याय - 5 -	कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति	168 - 196
5 1	ग्रामीण ऋणग्रस्तता एव भारतय रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त	168
5 2	कृषि एव ग्रामीण साख हेतु वित्तीय एजेन्सिया	182
5 3	भारत में कृषि साख व्यवस्था	186
5 4	भारत में कृषि वित्त में मौद्रिक एव साख नीति	192
अध्याय - 6 -	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा कृषि साख	197 - 222
6 1	नाबार्ड की स्थापना	197
6 2	नाबार्ड के कार्य तथा सगठनात्मक संरचना	198
6 3	नाबार्ड ससाधन एव लाभकारिता - कुछ प्रक्षेप	210
6 4	नाबार्ड कुछ महत्वपूर्ण सुझाव	220
अध्याय - 7 -	कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता	223 - 248
7 1	कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नीतिया	224
7 2	मौद्रिक एव साख नीति की सीमाए	224

7 3	कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नियोजन की प्रकृति तथा क्षेत्र	226
7 4	कृषि क्षेत्र में मौद्रिक लक्ष्य तथा नियोजित मुद्रा एव साख पूर्ति	230
7 5	2000 ए0डी0 तक मौद्रिक एव साख प्रक्षेप	233
7 6	कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नियोजन की आवश्यकता	243
अध्याय - 8 -	सारांश, निष्कर्ष एवं नीतिपरक सुझाव	249 - 281
	संदर्भ सूची	282 - 292

प्रावकथन

(PREFACE)

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मौद्रिक एवं साख नीतियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं । यह महत्व जहां विकास के साथ मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने से है, वहीं विशेष रूप से कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित है । भारत में आर्थिक विकास में प्राथमिकता की दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति में उल्लेखनीय तथा सरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं और अब यह विशेषकर साख नीति से सम्बन्धित होता जा रहा है । मौद्रिक नीति की तुलना में साख नीति, मुद्रापूर्ति के मात्र समग्रता को नहीं देखती, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों तथा मुद्रा के आवंटन से सम्बन्धित होती है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में व्यवस्थित ढंग से मौद्रिक एवं साख नीति का अध्ययन किया गया है मौद्रिक एवं साख नीति के उचित संचालन के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि देश में एक प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक हो । भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक होने के नाते इसका मुख्य कारण मौद्रिक स्थायित्व स्थापित करना तथा साख मुद्रा का नियंत्रण करना है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इस बात की विस्तृत विवेचना की गयी है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियायें नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन चयनात्मक नियंत्रण, नैतिक प्रभाव नीति आदि विधियों के द्वारा किस तरह नियंत्रण करता है । साथ ही 1951 से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है । भारत में मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अत्यल्प बचत से, विशेषकर ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों से अधिक से अधिक बचत निकालकर अर्थव्यवस्था में लगाना है । इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास में गति लाने के लिये ब्याज दर के ढांचे, साख नियंत्रण, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था आदि में प्रभावकारी परिवर्तन से है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर साख के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त की अत्यधिक

कमी होने के कारण आज भी उत्पादन तथा उत्पादिता में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है

- परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागेदारी लगातार कम होती गयी है और आज यह मात्र 32 प्रतिशत के ही आस पास है । ग्रामीण अंचल में साख ऋणों की वसूली भी एक गम्भीर समस्या है । भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के सम्यक् दृष्टिकोण से नाबार्ड के महत्व एवं योगदान को इस अध्ययन में स्पष्ट किया गया है । साथ ही कृषि साख तथा नाबार्ड से सम्बंधित कुछ प्रक्षेपों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है । हरितक्रांति का प्रभाव भी केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा है । देश के सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों एवं वर्गों, सीमान्त कृषकों भूमिहीन कृषकों के लिये उपयुक्त रोजगार के अवसरों के न होते हुये भी आज भी इस बात की भारी गुंजाइश है कि प्रभावी ढंग से कृषि क्षेत्र में साख का नियोजन किया जाय । वर्तमान व्यवस्था में ग्रामीण साख का लाभ सभी वर्गों को नहीं मिल पाता है। भारत में कृषि वित्त दो स्रोतों से प्राप्त होती है । सस्थागत स्रोत और गैर सस्थागत स्रोत । 1950-51 में कुल कृषि साख का लगभग छ प्रतिशत भाग सस्थागत स्रोतों से प्राप्त होता था । किन्तु अब इसके भाग में वृद्धि हुयी है । फलस्वरूप वर्तमान में कुल ऋण का लगभग पच्चास प्रतिशत भाग सस्थागत स्रोतों से प्राप्त होने लगा है । 1969 में चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सस्थागत साख में उल्लेखनीय प्रगति हुयी है । भारत में कृषि वित्त को तीन भागों में बाटा जा सकता है ।

1 अल्पकालीन या मौसमी साख,

2 मध्यकालीन साख,

3 दीर्घकालीन साख,

वर्तमान समय में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड के माध्यम से करता है । जो व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वितर्तियन करता है । नाबार्ड ने ग्रामीण एवं कृषि साख के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है ,

लेकिन आज भी आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र में साख का प्रवाह उत्पादक कार्यों के लिये किया जाय । इस शोध प्रबन्ध में इन समस्याओं के सदर्थ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को आठ अध्यायों में बाटा गया है और प्रत्येक अध्याय को आवश्यकतानुसार उप-अध्यायों में विभाजित करके अलग - अलग शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है । अध्यायों का विवरण निम्नलिखित है -

- 1 प्रस्तावना - शोध अध्ययन का स्वरूप, औचित्य एवं प्रमुख बातें,
- 2 मौद्रिक एवं साख नीति के सिद्धान्त,
- 3 मुद्रापूर्ति के सिद्धान्त, रिजर्व बैंक विश्लेषण, मौद्रिक नीति हेतु नीतिपरक बातें,
- 4 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति-पचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत,
- 5 कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति,
- 6 भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा कृषि साख,
- 7 कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता,
- 8 सारांश, निष्कर्ष एवं नीतिपरक सुझाव,

मैं शोध निर्देशक डा० बी० के० त्रिपाठी, उपाचार्य अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति आभारी हूँ, जिनके कुशल निर्देशन एवं व्यक्तिगत रुचि के परिणामस्वरूप यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत रूप में तैयार हो सका । प्रो० बी० के० आनन्द, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने समय-समय पर मेरे शोध की प्रगति में रुचि लेकर मेरा उत्साहवर्धक करते रहे । अर्थशास्त्र विभाग के समस्त अध्यापकों तथा शोधार्थियों का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने न केवल मुझे अपना पूरा सहयोग दिया, बल्कि समय - समय पर बहुमूल्य सुझाव भी दिये । मैं प्रो० वी० डी० मिश्रा, आचार्य, प्राचीन इतिहास

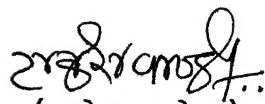
तथा पुरातत्व विभाग का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा ही मेरा मार्गनिर्देशन किया है । मैं प्रो० वाई० पी० सिंह, निर्देशक, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सतत शिक्षा संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे शोध कार्य के शिखर अवधि में तमाम अतिरिक्त कार्यालयीय कार्यों से मुक्त रखा ।

डा० जे० एन० मिश्र, उपाचार्य, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डा० बद्री विशाल त्रिपाठी, प्रवक्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय डिग्री कालेज, डा० राम शिरोमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता, एम० जी० पी० जी० कालेज, फतेहपुर, डा० राधेश्याम गुप्त, निर्देशक, एग्री एकनॉमिक रिसर्च सेण्टर, इलाहाबाद, डा० सुनीत सिंह, शोध सहायक, जी० वी० पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, श्री आर० डी० शुक्ल, जिला प्रबन्धक, राष्ट्रीय बैंक इलाहाबाद, श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी, सुल्तानपुर का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे शोध कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया । श्री० आर० के० सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष, तथा श्री जवाहर, पुस्तक सहायक, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्री एस० एन० पाण्डेय, पुस्तकालयाध्यक्ष, एग्री इकनॉमिक रिसर्च सेण्टर, इलाहाबाद तथा पुस्तकालयाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर एवं बम्बई को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से मैं यह शोध - प्रबन्ध इस रूप में प्रस्तुत कर सका ।

मैं अपने माता-पिता एवं भइया-भाभी तथा बहनो का भी आभारी हूँ, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा। मैं अपने चाचा श्री श्याम कृष्ण पाण्डेय एवं उनके परिवार तथा अपनी पत्नी के परिवार का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा ही मेरा उत्साह बढ़ाया है ।

मैं अपनी पत्नी डा० (श्रीमती) अमिता पाण्डेय, वनस्पति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके सहयोग के बिना यह शोध-प्रबंध पूरा न हो पाता ।

मैं किदवई कामर्शियल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद के श्री एम० आर० खान को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने परिश्रम और लगन के साथ कम्पोजिंग किये ।


(रakesh पाण्डेय)

प्रस्तावना

शोध अध्ययन का स्वरूप, औचित्य एवं प्रमुख बातें

(INTRODUCTION, NATURE, JUSTIFICATION AND MAJOR ISSUES
OF RESEARCH STUDY)

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य इस बात का विस्तृत अध्ययन एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से है कि विकासार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में विकास-समस्याओं और उनके समाधान हेतु मौद्रिक नीति तथा साख नीति का क्या महत्व और योगदान रहा है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की प्राथमिकताओं और विकास प्रक्रिया के वित्तीयन में मौद्रिक एवं साख नीति को विशेष महत्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तथा साथ ही साथ देश के अन्य बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का मुद्रा एवं साख के विस्तार में विशेष महत्व रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीय बैंक द्वारा देश की विकासात्मक कार्यों में समय-समय पर निर्धारित मुद्रा एवं साख नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया जायेगा और इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि देश की सम्पूर्ण आर्थिक विकास में और विशेषकर कृषि क्षेत्र में इन नीतियों की क्या भूमिका रही है और कहा तक इन नीतियों के द्वारा समस्याओं का समाधान हुआ है। यद्यपि भारतीय मौद्रिक एवं साख नीति मूलतः केन्द्रीय सस्ती मुद्रा नीति पर आधारित रही है तथा साथ ही साथ हाल के वर्षों को छोड़कर मौद्रिक एवं साख नीति, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सम्पन्न व्यापारियों, उद्योगपतियों तक ही सीमित रही, किन्तु देश के प्रमुख व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से तथा विशेषकर सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से एवं कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता तथा प्रधानता के सन्दर्भ में अब मौद्रिक तथा विशेषकर साख नीति के उद्देश्य से महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है, इस अध्ययन में प्रस्तुत किया जायेगा, वहीं मौद्रिक तथा साख नीति के प्रभावकारी होने में उन रुकावटों एवं बाधाओं का भी अध्ययन किया जायेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं साख सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी कृषि-वित्त एवं साख का उत्पादक, प्रभावकारी तथा सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।

चूँकि मौद्रिक तथा साख नीतियों का सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा अन्य बातों के पर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर ही मौद्रिक एवं साख नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि हम मौद्रिक एवं साख नीतियों के उपयुक्त एवं प्रभावकारी स्वरूप को देने के लिए विकास नीतियों और कार्यक्रमों के उपादेयता तथा प्रभावकारिता का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।

मौद्रिक और साख नीति का किसी भी देश के आर्थिक विकास से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है और साख नीति के उचित संचालन द्वारा जहाँ देश के मौद्रिक क्षेत्रों की वृद्धि मुद्रा पूर्ति के साथ - साथ राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि तथा मुद्रा और मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में मूल्य-स्थायित्वता की प्राप्ति आदि महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हैं, वहीं अनेक सैद्धान्तिक अनुभवगम्य विश्लेषणों के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि देश के आर्थिक क्रियाओं में और विशेषकर विकास प्रक्रिया में मुद्रापूर्ति, मौद्रिक शक्तियों एवं अन्य कारकों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपने मुद्रा परिणाम सिद्धान्त के आधार पर इस बात को स्थापित किया कि अर्थ-व्यवस्था के अस्थायित्वता का प्रधान कारण मौद्रिक शक्तियों में परिवर्तन से है और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि मौद्रिक आय तथा आर्थिक उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था को स्थायित्वता की ओर ले जाने में मुद्रा की मात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केन्स ने भी यद्यपि वित्तीय नीति पर विशेष महत्व दिया था, परन्तु अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्तियों को प्रभावित करने में मुद्रापूर्ति और मौद्रिक नीति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। केन्सोपरान्त फ्रीडमैन ने तो अपने सारे सैद्धान्तिक और अनुभवगम्य विश्लेषणों के आधार पर इस बात को बड़ी दृढ़ता से स्थापित किया है कि अर्थव्यवस्था में केवल मौद्रिक शक्तियाँ ही महत्वपूर्ण हैं। उनके नियन्त्रण द्वारा ही स्थायित्वता प्राप्त की जा सकती है। गर्ले-शॉ के विश्लेषण से भी स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के विकास में और आर्थिक क्रियाओं में मौद्रिक तथा वित्तीय सस्थाओं का कितना व्यापक और महत्वपूर्ण योगदान होता है। केन्सवाद और मौद्रिकवाद के महान विवाद से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति अपना विशेष महत्व रखती है। मोटे तौर पर 'मौद्रिक नीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के नियन्त्रण से सम्बन्धित नीति से है। हैरी जॉन्सन

का मानना है कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय केन्द्रीय बैंक के उस नियंत्रण नीति से है, जिसके द्वारा केन्द्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है।¹ मौद्रिक नीति का एक और अभिप्राय साख नियंत्रण से भी है। सेयर्स का मानना है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि मुद्रा की निर्माता भी है। यहाँ मुद्रा का निर्माण का अर्थ साख सृजन से है। बैंक जमा का एक विशिष्ट रूप है - साख जमा। साख, मुद्रापूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है।² हैरॉड, डोमर और शुम्पीटर ने अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में प्रवैगिक सिद्धान्तों या सवृद्धि-मॉडल का निर्माण किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य, साधनों की एक दी गयी मात्रा के पूर्ण प्रयोग का नहीं, बल्कि साधनों की मात्रा में ही वृद्धि की है। अल्पविकसित देशों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ, क्योंकि इसकी मुख्य समस्या मूल्य की स्थिरता तथा प्रभावी माग की वृद्धि की नहीं, बल्कि उत्पादन के साधनों तथा उत्पादकता में वृद्धि की है। इस प्रकार इन देशों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य 'स्थिरता के साथ आर्थिक विकास' है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने देश में मौद्रिक नीति के उद्देश्य के सम्बन्ध में नियन्त्रित विस्तार की नीति को प्रतिपादित किया है।³

मौद्रिक तथा साख नीति किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों आदि द्वारा निर्धारित होती है। आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का योगदान तभी अधिकतम कहा जायेगा, जब यह पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के साथ ही साथ मूल्य को एक निश्चित सीमा के अंदर रखे। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने एक अध्ययन में यह दिखाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1953 से आर्थिक

-
1. Harry G. Johnson, Monetary Theory and Policy, American Economic Review, 1962.
 2. R.S. Sayers, Modern Banking, p.213.
 3. Reserve Bank of India, Trend and Progress of Banking in India 1956, p. 56.

विकास की दर और अधिक रही होती, यदि प्रभावी माग को उत्पादन क्षमता के बराबर रखा गया होता। अल्पविकसित देशों के सदस्यों में वैन फिलिप्स का मत है कि इन देशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या गत्यावरोध को दूर करने की नहीं है, बल्कि इन अर्थव्यवस्थाओं के वांछित तथा प्रवैगिक विकास के द्वारा इसे भेदने की है।⁴ रेडक्लिफ समिति ने आर्थिक नीति के उद्देश्य को, जिससे मौद्रिक नीति सम्बन्धित है, बहुत ही उलझनपूर्ण बताया है, अल्पकाल में ये प्रत्यक्ष रूप से विरोधी हो सकते हैं और केवल समन्वय के द्वारा ही दीर्घकाल में इनमें सन्तुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।⁵ मोटे तौर पर मौद्रिक नीति का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के तीन स्वरूपों में देखा जा सकता है -

1. मौद्रिक नीति से देश के राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, विनियोग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव।
2. मौद्रिक नीति द्वारा मूल्य स्थायित्वता।
3. मौद्रिक नीति के द्वारा विकास के साथ सामाजिक न्याय अर्थात् विकास की प्राथमिकता, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी, बेरोजगारी तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास।

जहाँ मौद्रिक नीति का सम्बन्ध आर्थिक विकास के उपरोक्त रूपों से सामान्य रूप से जुड़ा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में यह विशेषरूप से महत्वपूर्ण है। यह महत्व

4. Van Philips, Public Finance and Less Developed Economy, p.58.

5. "The aims of economic policy to which monetary action is related, are complex, they can be directly in conflict with each other in the short term and only by adjustment can be held in balance in the long", Radcliffe Committee Report, p. 337.

जहा विकास के साथ मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने से है, वहीं विशेषरूप से कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बंधित है । आर्थिक विकास में प्राथमिकता की दृष्टिकोण से देश के केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण और सरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं । और यह परिवर्तन परम्परावादी मौद्रिक नीति से हटकर साख नीति के रूप में परिणित होता जा रहा है । यद्यपि मोटे तौर पर मौद्रिक और साख नीति में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है, परन्तु साख नीति के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें विशेष हैं, जो सामान्यरूप से मौद्रिक नीति में परिलक्षित नहीं होती । मौद्रिक नीति के तुलना में साख नीति मुद्रापूर्ति के मात्र समग्रता को ही नहीं देखती, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों तथा मुद्रा के आवटन से सम्बंधित है । मौद्रिक और साख नीति में इस तरह भेद करना इसलिये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे दोनों नीतियों के स्वरूप और उनके रूप निर्धारण को समझने में सहायता मिलेगी।

अल्पविकसित देश गरीबी के कुचक्र में फसे हुये हैं । इनमें आय, रोजगार तथा पूजी निर्माण का स्तर अत्यन्त नीचा है । इस प्रकार से ये एक तरह से अल्प स्तर के संस्थिति जाल में फसे हुये हैं । इन देशों की मुख्य समस्या इस 'जाल' से निकलने की है । डा० पी० डी० हजेला ने अपने एक ग्रन्थ में लिखा है कि जैसा हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति का अभिप्राय उन नियमों से है, जिनसे किसी देश की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक उस देश की आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रयोग की जाती है।⁶

एक प्रभावपूर्ण मौद्रिक एवं साख नीति के लिए यह आवश्यक है कि देश में एक शक्तिशाली केन्द्रीय बैंक हो । केन्द्रीय बैंक एक ओर वित्तीय संस्थाओं तथा मौद्रिक एवं साख नीति का संचालन करता है ,वही दूसरी ओर सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है । आज जब अल्पविकसित देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध तकनीक को अपनाया है, केन्द्रीय बैंक का महत्व इन देशों में और भी बढ़ गया है ।

6. P.D. Hajela, The problems of Monetary Policy In Underdeveloped Countries, p. 23.

भारत के मौद्रिक नीति के निर्माण एवं क्रियाशीलन तथा साख मुद्रा प्रणालियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं समायोजन स्थापित करने के उद्देश्य के दृष्टि से 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति ने एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया, फलस्वरूप एक अप्रैल, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, एक केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। आगे चल कर 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ ही कृषि वित्त के क्षेत्र में इसकी भूमिका विशेष रूप से बढ़ गयी। इसकी भूमिका जो अभी तक इस क्षेत्र में निष्क्रिय थी, वह अब सहकारी बैंकों को वित्तीय सहयोग देने तथा कृषि साख से सम्बंधित मामलों में विशेषज्ञ सलाह देने जैसा महत्वपूर्ण कार्य हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय बैंक होने के नाते इसका प्रमुख कार्य देश में मौद्रिक स्थायित्वता स्थापित करना एवं साख-मुद्रा का नियंत्रण करना है। हमारे देश में साख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तथा बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ नकद कोषों के अनुपात में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक प्रभाव नीति आदि विधियों से साख नियंत्रण का कार्य करता है। इस तरह रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा और साख के लिए नीति निर्धारण करना है। भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य अत्यल्प बचत से, विशेषकर ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों से अधिक से अधिक बचत निकाल कर अर्थव्यवस्था में लगाना है, क्योंकि यहाँ की मुख्य समस्या पूँजी की कमी है, परिणामस्वरूप उत्पादन तकनीक और उत्पादन स्तर नीचा है। इसके अलावा ब्याज दर के ढाँचे, साख नियंत्रण, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था में परिवर्तन से है, जिससे आर्थिक विकास को और अधिक गति प्राप्त हो सके।

भारत में कृषि, आय का एक प्रमुख स्रोत है, किन्तु यह अपनी निम्न उत्पादितता के कारण विकास में बाधक है। भारत की 72 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित

उद्योगों से जुडी है।⁷ फिर भी हम अभी तक कृषि को एक उन्नतिशील व्यवसाय का रूप नहीं दे सके हैं। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता का मूल कारण कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति है,

वे अपनी अत्यन्त अल्प आय में से अपनी आधार भूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हरित-क्रान्ति एवं कृषि की नवीन तकनीक से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है, जब कि शेष क्षेत्रों में किसानों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। केन्द्रीय बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने भी अपने प्रतिवेदन में ब्रिटिश भारत में कृषकों की दयनीय स्थिति की चर्चा की है। यह कहावत कि एक कृषक गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में जीता है और गरीबी में मरता है, भारतीय किसानों के लिए अतिशयोक्ति नहीं कही जायेगी। वैसे इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध काल (1939-45) और उसके बाद प्रगति के फलस्वरूप ग्रामीण कर्ज में वास्तविक कमी आयी है, फिर भी छोटे जमींदारों और कानूनकारों तथा कृषि-मजदूरों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। द बाम्बे प्राविसियल कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट तथा डा० बी०वी० नारायणस्वामी नायडू (मद्रास) ने भी अपने एक अध्ययन में इस तथ्य को स्वीकार किया है।

कृषि वित्त दो स्रोतों से प्राप्त होता है, पहला, सस्थागत और दूसरा, गैर सस्थागत स्रोत। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अधिकांश साख गैर-सस्थागत स्रोतों द्वारा ही प्रदान किया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर जब से हमने पंचवर्षीय योजनाएं बना कर विकास कार्य प्रारम्भ किया, इस स्थिति में सुधार हुआ है। गैर सस्थागत स्रोतों से 1951 - 52 से 1978 - 79 तक प्राप्त कृषि साख का विवरण हम सारणी सख्या 1.1 में देख सकते हैं।

7. Dr. Mali Ram, Currency and Banking, 1965, p. 364.

सारणी । ।

कुल कृषि साख में गैर - सस्थागत स्रोतों का भाग

वर्ष	कुल योग का प्रतिशत
1951 - 52	93 6
1961 - 62	85 0
1971 - 72	75 0
1978 - 79	65 0

स्रोत - रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मल्टी एजेन्सी एप्रोच इन एग्रीकल्चरल फाइनेन्स, 1978

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 1955 से, जब इम्परियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में पारिवर्तित हुआ तथा उससे कृषि - वित्त की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिए कहा गया और विशेषकर 1968 में व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण तथा 1969 में देश के चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों एव 1980 में अन्य छ व्यापारिक बैंकों के पुन राष्ट्रीयकरण के बाद (ये 20 राष्ट्रीकृत बैंक देश के कुल बैंकिंग व्यावसाय का 90 से 95 प्रतिशत पूरा करते हैं) कृषि वित्त के क्षेत्र में सस्थागत साख (व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितिया एव अन्य विशिष्ट सस्थाए) में उल्लेखनीय प्रगति हुई । इस प्रकार सस्थागत साख, जो 1951-52 में लगभग 6 प्रतिशत थी, वह 1978-79 में बढ़कर 35 प्रतिशत हो गयी । एक अनुभव के अनुसार, वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में आवश्यक कुल अल्पकालीन साख का लगभग 56 प्रतिशत तथा सभी विनियोग सस्थागत सस्थाओं द्वारा पूरा किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत कृषि साख को पूरी तरह सस्थागत रूप देने के निमित्त सगठनात्मक ढांचा को स्थापित करने और विकास का सम्पूर्ण दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक की है। इससे ग्रामीण साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण समाप्त होगा और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण का स्थान सस्थागत स्रोत ले लेंगे, जिससे किसानों की ऋण आवश्यकता को एक राष्ट्रीय साख नीति के अनुसार पूरा किया जा सकेगा। इस दिशा में पहला प्रयास 1904 में सहकारी व्यवस्था के उदगम से हो गया था।⁸ यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसके प्रभाव का ही परिणाम था कि 1954 में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रतिपादित समन्वित ग्रामीण साख योजना को सरकार ने स्वीकार किया। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि साख को पूरी तरह सस्थागत बनाना था। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (1954) तथा ऑल इण्डिया रूरल डेब्ट एण्ड इनवेस्टमेंट - सर्वे ने गैर सस्थागत तथा सस्थागत स्रोतों द्वारा दिये गये कृषि ऋण का विवरण प्रस्तुत किया था। सारणी 1.1 में विभिन्न स्रोतों द्वारा विभिन्न वर्षों में दिये गये कृषि वित्त का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 1.2

कृषि वित्त व्यवस्था में विभिन्न स्रोतों का स्थान

(प्रतिशत में)

स्रोत	1951-52	1961-62	1968-69
1 सरकार	3.3	2.6	9.7
2 सहकारी समितियाँ	3.1	15.5	33.0
3 व्यापारिक बैंक	0.9	0.6	5.3
4 साहूकार एवं जमींदार आदि	90.9	67.9	52.0
5 अन्य योग	1.8	13.9	0.0

Source - Report of the All India Rural Credit Review Committee, 1969, p. 100.

8. B.N. Choubey, Agricultural Banking in India, 1983, P. 12.

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से उपरोक्त योजना के एकीकरण और पूर्ण करने का अनुरोध किया था तथा सहकारी समितियों को पर्याप्त धन की व्यवस्था करने को कहा । 1969 तक सरकार इस नीति के द्वारा ही सस्थागत साख के विकास में लगी थी, किन्तु इसके बाद सहकारी साख सस्थाओं के परिणामों की समीक्षा करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुची कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि साख की तेजी से बढ़ती हुई माग को पूरा करने के लिये सहकारी सस्थाओं को सुदृढ होने का इतजार नहीं किया जा सकता । फलस्वरूप सरकार ने कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहु उद्देशीय उपागम नीति को अपनाया । अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख के सदर्भ में गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि उन राज्यों को छोड कर, जहा सहकारी सस्थाए पूर्ण रूप से विकसित एव सक्रिय हैं, शेष राज्यों में कृषि साख सस्थाए स्थापित की जाए ।

अमेरिकन रिफार्म कमेटी का यह मानना हे कि सभी लघु कालीन और दीर्घकालीन सस्थागत साख सुविधाए सहकारी सस्थाओं तथा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सम्पादित होना चाहिए । कृषि क्षेत्र के लिए आसान और उचित वित्त व्यवस्था में सलग्न सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए ।

कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया हे कि 1973-74 में सस्थागत स्रोतों (जैसे सहकारी समितिया, तथा व्यापारिक बैंक आदि) से कृषि साख, जो 1967-68 में लगभग 38 प्रतिशत था, में बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है । इस रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा कमेटी के अनुमान के अनुसार कुल आवश्यक साख रू0 4000 करोड में से कृषि क्षेत्र के लिए रू0 1,537 करोड (38 प्रतिशत) की गणना की गयी, जिसमें से रू0 919 करोड (23 प्रतिशत) व्यापारिक बैंकों द्वारा किया गया ।

भारत में कृषि से सम्बंधित वित्तीय आवश्यकताओं को तीन भागों में बाटा जा सकता है - (१) अल्पकालीन या मौसमी साख, (२) मध्यकालीन साख, (३) दीर्घ कालीन साख । अल्पकालीन साख के लिए रिजर्व बैंक कृषि साख की पूर्ति केवल राज्य सहकारी बैंक तथा अनुसूचित बैंकों के माध्यम से करता है । इस प्रकार कृषक सीधे रिजर्व बैंक से सम्पर्क में नहीं आता है । भारतीय रिजर्व बैंक कृषि साख की दिशा में कई कदम उठाये हैं । रिजर्व बैंक ने कृषि विकास में कृषि साख की आवश्यकता को देखते हुये एक अलग कृषि साख विभाग की स्थापना की है, जिसके द्वारा कृषि वित्त के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करके तथा विशेषज्ञ के रूप में सलाह देकर और कृषि सहकारी वित्त से सम्बंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट तथा साहित्य प्रकाशित करके रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह विभाग केन्द्र और राज्य सरकार, सहकारी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपना बहुमूल्य परामर्श देता है । यह राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों तथा ऋण पत्रों के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता है । यह भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र खरीद कर उनकी कार्यशील पूजी में वृद्धि करता है । बैंक लाइसेन्स प्राप्त गोदामों में रखी कृषि उपज के आधार पर ऋण देता है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सस्ती दरों पर ऋण देता है ।

जुलाई १९८२ में भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि साख विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यों और कृषि वित्त एव विकास निगम के समस्त दायित्वों को अलग से राष्ट्रीय बैंक स्थापित करके, इसके अधीन कर दिया गया। इस बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) रखा गया । राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एव साख के सदर्थ में ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना अपना विशेष महत्व रखती है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यद्यपि केन्द्रीय बैंक का योगदान प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व से ही रहा है, परन्तु योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बाद इसका विशेष महत्व रहा है, यद्यपि प्रारम्भ में मौद्रिक नीति को सीधे आर्थिक विकास से

नहीं जोड़ा गया था, फिर भी विभिन्न रूपों में मौद्रिक नीति के महत्व को स्वीकार किया गया था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक तथा साख नीति का प्रधान उद्देश्य साख की सुविधाओं द्वारा औद्योगिक व कृषि उत्पाद में वित्त उपलब्ध करना था । अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के नियन्त्रणात्मक दृष्टिकोण से साख नीति सामान्य तथा नियन्त्रित एवं प्रतिबन्धित थी, यद्यपि नियोजकों ने इस बात को माना कि मुद्रापूर्ति की वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्फीतिकारी होगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक नीति को एक विशेष मान्यता इस रूप में प्राप्त हुयी कि पूरी आर्थिक क्रियाओं के नियन्त्रण में तथा स्फीतिकारी दबावों को रोकने में यह महत्वपूर्ण है, यद्यपि घाटे की वित्त व्यवस्था को विकास के लिए मान्यता दी गई, फिर भी परिमाणत्मक तथा चयनात्मक विधियों के द्वारा साख को नियन्त्रित करने का प्रयास किया गया । इस योजना में मोटे तौर पर मौद्रिक नीति सफल न हो सकी, क्योंकि इसकी वित्तीय नीति से आवश्यक समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी मुद्रा स्फीति को रोकने के दृष्टिकोण से मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को सहारा लिया गया तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया गया । साख नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके छोटे उद्योगों और सहकारी क्रियाओं को प्रोत्साहित किया गया । साख को प्रतिबन्धित किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना में मौद्रिक नीति सामान्यतः वृद्धिकारी ही रही, जिसमें मुद्रापूर्ति तथा साखकी मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

चौथी पंचवर्षीय योजना में लगातार बढ़ते हुए मूल्य को नियन्त्रण करने के दृष्टिकोण से माग और पूर्ति में समानता रखते हुए घाटे की वित्त व्यवस्था को निर्धारित करने का उद्देश्य रखा गया । 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण विकास क्षेत्र की प्रधानता तथा प्राथमिकता के आधार पर साख प्रवाह किया गया और उपेक्षित क्षेत्रों के विकास में सहयोग किया गया । पाचवी योजना में विशेष रूप से मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों को प्रधावनता दी गई । इस योजना में मौद्रिक तथा वित्तीय नीति के विशेष समन्वय पर जोर दिया गया और मुद्रा साख के विस्तार पर प्रतिबन्ध

लगाने के दृष्टिकोण से बैंक दर को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया।

पाचवी योजना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक और साख नीति कृषि तथा लघु उद्योगों की ओर विशेषरूप से रही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, लीड बैंक स्कीम तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना, शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार योजना तथा ग्रामीण औद्योगिकरण सम्बन्धित अनेक आर्थिक क्रियाओं से विशाल पैमाने तथा पर रियायती तथा उदार बैंक ऋण एवं साख की व्यवस्था की गई।

छठी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसका निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में किया गया। विकासगत समस्याओं के निदान हेतु इसमें पंद्रह वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। योजना का कार्यक्रम न केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, रोजगार, बचत एवं विनियोग जैसे परम्परागत तत्वों पर आधारित था, बल्कि इसका विकास गरीबी के प्रतिशत, सम्भावित आय, खाद्यान्न, चीनी, वस्त्र आदि उपभोग एवं शिक्षा के दीर्घकालिक स्तरों के सदर्थ में भी किया गया था। इस योजना में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ कर दिया गया। छोटे एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों के विकास के लिये कृषि एवं सहायक व्यवसायों को विकसित किया गया। किन्तु इस योजना में सफीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं सुझाया गया था। योजनाकाल में सवृद्धि नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुयी। छठी योजना में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत था, जिसे योजनाकाल में प्राप्त कर लिया गया था।

सातवी योजना में नये भारत के निर्माण की सकल्पना की गयी। यह योजना कुछ मायनों में पिछली सभी योजनाओं से भिन्न थी। सातवी योजना भी दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार की गयी थी, जिसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों अर्थात् सन् 2000 ई तक स्वतः पोषित अर्थव्यवस्था का होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ समन्वय किया गया। इन कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय सस्थाओं के माध्यम से लागू किया गया। एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना तथा

राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार परियोजना के कार्य को और अधिक व्यापक किया गया है । सातवीं योजना में कृषि विकास एवं सिंचाई पर अधिक जोर दिया गया । कृषि विकास की गति को तेज करना और अधिक उपभोग के लिये खाद्यान्नों एवं खाद्य तेलों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना इस योजना के आधारभूत लक्ष्य थे । योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान पहले की योजनाओं के अनुरूप ही दिया गया, योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पहले से चली आ रही परियोजनाओं को पूरा किया जाये । सातवीं योजना में विकास दर 5 प्रतिशत वार्षिक रखी गयी, जो छठी योजना से कम थी । सातवीं योजना में कृषकों की साख आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास किये गये । सहकारी समितियों को विभिन्न चरणों में बहु-उद्देश्यीय समितियों में परिवर्तित करने की योजनाएँ बनाई गयी, जिससे कृषकों को विभिन्न सुविधाएँ एक साथ ही तथा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके ।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास तथा समस्याओं के समाधान हेतु विशेष सन्दर्भ में ग्रामीण साख तथा बैंक सुविधाओं के बढ़ते हुए महत्व से जहाँ यह आशा की जा रही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और देश की मूल भूत समस्याओं का समाधान होगा, वहीं इनसे सम्बन्धित अध्ययनों, सर्वेक्षणों और अनुभवों से यह भी शका व्यक्त की जा रही है कि व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में साख और वित्त का यह प्रवाह अधिकांशतः अनुत्पादक तथा अनियोजित ढंग से हो रहा है, जिससे विकास की क्रियाओं को प्रोत्साहन न मिल कर गैर उत्पादक व्यय तथा मुद्रास्फीति बढ़ रही है, साथ ही बैंक साख की वापसी की भी महत्वपूर्ण समस्या है । फलतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध साख सुविधायें अपेक्षित रूप से लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है और न ही उनका उपयुक्त और निर्धारित उद्देश्यों में प्रयोग ही हो रहा है । मौद्रिक और साख नीति के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है कि ग्रामीण साख और बैंकिंग सुविधाओं को इस प्रकार उत्पादक तथा विकास मूलक बनाया जाय ।

1.1 अध्ययन का उद्देश्य -

उपरोक्त बातों के सदर्थ में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्ययन का यह प्रमुख उद्देश्य है कि प्रथमतः भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक एवं साख नीतियों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करके उसकी दिशा तथा प्रवृत्ति को बताये।

दूसरे, मौद्रिक तथा साख नीति का आर्थिक विकास और मूल्य स्थायित्वता में योगदान का परिक्षण करे।

तीसरे, मौद्रिक तथा साख नीति की वर्तमान प्रवृत्ति कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा समस्याओं के लिए कहा तक उपयुक्त है।

चौथे, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक साख तथा साख सुविधायें कहा तक विकास नीतियों और विकास योजनाओं से जुड़ी है।

पाचवे, ग्रामीण साख तथा बैंक वित्त के उत्पादक और उपयुक्त प्रयोग में क्या-क्या बाधाएँ और रुकावट हैं।

छठे, ग्रामीण क्षेत्रों के सम्यक विकास और विशेषकर ग्रामीण औद्योगीकरण की दृष्टिकोण से मौद्रिक और साख का क्या स्वरूप होना चाहिए, इससे सम्बन्धित उपयुक्त सुझाव।

1.2 शोध - अध्ययन की परिसंकल्पना

भारती रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं साख नीति के मूल्यांकन और कृषि क्षेत्र के विशेष सदर्थ में उनके योगदान के सम्बन्ध में प्रस्तुत अध्ययन की निम्न परिसंकल्पनाएँ होगी -

1. क्या मौद्रिक एवं साख नीति विकास मूलक रही है अथवा स्फीतिजनक,

- 2 क्या मौद्रिक एवं साख नीति अब भी केन्सीय सस्ती नीति का ही एक रूप है,
- 3 मौद्रिक तथा साख नीति का कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की ओर झुकाव एक सही दिशा व कदम है,
- 4 ग्रामीण साख एवं बैंकिंग व्यवस्था कृषि विकास के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है ।

1.3 शोध - अध्ययन विधि

उपरोक्त परिसंकल्पनाओं के प्रत्यक्षीकरण को भारतीय आर्थिक विकास के अनुभवों तथा कृषि क्षेत्रों में बैंकिंग और साख उपलब्धियों के सदर्थ में किया जायेगा । शोध की विधि मूलतः विश्लेषणात्मक है, जिसमें प्रकाशित ग्रन्थों, सर्वेक्षणों, रिपोर्टों तथा अन्य सरकारी द्वितीयक आकड़ों और विवरणों के आधार पर किया गया है । इस तरह शोध अध्ययन के आधार पर यह आशा की जाती है कि देश के आर्थिक विकास के सदर्थ में उपयुक्त मौद्रिक एवं साख नीति का निर्माण किया जा सकेगा और देश के आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्य को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में विकास सम्बन्धी योगदान का परीक्षण करने हेतु कुछ सैद्धान्तिक विश्लेषणों को भी दिया गया है । विशेषकर मुद्रा पूर्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों का परीक्षण किया गया है और साथ ही साथ मौद्रिक तथा साख सिद्धान्तों का विवरण नीतिनिर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन-विधि सम्बन्धी विश्लेषण हेतु विभिन्न द्वितीयक आकड़े तथा उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण सारणी के द्वारा किया गया है । मुख्य रूप से द्वितीयक आकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के 'रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स,' तथा मथली बुलेटिन, भारत सरकार का इकनामिक सर्वे, स्टेट बैंक आफ अण्डिया का मथली रिव्यू, नाबार्ड की एनॅवल रिपोर्ट आदि से प्राप्त किया गया है ।

मुद्रा पूर्ति, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर के पारस्परिक सम्बन्ध को सह सबध गुणाक, प्रतिशत, अनुपात आदि सांख्यिकीय विधियों से विश्लेषित किया गया है । कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुयी साख की आवश्यकता और सम्यक ग्रामीण और कृषि के विकास के परिप्रेक्ष्य में जहा नाबार्ड के विश्लेषण सम्बन्धी सारणियों को प्रस्तुत किया गया है, वही कृषि के भौवी आश्यकताओं से सम्बन्धित प्रक्षेप सम्बन्धी अनुमानित आकड़ों को भी दिया गया है । आकड़ों के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक-दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अध्ययन विधि में इस बात की विवेचना की गयी है कि भारतीय मौद्रिक नीति कहा तक सस्ती मुद्रा एव साख नीति रही है । कृषि क्षेत्र में प्रदत्त साख को अल्प कालीन, मध्य कालीन तथा दीर्घ कालीन के रूप में रखकर इस बात को देखने का प्रयास किया

है कि कहा तक मौद्रिक एव साख नीति सीमान्त और भूमिहीन कृषकों के लिये उपयोगी सिद्ध हुयी है । व्यवस्थित अध्ययन की दृष्टिकोण से प्रस्तुत अध्ययन विधि में विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं में एक साथ क्रमबद्ध रूप में मौद्रिक एव साख नीति की विवेचना किया गया है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में साख सम्बन्धी आश्यकताओं और नियोजन के सम्बन्ध में उपयोगी सिद्ध होगी । साथ ही साथ इस बात का भी विश्लेषण करने में ध्यान रखा गया है कि भविष्य में कृषि सम्बन्धी साख आश्यकताओं को पूरा करने में नाबार्ड तथा अन्य वित्तीय सस्थाओं में क्या सस्थागत तथा सरचनात्मक परिवर्तन किया जाय कि कृषि क्षेत्र का नवीन विकास परिस्थितियों एव समस्याओं में उपयुक्त समाधान किया जा सके ।

1.4 उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

शोध विषय के अध्ययन और विश्लेषण के सबध में यह सहत्वपूर्ण होगा कि सम्बन्धित शोध विषय पर उपलब्ध साहित्य का अवलोकन तथा समीक्षा की जाय । कृषि एव ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुयी वित्तीय सस्थाओं द्वारा प्रदत्त एक आगत के रूप में साख एव ऋण वर्तमान कृषि एव ग्रामीण विकास के सदर्थ में शोध और अध्ययन महत्वपूर्ण विषय रहा है । यहा हम उपलब्ध साहित्य के अवलोकन में सैद्धान्तिक पक्ष एव मौद्रिक और साख नीति एव नियोजन हेतु व्यवहारिक

पक्ष को भारतीय मौद्रिक दशाओं की परिस्थितियों में विश्लेषण करेंगे । प्रो० एस० बी० गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ 'मॉनेट्री प्लानिंग फॉर इण्डिया' में मुद्रा पूर्ति तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा-जोखा विश्लेषण का सैद्धान्तिक पक्ष दिया है । साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य वित्तीय सस्थाओं एवं गैर बैंकिंग वित्तीय सस्थाओं की उपादेयता का परीक्षण किया है, उन्होंने अपने निष्कर्ष में इस बात पर बल दिया है कि भारत जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख नीति भी नियोजित होना चाहिए और उसका परिप्रेक्ष्य एक दीर्घकालीन साख और मौद्रिक नियोजन होना चाहिए । उन्होंने मुद्रा पूर्ति निर्धारण तथा साख - निर्धारण सम्बन्धित सैद्धांतिक पक्षों को देकर इस बात का परीक्षण किया है कि भारत के वास्तविक कृषि क्षेत्र में साख का निर्धारण एवं वितरण किस तरह किया जाता है। इसी तरह प्रो० पी० डी० हजेला ने अपने ग्रन्थ में मौद्रिक सिद्धान्तों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि भारतीय मौद्रिक नीति मोटे तौर पर सस्ती मुद्रा नीति तथा स्फीतिकारी मौद्रिक नीति रही है । उन्होंने अपने अध्ययन में ग्रामीण साख व्यवस्था का महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है और इस बात का प्रस्ताव रखा है कि उपयुक्त साख नियोजन द्वारा ही स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लग सकती है और मूल्य स्थायित्वता प्राप्त की जा सकती है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख के सैद्धान्तिक विश्लेषण के बाद यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत के विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में प्रयुक्त मौद्रिक एवं साख नीति का विवेचना किया जाय । इस दृष्टिकोण से डा० सी० आर० बसू ने 'सेन्ट्रल बैंकिंग इन ए प्लान्ड इकोनॉमी, दि इण्डियन एक्सपेरिमेंट' में विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में प्रयुक्त मौद्रिक एवं साख नीति एवं उपायों का व्यवस्थित विश्लेषण दिया है । इस विश्लेषण के आधार पर हम अपने शोध कार्य में आठवीं पंच वर्षीय योजना एवं उसके बाद की साख नीति एवं नियोजन के स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं । साथ ही साथ विभिन्न पंच वर्षीय योजनाओं में प्रयुक्त मौद्रिक एवं साख उपायों की उपब्धियों तथा असफलताओं का विश्लेषण शोध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अध्ययन के इसी क्रम में प्रो० एस०

एस0 मिश्र ने 'मैनी इनफ्लेशन एण्ड गोथ,' में मुद्रा पूर्ति तथा मुद्रा स्फीति सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन किया है और यह दिखाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास सदैव स्फीतिकारी रहा है।

मुद्रा पूर्ति विश्लेषण के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट (1961) तथा बाद में सेकेण्ड वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट (1977) का उल्लेख महत्वपूर्ण होगा। प्रथम रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मुद्रा पूर्ति के विश्लेषण को शुद्ध बैंकिंग सैद्धान्तिक तथा मौद्रिक दायित्वता तथा वित्तीय आदेशों के समानता के आधार पर किया गया है। इसमें मुद्रा पूर्ति की अवधारणा को सकीर्ण रूप में लिया गया है और व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंकों के समय जमाओं को मुद्रा पूर्ति से बाहर रखा गया है। दूसरी परिवर्तित दशाओं के सम्बन्ध में दी गयी रिपोर्ट मुद्रा पूर्ति की व्यापक अवधारणा को स्पष्ट करती है तथा मुद्रा पूर्ति को चार स्वतन्त्र स्तरों में विभक्त करके विश्लेषण करती है। इन उपर्युक्त रिपोर्टों के साथ प्रारम्भिक विश्लेषण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'फक्शन एण्ड वर्किंग आफ दि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,' पुस्तिका भी महत्वपूर्ण है। इसमें केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों तथा कार्यवधि पद्धति का विश्लेषण किया गया है, जो विभिन्न मौद्रिक नियंत्रणों तथा उपायों के विश्लेषण हेतु विशेषकर भारतीय कृषि क्षेत्र में चयनात्मक साख नियंत्रण विधि के लिये महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट 'ए रिव्यू आफ दि एग्रीकल्चरल, क्रेडिट सिस्टम इन इण्डिया' में भारतीय कृषि क्षेत्रों में साख व्यवस्था तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है। इसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम कृषि साख व्यवस्था नाबार्ड द्वारा संचालित की जाती है, जो व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्तीयन करता है। यह रिपोर्ट कृषि साख की आवश्यकता और भावी कृषि साख प्रेक्षकों के दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में संस्थागत तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप साख की संरचना, आवश्यकता एवं स्वरूप में

भी परिवर्तन आया है । इस आधार पर प्रस्तुत शोध कार्य में यह देखने का प्रयास किया जायेगा कि किस तरह उपयुक्त मौद्रिक एव साख नीति तथा नियोजन के आधार पर कृषि क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की साख आवश्यकता को उत्पादकता के दृष्टिकोण से पूरा किया जाये। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि वित्तीयन एव साख प्रबन्ध के सम्बन्ध में नाबार्ड की भूमिका और उसके प्रगति सम्बन्धी विश्लेषण को नाबार्ड के वार्षिक रिपोर्ट में, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रकाशित की जाती है, यह भी प्रस्तुत शोध की दिशा के लिये महत्वपूर्ण होगा । नाबार्ड की स्थापना के बाद से ही वार्षिक रिपोर्ट कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्वित्तीयन के माध्यम से साख - व्यवस्था में जो प्रगति किये हैं, वह जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं इस बात को इंगित करता है कि नाबार्ड की पुनर्वित्तीयन व्यवस्था तथा सम्पूर्ण ग्रामीण तथा कृषि साख की व्यवस्था के सदर्भ में क्या नीतिगत परिवर्तन किया जाय । प्रस्तुत शोध में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि नाबार्ड की नीतियों और कार्यपद्धति में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है।

शोध अध्ययन के साहित्य समीक्षा के दृष्टिकोण से एस0 एल0 एन0 सिम्हा तथा ए0 रमन द्वारा सम्पादित पुस्तक 'क्रेडिट प्लानिंग एण्ड पॉलिसी' में साख नियोजन तथा साख नीति निर्माण विशेष उल्लेखनीय है । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम साख नीति क्या रही है और कहा तक यह चयनात्मक साख नियंत्रणों को सफलतापूर्वक अपनाया है । इसमें इस बात को भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा किस तरह कृषि क्षेत्र का वित्तीयन किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम साख नियंत्रण नीति के सम्बन्ध में इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में सरकार शुद्ध बैंक साख, व्यापारिक क्षेत्र का शुद्ध बैंक साख तथा बैंकिंग क्षेत्र के विदेशी विनिमय आदेय हैं । साख नियोजन के स्वरूप और उसकी मात्रा निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विश्लेषण शोध कार्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । डा0 वी0 एस0 महाजन द्वारा सम्पादित एक पुस्तक 'स्टडीज इन इण्डियन' एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट में सस्थागत वित्त द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन वर्गों के लिये क्रियान्वित विकासात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया

गया है और इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सस्थाओं की वृद्धि तथा साख प्रवाह के बावजूद भी कमजोर वर्ग साख - सुविधाओं से वंचित रहे हैं। यह विश्लेषण इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत शोध साहित्य के लिये उपयोगी होगा कि सीमान्त कृषक, भूमिहीन श्रमिक तथा ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से किस तरह साख नीति और नियोजन किया जाय ।

भारतीय ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु बैंक वित्त के सम्बंध में सम्पादित एल० के० नायडू की पुस्तक 'बैंक फाइनेन्स फॉर रुरल डेवलपमेन्ट' में प्रकाशित लेख ' बैंक फाइनेन्स एण्ड एग्रीकल्चर' (लेखक - एस० नीलाकनियन) में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास गया है कि कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों की क्या भूमिका रही है । यहा इस बात को दिखाया गया है कि व्यापारिक तथा अन्य ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेषकर कृषि विकास हेतु ये बैंक परिवर्तित दशाओं में अपना योगदान कर सकते हैं ।

मौद्रिक नीति के सम्बंध में भारत के साथ अन्य अल्प विकसित देशों में मौद्रिक नीति सम्बंधी विश्लेषण एशियन डेवलपमेंट रिव्यू, फिलीपीन्स द्वारा सम्पादित 'एशियन डेवलपमेंट रिव्यू-स्टडीज ऑफ एशियन एण्ड पैसिफिक इकनॉमिक इश्यूज' में भारत, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, मयानमार, फिलीपीन्स, श्रीलंका, थाईलैण्ड आदि देशों में मौद्रिक नीति एवं उपायों का अध्ययन किया गया है और यह स्थापित किया गया है कि पिछले बीस वर्षों में एशिया के इन देशों में मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं । मौद्रिक नीति की सफलता की मात्रा हर देश में अलग - अलग रही है और इसकी प्रभावकारिता वित्तीय एवं आर्थिक सुधारों पर आधारित है ।

1.5 शोध अध्ययन का अध्याय क्रम -

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को निम्नलिखित अध्यायों में बाटा गया है -

अध्याय 1 - प्रस्तावना, शोध अध्ययन का स्वरूप, औचित्य एवं प्रमुख बातें ।

अध्याय 2 - मौद्रिक एवं साख नीति के सिद्धान्त

अध्याय 3 - मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्त, रिजर्व बैंक विश्लेषण, मौद्रिक नीति हेतु

नीति परक बातें

अध्याय 4 - भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं साख नीति - पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत

अध्याय 5 - कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति

अध्याय 6 - भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा कृषि साख ।

अध्याय 7 - कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता ।

अध्याय 8 - सारांश, निष्कर्ष एवं नीति परक सुझाव ।

प्रथम अध्याय, शोध प्रबन्ध के प्रस्तावना से सम्बन्धित है । इसमें शोध प्रबन्ध के विषय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । शोध विषय के महत्व पर प्रकाश डाला गया है तथा शोध कार्य के औचित्य को स्पष्ट किया गया है । इसमें शोध के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है तथा विषय से सम्बन्धित प्रमुख बातों पर प्रकाश डाला गया है । अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिनका परीक्षण एवं सत्यापन शोध विवरणों में किया जायेगा । मौद्रिक एवं साख नीति के बारे में सामान्य जानकारी दी गयी है और साथ ही एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति के महत्व को स्पष्ट किया गया है । भारत के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट किया गया है । मौद्रिक एवं साख नीति के महत्व को कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है । इसमें शोध अध्ययन

विधि का व्योरा दिया गया है । इस अध्याय में उपलब्ध - साहित्य की समीक्षा भी प्रस्तुत किया गया है ।

दूसरा अध्याय मौद्रिक एवं साख नीति के सिद्धान्त से सम्बंधित है । इसमें केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक एवं साख नीतियों के सैद्धान्तिक पक्ष का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मौद्रिक नीति एवं साख नीति क्या है, इसके अवयव क्या हैं, इनके उपकरण क्या हैं तथा इनके लक्षण और उद्देश्य क्या हैं । इसमें मौद्रिक एवं साख नीति का वित्तीय नीति, आय नीति, मजदूरी नीति तथा अन्य नीतियों से सम्बंध को स्पष्ट किया गया है । इस अध्याय में मौद्रिक एवं साख नीति की अवधारणा को दिया गया है तथा इसके अवरोधों का वर्णन किया गया है । आर्थिक नीति के समष्टिभावी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सस्ती मुद्रा नीति की मान्यताओं और महत्व का उल्लेख किया गया है । आर्थिक विकास और मूल्य स्थायित्वता के संदर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट किया गया है । इस अध्याय में रेडक्लिफ कमिटी की रिपोर्ट पर भी एक विहंगम दृष्टि डाली गयी है । अन्त में यह दिखाया गया है कि मौद्रिक नीति क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ।

तीसरे अध्याय में मुद्रापूर्ति के सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है । इसमें मुद्रापूर्ति के अर्थ और इसके विश्लेषण से सम्बंधित प्रमुख सिद्धान्तों की विवेचना किया गया है । इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रापूर्ति विश्लेषण तथा मुद्रापूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण भी किया गया है । मुद्रापूर्ति के सिद्धान्तों का विश्लेषण भारतीय संदर्भ में भी किया गया है । इसके साथ ही मुद्रापूर्ति के अर्थ एवं प्रमुख अवयवों को दिया गया है । इसमें मुद्रा साख गुणक के सिद्धान्त की विवेचना की गयी है । मुद्रापूर्ति का उच्चार्ध (एच) सिद्धान्त को भी दिया गया है । साथ में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा-जोखा मुद्रा पूर्ति का विश्लेषण किया गया है । अन्त में साख की पूर्ति तथा इसको निश्चित करने वाले तत्वों की व्याख्या किया गया है ।

चौथे अध्याय में योजनावधि में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति को दिया गया है । इसमें प्रथम एवं द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना से इसका विस्तृत अध्ययन किया गया है । साथ ही तीन वार्षिक योजनाओं में मुद्रा एवं साख नीति का विश्लेषण अलग से किया गया है । अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति में नवीनतम परिवर्तन का वर्णन किया गया है ।

पाचवें अध्याय में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति का अध्ययन कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया है । इसमें प्रारम्भ में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति को स्पष्ट किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने वाली अन्य वित्तीय एजेंसियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । भारत में कृषि साख व्यवस्था की व्याख्या की गयी है । अतः में भारत में कृषि वित्त में मौद्रिक एवं साख नीति के महत्व को स्पष्ट किया गया है ।

छठे अध्याय में भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के महत्व एवं योगदान को स्पष्ट किया गया है । इसमें नाबार्ड की स्थापना, कार्य एवं सगठनात्मक संरचना का विवरण दिया गया है । इसमें नाबार्ड के संसाधन एवं लाभकारिता से सम्बंधित कुछ प्रश्नों को भी प्रस्तुत किया गया है । अतः में नाबार्ड को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को दिया गया है ।

सातवें अध्याय में कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता का वर्णन किया गया है । इसमें मौद्रिक एवं साख नीति की सीमाओं को दिया गया है । इसमें दिखाया गया है कि वे क्या सीमाएँ हैं, जिनके कारण ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में विकास हेतु ये नीतियाँ पूरी तरह से प्रभावकारी नहीं हो पा रही हैं । कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख, ऋणों की वसूली की समस्या पर भी विचार किया गया है । इन क्षेत्रों में मौद्रिक एवं साख नीतियों की असफलता को

दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की प्रकृति और क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसी अध्याय में कृषि क्षेत्र में मौद्रिक लक्ष्य तथा नियोजित मुद्रा एवं साख पूर्ति के सदर्थ में चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट तथा उसकी सस्तुतियों का विवरण दिया गया है । इन क्षेत्रों में 2000 ए डी तक मौद्रिक एवं साख प्रक्षेप दिया गया है । अतः में कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है ।

आठवें और अन्तिम अध्याय में सम्पूर्ण शोध कार्य का सारांश और निष्कर्ष दिया गया है । साथ ही साथ इसमें कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए साख नीति से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को ही दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति की कमियों को दूर करने सम्बंधी सुझावों का उल्लेख तीव्र आर्थिक विकास के सदर्थ में किया गया है ।

उपरोक्त अध्यायों के विश्लेषण के साथ प्रारम्भ में मुद्रा पूर्ति तथा साख सृजन के सैद्धान्तिक पक्षों का विवेचन किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक के 1961 तथा 1976 के मुद्रा पूर्ति अवधारणा के सदर्थ में यह स्पष्ट किया गया है कि मुद्रापूर्ति तथा साख प्रवाह किस रूप में हुई है । मुद्रापूर्ति के इस सैद्धान्तिक विवेचन का उद्देश्य उन कारकों तथा अवयवों की व्याख्या करनी है, जो मुद्रापूर्ति तथा साख प्रवाह को प्रभावित तथा निर्धारित करते हैं तथा उनके नियन्त्रण के आधार पर मौद्रिक व साख नीतियों का निर्माण किया जाता है । मुद्रापूर्ति के वर्तमान अवधारणा के अनुसार समय जमायें भी सम्मिलित की जाती हैं, जो मोटे तौर पर गर्लें शों के गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के विश्लेषण के आधार पर है । मौद्रिक तथा साख नीति के स्वरूप तथा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा सुझाव बहुत कुछ मुद्रापूर्ति तथा साख प्रवाह के विश्लेषण से हैं । चूंकि आधुनिक मुद्रा पूर्ति की अवधारणा $एम_1$, $एम_2$, $एम_3$, $एम_4$ के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, अतः मौद्रिक नीति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है । मुद्रा पूर्ति के सैद्धान्तिक विश्लेषण के साथ-साथ इस बात की विस्तृत व्याख्या की गयी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास सदर्थों में मौद्रिक नीति और साख नीति के

क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों में मूल्य स्थायित्व, रोजगार में वृद्धि, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा असमानता को दूर करना, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में साख सुविधाओं के विस्तार के द्वारा विकास की सम्भावनाओं को उत्पन्न करना, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं का समाधान करना । इन उद्देश्यों के सदर्भ में मौद्रिक व साख नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करके यह प्रयत्न किया जायेगा कि मौद्रिक व साख नीति को इन उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु कैसे और प्रभावकारी बनाया जाय । इस तरह मौद्रिक एवं साख नीति से सम्बंधित विश्लेषण देश के वृषि क्षेत्र के विशेष सदर्भ में उपयुक्त तथा प्रभावकारी मौद्रिक साख नीति के निर्माण में सहयोगी होगा ।

मौद्रिक एवं साख नीति के सिद्धान्त

(THEORY OF MONETARY AND CREDIT POLICY)

प्रस्तुत अध्याय में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के मौद्रिक एवं साख नीतियों के सैद्धान्तिक पक्ष का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। देश के सम्पूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था के प्रधान संस्था के रूप में केन्द्रीय बैंक, मुद्रा और साख में परिवर्तन एवं नियंत्रण करके देश के आर्थिक नीतियों में समस्त भावी आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। अतः यहाँ प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति एवं साख नीति क्या है, इनके क्या अवयव हैं, इनके उपकरण क्या हैं तथा इनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। साथ ही साथ आर्थिक नीति के एक अंग के रूप में मौद्रिक नीति एवं साख नीति किस तरह वित्तीय नीति, आय नीति, मजदूरी नीति तथा अन्य नीतियों से जुड़ी हुयी है।

2.1 मौद्रिक सिद्धान्त तथा मौद्रिक नीति

वस्तुतः अर्थशास्त्र का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ वर्तमान दृष्टिकोण और समस्याओं के सम्बन्ध में विचार न दिये गये हों, जैसा कि मौद्रिक नीति के क्षेत्र में है। विश्व युद्ध के बाद अर्थशास्त्रियों ने मन्दी अवस्था को समाप्त करने के लिये मौद्रिक प्रसार को सामान्य उपचार माना था, किन्तु मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, क्या मुद्रा स्फीति का भी प्रभावी नियंत्रण है - यह बहुत ही संदेह का विषय रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह विशिष्ट विचार लिया कि मौद्रिक नियंत्रण पूर्णतः अप्रभावकारी है, किन्तु सामान्यतः यह अनुभव किया गया कि युद्ध काल के समय अत्यधिक सार्वजनिक ऋण के कारण मौद्रिक नीति के प्रयोग में प्रधान बाधा रही।¹ कोरिया युद्ध के पश्चात् अल्पकालीन उतारचढ़ाव के नियंत्रण में मौद्रिक नीति प्रमुख उपकरण के रूप में स्थापित हुयी। मौद्रिक नीति का प्राप्तता सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और प्रायः सभी अर्थशास्त्रियों ने साख के उपलब्धता और लागत के प्रभावों का विश्लेषण किया। केन्द्रीय अवधि के

1. H.G. Johnson, Essays in Monetary Economics, London, 1967
p. 51.

पूर्व ही इस तरह की अवधारणा की कल्पना की गयी थी, जब मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक नीति का एक मात्र स्थापित उपकरण माना जाता था और मूल्य स्थायित्वता इसका स्थापित उद्देश्य था। केन्सीय अर्थशास्त्र द्वारा वित्तीय और सरकारी क्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया गया और पूर्ण रोजगार द्वारा आर्थिक स्थायित्वता को प्राप्त करने का विचार प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में मुद्रापूर्ति के योगदान को विभिन्न विचारधाराओं द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में रखा गया। आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा पूर्ति पर बहुत महत्व नहीं दिया और इसके प्रभाव को मात्र अनुपातिक मूल्यों में वृद्धि तक ही सीमित रखा। इस तरह आर्थिक व्यवस्था के आधारभूत क्रियान्वयन में इसके योगदान को निष्क्रिय रूप में देखा गया। चूँकि इसका प्रभाव मूल्यों पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ता है, अतः इसे महत्वपूर्ण माना गया। वस्तुतः आर्थिक क्षेत्र में मुद्रामहत्व का विश्लेषण केन्स के योगदानों से स्पष्ट होता है, क्योंकि केन्सीय मौद्रिक सिद्धान्त का मूल तत्त्व इस बात को स्पष्ट करने में है कि एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था मूल रूप से एक लेन-देन अर्थव्यवस्था से भिन्न है और मुद्रा मात्र एक पर्दा नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।² केन्स ने अपने मौद्रिक विश्लेषणों और ब्याज-दर सिद्धान्त द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि ब्याज-दर में परिवर्तन किस तरह अर्थव्यवस्था में विनियोग तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है।

मौद्रिक नीति के उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि मौद्रिक और साख नीति का आधार मौद्रिक सिद्धान्त है और ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। वस्तुतः मौद्रिक सिद्धान्त मौद्रिक

-
2. The fundamental contention of Keynesian monetary theory is that a monetary economy is essentially different from a barter economy that money is not merely a veil but exercises an influence of its own in the working of the economy", - . H.G. Johnson, The General Theory After Twenty Five Years, American Economic Review, May 1961, p. 10.

नीति के लिये आधारशिला उत्पन्न करता है। अतः संक्षेप में मौद्रिक सिद्धान्तों में हुये विकास का अवलोकन मौद्रिक नीति के योगदान और महत्व को स्थापित करने में सहायक होगा। इस तरह मौद्रिक सिद्धान्त को उन सभी सिद्धान्तों के संयोग रूप में देखा जा सकता है, जो आर्थिक व्यवस्था पर मुद्रा की मात्रा के प्रभाव से सम्बन्धित है तथा मौद्रिक नीति को उस नीति के रूप में देखा जा सकता है, जिसका प्रयोग देश के केन्द्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण से आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।³

केन्सीय क्रान्ति के पूर्व मौद्रिक सिद्धान्त मुख्य रूप से मूल्यस्तर का सिद्धान्त था और सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित था।⁴ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को मात्र विनिमय का माध्यम माना था और इससे फिशर तथा केम्ब्रिज प्रमुख अर्थशास्त्री सम्बन्धित है। फिशर का प्रमुख विनिमय समीकरण $MV = PT$ तथा केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के नगद-शेष समीकरण $M = PKT$ मुख्य रूप से अनुपातिकता नियम को स्थापित करने से थे। विक्सल ने इसमें प्राकृतिक व्याजदर और बाजारी व्याज-दर के आधार पर अनुपातिकता नियम की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इस सैद्धान्तिक विश्लेषण को मौद्रिक नीति के लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सारी आर्थिक क्रियाओं के उतार-चढ़ाव के कारणों का एक मात्र आधार मुद्रा-पूर्ति में परिवर्तन को माना गया है। अतः मुद्रा-पूर्ति नियंत्रण के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थायित्वता प्राप्त की जा सकती है। इसका अभिप्राय यह भी है कि वित्तीय नीति का स्थायित्वता हेतु कोई योगदान नहीं है और इसका सम्बन्ध मात्र सार्वजनिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के बटवारे तक सीमित है। इस सैद्धान्तिक विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मुद्रा अपने प्रभावों में तटस्थ है और अर्थव्यवस्था में बचत, आय, उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

1928 के महान मन्दी के बाद अर्थव्यवस्था को मन्दी की स्थिति से दूर करने के सम्बन्ध में केन्सीय विश्लेषण के द्वारा मौद्रिक नीति के स्थान पर वित्तीय नीति का तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व स्थापित किया गया। केन्स ने अपने मौलिक समीकरणों तथा सामान्य

3. H.G. Johnson Op. cite., p.15

4. L.V. Chandler, An Out Line of Monetary Theory, Allahabad, 1973, p. 17.

सिद्धान्त में मौद्रिक सिद्धान्तों तथा ब्याज-दर विश्लेषण से इस बात को स्थापित किया कि मौद्रिक सिद्धान्त और मौद्रिक नीति के सम्बन्ध मात्र मूल्य स्तर के परिवर्तनों से नहीं है, अपितु यह अर्थव्यवस्था में बचत, विनियोग, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर से सम्बन्धित है। इस तरह केन्स ने अपने ब्याज-दर विश्लेषण और तरलता जाल सम्बन्धित विश्लेषण से मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक अधिकारियों की एक अधिकतम सीमा को स्पष्ट किया और इस बात को स्थापित किया कि जहाँ मौद्रिक अधिकारी अपने नीति एवं नियंत्रणों द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को उत्पन्न करने एवं विनियोग में वृद्धि करने में असफल रहते हैं, वहीं वित्तीय नीति एवं सरकारी हस्तक्षेप द्वारा पूर्ण रोजगार, उत्पादन एवं आय की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

केसोपरान्त मौद्रिक सिद्धान्त के विकास में डॉन पेटिन्किन, फ्रीडमैन, गर्ले-शॉ आदि अर्थशास्त्रियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। डॉन पेटिन्किन ने अपने वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धान्त द्वारा व्यक्ति एवं समष्टि स्तर पर केम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में निहित आनुपातिकता नियम को पुनः स्थापित किया और मुख्य रूप से मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार के अंतः प्रक्रिया द्वारा केन्सीय ब्याज सिद्धान्त के निष्कर्षों के विपरीत इस बात को स्थापित किया कि मुद्रा तटस्थ है और इसके परिवर्तन के परिणामस्वरूप ब्याज-दर एवं विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह इस विश्लेषण में भी मौद्रिक नीति की महत्ता स्थापित होती है।

शिकागो विश्वविद्यालय के मिल्टन फ्रीडमैन ने मौद्रिक सिद्धान्त का विश्लेषण सैद्धान्तिक एवं अनुभवगम्य दोनों रूपों में किया है। अपने सैद्धान्तिक विश्लेषण में मुद्रा माग सिद्धान्त के आधार पर यद्यपि वे किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके, पर उन्होंने अपने मुद्रा माग को एक स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित किया है, जिससे यह केम्ब्रिज मुद्रासिद्धान्त के सन्निकट हो जाता है। उन्होंने अमेरिका में 1887 से 1960 के अन्तर्गत प्रमुख चरों-मुद्रा पूर्ति, राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर, ब्याज दर, कुल उपभोग, व्यय आदि सम्बन्धित अनुभवगम्य तथ्यों तथा आँकड़ों के आधार पर मुद्रा के आय प्रचलन वेग को दीर्घकाल में स्थिर मानते हुये मौद्रिक नीति प्रभावकरिता को स्थापित किया।⁵ फ्रीडमैन ने

5. Milton Friedman and A.J. Schwartz, A Monetary History of United States, 1867- 1960, Princeton University Press.

मौद्रिक विश्लेषण को मौद्रिक नीति और आर्थिक नीति के क्रियान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण सुझावों से सम्बन्धित किया है। यदि मुद्रा मांग फलन को स्थिरांक के रूप में दिखाया जा सके तो यह सरकार के लिये आर्थिक नीति हेतु बहुत उपयोगी होगा और इसके द्वारा मुद्रापूर्ति के द्वारा अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभावों को दिखाया जा सकता है और इस तरह मौद्रिक क्षेत्र में पूर्वानुमानों द्वारा मौद्रिक महत्व को दिखाया जा सकता है। फ्रीडमैन समस्त स्तर पर आर्थिक नीति हेतु यह मानते हैं कि रोजगार तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु मुद्रा नीति की वृद्धि आवश्यक है। उन्होंने अपने विश्लेषण से स्थापित किया है कि केन्सीय आय गुणक की तुलना में आय प्रचलन वेग अधिक स्थायी है।⁶ उन्होंने यह भी माना है कि मुद्रा की मांग व्याज-दर परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती और इसलिये इसकी वृद्धि हेतु चलन में मुद्रा पूर्ति का होना आवश्यक है और इस तरह उन्होंने समग्र मुद्रा मांग को बढ़ाने में मौद्रिक नीति को प्रमुख आधार माना। फ्रीडमैन के विश्लेषण में अर्थव्यवस्था के मौद्रिक आय तथा मूल्य नियंत्रण में मुद्रा पूर्ति एक केन्द्र बिन्दु है और इसलिये वर्ष-प्रतिवर्ष मुद्रा स्टॉक की वृद्धि एक निश्चित दर से होनी चाहिये। इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए एक अनुकूलतम मुद्रा की मात्रा होना आवश्यक है और इसी रूप में मूल्य स्थायित्वता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यह दिखाया कि चूंकि आर्थिक नीतियों की प्रभावकारिता में समय-अन्तराल की कोई निश्चितता नहीं है, अतः बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ तथा अन्य विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतियाँ अर्थव्यवस्था में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में स्थायित्वता हेतु उन्होंने गर विवेकपूर्ण नीतियाँ का प्रस्तावित किया। वर्तमान समय में क्रियान्वित की जाने वाली आर्थिक नीतियों का मंत्रिमण्डल में अधिक प्रभावी होने के लिये फ्रीडमैन ने स्थायी आय तथा मूल्य प्रत्याशित परिवर्तन दर एवं लोगों की अभिरूचियों और पसन्दगियों आदि को महत्वपूर्ण आधार बनाया।⁷ इस तरह मौद्रिक नीति के महत्व को स्थापित करते हुए उन्होंने यह दिखाया कि वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति का एक अंग है और अपने आपमें इनकी कोई अलग स्तुता

6. Milton Friedman, *Dollars and Deficit*, 1968, p. 14.

7. Milton Friedman, *A Theory of Consumption Function*, 1957, p. 57.

नहीं है।

फ्रीडमैन के मौद्रिक विश्लेषण के बाद रेडक्लिफ कमेटी रिपोर्ट तथा गर्ले-शॉ के मौद्रिक सिद्धान्त सम्बन्धित सस्थागत उपागमों के आधार पर मौद्रिक सिद्धान्त एवं मौद्रिक नीति को एक नया रूप दिया गया।⁸ इसमें मुद्रापूर्ति को एक व्यापक अर्थ में अर्थव्यवस्था के सामान्य तरलता के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय सस्थाओं तथा मध्यस्थों के उदय होने से बाह्य मुद्रा में आन्तरिक मुद्रा के समावेश द्वारा इस बात को स्पष्ट किया कि मुद्रा गैर तटस्थ है और यह महत्वपूर्ण रूप से व्याज-दर को प्रभावित करती है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ लगभग वही कार्य करते हैं, जो व्यापारिक बैंक करते हैं। अतः ये महत्वपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं एवं विनियोग आदि निर्णयों को प्रभावित करते हैं।⁹ इस तरह गर्ले-शॉ के विश्लेषण से मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन क्षेत्र तथा प्रभावकारिता बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि व्यापक अर्थ में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को पूरी बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के क्रियाओं को भी नियंत्रित करना चाहिये और इस तरह अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति के व्यापक अर्थ में तरलता तथा मौद्रिक ससाधनों को नियंत्रित करने से है। उनका यह मानना था कि इस तरह मौद्रिक नीति के संचालित न होने पर इसकी प्रभावकारिता बहुत कम हो जायेगी।¹⁰

2.2 मौद्रिक एवं साख नीति की अवधारणा

मौद्रिक नीति का अभिप्राय मुद्रापूर्ति सम्बन्धी परिवर्तनों की नीति से है। इसका सम्बन्ध ऐसे उपायों से है, जो अर्थव्यवस्था के कार्यशीलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुद्रा की उपलब्धता और

8. J.G. Gurley and E.S. Shaw, Money in a Theory of Finance, 1960, p.1.

9. Richard Thorn, IMF Staff Papers, Nov. 1958, pp. 271-72.

10. J.G. Gurley and E.S. Shaw, Financial Aspects of Development, p. 527.

इसकी लागत को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में मौद्रिक नीति के अन्तर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं, जो किसी देश के केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों के द्वारा साख-नियंत्रण हेतु प्रयोग किये जाते हैं। मोटे तौर पर मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से तीन अवयव होते हैं-मुद्रा की मात्रा, साख की मात्रा और ब्याज-दर। केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर में परिवर्तन करके ब्याज-दर और ब्याज संरचना में परिवर्तन करती है और इसी आधार पर देश में मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसी तरह मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएँ तथा आरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन करती है। केन्द्रीय बैंक के मुद्रा और साख नियंत्रण की चयनात्मक विधियाँ भी हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा तथा साख की मात्रा और दिशा का नियंत्रण किया जाता है। इस तरह मौद्रिक नीति के अन्तर्गत ही केन्द्रीय बैंक की परिमाणात्मक और चयनात्मक मुद्रा और साख नियंत्रण की विधियाँ निहित हैं।

मौद्रिक नीति की ही तरह साख नीति भी साख पूर्ति परिवर्तनों से सम्बन्धित हैं, किन्तु मौद्रिक नीति की तुलना में साख-नीति कई कारणों से भिन्न है। प्रथमतः मौद्रिक नीति की अपेक्षा साख नीति मात्र समग्र पूर्ति से ही सम्बन्धित नहीं है, अपितु विभिन्न क्षेत्रों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच उसके निर्धारण से सम्बन्धित है। इसी तरह साख के स्रोतों में भी भिन्नता है, इसमें सस्थागत और गैर-सस्थागत स्रोत हैं और सस्थागत स्रोतों में भी बैंक केवल एक स्रोत है। मात्रा के अलावा साख के अन्य पहलू जैसे, इसकी लागत, इसकी शर्तें एवं दशाएँ, अवधि, इसका पुर्निकरण, जोखिम आदि उधार लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह साख नीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मौद्रिक और साख नीतियों में कुछ और भी अन्तर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो प्रस्तुत विश्लेषण के लिये उपयोगी हैं। मुख्य रूप से मुद्रा एक आदेह, जो लोग अपने पास रखते हैं, किन्तु यह सरकार और रिजर्व बैंक का दायित्व भी है, जबकि बैंक-साख बैंकों का आदेह तथा उधार लेने वाले लोग तथा सरकार का दायित्व है। इस तरह आदेह तथा दायित्व का अन्तर मौद्रिक और साख नीति के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अन्तर मौद्रिक नीति और मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के लिये भी आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट किया जा सकता है कि केम्ब्रिज उपागम एवं केन्सीय उपागम मौद्रिक नीति का आधार होगा। मोटे तौर पर यदि मुद्रा मांग फलन भी हो, तो भी मुद्रा पूर्ति

मे एक स्वायत्त परिवर्तन या तो प्रत्यक्ष मौद्रिक आय पर परिवर्तन करता है अथवा प्रथमतः ब्याज-दर में परिवर्तन करके, विनियोग दर में परिवर्तन के द्वारा, अन्ततः आय में परिवर्तन करता है। किन्तु इसी तरह साख-पूर्ति प्रभाव के सम्बन्ध में बैंक-साख में परिवर्तन किस तरह आन्तरिक चरणों को परिवर्तित करेगा, इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त विकसित नहीं करेगा, चूँकि केन्द्र के मौद्रिक सिद्धान्त में आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव मुद्रापूर्ति-परिवर्तन के द्वारा प्रथमतः ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा दिखाया जाता है, अतः यह सिद्धान्त साख लागत का सिद्धान्त कहा जा सकता है। इसी कारण केन्द्र के मौद्रिक नीति में सबसे अधिक जोर ब्याज दर परिवर्तन पर दिया जाता है और यह अन्तर केन्सीय मौद्रिक नीति सिद्धान्त से मौद्रिक अर्थशास्त्रियों के मौद्रिक नीति सिद्धान्त, मुद्रा पूर्ति और बैंक साख पूर्ति के सिद्धान्त में कई बिन्दु समान हैं। समान अधिकारी के रूप में केन्द्रीय बैंक दोनों नीतियों का निगमन करता है। समस्त स्तर पद दोनों के उपकरण समान हैं तथा मुद्रा पूर्ति एवं साख नीति को एक ही तरह की शक्तियाँ निर्धारित करती हैं और इस तरह यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि मौद्रिक एवं साख नीति समान हैं।¹¹

मौद्रिक नीति के सिद्धान्त में वर्तमान विश्लेषण में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों, लक्ष्यों, सूचकों तथा उपकरणों में भेद किया जाता है। इस सम्बन्ध में भ्रम को दूर करने की दृष्टिकोण से इनके अन्तर को निम्न रूप से दिखाया जा सकता है -

मौद्रिक नीति

(MONETARY POLICY)

उद्देश्य (Goals)

- 1 अधिकतम सम्भाव्य उत्पादन
- 2 उच्च आर्थिक विकास
- 3 पूर्ण रोजगार
- 4 मूल्य स्थायित्वता या मुद्रा स्फीति की अनुकूलतम दर
- 5 धन एवं आय वितरण में अधिक समानता

6 भुगतान-संतुलन में स्वस्थ संतुलन

लक्ष्य (Targets)

- 1 मुद्रा पूर्ति
- 2 बैंक साख
- 3 ब्याज-दर

सूचक (Indicators)

- 1 उच्च अर्ध मुद्रा
- 2 मुद्रा पूर्ति
- 3 बैंक साख
- 4 ब्याज-दर

उपकरण (Instruments)

- 1 घाटे की वित्त व्यवस्था
- 2 खुले बाजार की क्रियाएँ
- 3 आरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन
- 4 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का साख
- 5 वैधानिक तरलता अनुपात
- 6 चयनात्मक साख नियंत्रण

मौद्रिक नीति के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इसका तात्पर्य उन अनेक मौद्रिक उपायों तथा विधियों से है, जिसके आधार पर किसी देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा, साख की मात्रा तथा ब्याजदर में परिवर्तन की सारी क्रियाएँ मौद्रिक नीति के अन्तर्गत रखते हैं। मौद्रिक नीति के एक विस्तृत अर्थ में अर्थव्यवस्था के उन सभी मौद्रिक तथा वित्तीय उपायों को सम्मिलित करते

है, जिनका नियमन तथा संचालन पूरी तरह बैंकिंग व्यवस्था द्वारा होती है।

इस रूप में केन्द्रीय बैंकों के साथ-साथ व्यापारिक बैंकों तथा गैर-वित्तीय बैंकों के उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सम्बन्ध मुद्रा दर, साख परिवर्तन से है। मौद्रिक नीति के इस व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि अल्पकालीन समयावधि प्रतिभूतियों को खरीदने तथा दीर्घ कालीन प्रतिभूतियों को बेचने में भी मुद्रा तथा साख परिवर्तित होती है।¹² अब यदि अर्थव्यवस्था के अनेक मौद्रिक तथा वित्तीय कार्यों का सम्बन्ध मौद्रिक नीति से है तो ऐसी दशा में मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति में अन्तर करना तथा विभाजन करना मुश्किल है और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था की सामान्य आर्थिक नीति में मौद्रिक नीति को स्थापित करते हुए आधुनिक मौद्रिक अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का यह विचार है कि वित्तीय नीति वास्तव में मौद्रिक नीति का ही एक अंग है और इसकी अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।

क्योंकि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था की सामान्य आर्थिक नीति का एक अंग है। अतः वित्तीय नीति तथा अन्य आर्थिक नीतियों से इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है, पर इस सम्बन्ध का तात्पर्य यह नहीं है कि वित्तीय नीति मौद्रिक नीति का एक मात्र अंग है और इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यद्यपि यह बात तो सही है कि मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति में कोई स्पष्ट अन्तर तथा विभाजन रेखा दिखाना संभव नहीं है, पर मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बजट अतिरेक के आकार में परिवर्तन वित्तीय नीति में परिवर्तन तथा ब्याजदर में परिवर्तन मौद्रिक नीति का सूचक है। वित्तीय नीति के इस अन्तर के साथ जहाँ तक उनके सम्बन्ध की बात है, उसमें मौद्रिक नीति अपने फलनात्मक क्रिया के द्वारा कभी-कभी वित्तीय नीति का रूप ले लेती है और इसी तरह वित्तीय नीति भी कभी-कभी मौद्रिक नीति में बदल जाता है। उदाहरण के लिए यदि अर्थव्यवस्था में घाटे के बजट को पूरा करने के लिए करें, सार्वजनिक ऋणों तथा अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ यह वित्तीय नीति से सम्बन्धित है, पर यदि घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त

12. G.K. Shaw, An Introduction to the Theory of Macro Economic Policy, p. 65.

मुद्रा को छाप कर घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है तो यहाँ मौद्रिक नीति का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि मौद्रिक तथा वित्तीय नीति पारस्परिक सहयोग अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

पिछले समयों से मौद्रिक नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन हुआ है। किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक को अब यह निर्णय करना होता है कि साख प्रदान करने तथा विनिमय निर्णय अधिकारियों को नीतियों में परिवर्तन करने है। इस विशिष्ट अर्थ में मौद्रिक नीति को परिभाषित करने के लिए यह मुद्रा एव साख की उपलब्धता, लागत तथा प्रयोग के नियंत्रण से सम्बन्धित है।¹³ मौद्रिक नीति का परम्परागत कार्य केन्द्रीय बैंक करता है, जो एक मौद्रिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य करता है और इसका सम्बन्ध मोटे तौर पर देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था से है।

डॉ पॉल इनजिग ने मौद्रिक नीति को इस तरह परिभाषित किया है कि यह किसी देश की मौद्रिक व्यवस्था, जो इसके नियंत्रण में है उसके प्रति राजनैतिक अधिकार की प्रवृत्ति है।¹⁴ इसी तरह क्राउथर ने भी मौद्रिक नीति की परिभाषा इस रूप में की है कि मौद्रिक व्यवस्था की क्रियान्वयन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के प्रभाव का न्यूनतम करना है।¹⁵

एक क्रियात्मक मौद्रिक नीति इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यह मौद्रिक अधिकारियों द्वारा लिए गये उन उपायों से है, जिससे आर्थिक कल्याण तथा अर्थव्यवस्था का सामाजिक दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाता है। मौद्रिक नीति एक दूसरे दृष्टिकोण से भी परिभाषित किया जाता सकता है। ऐसे सभी मौद्रिक निर्णय और उपाय बिना इस बात का ध्यान रखे कि उनका उद्देश्य मौद्रिक या गैर-मौद्रिक है और इस तरह सभी गैर-मौद्रिक निर्णय और

13. C.S. Nagpal, Monetary Policy and Inflation in India p.11.

14. Dr. Paul Einzig, How Money is Managed, London, 1954 p. 38.

15. G. Crowther, An outline of Money, Delhi, 1969, p.176.

उपाय, जिनके उद्देश्य मौद्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने से है, वे सभी मौद्रिक नीति के अन्तर्गत आते हैं।¹⁶

मौद्रिक नीति के अर्थ को स्पष्ट करने में यह भी आवश्यक है कि इससे सम्बन्धित अन्य सामान्य नीतियों से इसका अन्तर दिखाया जाय। मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति और बैंकिंग नीति से बहुत समान है। इनमें सम्बन्ध और समानता इतना अधिक है कि प्रायः मौद्रिक नीति और बैंकिंग नीति एक ही मान लिया जाता है, जबकि वित्तीय नीति को मौद्रिक नीति का साध्य और साधन मान लिया जाता है। कभी कभी वे एक दूसरे के पूरक होती हैं, उनमें अन्तर स्पष्ट करना कठिन है, फिर भी उनमें अन्तर है। वित्तीय नीति का सम्बन्ध उन उपायों से है, जो बजट क्रियाओं से सम्बन्धित है। यह सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण से सम्बन्धित नीतियों तथा उपायों के विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। इनका सम्बन्ध तथा क्रियान्वयन वित्तीय नीति द्वारा किया जाता है। इसी तरह मौद्रिक नीति और बैंकिंग नीति में अन्तर इस रूप में किया जा सकता है कि बैंकिंग नीति मौद्रिक नीति का एक भाग है। बैंकिंग नीति कभी-कभी मौद्रिक नीति में परिवर्तन नहीं करते। उदाहरण के लिए चयनात्मक साख नियंत्रण विधियों से सम्बन्धित निर्णय, जबकि बैंकिंग नीति को परिवर्तित करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं करते।

2.3 मौद्रिक नीति के उद्देश्य

यदि मौद्रिक नीति को हम अर्थव्यवस्था की सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक के रूप में मानें तो यह कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति का स्वतः अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है और अपने अधिकतम महत्व के रूप में यह सामान्य आर्थिक नीति की सहायक है।¹⁷ अतः विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं के आधार पर क्रियान्वित की जाने वाली सामान्य आर्थिक नीतियों के ही अनुरूप मौद्रिक

16. Report of the Commission on Money and Credit, 1968, p. 46.

17. Dr. P.D. Hajela, Problems of Monetary Policy in underdeveloped Countries, p. 23.

नीति के उद्देश्य होने चाहिये। स्वतन्त्र आर्थिक नीतियों के स्थान पर आर्थिक क्रियाओं में बढ़ते हुये सरकारी हस्तक्षेप तथा महत्व के कारण आर्थिक नीतियों के बढ़ते हुए महत्व के कारण मौद्रिक नीति का भी महत्व बढ़ा है। आर्थिक नीति के उद्देश्यों में समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक नीति के अनुसार मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित आधार पर दिखाया जा सकता है -

- 1 अधिकतम् आर्थिक सृष्टि
- 2 अधिकतम् उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार
- 3 विनिमय दर का स्थिरीकरण
4. मुद्रा की तटस्थता
- 5 आय का उचित वितरण

आधुनिक आर्थिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में अधिकतम् सम्भाव्य आर्थिक विकास की दर प्राप्त करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में मौद्रिक नीति का भी यह एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है कि मौद्रिक साधनों तथा विधियों में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सृष्टि अधिकतम् हो सके। आर्थिक सृष्टि दर को बढ़ाने में कई महत्वपूर्ण कारण हैं। बिना आर्थिक सृष्टि की वृद्धि की अर्थव्यवस्था के अन्य उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तथा वित्तीय साधनों का प्रयोग आर्थिक सृष्टि दर को बढ़ाने में लगाया जाय। आज जहाँ विकसित तथा अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक सृष्टि को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, वहाँ मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि वह अर्थव्यवस्था के अधिकतम् आर्थिक विकास की प्राप्ति में सहयोग दे। यद्यपि आर्थिक विकास को अधिकतम् करने से सम्बन्धित मौद्रिक नीति के उद्देश्य में बहुत विवाद है, फिर भी अब यह सर्वमान्य विचार है कि अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन आर्थिक विकास की समस्याओं और सम्भावनाओं में मौद्रिक नीति का प्रमुख योगदान है। उपर्युक्त दशाओं में सस्ती तथा महंगी

मुद्रा नीतियों के आधार पर प्रसारपूर्ण तथा सकुचित मौद्रिक दशाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सृद्धि को बढ़ाया जा सकता है।

वर्तमान आर्थिक विकास की विभिन्न सम्भावनाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा अर्द्ध रोजगारी की समस्या विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की सबसे प्रमुख समस्या बनी हुई है, चूंकि बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक है और वह एक चिन्ता की विषय होती जा रही है, अतः मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वह अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में सहायक हो। केन्स ने सबसे पहले इस बात को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया कि यदि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र आर्थिक नीतियों पर छोड़ दिया जाय तो बेरोजगारी की समस्या स्वतः दूर नहीं होगी। अतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया और तभी से पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया है। पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के रूप में मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, ताकि उत्पादकता वृद्धि के साथ उत्पादन तथा आय की मात्रा में वृद्धि हो। इस तरह मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, आय तथा रोजगार के वृद्धि में सहायक होती है। अधिकतम उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन इस रूप में होना चाहिए कि विनियोग की मात्रा बढ़ती रहे। केन्स ने यह दिखाया कि अर्थव्यवस्था में जब तक अप्रयुक्त साधन विद्यमान हैं, तब तक बचत की तुलना में विनियोग की बढ़ती हुई मात्रा से उत्पादन, आय तथा रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है। केन्स ने बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में बैंक-दर (और इसलिए व्याज-दर) में कमी के आधार पर सस्ती मुद्रा नीति का समर्थन किया और इन मौद्रिक परिवर्तनों द्वारा उपयोग तथा विनियोग व्यय के वृद्धि को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बताया। यद्यपि सस्ती मुद्रा नीति के द्वारा रोजगार को बढ़ाना अर्धविकसित देशों में सम्भव नहीं है और इस आधार पर उत्पादन व आय न बढ़कर केवल मुद्रा-स्फीति ही बढ़ती है, पर मौद्रिक नीति के विभिन्न विकल्प विधियों द्वारा रोजगार, उत्पादन तथा आय की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। मौद्रिक नीति द्वारा अधिकतम उत्पादन तथा

पूर्ण रोजगार का तात्पर्य अनुकूलतम् उत्पादन तथा रोजगार से है, जो अर्थव्यवस्था के सामाजिक तथा सस्थागत संरचना पर आधारित है, जहाँ उत्पादन के सभी साधनों को उनकी इच्छानुसार कार्य के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो इससे न केवल उत्पादन की मात्रा कम होती है, अपितु यह मानवीय समस्या के रूप में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये खतरा है। अतः अर्थव्यवस्था में अधिकतम् उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार प्राप्त करना मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

मौद्रिक नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य, जिसे सरकार तथा केन्द्रीय बैंक को प्राप्त करना होता है, वह आन्तरिक मूल्य का स्थिरीकरण है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास के साथ स्थायित्व को प्राप्त करने की समस्या आर्थिक नीति का प्रधान लक्ष्य होता जा रहा है। अतः अर्थव्यवस्था में अधिकतम् उत्पादन एवं पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक विकास के उद्देश्य के प्राप्ति सही माने में तभी हो सकती है, जबकि मूल्य स्तर में अत्यधिक तथा हानिकारक वृद्धि न हो। यदि अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर में वृद्धि या कमी अप्रत्याशित एवं अवाछनीय रूप से होती है तो अत्यधिक लाभ या हानिकारी दशाओं के कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उत्पादन आदि सम्बन्धी सभी दशाएँ तथा योजनाएँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास पर अत्यधिक मुद्रा स्फीति (बढ़ती कीमतें) या मुद्रा संकुचन (घटती कीमतें) का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था के उत्पादन, वितरण, आय तथा रोजगार स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। मूल्य स्तर में अप्रत्याशित परिवर्तन समाज के विभिन्न वर्गों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था का सामान्य आर्थिक विकास खतरे में पड़ जाता है। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक बढ़ती हुई कीमतें आर्थिक विकास के लिए हानिकारक तथा अवाछनीय होती हैं। अतः आर्थिक विकास और स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरह की कीमतों के परिवर्तन को रोका जाय। सामान्यतया मुद्रा-स्फीति तथा संकुचन की दशाओं की मुद्रा तथा साख की मात्रा के आधार पर व्याख्या की जाती है। चूँकि मूल्यों में परिवर्तन को सीधे पूर्ति के परिवर्तन से सम्बन्धित किया जाता है, अतः मूल्य स्थिरीकरण हेतु मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य होना चाहिए कि मुद्रा तथा साख की मात्रा के परिवर्तन द्वारा मूल्य में स्थायित्व हो।

आर्थिक विकास के लिये मूल्य स्थायित्व वाछनीय है और इस कारण मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को सदैव हानिकारक माना जाता है। पर इस सम्बन्ध में मूल्य स्थायित्व का क्या स्वरूप है, इसमें कोई सामान्य मत नहीं है। इस सम्बन्ध में मूल्य परिवर्तन की निम्न तीन विशेष दशाओं का विश्लेषण किया जा सकता है¹⁸ -

- 1 धीमी गति से बढ़ती कीमतें
- 2 धीमी गति से गिरती कीमतें
- 3 स्थिर कीमतें

अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि एक मंद गति से बढ़ती हुई कीमतें अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक न होकर उत्पादन, रोजगार तथा आर्थिक सवृद्धि के लिये आवश्यक है। यदि मूल्य स्तर में वृद्धि अत्यधिक नहीं है और यह नियंत्रित रूप में है तो इससे वांछित विकास तथा स्थायित्व को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह "यदि कीमतों की वृद्धि को कम करके 2-3 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाय तो लगातार होने वाले मन्द गति से इस मुद्रास्फीति का कोई खतरा नहीं रहता।"¹⁹ मूल्यों का सामान्य गति से बढ़ना अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय तथा रोजगार वृद्धि के लिये आवश्यक है। कीमतों की वृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादक तथा विनियोगकर्ता के दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है और इस तरह आर्थिक विकास में सहायक है।

इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि मूल्य स्तर में कमी के द्वारा अर्थव्यवस्था का स्थायित्व अधिक वाछनीय है। यहाँ पर कीमतों का गिरने का तात्पर्य लगातार किसी दर से गिरना न हो कर वास्तव में उत्पादन की वास्तविक लागत में गिरना है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को घटी हुयी मौद्रिक कीमतों के रूप में प्राप्त होना चाहिए। पर इस सम्बन्ध

18. W.W. Haines, Money, Prices and Policy, p. 550.

19. "If price increase could be held down to, say 2 percent per year, such a mild steady inflation need not cause too great alarm", P.A. Samuelson, Economics (4 rth Ed.) p. 270

मे अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि लगातार मुद्रा सकुचन की स्थिति आर्थिक क्रियाओं को लगातार कम उत्पादन तथा कम रोजगार की दशाओं पर ले जायेगी।²⁰

मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा सकुचन की इन उपर्युक्त दशाओं के बीच अर्थव्यवस्था के स्थायित्व को स्थिर कीमत स्तर के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यह स्थिति मुद्रा स्फीति तथा सकुचन की अत्यधिक वृद्धि सीमा से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करती हुयी कुछ अन्य लाभों को लिये हुए है। स्थिर कीमतों के कारण व्यापारिक अनिश्चतता दूर की जा सकती है और इससे आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि अधिक तेजी से सम्भव है। पर यदि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो रही हो, तो यह बेरोजगारी तथा स्थिरकीमत स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होगी।

विनिमय दर के स्थायित्व को कायम बनाये रखना भी मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में लगातार निर्यात की तुलना में आयात बढ़ रहे हों, जिससे विदेशी विनिमय की समस्या हो गयी हो तो ऐसी दशा में इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अन्य प्रभावों को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि विनिमय दर में स्थायित्व प्रदान किया जाय। विनिमय दर में अस्थायित्व के कारण अर्थव्यवस्था के उत्पादन, रोजगार तथा आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः इन प्रभावों को दूर करने के लिये मौद्रिक नीति के लिये यह आवश्यक है कि विनिमय दर को स्थायी बनाया जाय। सामान्यतः मुद्रा नीति के उपर्युक्त प्रयोग के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के बाह्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में करना चाहिये। घाटे के भुगतान सन्तुलन की स्थिति, पूँजी प्रवाह आदि के सम्बन्ध में मौद्रिक नीति अधिक महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्थव्यवस्था के इन बाह्य क्षेत्रों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विनिमय दर से है, अतः विनिमय दर के स्थायित्व के द्वारा मौद्रिक नीति भुगतान सन्तुलन के घाटे तथा पूँजी प्रवाह की समस्या का समाधान कर सकती है। विनिमय दरों में होने वाली लगातार परिवर्तन से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में अनिश्चतता उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यापार की दशा तथा मात्रा प्रभावित होती है।

20. W.W. Haines, Money, Prices and Policy, p. 555.

विनिमय दर की अस्थिरता के कारण देश के आन्तरिक मूल्य पर भी प्रभाव पड़ता है और आन्तरिक तथा विदेशी क्षेत्रों में सट्टेबाजी प्रवृत्तियाँ आरम्भ हो जाती हैं। ऐसे देश जिनका अन्य देशों के साथ घाटे का भुगतान सन्तुलन है और जिनका बहुत सा विकासत्मक आयात अन्य विकसित देशों से है, वहाँ विनिमय दर के परिवर्तित होते रहने पर अनेक आन्तरिक तथा बाह्य समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः अर्थव्यवस्था की आन्तरिक तथा बाह्य स्थिरता के लिये यह आवश्यक है कि मौद्रिक नीति विनिमय दर को स्थायी बनाये।

मौद्रिक नीति के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा को तटस्थ बनाया जाय। मुद्रा की तटस्थता का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं पर मुद्रा का प्रभाव नहीं होना चाहिये। हेयक, हाट्रे तथा विक्स्टीड आदि अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में उतार-चढ़ाव प्रधानतया मौद्रिक कारणों से होते हैं। मुद्रा की मात्रा इस तरह नियंत्रित करना चाहिये कि रोजगार, उत्पादन तथा मूल्य स्तर पर इसके हानिकारक प्रभाव न पड़ सकें। इस रूप में तटस्थ मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों पर मुद्रा की मात्रा से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों तथा परिवर्तनों को दूर करता है। इसके अन्तर्गत मुद्रा की स्थायी मात्रा द्वारा अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकना तथा मूल्य स्तर में स्थायित्व प्रदान करता है। चूँकि अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मूल्य स्तरों में वृद्धि या कमी का कारण प्रधानतया मुद्रा की मात्रा में ही वृद्धि या कमी है। अतः तटस्थ मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा को इस तरह अनुकूलतम तथा वांछनीय रूप में बनाना चाहिये कि अत्यधिक बढ़ती हुई या घटती हुई कीमतें स्थायी बनायी जा सकें। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तथा स्थायित्व के लिये यह आवश्यक है कि मौद्रिक अधिकारी मुद्रा को अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में तटस्थ रखे। वर्तमान समय में आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का तटस्थ होना सम्भव नहीं है, जिसके कारण यह उद्देश्य अब महत्वपूर्ण नहीं है।

मौद्रिक नीति का अन्तिम प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों में उत्पादन तथा आय के उचित व समान वितरण को प्राप्त करना है। किसी अर्थव्यवस्था में व्याप्त आर्थिक असमानताएँ तथा आय का असमान तथा अनुचित वितरण अब आर्थिक नीति के

प्रमुख उद्देश्यों का विषय बनता जा रहा है, जिससे मौद्रिक नीति का यह भी उद्देश्य हो जाता है कि वह आर्थिक असमानता को दूर करे तथा आय के वितरण को समान तथा न्यायपूर्ण बनाये। वर्तमान समय के आर्थिक व सामाजिक विकास में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय की समस्या के बढ़ते हुए महत्व के कारण अब सरकार तथा मौद्रिक अधिकारियों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अर्थव्यवस्था के सामान्य आर्थिक व सामाजिक हित के लिये आय की असमानता को दूर करते हुए वितरण की उचित व्यवस्था को स्थापित करे।

वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये अन्य बहुत से उद्देश्य होते हैं। प्राकृतिक साधनों का सचयन, अधिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अधिक प्रभावपूर्ण विदेशी नीति तथा साधनों को अधिक गतिशील बनने से सम्बन्धित उद्देश्यों में मौद्रिक नीति का सहयोग अपेक्षित है। ऊपर हमने मौद्रिक नीति के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्यों का ही विश्लेषण किया है, पर किसी देश की मौद्रिक नीति में इन उद्देश्यों के साथ अन्य और उद्देश्य भी सम्मिलित हो सकते हैं।

मौद्रिक नीति के इन उपर्युक्त विभिन्न उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्देश्यों में यह आवश्यक नहीं है कि पारस्परिक मेल या सगति हो। सामान्यतया इन उद्देश्यों में पारस्परिक सघर्ष या विरोध होता है। अतः मौद्रिक नीति के संचालन में यह समस्या है कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने में दूसरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। उदाहरण के लिये, यदि एक ओर मौद्रिक नीति अधिकतम उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार प्राप्त करना चाहती है तो अर्थव्यवस्था में आन्तरिक मूल्य स्थायित्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने की प्रक्रिया में मूल्य स्तर में वृद्धि स्वाभाविक है। इसी तरह मूल्य स्थायित्व तथा विनिमय दर में स्थायित्व को एक साथ प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इन उद्देश्यों में मेल नहीं है। साथ ही साथ यदि अर्थव्यवस्था आर्थिक सवृद्धि को बढ़ाने में लगी है तो यह पूर्ण रोजगार से या कीमत स्थिरीकरण उद्देश्य से मेल नहीं खाता। यदि उत्पादन तथा आर्थिक सवृद्धि की मात्रा को बढ़ाने के लिये एक ओर विकसित पूँजी प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाता है तो दूसरी ओर श्रम की दशा में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह यदि समाज में वितरण की न्यायपूर्ण

व्यवस्था तथा आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो तीव्र आर्थिक विकास सम्भव न हो सकेगा। इससे स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में पारस्परिक सगति नहीं है। इस असगति के कारण ही किसी अर्थव्यवस्था में समयसमय पर अलग-अलग उद्देश्यों को लिया जाता है। यद्यपि इन विभिन्न उद्देश्यों में सगति स्थापित करना असम्भव नहीं है, फिर भी एक साथ सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन है। यही कारण है कि एक अर्द्धविकसित देश सामान्यतया रोजगार के कम स्तर पर भी आर्थिक सृष्टि की दर को बढ़ाने में रुचि रखता है, क्योंकि इन देशों की अनेक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान आर्थिक विकास की वृद्धि में ही सम्भव है। इसके विपरीत एक विकसित अर्थव्यवस्था में यह सम्भव है कि उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि की दर के साथ-साथ बाह्य तथा आन्तरिक स्थायित्व को भी प्राप्त किया जा सके।²¹

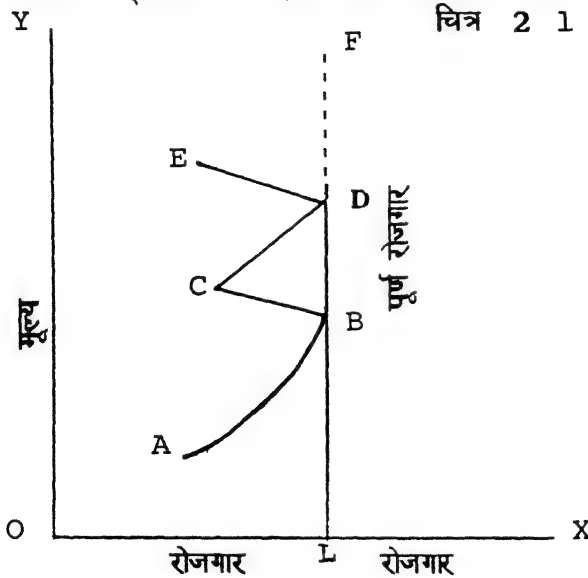
अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में इन विभिन्न उद्देश्यों में सगति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की विभिन्न नीतियों में मेल स्थापित किया जाय। इस बात को मूल्य एवं रोजगार में एक साथ सम्बन्ध देख कर विश्लेषित किया जा सकता है।

यहाँ पर हम पूर्ण रोजगार एवं मूल्य वृद्धि के पारस्परिक विसगति को स्पष्ट करेंगे। पूर्ण रोजगार तथा मूल्य में स्थायित्व का उद्देश्य अर्थशास्त्रियों व अन्य लोगों में मान्यता प्राप्त है। परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि इन दोनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ये दोनों उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी हैं, अतः इनमें से केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति का चुनाव किया जा सकता है। इस बात को संक्षेप में इस तरह से देखा जा सकता है कि यदि हम अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी की दशा से आरम्भ करें और यह मानते हुए कि मूल्य निम्न स्तर पर है तथा व्यापारिक क्रियाओं का पुनरुद्धार की दशा है तो इसका पहला प्रभाव यह होगा कि उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होगी। यह सम्भव है कि साथ-साथ मूल्य में वृद्धि न हो। पर जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में विस्तार होता जाता है, उत्पादन

21. P.D. Hajela, Problems of Monetary Policy in under developed Countries, p. 26.

एव रोजगार वृद्धि में अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं और मूल्य में भी वृद्धि होने लगती है।^० जितना अधिक हम पूर्ण रोजगार के समीप पहुँचेंगे, उतना अधिक मूल्य में वृद्धि होगी।

इस स्थिति को चित्र 2.1 में दिखाया गया है। चित्र में यदि हम मन्दी की दशा A से प्रारम्भ करते हैं तो पूर्ण रोजगार की दशा में तभी पहुँचते हैं जब अपेक्षाकृत अधिक तीव्र मूल्य वृद्धि B के रूप में होती है। यदि इस ऊँचे स्तर पर हम मूल्य में स्थायित्व चाहते हैं तो हम यह पायेंगे कि रोजगार की स्थिति C की ओर गिरने को होगी। बिन्दु D पर पुनः पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते मूल्य में पुनः वृद्धि हो। E बिन्दु की ओर रोजगार में कमी को रोकने के लिए मूल्य में लगातार वृद्धि F की ओर होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों में इस तरह विसंगति तथा पारस्परिक विरोध के कारण इसके



क्रियान्वयन में अनेक रुकावटें या अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। अतः मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्रियान्वयन प्रक्रिया में आने वाले प्रमुख अवरोधों को स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा।

2.4 मौद्रिक नीति के अवरोध

मौद्रिक नीति के उद्देश्य तथा इसके कार्य क्षेत्र और सामर्थ्यता सम्बन्धी दिये गये विश्लेषण से दो महत्वपूर्ण बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम, यह कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य उन व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, जो किसी देश में अधिकारी या सत्ता से सम्बन्धित हैं। अतः अर्थशास्त्रियों और मौद्रिक सैद्धान्तिकों के लिये निर्धारित उद्देश्य एक प्रकार से दिये हुये

आकडे के रूप में होते हैं। देश के केन्द्रीय बैंक उन उद्देश्यों पर कोई प्रश्न या आपत्ति नहीं करके उनके सहयोग हेतु होते हैं। दूसरा, यह कि ये उद्देश्य आपस में एक दूसरे के संगत नहीं होते।²² ये बहुत ही उलझनपूर्ण हैं, अल्पकाल में ये परस्पर प्रत्यक्ष रूप से विरोधी हो सकते हैं और केवल समन्वय के द्वारा ही दीर्घ काल में इनमें सन्तुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणार्थ यदि कोई देश अपने आर्थिक विकास को अधिकतम करने की दृष्टि से उत्पादक वस्तुओं की अधिकतम मात्रा और उपभोग वस्तुओं की कम मात्रा उत्पन्न करता है तो व्यवस्था में स्फीतिकारी दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। परिणामतः मूल्यों में स्थायित्वता प्राप्त करने का उद्देश्य कठिन हो जाता है और इसी तरह यदि कोई देश उत्पादन में पूँजी प्रधान विधियों पर अधिक जोर देता है तो रोजगार उस दर से सृजित नहीं हो सकेगा, जिससे देश में पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसी तरह यदि आय एवं सम्पत्ति के समान वितरण के उद्देश्य को लिया जाय तो यह सर्वमान्य विचारधारा कि आय में असमर्थता का अभिप्राय लाभ-कर्ताओं में अधिक आय से है। अर्थव्यवस्था के समृद्धि दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि लाभ-प्राप्त-कर्ताओं की आय में अधिक वृद्धि हो, न कि उपभोक्ताओं की आय में, क्योंकि लाभ-कर्ता ही विनियोग दर, उत्पादन दर, रोजगार दर और आर्थिक दर में वृद्धि करते हैं। अतः किसी सरकार के लिये यह बहुत ही कठिन कार्य है कि सारे उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त कर सके। अतः यहाँ यह महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किसी समय प्राथमिकता के आधार पर कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करे और किसी दूसरे समय दूसरे उद्देश्य को। उदाहरण के लिये अल्प विकसित देशों में यह चुनाव पहले उच्च आर्थिक विकास प्राप्त करने से हो न कि रोजगार वृद्धि और समान आय वितरण से, जबकि एक विकसित देश की सरकार आर्थिक विकास के तीव्र गति के साथ रोजगार स्तर एवं आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रों में स्थायित्वता को प्राप्त कर सकती है। इस तरह मौद्रिक नीति के

22. The aims of Economic Policy to which monetary action is related are complex . They can be directly in conflict with each-other in the short term and only by adjustment can be held in balance in the long"- Radcliffe Committee Report, p. 337.

विभिन्न उद्देश्यों में समन्वय एवं सगति प्राप्त करना असम्भव नहीं है, किन्तु ऐसे समन्वय एवं सगति के लिये आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर उपयुक्त आर्थिक पृष्ठभूमि उत्पन्न की जाय।

इसी तरह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में पूर्ण क्षमता स्तर पर उत्पादन और समृद्धि के साथ मूल्य स्तर में स्थायित्वता उद्देश्य के सम्बन्ध में कई सरचनात्मक अवरोध उत्पन्न होते हैं। ऐसे अवरोधों का एक समूह स्थिर स्फीतिकारी दशा से सम्बन्धित है और दूसरा लागत वृद्धि शक्तियों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। जहाँ तक स्थिरावस्था स्फीतिकारी दशा का सम्बन्ध है, वह ऐसी दशा को निर्देशित करता है, जिसमें स्फीति के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि हो रही हो। ऐसी स्थिति में समग्र मांग, उत्पादन से अधिक होता है और मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप बेरोजगारी की दशा विद्यमान रहती है। इस तरह जैसा कि फिलिप्स मॉडल में मुद्रा स्फीति दर और बेरोजगारी दर को साथ-साथ स्पष्ट किया गया है। वह अर्थव्यवस्था में उद्देश्यों के चुनाव के सामने इस समस्या के रूप में उत्पन्न होता है कि अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित दर से बेरोजगारी दूर करने के लिये कितनी मुद्रा-स्फीति की दर बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह मुद्रा स्फीति की एक निश्चित दर को कम करने के लिये कितनी बेरोजगारी दर में वृद्धि करनी पड़ेगी।²³

इसी तरह अर्थव्यवस्था के सरचनात्मक अवरोधों में लागत वृद्धि स्फीतिकारी दशाओं का उत्पन्न होना, जो मुख्य रूप से आयातित वस्तुओं और सेवाओं के बढ़े हुये मूल्यों से सम्बन्धित है। इस तरह से यदि आवश्यक आयातों का मूल्य जैसे, तेल, पूँजीगत वस्तुएँ, स्पेयर पार्ट्स, आवश्यक कच्चे माल और कुछ उपभोग वस्तुएँ, खाद्य तेल आदि का मूल्य बढ़ जाय तो इस तरह से देश में स्फीतिकारी दशाओं में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह लागत वृद्धि स्फीतिकारी दशाओं का प्रसार प्रशासनिक कीमतों में वृद्धि से होता है। इस तरह बढ़ी हुयी प्रशासनिक कीमतें सामान्य मूल्य स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है।

23. S.B. Gupta, Monetary Economics, Institutions, Theory and Policy, 1990, p. 360.

कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि मौद्रिक नीति अल्प विकसित देशों में अप्रभावकारी होगी, जहाँ बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति बेरोजगार है तथा यह नीति सम्पन्न देशों में मन्दी की अवस्था में अधिक प्रभावी होगी। देश में तरलता जाल की स्थिति और विनियोग फलों का ब्याज से बेलोच होने की दशा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जहाँ मौद्रिक नीति गैर महत्व की हो, किन्तु अल्प विकसित देशों के सन्दर्भ में ऐसी दृढ़ धारणा गलत हो सकती है कि लोब बड़ी मात्रा में अनुपयुक्त मुद्रा शेषों को अपने पास रखें। वस्तुतः विनियोग वित्त हेतु यहाँ एक सक्रिय माग होती है और इन अल्प विकसित देशों में पूँजी पर प्रतिफल दरे ऊँची होती है।²⁴ परन्तु मौद्रिक नीति वास्तविक शक्तियों को उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है और देश के उत्पादक कार्यों में गैर कुशलता और अभाव को समाप्त नहीं कर सकती।

अल्प विकसित देशों में एक बड़े गैर मौद्रिक क्षेत्र की स्थिति के कारण मौद्रिक नीति सीमित हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई क्षेत्र गैर मौद्रिकृत है। यहाँ कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा भाग प्रायः बाजारी स्थिति का न होकर जीवन निर्वाह हेतु है। इन देशों के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वस्तु लेन-देन प्रथा विद्यमान है और इस तरह यहाँ सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण भाग मौद्रिक नीति के क्षेत्र के परे है।²⁵ इस तरह यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐसे देशों में ब्याज दर को निम्न रखने का उद्देश्य मौद्रिक नियंत्रणों के क्रियान्वयन पर गम्भीर बाधक सिद्ध होता है और मुद्रा स्फीति दरके नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी तरह यदि सरकार निम्न ब्याज दर की नीति को छोड़ दे तो सार्वजनिक ऋणों की सेवा लागत में वृद्धि हो सकती है। इसका अभिप्राय ऊँचे कर से होगा, जिसका परिणाम कुछ आर्थिक हानि से होगी, क्योंकि इससे साधनों के निर्धारण

24. L.V. Chandler, Central Banking and Economic Development, Bombay, 1962, p. 22.

25. Arthur I, Bloomfield, Monetary Policy in Underdeveloped Country, Vol. 7, 1956, p. 236.



की कार्य-क्षमता कम होती है। इसी तरह निम्न ब्याज दर नीति को व्यवस्था के विपरीत दिखाया जा सकता है और इसके लिये मौद्रिक अधिकारियों को साख प्रसार पर अवरोध और वास्तविक ब्याज दरों के आधार पर बचत को प्रोत्साहित और ऋण देय वित्त के उत्पादन निर्धारण पर बल दिया जाता है।²⁶

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि वास्तविक ब्याज दर, जो प्राकृतिक या सस्थिति ब्याज दर के समकक्ष हो, वह वांछित विकास एवं स्थायित्वता के लिये आवश्यक है। इस तरह इन देशों में ब्याज दर, खुले बाजार की क्रियाएँ बहुत अधिक प्रभावी न होकर सीमित प्रभाव से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में गुनार मिर्डल ने यह सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण रूप से ऊँची ब्याज दर के साथ अर्थव्यवस्था में हर तरह के नियंत्रणों का समाप्त करना, पश्चिमी एशिया के देशों में पूँजी अभाव की स्थिति के साथ अधिक सगत होगा और अर्थव्यवस्था को पूँजी के प्रयोग हेतु प्रेरित करेगा। यह विदेशी पूँजी के अन्त प्रवाह को त्वरित करेगा और उत्पादक रूपों में आन्तरिक बजट को सगठित करेगा।²⁷

563001

2.5 मौद्रिक नीति के उपकरण

किसी देश के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में मौद्रिक नीति, विकास आवश्यकताओं में मुद्रा के समायोजन, प्राथमिक क्षेत्रों और उद्देश्यों में कित्त प्रवाह के संचालन तथा आर्थिक क्रियाओं के विशिष्ट क्षेत्र में सस्थागत साख और अन्य सुविधाओं द्वारा देश के आर्थिक विकास एवं स्थायित्वता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मोटे तौर पर मौद्रिक नीति उन उपायों से सम्बन्धित है, जो देश के केन्द्रीय बैंकिंग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा साख की उपलब्धता एवं लागत को नियंत्रित करने से ली जाती है। मौद्रिक एवं साख नीति पांच अन्तरपरस्परिय कारकों पर आधारित है अर्थात् साख की उपलब्धता, मुद्रा की मात्रा ऋण की

3774-10
6252

26. Committee for Economic Development, How low income Countries can advance their own growth, New York, 1966, p. 56.

27. Gunal Myrdal, Asian Drama, Vol. III, 1968, p. 354.

लागत पूँजी, आदेयों की कीमतें तथा अर्थव्यवस्था की सामान्य तरलता।²⁸ देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी अनुकूलतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में तथा उपलब्ध ससाधनों के पूर्ण प्रभावी प्रयोग में मौद्रिक एवं साख नीति को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में माना गया है।²⁹ एक विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के उपकरणों का क्रियान्वयन सुनियंत्रित पक्ष से सम्बन्धित है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में इनका सम्बन्ध नियंत्रणात्मक पक्ष से है।³⁰

इस तरह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में दो पक्ष निहित हैं। पहला, धनात्मक पक्ष, जो साख और बचतों को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन से सम्बन्धित है। दूसरा, नकारात्मक पक्ष, जो साख प्रसार के नियंत्रण से सम्बन्धित है। वस्तुतः मौद्रिक नीति के उपकरणों का संचालन एवं क्रियान्वयन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक वातावरण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से भारत में मौद्रिक नीति मुद्रा एवं साख के प्रोत्साहन तथा नियंत्रण दोनों से सम्बन्धित है। भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के मौद्रिकीकृत प्रक्रिया में सहयोग से सम्बन्धित है। इसमें विनियोग तथा उत्पादन में मुद्रा एवं साख का प्रवाह के नियंत्रण से सम्बन्धित है। इस तरह वस्तुतः मौद्रिक नीति की प्रभावकरिता मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उपकरणों पर आधारित है। इस सम्बन्ध में भारत के केन्द्रीय बैंक की परिवर्तित भूमिका प्रथम पंच वर्षीय योजना से ही महत्वपूर्ण रही है।³¹

28. Desai and Ghonasgi (Ed.), Monetary Policy and Central Banking in India, Bombay, 1969, p. 145.

29. First Five Year Plan, Planning Commission, Government of India, 1952, p. 37.

30. C.N. Vakil and P.R. Brahmanand, Planning for An Expanding Economy, 1966, p. 36.

31. Central banking in planned economy can hardly be confined to the regulation of the over all supply of credit are to a some what negative regulation of the flow of bank credit. It would have to take or a direct an active role firstly in increasing are helping to create machinery needed for financial developmental activity all over the country and secondly in insuring that the finance available flows in the direction needed", Government of India, First Five Year Plan, 1952, p. 38.

मौद्रिक नीति के अतिमहत्वपूर्ण और विशिष्ट रूपों में प्रयुक्त उपकरण मोटे तौर पर बैंक - दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, आरक्षित अनुपात कोष में परिवर्तन, घाटे की वित्त व्यवस्था, रिजर्व बैंक की विकास बैंकों को दिये गये साख की उपलब्धता तथा लागत में परिवर्तन, बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियंत्रण एवं नैतिक दबाव आदि हैं।

मौद्रिक नीति के उपकरणों में मौद्रिक नियंत्रण की सरकारी उपकरण, घाटे की वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित है। यहाँ पर हम योजना आयोग तथा चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट (1985) में प्रयुक्त घाटे की वित्त व्यवस्था के अर्थ को लेते हुए विश्लेषण कर सकते हैं। मौद्रिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में घाटे की वित्त व्यवस्था के योगदान परीक्षण हेतु हम उच्च अर्ध मुद्रा तथा मुद्रा पूर्ति में गुणक प्रभाव द्वारा वृद्धि को देखते हैं। अब इस तरह यदि घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा सरकार एक ऊँची दर से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि चाहती है तो इसे ऊँचे दर से बजट में घाटा दिखाना पड़ता है, किन्तु यदि सरकार मुद्रा पूर्ति दर में धीमी वृद्धि चाहती है तो तुलनात्मक रूप से बजट का घाटा कम होना चाहिये। सरकार के लिये यह उपाय करना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि इसके लिये या तो अन्य स्रोतों जैसे, बढ़े हुये सार्वजनिक ऋण आदि से आय प्राप्त करनी होगी या व्ययों में कमी करनी होगी। दोनों ही दशाओं में देश के कुछ न कुछ लोगों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। फलतः जनता के विरोध एवं अन्य स्थितियों के बचाव से सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है।

जहाँ तक बैंक - दर का प्रश्न है यह वह दर है, जिस पर केन्द्रीय बैंक अपने समस्त अग्रिमों एवं अन्य भुगतानों को करती है। दूसरे शब्दों में यह केन्द्रीय बैंक से पूरी बैंकिंग व्यवस्था द्वारा ऋण लेने की लागत है। इस दर में परिवर्तन द्वारा केन्द्रीय बैंक अपने ऋण की लागत, साख की माग तथा व्यापारिक बैंकों की ऋणों में परिवर्तन करता है, क्योंकि मुद्रा बाजार में बैंक दर तथा अन्य अल्पकालीन मौद्रिक व्याज दरों में महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है। मोटे तौर पर इस उपकरण का प्रभाव विनियोग एवं साहसोद्यमियों के प्रत्याशाओं और लाभकरिता तथा नये विनियोग हेतु साख की माग पर पड़ता है। इसी तरह वित्तीय संस्थाओं के साख राशिनिग नीति को भी प्रभावित करती है। इस दर का प्रभाव सरकारी बाड दरों तथा प्रतिभूतियों के

विक्रय को भी प्रभावित करता है। जैसा कि हाट्रे ने यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय बैंक को इस बैंक दर को वांछित स्तर तक बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिये और इस दर द्वारा वास्तविक प्रभावकारिता प्राप्त की जा सकती है।³² वर्तमान समय में बैंक दर के प्रभावकारिता के सम्बन्ध में बहुत विवाद रहा है। यहाँ तक कि रेडक्लिफ़ कमेटी ने भी मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।³³ परन्तु बैंक दर का दूसरा पक्ष विशेष महत्व का है और भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ नियोजित व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, वहाँ विनियोग को प्रभावित करने में यह एक शक्तिशाली उपकरण सिद्ध होता है। किन्तु अपने आपमें ब्याज दर और इसकी प्रभावकारिता बहुत सीमित है और अनेक कारक इसके प्रभावकारिता को सीमित करते हैं।

मौद्रिक नीति के दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण का सम्बन्ध केन्द्रीय बैंक के खुले बाजार की क्रियाओं से सम्बन्धित है। इस क्रिया का अभिप्राय रिजर्व बैंक द्वारा लोगों तथा अन्य बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय से है। सरकार के बैंक तथा सार्वजनिक ऋण के व्यवस्थापक होने की दृष्टि से रिजर्व बैंक सरकार के सभी ऋणों एवं प्रतिभूतियों को खरीदता है और अपने स्तर पर बाजार में इन्हें विक्रय हेतु प्रस्तुत करता है। इस क्रिया द्वारा खुले बाजार में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय से मुद्रापूर्ति तथा उच्च अर्ध मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और प्रतिभूतियों के विक्रय से यह मात्रा घट जाती है। विकसित देशों अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि में खुले बाजार की क्रिया मौद्रिक नीति के सर्वोच्च कुशल उपकरण माने जाते हैं। इन क्रियाओं को कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी ब्याज दरों के परिवर्तन, ऋण लेने और भुगतान क्रियाओं आदि पर पड़ता है। किन्तु भारत में रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएँ मौद्रिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली उपकरण नहीं रहा है। इसके प्रभावी होने के लिये कम से कम तीन दशाओं का होना आवश्यक है। प्रथम, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार विकसित एवं सुसंगठित हो। दूसरा, केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय का पर्याप्त शक्ति रखता

32. R. Hawerey, Income and Money, London, 1967, pp. 167-170.

33. Radcliffe Committee Report, p. 162.

हो तथा तीसरा, केन्द्रीय बैंक इन क्रियाओं का सम्पादन में अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर अप्रभावी न हो सके। भारत में केवल दशा, जिसमें रिजर्व बैंक को प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का पर्याप्त अधिकार है, पायी जाती है। भारत में इस क्रिया का तुलनात्मक महत्व सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सीमित हो जाता है। रिजर्व बैंक मोटे तौर पर इस क्रिया का प्रयोग सरकार के बढ़ते हुये ऋण कार्यक्रमों में करती है। भारत में बढ़ते हुये ऋण प्रबन्ध का उद्देश्य खुले बाजार की क्रिया और इसके प्रभाव को सीमित कर देना है।

मौद्रिक नीति के एक दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में आरक्षितों से परिवर्तन से सम्बन्धित है। प्रायः सभी बैंक अपने कुल आदेयों का निश्चित प्रतिशत नगदी के रूप में रखते हैं। प्रथमतः वैधानिक आरक्षितों को पूरा करने के लिये दूसरे अपने दिन प्रतिदिन के नगद भुगतान हेतु। बैंकों के ये आरक्षित वांछित आरक्षित तथा अतिरिक्त आरक्षित के रूप में होते हैं। वांछित आरक्षित बैंकों द्वारा वे नगद शेष हैं, जिन्हें बैंकों को वैधानिक रूप से रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। इस तरह रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों पर तीन से पन्द्रह प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात रखने का अधिकार है। इन वांछित आरक्षितों के अलावा बैंक अतिरिक्त आरक्षितों को भी अपने पास रखते हैं, जो वांछित आरक्षित के अतिरिक्त होते हैं। इन्हीं आरक्षितों द्वारा वे अपने जमा-कर्ताओं के भुगतान करते हैं। नियंत्रक के रूप में आरक्षित अनुपात का परिवर्तन मुद्रापूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है और केन्द्रीय बैंक इन आरक्षितों के दरों में परिवर्तन करके मुद्रा प्रसार एवं सकुचन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह नगद आरक्षित अनुपात में कमी द्वारा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और इसकी वृद्धि द्वारा मुद्रापूर्ति में कमी लायी जा सकती है। यह सामान्य धारणा है कि खुले बाजार की क्रिया की तुलना में आरक्षित अनुपात उपकरण कम प्रभावी है। इसमें सदस्य बैंकों के अपने पोर्टफोलियो व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे बैंकिंग क्रियाओं में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निर्देश का समयानुसार पालन न करने पर तथा केन्द्रीय बैंक को अन्य स्रोतों से क्षतिपूरक ऋणों की वृद्धि के द्वारा तथा अन्य बैंकों के द्वारा बढ़े हुए एवं क्षतिपूरक सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय आदि द्वारा इस उपकरण का प्रयोग सीमित हो जाता है। बैंकों तथा विकास बैंकों को रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता तथा लागत में परिवर्तन भी

मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त विश्लेषण में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि बैंकों को रिजर्व बैंक की साख द्वारा उच्च अर्धमुद्रा {एच} में विस्तार करता है। रिजर्व बैंक की मोटे तौर पर दो रूपों में साख प्रदान करता है। पहला, मान्य प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिमों के द्वारा तथा दूसरे उनके बिलों के बट्टा {डिस्काउंट} के द्वारा। बैंकों को यह साख प्रथमतः उनके परंपरागत बैंकों के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा दूसरे कुछ नये नीति उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। इसी के साथ-साथ रिजर्व बैंक इन बैंकों को व्यस्त मौसमी वित्त भी प्रदान करता है। बैंकों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक अन्य विकास बैंकों को भी साख प्रदान करता है। मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के द्वारा विकास बैंकों को प्रदत्त साख उच्च अर्ध मुद्रापूर्ति में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किन्तु इस साख द्वारा मुद्रा प्रसार की अधिक संभावना रहती है।

मौद्रिक नीति के विशेषकर वर्तमान समय में वैधानिक तरलता अनुपात {S L R} एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उत्पन्न हुआ है। समग्र मौद्रिक नियंत्रण में यह प्रत्यक्ष कार्य करने की तुलना में अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जिससे मौद्रिक नियंत्रण में इसके योगदान का सही परीक्षण नहीं किया जाता। इस विधि का प्रधान योगदान व्यापारिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच बैंक साख के आवंटन से है। इस सम्बन्ध में इसी विधि के कार्यशीलता के दो रूप हैं। प्रथमतः, रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को प्रभावित करके और दूसरा, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करके। इन दोनों दशाओं में उच्च अर्ध मुद्रा का सृजन प्रभावित होता है और इस तरह मुद्रा पूर्ति का परिवर्तन भी प्रभावित होता है। भारत में बैंक न केवल नगद आरक्षितों से सम्बन्धित है, अपितु वे वैधानिक तरलता अनुपात से भी सम्बन्धित हैं। इस वैधानिक तरलता अनुपात के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को वैधानिक रूप से अपनी कुल मांग तथा समय आदेशों का एक निश्चित न्यूनतम अनुपात रखना पड़ता है। इस तरह वैधानिक तरलता अनुपात {S L R} को निम्न समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है -

$$SLR = \frac{ER + I' + CB}{L}$$

जहाँ, ER = अतिरिक्त आरक्षित,

I' = सरकारी तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों
में विनियोग,

CB = अन्य बैंकों के साथ चालू खातों का शेष,

L = कुल मांग और समय आदेय

भारत में वैधानिक तरलता अनुपात मौद्रिक नीति का एक परिवर्तनशील उपकरण नहीं रहा है और सामान्यतः

इसका प्रयोग उर्ध्वमुखी परिवर्तन से सम्बन्धित रहा है।
भारत में वैधानिक तरलता अनुपात प्रथम बार 1950 में लागू किया गया और यह 20 प्रतिशत था।

इसके बाद यह लगभग पन्द्रह वर्षों तक इसी प्रतिशत तक बना रहा और 1964 में इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। पुन 1970 में इसे बढ़ा कर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया। जनवरी-मार्च, 1993 में वैधानिक तरलता अनुपात लगभग 37.5 प्रतिशत था, इसमें 2.5 प्रतिशत की कटौती की गयी। पुन अक्टूबर, 1993 में 2.5 प्रतिशत की कमी करके 37.25 प्रतिशत से 34.75 प्रतिशत कर दिया गया।

उपर्युक्त मुद्रा साख के परिमाणात्मक उपकरणों के साथ-साथ मौद्रिक नीति के कुछ चयनात्मक नियंत्रण विधिया भी हैं। मुद्रा और साख का कुछ विशिष्ट उद्देश्य और क्षेत्र के साथ नियंत्रण चयनात्मक या गुणात्मक साख कहा जाता है। जिसमें कुल साख तथा मुद्रा की मात्रा के स्थान पर साख का वितरण भी क्षेत्रानुसार निर्धारण किया जाता है। ये चयनात्मक विधिया सामान्यतः प्रतिभूति उन्मुख होती हैं। यदि अर्थव्यवस्था में व्यापारिक और विनियोगर्ता बैंक वित्त पर आधारित न हों आधारित न हों और उनके अन्य वित्त के स्रोत हों तो चयनात्मक साख विधियों का प्रभाव कम हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये विधियाँ परिमाणात्मक साख विधियों के सहयोगी के रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं। भारत में इन विधियों को प्रथमतः 1956 में प्रयोग किया गया था। तब से इनके क्षेत्र एवं स्थिति में काफी विस्तार होता रहा। वर्तमान समय में जो वस्तुएँ इन विधियों से सम्बन्धित हैं, उनमें खाद्यान्न, महत्वपूर्ण तिलहन, खाद्य तेल, सूत तथा कपास, चीनी, गुड़ तथा खाड़सारी, सूती कपड़ा, आदि सम्बन्धित हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक चयनात्मक साख विधियों का चयन करता है। इसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों के बदले ऋणों की न्यूनतम सीमा के परिवर्तन के द्वारा, किसी ऋण ग्राहक के अधिकतम अग्रिमों पर सीमा के द्वारा, विवेचनात्मक ब्याज दर के द्वारा, वस्तुओं के सग्रह हेतु वित्तीयन पर नियंत्रण के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के विक्रय के बिलों के डिस्काउट पर रोक आदि के द्वारा चयनात्मक साख विधियों का प्रयोग किया जाता है।

2 6 सस्ती मुद्रा नीति

अर्ध विकसित भारत की आर्थिक नीति के समष्टिभावी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किस तरह की मौद्रिक नीति हो, इस सम्बन्ध में सस्ती मुद्रा नीति तथा इसकी मान्यताओं और महत्व का उल्लेख आवश्यक होगा। केन्स के सामान्य सिद्धान्त [1936] के बाद विश्व के अधिकांश विकसित और अर्ध विकसित देशों ने महगी मुद्रा नीति के स्थान पर सस्ती मुद्रा नीति को बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया है, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण होगा कि हम इसकी मान्यताओं का परीक्षण करें, जिसके अन्तर्गत यह प्रभावी रूप से क्रियाशील होती है और भारत जैसे अल्प अविकसित देश में इसकी क्या उपादेयता है।

सर्वप्रथम, सस्ती मुद्रा नीति का अभिप्राय यह है कि सम्बन्धित अर्थव्यवस्था में मुद्रा-बाजार पूर्णतया सगठित और विकसित हों। यदि ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें मुद्रा-बाजार असगठित और अविकसित है तो ऐसी दशा में अप्रयुक्त मुद्रा शेषों की माग कम होगी।³⁴ निश्चित ही इस तरह की माग वित्तीय विनियोगों जैसे-बॉण्ड, प्रतिभूतियाँ, इक्विटी आदि नहीं होगी, जैसा कि इनका सम्बन्ध विकसित बाजार में होगा। इस तरह अप्रयुक्त मुद्रा शेषों और वित्तीय विनियोगों के बीच इस क्षीण सम्बन्ध के होने से बढ़ी हुयी मुद्रा की मात्रा द्वारा ब्याज दर कम नहीं होगी। इसी के साथ-साथ दूसरी प्रमुख मान्यता यह होगी कि विनियोग अधिकतर मौद्रिकृत हों।³⁵ यदि किसी अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग का बड़ा भाग गैर मौद्रिकृत विनियोग से सम्बन्धित है, तो सस्ती मुद्रा नीति, जो केवल मौद्रिकृत विनियोग को प्रभावित करती है तो अर्थ व्यवस्था पर ऐसी नीति का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव

34. Some thirty years ago, the unorganised market Financed as much as ninety percent of the internal track of India, with the expansion of Banking, The percentage has come down but even show it is estimated to be as high as Fifty percent at present, H.V.R. Iyengar, Monetary Policy and Economic Growth, 1962 pp. 192-193.

35. Rough estimates for sample survey suggest that between 20 & 25 percent of all savings & investments was non mortalis in the preplan years, Wilfred Malendaum in East & West in India's Economic development, 1959, p.25.

नहीं होगा। सस्ती मुद्रा नीति की एक और महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि पूँजी की सीमान्त दक्षता गिर रही हो। इसका अभिप्राय यह है कि विनियोग जो किये जा रहे हों तथा अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा आय के स्तर बढ़ रहे हों तथा भविष्य की प्रत्याशा और तकनीकी ज्ञान का स्तर अपरिवर्तित हो। यह स्पष्ट है कि यदि अर्थव्यवस्था में किसी तरह का तकनीकी विकास हो रहा हो तो नये विनियोगों की उत्पादिता बढ़ेगी और यदि विनियोगकर्ताओं की प्रत्याशा में कोई परिवर्तन न हो रहे हों तो पूँजी की सीमान्त दक्षता बढ़ जायेगी। ऐसे सन्दर्भ में विनियोग प्रेरक में वृद्धि तकनीकी विकास के द्वारा ही होगी और विनियोग को प्रेरित करने के लिये ब्याज-दर का गिरना आवश्यक नहीं है। यहाँ इस सम्बन्ध में एक और बात भी महत्वपूर्ण है-अर्थव्यवस्था में विनियोग का दृष्टिकोण व्यक्तिगत दृष्टिकोण से न होकर सामाजिक दृष्टिकोण से हो सकता है।³⁶ ऐसे सन्दर्भ में पूँजी की सीमान्त दक्षता को विनियोग द्वारा होने वाले उस लाभ को लेंगे, जिसकी प्राप्ति समाज को होती है, न कि व्यक्ति विशेष को। वर्तमान समय में जब राज्य तीव्र गति से सामाजिक कल्याण की ओर उन्मुख है, इस तरह का दृष्टिकोण बहुत महत्व का है। ऐसे सन्दर्भ में हमें सस्ती मुद्रा नीति के अलावा अन्य आधारों पर ब्याज दर तथा विनियोग निर्णय को सोचना होगा। साथ ही साथ सस्ती मुद्रा नीति की यह भी मान्यता है कि विनियोग की मांग, ब्याज लोचशील है अर्थात् नये विनियोग की मांग बढ़ेगी, यदि ब्याज दर में कुछ कमी हो। यहाँ साहसोद्यम में लागत संरचना के सन्दर्भ में ब्याज दर इतना कम हो सकती है कि यह सम्भव न हो और विनियोग करने की प्रवृत्ति मजदूरी में कमी तथा कर रियायतों से अधिक और ब्याज दर में कमी से कम हो सकती है। यहाँ पर केन्सीय विचार के अनुसार अर्थव्यवस्था की तेजी तथा मन्दी की दशाएँ एक प्रति अर्थव्यवस्था में पूँजी की सीमान्त दक्षता के उतार-चढ़ाव से निर्धारित होते हैं, जिसका स्वयं निर्धारण उत्पादकों के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव से सम्बन्धित है। यहाँ केन्सीय सस्ती मुद्रा नीति के सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात है कि सस्ती मुद्रा नीति उस दशा से सम्बन्धित है कि विनियोग इतने महत्वपूर्ण हो गये हों कि उनकी सीमान्त दक्षता में तीव्र और लगातार कमी हो रही हो।

36. Third Five Year Plan, Government of India, p.9.

सस्ती मुद्रा नीति की उपादेयता श्रम की प्रवृत्ति के मूल्यांकन पर आधारित है। यह सुझाव कि ऐसी मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप यदि कीमतों में वृद्धि तथा श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाय तो इससे लागत जनित मुद्रास्फीति नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार के पूर्व श्रमिक अपने रहन-सहन लागत में वृद्धि और वास्तविक मजदूरी में कटौती का विरोध नहीं करते। यह बात इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ण रोजगार पर मजदूरी श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता तथा सीमान्त त्याग के बराबर होती है और पूर्ण रोजगार से कम की सभी दशाओं में मजदूरी केवल सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। अतः पूर्ण रोजगार पहले की दशा में मजदूरी सीमान्त त्याग से अधिक होगी और श्रमिकों की आय में एक अंश लगान अर्जन का होगा। ऐसी स्थिति में वे अपनी वास्तविक मजदूरी में कमी का विरोध नहीं करते। अतः बढ़ती हुयी कीमतों की स्थिति में वास्तविक मजदूरी में लगातार कमी की स्थिति के द्वारा सस्ती मुद्रा नीति घाटे की वित्त व्यवस्था और अधिक उत्पादन तथा रोजगार से सम्बन्धित सस्ती मुद्रानीति तब तक कार्य कर सकती है, जब तक श्रमिक इसका विरोध न करे। एक अल्प विकसित देश में सस्ती मुद्रा नीति की मान्यता को स्वीकार करना सम्भव न होगा, क्योंकि यहाँ मजदूरी जीवन निर्वाह के इतने सन्निकट है कि इसमें किसी तरह की कटौती लोगों स्वीकार न होगी³⁷। इस तरह सस्ती मुद्रा नीति अल्प विकसित देशों में बढ़ती हुयी मजदूरी की दशाओं में उपयुक्त न होगी, क्योंकि यदि हम इस मान्यता से चले कि इन देशों में[°] विनियोग की अतिरिक्त मात्रा समय-अन्तराल व अन्य अवरोधों के कारण उत्पादन में वृद्धि न कर सके तो सस्ती मुद्रा नीति द्वारा सृजित मुद्रा पूर्ति में वृद्धि द्वारा कीमतों में वृद्धि होगी और वास्तविक मजदूरी में कमी होगी, किन्तु यह लोगों को मान्य न होगी। भारत में फैक्टरी श्रमिकों की मजदूरी 1958-59 में 1952 की तुलना में कम थी³⁸ और 1960-61 में ही उस स्तर से कुछ बढ़ सकी। इसी के साथ उपभोग मूल्य सूचकांक वृद्धि के साथ उनकी मौद्रिक मजदूरी में भी वृद्धि हुयी। अन्य वर्गों के श्रमिकों के सबंध में विशेषकर भवन निर्माण में लगे हुये श्रमिकों के सम्बन्ध में

37. A.K. Das Gupta, *Kayensian Economics & Underdeveloped Countries*, Ed. Book by V.B. Singh, 1956, pp. 156-157.

38. Reserve Bank of India Bulletin, April 1964, p. 424.

बढ़ती हुयी कीमतों से घटती हुयी वास्तविक मजदूरी और बढ़ी हुयी मौद्रिक मजदूरी की स्थिति विद्यमान रही। भारत के सन्दर्भ में बढ़ती हुयी मौद्रिक मजदूरी और मुद्रा स्फीति की स्थिति को सरकारी क्षेत्रों व कार्यालयों में देखा जा सकता है। अतः केन्सीय सस्ती मुद्रा नीति अल्प विकसित भारतीय मौद्रिक और वित्तीय वास्तविकता के सन्दर्भ में जहाँ एक ओर स्फीतिकारी दबावों को बढ़ाने में सहायक है, वहीं उत्पादन, आय व रोजगार तथा विनियोग के स्तर को बढ़ाने में असमर्थ है।³⁹

2.7 घाटे की वित्त व्यवस्था और मौद्रिक नीति

आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों में केन्द्रीय बैंक के मौद्रिक कार्य-कलापों में घाटे की वित्त व्यवस्था और उसकी मात्रा महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय विकसित देशों की तुलना में भिन्न है। सामान्यतया भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त मुद्रा का सृजन और सरकार का साख-सृजन व्यवस्था निहित है। अतः जितना अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था होगी, उतना अधिक साख की मात्रा होगी और उतना ही अधिक मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। अतः सरकार का यह वित्तीय निर्णय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति में मुद्रा और साख को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

योजना आयोग ने इस बात का तर्क दिया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करता है।⁴⁰ भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था, जिस तरह से परिभाषित की जाती है, उसका अभिप्राय वास्तव में ऋण की मात्रा में वृद्धि और सरकार के नकद-शेषों में कमी है, जिसका परिणाम मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने से होता है। यद्यपि सभी अल्पकालीन ऋण आवश्यक रूप से मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि नहीं करते। जहाँ तक इन ऋणों को केन्द्रीय बैंक से लिया जाता है, वहाँ अर्थव्यवस्था में चलन में सीधे केन्सी की मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि सरकार के अधिकतर अल्पकालीन ऋण केन्द्रीय बैंक के पास होता है, अतः हम यह कह सकते हैं कि इस पूरी

39. P.D. Hajela, Problems of Monetary Policy in Underdeveloped Countries, 1969, pp. 34-36.

40. Government of India, Second Five Year Plan, 1956, p. 184.

मात्रा के बराबर मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि होती है। चूँकि घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि होती है, अतः इसको सीधे मौद्रिक नीति से सम्बन्धित होना चाहिये। इस स्थिति में केन्द्रीय बैंक की साख में वृद्धि सरकार को दी गयी साख और बैंकिंग क्षेत्र में दी गयी साख के बराबर होती है और इसका परिणाम अर्थव्यवस्था में बहुस्तरीय साख वृद्धि से होता है। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा एव साख के उपयुक्त व्यवस्था का अभिप्राय सरकार तथा बैंकिंग क्षेत्र में केन्द्रीय बैंक के साख नियंत्रण से है। योजना प्रक्रिया के समयावधि में बैंक और सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा निश्चित करते हैं और ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की घाटे की मात्रा के निर्णय के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं होता और भारतीय सन्दर्भ में घाटे को पूरा करने के लिये रिजर्व बैंक बाध्य होती है। इसका परिणाम गैर स्फीतिकारी नीतियों द्वारा स्थायित्वता प्राप्त करने में अनेक रूकावटों से है।

कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था आवश्यक रूप से स्फीतिकारी न होकर पूँजी निर्माण और आर्थिक विकास में प्रयोग होती है। प्रो० वी०के०आर०वी० राव⁴¹ तथा प्रो० पी०आर०ब्रह्मानन्द⁴² ने अपने विश्लेषण में यह दिखाया है कि एक सीमित तथा लगातार घाटे की वित्त व्यवस्था मूल्य वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं की मात्रा में भी वृद्धि करती है और पूँजी निर्माण में भी सहायक होती है। अतः अर्थव्यवस्था में होने वाले स्फीति की दशाओं को घाटे की वित्त व्यवस्था का परिणाम नहीं माना जा सकता है। प्रो० राव का यह मॉडल गुणक मॉडल है और यह दिखाता है कि वांछित घाटे की वित्त व्यवस्था और मूल्य-स्तर पर इसका प्रभाव लोगों की कर अदा करने की सीमान्त प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। पर यदि अर्थव्यवस्था में ये दशाएँ विद्यमान न हों तो घाटे की वित्त व्यवस्था अत्यन्त हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ-साथ यदि पूँजी का निर्माण करती है तथा बलात् बचत के रूप में यह आर्थिक विकास में वित्तियन हेतु सहयोगी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी आधार पर घाटे की वित्त व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। वस्तुतः घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव देश के वातावरण और अन्य नीतियों के

41. V.K.R.V. Rao, Essays in Economic Development, New York, 1964, pp. 105-41.

42. P.R.Brahmanand, Growthless inflation by means of stockless Money Supply, p. 451.

प्रभाव से सम्बन्धित है, यदि अर्थव्यवस्था में पहले से स्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं तो घाटे की वित्त व्यवस्था से समस्याएँ और जटिल हो सकती हैं, पर यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव अधिक नहीं है, तो ऐसी दशा में इस वित्तीय विधि का प्रयोग किया जा सकता है, पर एक ठोस साख नीति के अन्तर्गत इसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए तथा साथ ही साथ मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण में अन्य उपाय होने चाहिए। इस तरह स्फीति को रोकने और आर्थिक विकास का स्थिरता के साथ बढ़ाने के सम्बन्ध में घाटे की वित्त व्यवस्था सबद्ध हो सकती है। इस तरह घाटे की व्यवस्था का सम्बन्ध जहाँ मौद्रिक नीति से है, वही इसका सम्बन्ध साख नीति से भी है। पर यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि आर्थिक विकास के साथ स्थायित्वता का उद्देश्य है तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अनुकूलतम मात्रा होनी चाहिए। यद्यपि इसका निर्धारण बहुत जटिल है, पर मुद्रापूर्ति के वृद्धि के आधे भाग के रूप में बिना स्फीतिकारी जोखिम के इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह वास्तव में घाटे की वित्त व्यवस्था को साख नीति से जोड़ देना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था का निश्चित आकार निर्धारित कर सकती है। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग आर्थिक विकास को तेज करने तथा मूल्य स्थायित्वता को प्राप्त करने में किया है और इसमें परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में सत्तर प्रतिशत (17%) की कमी हुयी, पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विकासात्मक देयों को पूरा करने में बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में चीन और पाकिस्तान युद्ध के व्ययों के बढ़ने के कारण अतिरिक्त घाटे की वित्त व्यवस्था का प्राविधान किया गया। इस तरह आर्थिक विकास की परिस्थिति और विकासात्मक देयों के लगातार बढ़ने के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था अपरिहार्य हो गयी ।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और मूल्य स्थायित्वता के सन्दर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति नियंत्रण और स्फीतिकारी प्रवृत्ति के दबाव को कम करने तथा विकासात्मक देयों द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के सम्बन्ध में मौद्रिक एवं साख नीति का महत्वपूर्ण रूप से घाटे की वित्त व्यवस्था से सम्बद्ध हो जाता है।

2.8 रेडक्लिफ समिति की रिपोर्ट

बिट्रिश सरकार द्वारा लार्ड रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1968 में प्रस्तुत की और जिसका सन्दर्भ ग्रेट ब्रिटेन में मौद्रिक समस्याओं का पुनर्परीक्षण तथा मौद्रिक प्रक्रिया किस तरह कार्य करती है, से सम्बन्धित था ⁴³, और इस समिति को ब्रिटेन की मौद्रिक नीति और क्रियान्वयन के परीक्षण के लिए कहा गया, क्योंकि 1950 के समयावधि में ब्रिटेन में मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन से सभी जुड़े थे। इस तरह समिति का एक मात्र कार्य ब्रिटेन में मौद्रिक व्यवस्था के कार्यशीलता से सम्बन्धित था और उसमें मुद्रा स्फीति की समस्या के समाधान हेतु कोई सन्दर्भ नहीं दिया गया। इसी तरह इस समिति का सन्दर्भ वित्तीय या बजट अथवा राजकोषीय नीति से सम्बन्धित नहीं था। इस समिति ने ब्रिटिश मौद्रिक नीति के सैद्धान्तिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। मोटे तौर पर इस रिपोर्ट को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है

- ॥१॥ आन्तरिक बैंकिंग व्यवस्था में ट्रेजरी बिलों की पूर्ति को प्रभावी नियंत्रण हेतु माना जायेगा, न कि कैश की पूर्ति हेतु। (पैरा 583)
- ॥२॥ कुल मांग को प्रभावित करने में ब्याज दर प्रेरकों पर बहुत कम विश्वास किया जा सकता है। (पैरा 397)
- ॥३॥ पूरे सन्दर्भ में तरलता स्थिति पर मौद्रिक अधिकारियों को कार्य करना चाहिए। (पैरा 312)
- ॥४॥ फर्मों तथा वित्तीय संस्थाओं की तरलता स्थिति के परिवर्तन के द्वारा मौद्रिक उपाय कार्य करते हैं तथा मात्र मुद्रा पूर्ति ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। (पैरा 365)

इस समिति ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बैंकों के सन्दर्भ में उनके आदेय

43. Sir Oliver Franks, Some Reflection on Monetary Policy in the Right of Redcliffe Report, Sir Dorab Tata Memorial Lectures, Asia, 1960, p. 1.

सहायता का कार्य करती है। इस सन्दर्भ में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि मौद्रिक नीति किन सन्दर्भों में क्या कर सकती है और मौद्रिक नीति की क्या सीमाएँ हैं।

इस समिति का इस प्रकार मुख्य निष्कर्ष यह है कि मुद्रापूर्ति जो प्रत्यक्ष रूप से व स्पष्ट रूप से केन्द्रीय बैंक के प्रभाव में है, वह सभी मौद्रिक कार्यों का एक मात्र कारक नहीं हो सकता और इस सन्दर्भ में लोगों के व्यय करने सम्बन्धी निर्णयों में अर्थव्यवस्था की तरलता महत्वपूर्ण है और इस तरह लोगों के विनियोग व व्यय सम्बन्धी निर्णय मात्र मुद्रापूर्ति से ही नियंत्रित नहीं होते, अपितु वे इस बात से प्रभावित होते हैं कि लोग या व्यापारिक फर्म गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से कितना ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह तरलता के विस्तृत अर्थ में बैंकों में समय जमाएँ, बचतें, ऋण, शेयर आदि भी उसी तरह तरल हैं। इस तरह की तरलता के सृजन में मात्र व्यापारिक बैंकों का योगदान नहीं है, अपितु गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ भी साख सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इस तरह रेडक्लिफ समिति के अनुसार आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का बहुत अधिक योगदान नहीं है और अर्थव्यवस्था के स्थायीत्वता में मौद्रिक नीति का कोई विशेष योगदान नहीं है।

2.9 मौद्रिक नीति का कार्यक्षेत्र एवं गैर कार्य क्षेत्र

मौद्रिक नीति और ऐतिहासिक अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मौद्रिक नीति कर सकती है, वह मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण द्वारा देश में अस्थायित्वता उत्पन्न करने वाले कारकों को नियंत्रित कर के उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था को उचित लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, जो मौद्रिक नीति कर सकती है, वह अर्थव्यवस्था को एक स्थायी पृष्ठभूमि दे सकती है। वस्तुतः यह मौद्रिक व्यवस्था के आर्थिक धुरी में तेल का कार्य करती है, क्योंकि यह आर्थिक व्यवस्था के पहियों को तीव्र गति से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को उत्पादकों, उपभोक्ताओं और नियोजकों में पूर्ण विश्वास हो और भविष्य में मूल्य स्थायित्वता आदि की निश्चितता हो। इसी तरह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले

महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रेरक कारकों पर नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है और इस तरह आवश्यकतानुसार तीव्र और मन्द गति से मौद्रिक विकास और विस्तार के द्वारा वांछित उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। स्फीतिकारी और घाटे के बजट की स्थिति में अल्पकालीन ब्याजदर में वृद्धि के द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति में मौद्रिक नीति सहयोग कर सकती है।⁴⁵

यद्यपि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों तथा उनकी मात्रा के निर्धारण पर प्रभाव नहीं डालती, पर इनके प्रभावों में यह महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। वस्तुतः मुद्रा पूरी आर्थिक व्यवस्था की एक मशीन है और यह एक विशिष्ट और कुशल मशीन है और बिना इसके अप्रत्याशित विकास, उत्पादन और जीवन स्तर प्राप्त करना सम्भव न हुआ होता। मौद्रिक अधिकारी और सरकार देश की मौद्रिक व्यवस्था के द्वारा देश में विकास एवं स्थायित्वता को सही दिशा दे सकते हैं और इस तरह मौद्रिक नीति आर्थिक नीति के अंग के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। फ्रीडमैन ने जे० एस० मिल के इस कथन कि "अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अलावा और कोई भी बेकार चीज नहीं है, जिसका समाज ने आविष्कार किया हो", का विरोध करते हुए अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्थितियों और कार्य क्षेत्रों में मौद्रिक नीति और मुद्रा के विशेष महत्व को स्थापित किया।⁴⁶ इसके लिए यह आवश्यक है कि यह उन उपायों से निर्देशित होने चाहिए, जिन्हें यह नियंत्रित कर सकते हैं और उन उपायों से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए, जो इनके नियंत्रण से परे हों। उन विभिन्न वैकल्पिक उपायों को, जो मौद्रिक अधिकारी नियंत्रित कर सकते हैं, वे हैं विदेशी विनिमय दर, मूल्य स्तर, मुद्रा की मात्रा, करेन्सी तथा मांग जमाएँ और विस्तृत अर्थ में समय जमाओं को भी लिया जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति किस तरह से संचालित की जाय। ऊपर निर्दिष्ट विकल्प नियंत्रकों में मूल्य स्तर सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर मौद्रिक नीति का सीधा प्रभाव है तथा साथ ही साथ इस सम्बन्ध में पूर्व कथन सम्भव किया जा सकता है। मौद्रिक नीति

45. C.S. Nagpal, Monetary Policy and Inflation in India, 1982, pp. 32-33.

46. W.L. Smith and R.L. Teigen (Ed.), Reading in Money, National Income and Stabilization Policy, 1970, What Monetary Policy can do by Milton Friedman, pp.484-485.

के संचालन की दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मौद्रिक अधिकारियों के ध्यान देने योग्य है, वह मौद्रिक नीति में तीव्र उतार चढ़ाव से बचे और इस तरह वर्ष प्रतिवर्ष जैसा कि फ्रीडमैन ने मौद्रिक नीति के योगदान के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि लगातार एक निश्चित वृद्धि दर (3 से 5%) से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए।⁴⁷

मौद्रिक नीति के उपर्युक्त कार्य - क्षेत्र और कार्य - सामर्थ्यता के साथ - साथ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति क्या नहीं कर सकती और इसकी क्या सीमाएँ हैं। इस सम्बन्ध में मौद्रिक नीति की प्रथम सीमा यह है कि यह दीर्घ कालीन समय तक ब्याज दर को स्थिर नहीं बनाये रह सकती। यह सीमा मुद्रा और ब्याज - दर के सम्बन्ध में भ्रामक स्थिति के कारण है। ब्याज दर को नीचा रखने के लिए समान्यतया केन्द्रीय बैंक लोगों से प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिससे उनके मूल्य बढ़ जाते हैं और उन पर प्राप्तियाँ घट जाती हैं। इस प्रक्रिया में यह बैंकों के आरक्षितों को बढ़ा देते हैं। फलतः बैंक - साख और अन्ततः पूरी मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई मुद्रा ब्याज दर को गिरा देती है। तरलता पसन्दगी रेखा का नकारात्मक ढाल इस बढ़ी हुई मुद्रा की मात्रा इस तरलता पसन्दगी को बढ़ा सकती है और ऋणों के लिए माग में वृद्धि हो सकती है। यह मूल्य में वृद्धि कर सकती है, जिससे मुद्रा - मात्रा का वास्तविक माग घट सकता है। इन प्रभावों का परिणाम ब्याज दर के गिरने पर पड़ने वाले दबाव को विपरीत कर सकता है। इस स्थिति में ब्याज - दर पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव न पड़ने का विश्लेषण इसके पूर्व केन्सीय सस्ती मुद्रा नीति और उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में किया जा चुका है। अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से मौद्रिक विकास निम्न बाजारी ब्याज दरों तथा अन्य व्ययों पर पड़ने वाले दबावों के परिणामस्वरूप कुल व्यय को बढ़ाती है और इस तरह वांछित स्थिति से अधिक ऊँचे नकद शेषों के तुलनात्मक कीमतों में वृद्धि होती है और इस तरह आय के बढ़ने से तरलता पसन्दगी वक्र ऊपर बढ़ जाता है और

47. Milton Friedman, *The Optimum Quantity of Money* p.165

ब्याज दर बढ़ जाती है। इस तीव्र मौद्रिक विकास के साथ नीचे ब्याज दर के स्थान पर ऊँचा ब्याज दर कार्यरत होता है। तीव्र मौद्रिक विकास के साथ बढ़ती हुयी कीमतें और लोगों के द्वारा भविष्य में कीमतें बढ़ने की प्रत्याशा के परिणाम स्वरूप मुद्रा ऊधार देने वाले लोग ऊँचे ब्याज दर की माग करते है, जैसा कि इरविंग फिशरने अपने ग्रन्थ "परचेजिंग पावर ऑफ मनी" में दिखाया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि ब्राजील, चिली, अमेरिका आदि देशों में तीव्र मौद्रिक विकास के साथ ऊँचा ब्याज - दर रहा है और निम्न मौद्रिक विकास के साथ नीचा ब्याज दर सम्बन्धित रहा है। इस तरह मौद्रिक अधिकारी निम्न ब्याज दर के साथ अर्थव्यवस्था को मन्दी दशा की मौद्रिक नीति और ऊँचे ब्याज दर के साथ स्फीतिकारी मौद्रिक नीति से सम्बन्धित रहे है। ये बातें न केवल मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करते है कि यह ब्याज दर को क्यों स्थिर नहीं बनाये रख सकती, अपितु इनसे यह भी स्पष्ट है कि ब्याज दर मौद्रिक नीति, सस्ती मुद्रा नीति या महगी मुद्रा नीति पर आधारित है, के सम्बन्ध में एक भ्रामक सूचक है।⁴⁸

मौद्रिक नीति की दूसरी महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यह बेरोजगारी दर को भी बहुत समय तक स्थिर नहीं बनाये रख सकती। यहाँ पर यह बात इस सामान्य मान्यता के विपरीत लगती है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना अथवा इसका उद्देश्य रोजगार सृजन से है, पर वास्तविकता यह है कि मौद्रिक नीति यह करने में असमर्थ है। इसका कारण मुख्य रूप से ब्याज दर ही है। इस सम्बन्ध में ऐसी नीति के तात्कालिक और समयान्तर परिणामों में अन्तर का होना है। किसी भी समय - बिन्दु पर कोई न कोई बेरोजगारी का स्तर होता है, जो वास्तविक मजदूरी दरों की संरचना में संस्थिति के लिए जगत में बने रहने का गुण लिए रहता है। इस बेरोजगारी स्तर पर औसत रूप से वास्तविक मजदूरी दरें एक सामान्य अस्थायी दर से बढ़ने की प्रवृत्ति रखते है। बेरोजगारी दर का निम्न स्तर इस बात का सूचक है कि श्रम की अतिरिक्त माग

48. Milton Friedman, The Role of Monetary Policy in Reading in Money, National Income and Stabilization Policy by W.L. Smith and R.L. Teaigen. pp. 479-80.

है, जिसका प्रभाव वास्तविक मजदूरी दरों को बढ़ाने से होगा, दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी का प्राकृतिक दर वह स्तर है, जो वालरा के सामान्य सतुलन विश्लेषण के आधार पर अर्थव्यवस्था में समायोजन कर सकेगा।⁴⁹ इस तरह से मौद्रिक अधिकारी ब्याज दर से अंकित मौद्रिक मानों को परिवर्तित कर सकते हैं, पर वास्तविक मानों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इस तरह लगातार मुद्रापूर्ति में वृद्धि से मौद्रिक मजदूरी और अन्ततः वास्तविक मजदूरी गिरने की दशा में और श्रमिकों के द्वारा उँची मजदूरी दर की माग की स्थिति में तथा मूल्यों की वृद्धि की स्थिति में बेरोजगारी दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह मौद्रिक मानों के आधार पर वास्तविक ब्याज - दर, बेरोजगारी - दर, वास्तविक राष्ट्रीय आय स्तर, वास्तविक मुद्रा पूर्ति तथा वास्तविक मुद्रा मात्रा वृद्धि दर को स्थिर नहीं बनाया जा सकता है।⁵⁰

49. Milton Friedman, A programme for Monetary Stability in Reading in Financial Institutions, Ed. by M.D. Ketchum and L.T. Kendall, 1965.

50. Milton Friedman, the Role of Monetary Policy American Economic Review, Vol. 63, 1968, pp. 11-17.

मुद्रापूर्ति के सिद्धान्त, रिजर्व बैंक विश्लेषण, मौद्रिक नीति हेतु नीतिपरक बातें

(THEORIES OF MONEY SUPPLY, RBI ANALYSIS - IMPLICATIONS
FOR MONETARY POLICY)

प्रस्तुत अध्याय में मुद्रा पूर्ति और इसके विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों की विवचना की जायेगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण से है। सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है। यहाँ मुद्रापूर्ति के विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों के साथ रिजर्व बैंक के मुद्रापूर्ति विश्लेषण तथा मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया गया है। चूँकि मुद्रापूर्ति किसी एक देश से सम्बन्धित नहीं होती है, अतः यहाँ पर मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्तों के विश्लेषण भारतीय संदर्भ में किया जायेगा, इसके पूर्व सामान्य मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया जायेगा। यहाँ यह आवश्यक होगा कि हम भारत में मुद्रा पूर्ति के अर्थ एवं अवयवों को स्पष्ट कर दें।

रिजर्व बैंक के 1961 के प्रथम वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि मुद्रा-पूर्ति की कोई सामान्य और सैद्धान्तिक परिभाषा नहीं दी जा सकती है। मुद्रा पूर्ति की अवधारणा एक फलनात्मक है, अतः इसकी परिभाषा भी फलनात्मक और व्यवहारिक होनी चाहिए। इस तरह भारत में मुद्रापूर्ति की विशेषताओं में क्रय शक्ति, तरलता के गुण होने चाहिए।¹ इस आधार पर भारत में लोगों के पास मुद्रा पूर्ति को निम्नलिखित समीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।²

$$MS = C + DD + OD$$

यहाँ, MS = कुल मुद्रा पूर्ति है,

C = रिजर्व बैंक द्वारा नियमित कुल करेंसी नोट की मात्रा है,

-
1. R.B.I. Report of the First Working Group, July, 1961, pp. 65 - 66.
 2. R.B.I. Report of the Committee to Review the working the Monetary system, 1985, p. 96.

DD = व्यापारिक और सहकारी बैंको में लोगों की माग जमाए हैं, इसमें समय जमाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता,

OD = रिजर्व बैंक की दीर्घ जमाए हैं, जिसमें रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की पेन्शन, भविष्यनिधि तथा अर्ध सरकारी सस्थाओं की जमा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खाता सख्या दी शामिल रहते हैं ।

मौद्रिक सिद्धान्तों और बैंकिंग क्रियाओं के विकास और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह आवश्यक समझा गया कि भारत में मुद्रापूर्ति के उपागम और विश्लेषण में परिवर्तन किया जाय । इसके परिणाम स्वरूप 1976 में रिजर्व बैंक का द्वितीय बैंकिंग ग्रुप नियुक्त किया गया और मुद्रा पूर्ति के नये अर्थ में चार स्वतंत्र मापों को दिया गया । ये माप एम₁, एम₂, एम₃, एम₄ के रूप में है । एम₁ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के द्वारा कुल निर्गमित करेन्सी नोट की मात्रा, व्यापारिक और सहकारी बैंक की माग जमाए तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाए आती हैं । एम₂ के अन्तर्गत एम₁ तथा डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाए आती हैं । एम₃ के अन्तर्गत एम₁ तथा व्यापारिक और सहकारी बैंकों की समय जमाए (या बचतें) सम्मिलित की जाती है। और एम₄ के अन्तर्गत एम₃ तथा डाकघर बचत व्यवस्था की कुल जमाए सम्मिलित हैं ।

इस नये मुद्रा पूर्ति की अवधारणा में एम₁ वही है, जो पूर्व मुद्रा पूर्ति के रूप में परिभाषित की गयी थी तथा एम₃ कुल मौद्रिक योग है । यहा पर व्यापारिक और सहकारी बैंको की समय जमाओं को भी मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित किया गया है । इस तरह मुद्रा पूर्ति का यह नया विश्लेषण भारतीय मौद्रिक आकड़ों का परिष्कार मुख्य रूप से दो अर्थों में करेगा । प्रथमतः तरलता परिवर्तन के आधार पर यह नया उपागम मौद्रिक योगों के लिये अधिक विस्तृत अर्थ प्रस्तुत करता है, दूसरे, नया मुद्रा माप अपने विस्तार वृद्धि के साथ मौद्रिक आकड़ों का वास्तविकता के सन्निकट लायेगा तथा यह आशा की जाती है कि मौद्रिक प्रवृत्तियों का अधिक वास्तविक तथा विशिष्ट

विश्लेषण किया जा सकेगा । ³

3। मुद्रा पूर्ति विश्लेषण - बैंकिंग सर्वसमिका

1961 के रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा पूर्ति फलन को एक बैंकिंग सर्वसमिका के आधार पर दिया गया है । इसे विशुद्ध बैंकिंग कहा जा सकता है । इसमें यह दर्शाया गया है कि बैंकिंग व्यवस्था के कुल दायित्व कुल आदेयों के बराबर होता है । कुल दायित्व को मौद्रिक दायित्वों तथा गैर मौद्रिक दायित्वों में विभाजित किया जा सकता है और इसी तरह कुल आदेयों को वित्तीय आदेयों तथा गैर वित्तीय आदेयों में विभाजित किया जा सकता है और इस आधार पर निम्नलिखित बैंकिंग समीकरण प्राप्त किया जा सकता है -

-
3. "On the whole, therefore, the new categories of money stock measures may be said to carry forward the process of refinement of India monetary data in two distinct areas. Firstly, the new categories provide for a much wider spectrum of monetary aggregates, on the basis of their varying degrees of liquidity. Secondly, the new categories, by extending their coverage, would bring the data closer to reality. The new series, it is hoped, would therefore facilitate a more sophisticated and realistic analysis of monetary trends." - R.B.I., Report of the Second Working Group, 1977, p.9

$$\begin{aligned}
 TL &= TA \\
 ML + NML &= FA + NFA \\
 ML &= FA + NFA - NML \\
 ML &= FA - (NML - NFA) \\
 ML &= FA - NNML
 \end{aligned}$$

यहा पर ML या मुद्रा पूर्ति, (FA, NFA और NML) का फलन है। मुद्रा पूर्ति के पुलन के इस सिद्धान्त से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय आदेयों, गैर वित्तीय आदेयों और गैर मौद्रिक दायित्वों के परिवर्तन के साथ किस तरह मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन होता है। यहा यह दिखाया जा सकता है कि यदि वित्तीय आदेयों में कमी या वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में भी उसी तरह परिवर्तन होते हैं। इसी तरह गैर वित्तीय आदेयों के परिवर्तन के साथ धनात्मक रूप में मुद्रा पूर्ति परिवर्तित होती है। जहा तक गैर मौद्रिक दायित्वों का सम्बन्ध है, मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन इसके विपरीत होता है। गैर मौद्रिक दायित्वों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रा पूर्ति में कमी होती है, जबकि गैर मौद्रिक दायित्वों में कमी होने से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति के इस फलनात्मक सम्बन्ध को निम्न समीकरण से दिखाया जा सकता है -

$$\begin{aligned}
 \Delta (MS_0) &= \frac{\Delta MS_0}{\Delta (FA)} \cdot \Delta (FA) + \frac{\Delta MS_0}{\Delta (NFA)} \cdot \Delta (NFA) \\
 &+ \frac{\Delta MS_0}{\Delta (NML)} \cdot \Delta (NML)
 \end{aligned}$$

मुद्रा पूर्ति परिवर्तन का यह सिद्धान्त बहुत समिति और सकीर्ण है और इसी के साथ - साथ इसका स्वभाव तकनीकी है। यहा मुद्रा पूर्ति विश्लेषण, एक सतोषप्रद व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करने में असफल है।

3.2 मुद्रा या साख गुणक का सिद्धान्त

केन्द्रीय बैंक के उपर्युक्त मुद्रा पूर्ति परिवर्तन को कई कारणों से दोषपूर्ण मानने के कारण अधिक व्यवहारिक तथा मौद्रिक नियोजन की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से मुद्रा गुणक सिद्धान्त दिया जाता है। अति संक्षेप में हम मुद्रा गुणक की निम्न व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन को मौद्रिक देयता में परिवर्तन (ΔML) तथा मुद्रा गुणक परिवर्तन (ΔMK) के द्वारा दिखाया जाता है। अतः

$$\Delta MS = \Delta ML + \Delta MK$$

$$\text{तथा, } K = \frac{1}{C + r(1-C)}$$

जहाँ C कुल मुद्रा पूर्ति में करेन्सी का अनुपात है, r व्यापारिक बैंकों का मुद्रा माग के प्रति सुरक्षित कोष अनुपात, यहाँ पर ΔML को पुनः विभाजित किया जा सकता है, जो केन्द्रीय बैंक के शुद्ध विदेशी परिसम्पत्तियाँ में परिवर्तन (ΔMF), सरकार को दी गयी साख में शुद्ध परिवर्तन (ΔMG) तथा केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन (ΔMP) के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार,

$$\Delta ML = \Delta MF + \Delta MG + \Delta MP$$

इस तरह ΔMK में गुणक से सम्बन्धित सुरक्षित कोष में दो तत्व हैं - वांछित सुरक्षित कोष (r) तथा अतिरिक्त सुरक्षित कोष (r_2)। अब चूँकि K निर्धारित किया जाता है C तथा r से, अतः हम लिख सकते हैं -

$$\Delta ML = \Delta MC + \Delta Mr_1 + \Delta Mr_2$$

यहाँ ΔMC मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन को दिखाता है, जो करेन्सी अनुपात में परिवर्तन के कारण हुआ है।

इस तरह मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन को निम्न अवयवों के परिवर्तन का परिणाम माना जाता है -

$$\Delta MS = (\Delta MF + \Delta MG + \Delta MP) + (\Delta MC + \Delta Mr_1 + \Delta Mr_2)$$

मुद्रा गुणक की उपर्युक्त व्याख्या के साथ मुद्रा गुणक और मुद्रा फलन को निम्न रूप में अधिक स्पष्टतया के साथ रखा जा सकता है -

प्रथमतः चूँकि मोटे तौर पर मुद्रा पूर्ति (MS) में करेन्सी (C) तथा माग जमाएँ (DD) आती हैं, अतः मुद्रा पूर्ति इनके योग के बराबर है,

$$MS = C + DD \dots\dots\dots (1)$$

इसी के साथ मौद्रिक आधार, वास्तविक बैंक संचितों (R) तथा करेन्सी (C) के योग के बराबर है, जिससे,

$$B = R + C \dots\dots\dots (2)$$

अब समीकरण (1) को मुद्रा पूर्ति (MS) से विभाजित करने पर

$$B / MS = R / MS + C / MS \dots\dots\dots (3)$$

अब समीकरण (3) से R/MS को बाहर करके इसे अनेक रूपों में विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथमतः इसे इकाई से गुणा करने पर अथवा $\frac{MS}{D} - C$ (या D/D) से गुणा करने पर -

$$\frac{R}{MS} = \frac{R}{MS} \cdot \frac{MS - C}{D} \dots\dots\dots (4)$$

या,
$$\frac{R}{MS} = \frac{R (MS - C)}{MSD}$$

इससे हमें निम्न रूप प्राप्त होता है -

$$\frac{R}{MS} = \frac{RMS}{DMS} - \frac{RC}{DMS} \dots\dots\dots (5)$$

चूँकि $\frac{MS}{MS}$ इकाई के बराबर है, अतः समीकरण (5) को सरल करने पर

$$\frac{R}{MS} = \frac{R}{D} - \frac{RC}{DMS} \dots\dots\dots (6)$$

अब समीकरण (3) में समीकरण (6) को परिस्थापित करने पर निम्न प्राप्त होता है -

$$\frac{B}{MS} - \frac{R}{D} - \frac{RC}{DMS} + \frac{C}{MS} \dots\dots\dots (7)$$

अब यदि समीकरण (7) के दोनों पक्षों को B से भाग दें और उनका प्रतिलोम (Reciprocal) प्राप्त करें तो निम्न रूप प्राप्त होगा -

$$MS = \frac{R}{\frac{R}{D} + \frac{C}{MS} - \frac{RC}{DMS}} \dots\dots\dots (8)$$

इस समीकरण से स्पष्ट है कि मुद्रा पूर्ति, मौद्रिक आधार (B) से सीधे प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित होती है और R/D से विपरीत रूप से। मुद्रा पूर्ति के निर्धारकों को और अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिये आरक्षित कोष अनुपात (R/D) को निम्न रूप में पुनर्विभाजित करके रखते हैं -

$$\frac{R}{D} = \frac{ER}{D} + \frac{LR}{D} \dots\dots\dots (9)$$

जहाँ, E R = अतिरिक्त आरक्षितों तथा LR = केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कानूनी आरक्षितों को दिखाते हैं। इस तरह इस विभाजन के साथ अब समीकरण (8) को निम्न रूप में दिखाया जा सकता है -

$$MS = \frac{B}{\frac{ER}{D} + \frac{LR}{D} + \frac{C}{MS} - \frac{C (LR + ER)}{DML}} \dots\dots\dots (10)$$

इस समीकरण को सामान्यतया मुद्रा गुणक के रूप में भी रखा जा सकता है। सरल रूप में इसे निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है -

$$MS = B (m) \dots\dots\dots (11)$$

अब समीकरण (10) को मुद्रा पूर्ति फलन रूप में भी रखा जा सकता है, यदि ER/D तथा C/MS को निर्धारित करने वाले चरों को अलग किया जा सके । अब यदि ER/D आरक्षितों को (r) बनाये रखने से होने वाले शुद्ध लाभ पर तथा C/MS को वास्तविक प्रति व्यक्ति आय Y/N पर निर्धारित माना जाय तो मुद्रा पूर्ति फलन का निम्न रूप लिखा जा सकता है -

$$MS = f \left(Br \frac{Y}{N} \right)$$

अब मुद्रा पूर्ति मुद्रा गुणक तथा मुद्रापूर्ति फलन से सम्बन्धित उपर्युक्त समीकरणों के आधार पर यह सम्भव है कि मुद्रा पूर्ति से सम्बन्धित विस्तृत विश्लेषण को प्रस्तुत किया जा सके⁴।

3.3 मुद्रा पूर्ति का उच्च अर्थ (एच) सिद्धान्त

मुद्रा पूर्ति की व्याख्या समझने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम साधारण - मुद्रा और उच्च अर्थ मुद्रा के अर्थ और अन्तर को समझ लें । इस अध्याय में मुद्रा पूर्ति के सम्बन्ध में पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है । उन सबका सम्बन्ध साधारण मुद्रा से है । हमने साधारण मुद्रा को निम्न रूप में परिभाषित किया है -

$$M = C + DD + OD \dots\dots\dots(1)$$

जिसमें M मुद्रा पूर्ति है, C रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी की कुल मात्रा है और OD रिजर्व बैंक के अन्य जमाएँ हैं । यहाँ पर हम सरलता के लिये OD को मुद्रा (M) से बाहर कर देते हैं और ऐसा करने से विश्लेषण में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा, क्योंकि कुल मुद्रा में

4. Makinen, Money, Prices and Interest, p. 302.

OD का प्रतिशत लगभग एक के बराबर है ।

उपर्युक्त साधारण मुद्रा के विपरीत उच्च अर्ध मुद्रा (H) वह मुद्रा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा निर्गमित (Produced) हुई और जो लोगों एव बैंक के पास है। इस उच्च अर्ध मुद्रा (H) को भारतीय रिजर्व बैंक आरक्षित मुद्रा कहती है । इस तरह H में निम्नलिखित सम्मिलित रहते हैं-

(1) लोगों के पास करेन्सी (C),

(11) बैंकों के नकद आरक्षित (R),

(111) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की अन्य जमाएँ (OD) उपर्युक्त आधार पर हम लिख सकते हैं कि

$$H = C + R + OD \dots\dots\dots (2)$$

साधारण मुद्रा तथा उच्च अर्ध मुद्रा (H) के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इन दोनों में प्रमुख अन्तर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है । अगर दोनों समीकरणों (1) तथा (2) को देखे तो यह स्पष्ट होगा कि C तथा OD डी दोनों में समान हैं। दानों समीकरणों में जो अंतर है वह समीकरण (1) के M में DD है तथा समीकरण (2) के H में R है । मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्त के लिए यह अन्तर बहुत महत्वपूर्ण है । यह अन्तर बैंकों के उपस्थिति के कारण होती है, जो माग जमाओं को उत्पन्न करती हैं, जिसको करेन्सी (C) के समरूप ही मुद्रा माना जाता है । बैंको को इन माग जमाओं को उत्पन्न करने के लिए R रखना आवश्यक होता है

और R यहा H का ही एक मात्र भाग है चूँकि माग जमाएँ (DD) R के एक गुणाक होते हैं और जो H के ही अवयव हैं, इससे H को उच्च अर्ध का मान प्राप्त हो जाता है । अर्थात् H को वह शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो आधार बनकर DD के गुणाक उत्पन्न करता है । यही कारण है कि H को आधार मुद्रा कहते हैं ।

H सिद्धान्त को मुद्रा पूर्ति का मुद्रा गुणक सिद्धान्त भी कहते हैं, परन्तु इस सिद्धान्त को H सिद्धान्त कहना अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि पूरे सिद्धान्त का विश्लेषण H के माग और पूर्ति

के आधार पर किया जाता है । इस रूप में मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त को माग और पूर्ति का आधार भी प्राप्त हो जाता है ।

H सिद्धान्त की व्याख्या के सम्बन्ध में सबसे पहले हम H की पूर्ति को लेंगे । मान्यता रूप में यह मान लिया जाता है कि H की पूर्ति (H^S) नीति द्वारा निर्धारित है । इस मान्यता के आधार पर हम H के पूर्ति को निम्न रूप में लिख सकते हैं -

$$H^S = \bar{H} \quad \dots\dots\dots (3)$$

यहा पर H के ऊपर पडी रेखा यह दिखाती हे कि यह लोगों एव बैंकों से बहिर्जातीय रूप में है ।

मुद्रा पूर्ति के H सिद्धान्त में H की पूर्ति की तुलना में H की माग (H^d) अधिक महत्वपूर्ण है । इसका महत्वपूर्ण पक्ष इसे DD अथवा M से सम्बन्धित करना है । इसे हम नीचे समझायेगे ।

हम पहले से ही देख चुके हैं कि H लोगों द्वारा आंशिक रूप में करेन्सी (C) के रूप में तथा आंशिक रूप में बैंको द्वारा आरक्षित (R) के रूप में मागा जाता हे । इस तरह हमारे विश्लेषण में H मान के यही उपर्युक्त दो स्रोत हैं । मुद्रा (M) के एक अवयव के रूप में करेन्सी की माग (C^d) उन्हीं कारकों से प्रभावित होती है । है जिनसे मुद्रा जैसे आय का स्तर और व्याज दर । और यही बात माग जमाओं (DD^d) के बारे में सत्य है । इस लिए प्राथमिक रूप से यह मानना तार्किक होगा कि करेन्सी की माग (C^d) तथा माग जमाओं की माग (DD^d) अत्यधिक सह-सम्बन्धित होगी । अथवा यह कहा जा सकता है कि C^d एक आनुपातिक फलन होगा DD का । इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है-

$$C^d = C \cdot DD \quad \dots\dots\dots (4)$$

यहा DD और C^d का C अनुपात है । संक्षेप में इसे हम लोगों का करेन्सी जमा अनुपात कहते हैं । यहा पर C लोगों के करेन्सी अथवा माग जमाओं के बीच पसन्दगी को प्रकट

करेगा । इस रूप में यह कई कारकों द्वारा प्रभावित होगा । फलस्वरूप यह समयोपरि परिवर्तित हो सकता है । इस रूप में C एक फलनात्मक अनुपात है । हम आरक्षितों (R^d) के लिए बैंक की माग पर ध्यान देंगे । बैंको के आरक्षित सामान्त्या दो मर्दों में विभाजित रहते हैं । प्रथम आवश्यक आरक्षित (RR) तथा अतिरिक्त आरक्षित (ER) यह देखा जा सकता है । RR तथा ER^d और इसलिए R^d बैंको के कुल माग एव समय दायित्वों के वृद्धि मान फलन हैं कि बैंको के मान एव समय दायित्वों का रूप प्रधान तथा लोगों को माग एव जमाओं के कारण है । इसके अतिरिक्त दायित्वों और जमाओं के बीच यह अनुपात एक दीर्घकालीन रूप में स्थायी है और सरलता के रूप में हम कह सकते हैं कि R^d अधिकांशतः बैंकों के कुल जमाओं का एक आनुपातिक फलन है इसे हम निम्न रूप में रख सकते हैं -

$$R^d = r D \dots\dots\dots (5)$$

यहा पर r बैंको के कुल जमा और R^d में अनुपात है । संक्षेप में इसे आरक्षित जमा अनुपात कहा जा सकता है ।

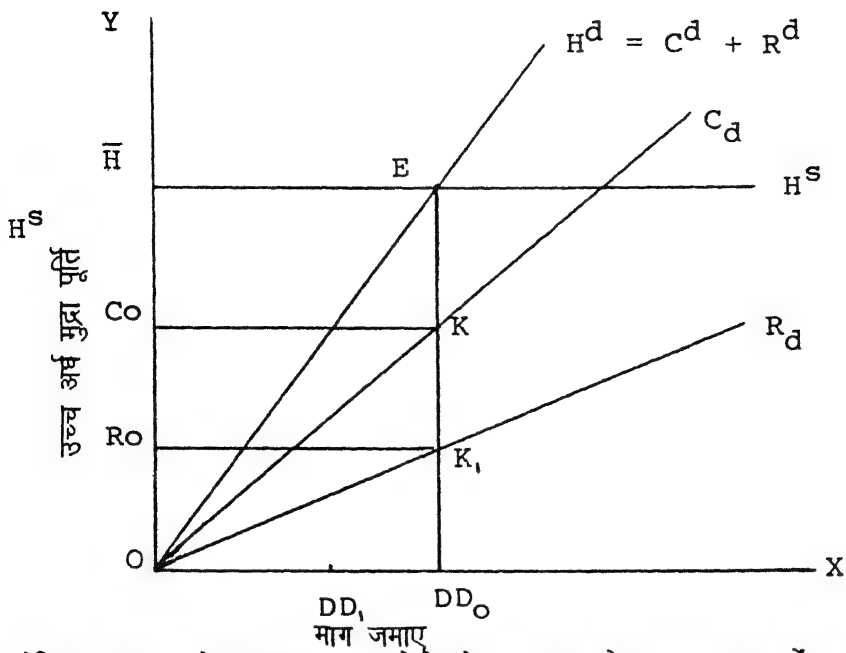
मुद्रा पूर्ति विश्लेषण में हम देख चुके हैं कि बैंकों की जमायें दो प्रकार की होती हैं । प्रथम माग जमाये (DD) तथा दूसरे समय जमाये (TD) । हमने यह भी देखा था कि माग जमा (DD) को मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित करते हैं और समय जमाओं (TD) को इसमें सम्मिलित नहीं करते । बैंको में DD की तुलना में कितना TD रखना है, यह लोग ही निर्धारित करते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि TD^d एक DD का वृद्धि आनुपातिक फलन है । यथा ,

$$TD^d = t DD \dots\dots\dots (6)$$

यहा पर t जो है वह DD और TD^d का अनुपात है । संक्षेप में इसे सावधि जमा अनुपात कहते हैं । H सिद्धान्त में मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करने में निम्न चित्र का प्रयोग किया जा सकता है । चित्र में H को OY अक्ष पर तथा DD को OX पर दिखाया गया है

चूँकि H की पूर्ति मौद्रिक अधिकारियों द्वारा दी हुयी होती है इसलिये H की

चित्र- 3 ।



रेखा क्षेत्रिज OX के समानान्तर होती है । यह रेखा इस रूप में यह दिखाती है कि H पूर्णतया DD से बेलोच होती है । H के माग की तीन रेखाएँ R^d , C^d तथा H^d नीचे मूल बिन्दु O से ऊपर की ओर सीधे जाती है ।

चित्र में H^d रेखा और H रेखा के कटान बिन्दु E पर H के बाजार में संस्थिति को दिखाती है । इस बिन्दु पर लोग तथा बैंक दोनों H के सम्पूर्ण मात्रा को रख कर सतुष्ट रहते हैं, जो मात्रा मौद्रिक अधिकारी मुद्रा बाजार में रखना चाहते हैं । यहा पर DD की संस्थिति मात्रा DD_0 है । यहा लोगों के पास करेन्सी की मात्रा C_0 है । अब H का अवशेष अर्थात् $H - C_0 = R_0$ बैंको के पास है । DD_0 मात्रा हेतु यह पूर्णतया बैंकों के R^d के बराबर है। यहा यह भी स्पष्ट है यदि C^d फलन दिया हुआ हो तो C_0 ठीक करेन्सी की वह मात्रा होती है, जिसे लोग अपने पास रखना चाहते हैं, जब कि $DD = DD_0$ है।⁵

उपर्युक्त विश्लेषण का मुख्य अभिप्राय यह है कि माग जमाओं के आधार पर मुद्रा पूर्ति के वृद्धि में द्वितीयक योगदान को स्पष्ट करना है । यहा पर मुद्रा पूर्ति परिवर्तनों में बैंक के योगदान को भी स्पष्ट किया गया है । यह बात और अधिक तब स्पष्ट हो जाती है, जब हम मुद्रा

5. S.B. Gupta, Monetary Economics, Institutions, Theory and Policy, 1982, pp. 286-92.

गुणक प्रक्रिया को समझते हैं । साथ ही साथ हम x तथा R बाजारों के सन्तुलन विश्लेषण का भी यह अध्ययन करते हैं ।

अतिरिक्त आरक्षितों पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होती, अतः बैंक अवाक्षित अतिरिक्त वाक्षितों से छुटकारा पाने के लिये लाभ अर्जित आदेशों की ओर उन्मुख होते हैं । लाभ अर्जित आदेशों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - (1) विनियोग और (2) ऋण एवं अग्रिम । विनियोग सरकारी या व्यक्तिगत क्षेत्रों के बाजारी प्रतिभूतियों में किया जाता है । 'एच' मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त की यह मान्यता है कि प्रचलित ब्याज दर के सन्निकट लाभ अर्जित करने वाले आदेशों की पूर्ति अत्यधिक लोचदार होती है और सामान्यतया बैंक अपने अवाक्षित अतिरिक्त आरक्षितों के द्वारा इन लाभ अर्जित आदेशों की ओर उन्मुख नहीं होते । इस तरह 'एच' सिद्धान्त की यह महत्वपूर्ण मान्यता है कि बैंक अपने आरक्षितों जमाओं में संस्थिति प्राप्त करते हैं । किसी समय के सन्दर्भ में पहले बैंकों को अधिकांश लाभ अर्जित करने वाले आदेशों को ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में रखा जाता था और प्रतिभूतियों में विनियोग बहुत कम होता था । इसका प्रधान कारण सरकारी ऋणों और प्रतिभूतियों के निम्न स्तर का होना था । मदी की ऐसी दशाओं में बैंक ऋणों और अग्रिमों की माग बहुत तेजी से गिरती थी और बैंकों के पास अवाक्षित अतिरिक्त आरक्षित बचते थे । अनेक कारणों से अधिकांश समयों में बैंकों के ऋण का बाजार अतिरिक्त पूर्ति की तुलना में अतिरिक्त माग से प्रभावित रहता है । सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से जब से सरकार ने नियोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाया है, तब से सरकार को वित्त की आवश्यकता सदैव पड़ती रहती है और इस तरह सरकार खुले बाजार से बैंकों तथा अन्य स्रोतों से उधार लेने के लिये तत्पर रहती है । सार्वजनिक ऋण के प्रबन्धक के रूप में रिजर्व बैंक ने सरकारी ऋणों के बाजार विस्तार पर विशेष बल दिया है । अतः अल्प काल में बिना पूँजी हानि के जोखिम उठाये बैंक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ काफी बड़ी मात्रा में विनियोग कर सकते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि चाहे बैंक ऋणों और अग्रिमों की माग महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाये, फिर भी बैंक अवाक्षित नकद आरक्षितों में अवसृद्ध के लिये वाक्षित नहीं है । वे लाभ अर्जित आदेशों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की ओर उन्मुख हो सकते

हैं । इन सभी को हम भारतीय मौद्रिक अनुभवों के आधार पर सत्यापित कर सकते हैं । अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के कुल माग और समय - जमाओं में अतिरिक्त आरक्षितों के अनुपात 1950-51 में 6 84 से लगातार गिरते हुये 1960-61 में 2 91 हो गये । इस स्थिति के अनेक महत्वपूर्ण कारण हैं, किन्तु यहा इनका विवरण देना सम्भव न होगा । यह बात हमारे सैद्धान्तिक मान्यता की पुष्टि करता है कि बैंकों की क्षमता लाभ अर्जित करने वाले आदेशों की ओर उन्मुख होने की तब होती है, जब उनके पास अवांक्षित अतिरिक्त आरक्षित होते हैं और वे वास्तविक अतिरिक्त आरक्षितों को वांक्षित अतिरिक्त आरक्षितों के बराबर रखते हैं ।

यहा पर 'एच' को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण भी महत्वपूर्ण होगा । यह माना जाता है कि एच का निर्धारण नीतिगत है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में यह इतना आसान नहीं है । हम जानते हैं कि 'एच' व मुद्रा पूर्ति है, जो मौद्रिक अधिकारियों - सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा उत्पन्न की जाती है और लोगों तथा बैंको द्वारा रखी जाती है । इस तरह यह सरकारी करेन्सी तथा आरक्षित बैंक मुद्रा हैं, जो लोगों और बैंको द्वारा रखी जाती है । 'एच' का कुल स्टॉक मात्रा में सरकारी करेन्सी का भाग बहुत कम है । 1975-76 में यह 7 3 प्रतिशत था और इस तरह आरक्षित बैंक मुद्रा इसका सबसे बड़ा हिस्सा है । सरकारी करेन्सी में परिवर्तन का निर्धारण आरक्षित बैंक मुद्रा द्वारा होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित ऊँचे मूल्य के करेन्सी के सदर्भ में यह लोगों के छोटे सिक्के की माग को दिखाता है । इस तरह आरक्षित बैंक द्वारा मुद्रा में होने वाले परिवर्तन ही वस्तुतः एच में होने वाले सभी परिवर्तनों के लिये जिम्मेदार है । नीचे हम आरक्षित बैंक मुद्रा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक इसे पूरी तरह से परिवर्तित नहीं करती । यहा पर पूर्णतया लेखा - जोखा का विवरण दिया गया है । पर यह प्रारम्भिक विश्लेषण है, जिसके आधार पर 'एच' पर कार्यशील जटिल शक्तियों को समझा जा सकता है ।

मुद्रापूर्ति का उच्च अर्थ सिद्धान्त एक तरह से मुद्रा गुणक का ही सिद्धान्त है । इसमें आरक्षितों के होने के कारण उससे आधार पर मुद्रा को सृजित करने की शक्ति प्रदान हो जाती है ।

इसलिए इसे आरक्षित मुद्रा, उच्च अर्घ का मुद्रा मौद्रिक आधार कहते हैं।⁶

3.4 भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा-जोखा मुद्रा पूर्ति विश्लेषण

यहा पर हम भारतीय रिजर्व बैंक के एक लेखा-जोखा चार्ट सर्वसमिका के रूप में प्रारम्भ करते हैं ।

$$\text{मौद्रिक दायित्वता} + \text{गैर मौद्रिक दायित्वता} = \text{वित्तीय आदेय} + \text{अन्य दायित्वता}$$

यहा पर हम देखते हैं कि शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्वता तथा अन्य आदेयों के अन्तर के बराबर है और इसतरह उपर्युक्त सर्वसमिका को निम्न रूप में लिख सकते हैं मौद्रिक दायित्वता = वित्तीय आदेय, ऋण, शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्वता ।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक दायित्वता वही है, जो आरक्षित बैंक मुद्रा है और इस तरह आरक्षित बैंक मुद्रा को प्रभावित करने वाले कारक भी वही हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय आदेय अपने लेन - देन क्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं अतः इन्हें क्षेत्रवार विभाजित किया जा सकता है, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसी प्रकार का क्षेत्रवार विभाजन गैर मौद्रिक दायित्वों के बारे में उपलब्ध नहीं है । एच को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के लेन - देन कार्यों को चार क्षेत्रों में बाटा जा सकता है - (1) सरकार, (2) बैंक, (3) विकास बैंक, (4) विदेशी क्षेत्र । भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें साख प्रदान करती है । अपने वित्तीय आदेयों को प्राप्त करती है और आरक्षित बैंक मुद्रा को सृजित करती है । इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय आदेयों तथा शुद्ध साख को निम्न रूप से लिखा जा सकता है -

6. Report of the committee to Review the Working of the Monetary System, 1985, p. 65.

- आरक्षित बैंक मुद्रा = (1) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध साख
 + (11) भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकों को शुद्ध साख
 + (111) भारतीय रिजर्व बैंक का विकास बैंकों को शुद्ध साख
 + (1V) भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध विदेशी विनिमय आदेय
 - (V) भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्व

'एच' को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों के परिप्रेक्ष्य में तथा उपर्युक्त दी गयी भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सर्वसमिका के सदर्थ में रिजर्व बैंक के मुद्रा पूर्ति के विश्लेषण को देना उपयुक्त होगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रापूर्ति के किसी भी सिद्धान्त का अनुकरण नहीं करती। इसके स्थान पर यह प्रत्येक माह शुद्ध लेखा - जोखा के विश्लेषण को प्रकाशित करती है, जिससे यह मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों अथवा मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन के स्रोतों के रूप में सम्बोधित करती है। इस तरह के तथाकथित मुद्रा पूर्ति विश्लेषण को सभी कार्यशील एजेन्सियों तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुसरण किया जाता है और इस तरह एक बिल्कुल लेखा - जोखा के रूप में मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त का स्थान ले लिया है। मुद्रा पूर्ति पर कार्यशील शक्तियों तथा सही मौद्रिक नीति निर्माण हेतु इस तरह का विश्लेषण बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को स्पष्ट करने के पूर्व यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा - जोखा मुद्रापूर्ति विश्लेषण को प्रथमतः दिखाया जाय। इसे निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है -

मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के स्रोत -

- (1) सरकार को शुद्ध बैंक साख (अ + ब)
 (अ) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध साख (1-11)
 (1) सरकार पर अदायगी,
 (11) रिजर्व बैंक में सरकार की जमाएँ,
 (ब) सरकार को अन्य बैंक साख

- (2) व्यापारिक क्षेत्र में बैंक साख (अ + ब)
(अ) व्यापारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक साख
(ब) व्यापारिक क्षेत्र में अन्य बैंकों का साख
- (3) बैंकिंग क्षेत्र के शुद्ध विदेशी विनियम आदेय (अ + अ)
(अ) भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध विदेशी विनियम आदेय
(ब) अन्य बैंकों के शुद्ध विदेशी विनियम आदेय
- (4) लोगों को सरकार की करेन्सी दायित्वता
- (5) बैंकिंग क्षेत्र को शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्वता (अ + ब + स)
(अ) बैंकों की समय जमायें,
(ब) भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्वता
(स) बैंकों की अन्य शुद्ध गैर मौद्रिक दायित्वता

इन उपरोक्त कारकों के सदर्थ में हम मुद्रा पूर्ति को निम्न रूप में लिख सकते हैं -

$$\text{मुद्रा पूर्ति} = 1 + 2 + 3 + 4 - 5$$

मुद्रा पूर्ति के उपर्युक्त विश्लेषण को भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के सग्रथित लेखा - जोखा चार्ट से प्राप्त किया गया है । इसको इसके वित्तीय आदेयों को क्षेत्रवार विभाजित करके बनाया जाता है । यहा यह उपर्युक्त होगा कि मुद्रा पूर्ति के इस लेखा - जोखा विश्लेषण को कुछ आलोचनात्मक बिन्दुओं का सकेत किया जाय ।

भारतीय रिजर्व बैंक इस मुद्रा पूर्ति विश्लेषण में व्याख्यात्मक गुण नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध लेखा - जोखा विश्लेषण है । यह अनेक नीतियों एव गैर नीतियों में होने वाले परिवर्तन के कारण उनके मुद्रा पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है । उदाहरणार्थ भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ अथवा आरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन अथवा शुद्ध विदेशी

सहायता में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न प्रभावों को नहीं समझा जा सकता । कुल मिलाकर के यह मुद्रा स्टॉक की माप कर सकता है, किन्तु उसके अनुमानों का विश्लेषण नहीं कर सकता । आकड़ों का वर्गीकरण किसी भी व्याख्या को स्पष्ट नहीं करता और यह मुद्रा पूर्ति के किसी सिद्धान्त का प्रतिस्थापन रूप ले सकता है । यह सभी तर्क मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण पर भी लागू होते हैं । यदि हमें मुद्रा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना है तो मुद्रा पूर्ति के किसी सिद्धान्त का आश्रय लेना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में हमने पहले ही ऐसे सिद्धान्त की व्याख्या की है, जो 'एच' के परिवर्तन रूपों में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तनों की व्याख्या करता है । दूसरी बात जो इस विश्लेषण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, वह यह है कि मुद्रा पूर्ति का लेखा - जोखा विश्लेषण 'एच' और 'एम' के अवयवों के योग को प्रस्तुत करता है और इसमें एच पर 'एम' के आश्रित होने पर ध्यान नहीं दिया जाता । इसके परिमणाम स्वरूप इस विश्लेषण में मुद्रा गुणक विश्लेषण की प्रक्रिया का पूर्णतया अभाव है । यह बात किसी मौद्रिक अर्थशास्त्री अथवा रिजर्व बैंक द्वारा गभीरतापूर्वक नहीं किया गया था, क्योंकि मुद्रा पूर्ति सम्बन्धी उपागमों में इसके कारण कई कमियां आ जाती हैं । यह दिखाया जाता है कि मुद्रा पूर्ति पर सरकारी क्षेत्र का कुल प्रभाव है, कुल बजट घाटे और इसके भारतीय रिजर्व बैंक से शुद्ध विदेशी आदेयों के क्रय के अन्तर के बराबर । किन्तु यह तथ्य पूर्णतः गलत है । साथ ही साथ यह बात भी स्पष्ट की गयी है कि सरकार को अन्य बैंकों का साथ उसी मात्रा में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करता है । परन्तु यह तथ्य भी सही नहीं है । इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा - जोखा सारणी मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले एक कारक के रूप में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की साथ को पूर्णतया अपेक्षित करता है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था के समग्र आदेयों तथा दायित्वों को संग्रहित करने में यह आन्तरिक लेन - देन के रूप में छिप जाता है, किन्तु यह बात गलत है, क्योंकि बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना 'एच' और अन्ततः एम में वृद्धि करता है ।⁷

7. R.B.I., Report on Currency and Finance, (Various Issues)

3 5 साख की पूर्ति तथा इसका निर्धारण

मुद्रा पूर्ति और सम्बन्धित सिद्धान्तों के विश्लेषण के साथ यहा पर साख - पूर्ति और उसके निर्धारण से सम्बन्धित विश्लेषण को भी देना उपयुक्त होगा । यहा पर प्रथमतः कुल बैंक साख पूर्ति सिद्धान्त का विश्लेषण तथा सस्थागत साख के निर्धारण सम्बन्धी कारकों का विश्लेषण किया जायेगा । प्रथम रूप में मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा और मुद्रा गुणक विश्लेषण को साख पूर्ति के विश्लेषण में प्रयोग किया जायेगा । साथ ही साथ कुल साख की मात्रा के साथ बैंकों से साख के अन्तर ऋण ग्राहकों का निर्धारण भी महत्वपूर्ण है । यहां हम बैंक तथा गैर बैंक साख में भेद नहीं करेंगे, अपितु हर तरह के सस्थागत साख को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करेंगे ।

प्रारम्भ में बैंक साख और बैंक जमाओं सिद्धान्त का विश्लेषण किया जा सकता है । यहा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बैंक साख और बैंक जमाओं का पारस्परिक सम्बन्ध है । वस्तुतः वे एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं अर्थात् बैंकों का लेखा-जोखा चार्ट, यद्यपि पहले मौद्रिक अर्थशास्त्रियों में इन दोनों के सम्बन्ध को लेकर विवाद रहा है, विशेषकर इस बात से कि को कारक है और कौन परिणाम यह इस रूप में विवाद का विषय रहा है कि क्या ऋणों से जमाएँ बढ़ती हैं या जमाओं से ऋण बढ़ता है । इस सम्बन्ध में दो प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं । एक रूप में यह कहा जा सकता है कि एक छोटे बैंक के दृष्टिकोण से यह कहना अधिक उपयुक्त है कि जमाओं से ऋण में वृद्धि होती है, किन्तु पूरी बैंकिंग व्यवस्था की दृष्टि से यह कहना अधिक सही होगा कि ऋणों से जमाएँ बढ़ती हैं । दूसरे तरह का उत्तर पहले के इस उत्तर से भिन्न है । पूरी बैंकिंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये यहा पर दूसरे तरह के उत्तर में बैंक जमाओं और साख के बीच सम्बन्ध को एक चक्रीय रूप में देखा जाता है, जिससे यह बात कहना सही है कि जमाएँ ऋण उत्पन्न करती हैं और ऋण जमाएँ उत्पन्न करती हैं । इसी तरह का विश्लेषण केन्स के आय -

निर्धारण सिद्धान्त में आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह⁸ के रूप में देखा जा सकता है, किन्तु दोनों दशाओं में बैंक जमाओं तथा साख सम्बन्धी चरों का साथ - साथ निर्धारण किया जाता है, न कारण रूप में और न ही परिणाम के रूप में। वस्तुतः दोनों एक तीसरे स्वतन्त्र कारक के द्वारा निर्धारित होते हैं और व्यवस्था के कुछ फलनात्मक सम्बन्धों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः इस सिद्धान्त का कार्य है कि इस तीसरे कारक को दिखाये और व्यवहारिक सम्बन्धों को स्पष्ट करे और ब्याज, बैंक जमाओं और साख के पारस्परिक निर्भरता के सम्बन्ध में इनके पारस्परिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करे। इस सम्बन्ध में साख - सिद्धान्त का रूप मुद्रा पूर्ति के 'एच' सिद्धान्त का सरलीकरण रूप होगा, जिसे हम बैंक जमाओं का 'एच' सिद्धान्त कहेंगे। क्योंकि मुद्रा पूर्ति, बैंक जमाओं और बैंक साख को निर्धारित करने वाले कारकों में बहुत गहरा सम्बन्ध है। अब हम बैंक साख अथवा बैंक साख गुणक सिद्धान्त को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर मुद्रा पूर्ति के एच सिद्धान्त से इसका अन्तर मुद्रा और बैंक साख के अलग - अलग परिणाम के कारण होता है यहाँ पर मुद्रा पूर्ति को सकीर्ण अर्थ में कुल करेन्सी तथा माग जमाओं के योग के रूप में दिखाते हैं, जो लोगों के पास है वहीं हम बैंक साख (BC) को विस्तृत रूप में सरकार और व्यापारिक बैंकों के कुल साख योग के रूप में दिखाते हैं। एक लेखा - जोखा चार्ट के रूप में यह हर तरह के ऋणों और अग्रिमों (LA) तथा विनियोगों (I) योग है। विनियोग और ऋण तथा अग्रिमों को साथ - साथ बैंकों के लाभार्जित आदेय (EA) भी कहते हैं। इस तरह हम निम्न रूप में पाते हैं -

$$BC = I + LA = EA \quad \dots\dots\dots (1)$$

इसको सरल रूप में हम यह मानते हैं कि सभी संग्रथित बैंकों का लेखा - जोखा चार्ट निम्न रूप में दिखाया जा सकता है -

$$DD + TD = R + I + LA \quad \dots\dots\dots (2)$$

यहाँ पर DD, कुल माग जमाएँ, TD, कुल समय जमाएँ तथा R, कुल बैंक आरक्षित हैं।

8. R.D. Gupta, Keynes and Post Keynesian Economics, p. 65.

यहा यह उल्लेखनीय है कि पूरे बैंक के दृष्टिकोण से अतर बैंक जमाओं, तात्कालिक ऋण तथा अन्य ऋणों के रूप में अन्तर बैंक लेन - देन का समायोजन हो जाता है और बैंको के सग्रथित लेखा - जोखा चार्ट पर इसे नहीं दिखाया जाता । मुद्रा पूर्ति सिद्धान्त के पिछले विवरण के आधार पर हम निम्न समीकरण प्राप्त कर सकते हैं -

$$T D_d = t DD \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$D = DD + TD$$

$$= (1+t) DD \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$R_d = r(1+t) DD \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$DD = [c + r (1+t)]^{-1} H \quad \dots\dots\dots (6)$$

अब समीकरण (1) तथा (2) से निम्न प्राप्त कर सकते हैं -

$$B C = I + L A$$

$$= DD + TD - R \quad \dots\dots\dots (7)$$

अब संस्थिति हेतु, जिसमें $R = R_d$ तथा TD_d समीकरण

(4), (5) तथा (7) के रूप में हम निम्न प्राप्त कर सकते हैं -

$$B C = (I - r) D$$

$$= (I - r) - (I+t) DD \quad \dots\dots\dots (8)$$

अब समीकरण (6) का प्रयोग करने पर हम निम्न पाते हैं -

$$B C = \frac{(I - r) (I + t)}{c + r (I + t)} \cdot H \quad \dots\dots\dots (9)$$

समीकरण (9) में $B C$ को H का आनुपातिक फलन बनाता है, जहा कारक अनुपातिता तीन फलनात्मक आदेय अनुपातों c, t तथा r के फलन रूप में हैं । इस कारक को बैंक साख गुणक b कहा जा सकता है , जिससे समीकरण (9) को निम्न रूप में लिखा जा सकता है -

$$B C = b (.) H \quad \dots\dots\dots (10)$$

जहा,

$$b = \frac{(I-r) (I+t)}{c + r (I+t)}$$

यहा पर समीकरण (9) में बैंक साख गुणक प्रक्रिया वही है, जो पहले त्वरक गुणक में देखी गयी थी, यदि b को समयोपरि स्थिराक मान लिया जाय तो $B_C H$ का बढ़ता हुआ आनुपातिक फलन है । यही बैंक साख के 'एच' सिद्धान्त का मूल तथ्य है । नीति नियोजन के सन्दर्भ में इसका अभिप्राय यह होगा कि कुल बैंक साख पूर्ति के नियंत्रण के लिये 'एच' का नियंत्रण आवश्यक होगा । अब समीकरण (9) को मुद्रा पूर्ति समीकरण से तुलना करने पर हम दोनों में बहुत बड़ी समानता पाते हैं और साथ ही साथ यह समानता मुद्रा पूर्ति के 'एच' सिद्धान्त में और बैंक साख के 'एच' सिद्धान्त में भी है । यहा पर 'एच' को प्रभावित करने वाली वही शक्तिया तथा फलनात्मक आदेय अनुपात c, t, r , दोनों को निर्धारित करते हैं । ये तीनों आदेय अनुपात मुद्रा गुणक तथा बैंक साख गुणक के अनुमानित कारक है । इस तरह बैंक जमाओं का मिद्धान्त इस विश्लेषण में पूरी तरह निहित है । अब समीकरण (4) तथा समीकरण (6) से निम्न प्राप्त करते हैं -

$$D = \frac{1 + t}{c + r (1 + t)} \dots\dots\dots (11)$$

जहा पर एच को गुणा करने वाला अनुपात कुल जमा गुणक के मान को प्रदान करता है । पहले जो बैंक साख को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कहा गया है, वही बैंक जमाओं के बारे में भी उपयुक्त होगा । ⁹

साख निर्माण के सामान्य प्रश्न पर मानक सिद्धान्त अत्यन्त सरल है । यहा पर एक समरूप साख बाजार की मान्यता है, जिसमें ऋण ग्राहकों के सभी साख आदाओं को साख देने की एक जैसी बात कही जाती है । साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि बाजार के दोनों पक्षों में पूर्ण प्रतियोगिता कार्यशील है, जिससे कुल माग कुल पूर्ति के आधार पर एक ही समरूप ब्याज दर का निर्धारण होता है । इसतरह का बाजारी निर्धारित ब्याज दर प्रतिस्पर्धा ऋण ग्राहकों और ऋण

9. S.B. Gupta, Monetary Economics - Institutions, Theory and Policy, 1982, pp. 298 - 299.

दाताओं में विभिन्न उद्देश्यों के लिये एक निर्धारक के रूप में कार्य करता है । विशेष रूप में यहाँ यह निहित है कि प्रत्येक ऋण ग्राहक, जितनी भी मात्रा में ऋण लेना चाहे, वह प्रचलित बज दर पर वह ले सकता है अर्थात् व्यवस्था में कोई भी साख राशिनिग नहीं है । इस तरह के साख बाजार का फलन पूर्णतः अवास्तविक है । न तो साख बाजार पूर्णतः समरूप होते हैं और न ही इन बाजारों में सदैव पूर्ण प्रतियोगिता रहती है । पूर्ति साख के पूर्ति पक्ष पर बड़ी वित्तीय सस्थाओं का अधिपत्य रहता है और माग पक्ष पर प्रभावी व्यक्तिगत उधार ग्राहकों के साख की प्रतिज्ञा एक जैसे नहीं रहती है। यहाँ पर प्रत्येक ऋण ग्राहक की साख योग्यता इन वित्तीय सस्थाओं के सामने रहती है। ये सभी बातें सस्थागत साख तथा सस्थागत प्रक्रिया को बाजारी प्रक्रिया से दूर रखती हैं। यहाँ पर सस्थागत प्रक्रिया बाजारी प्रक्रिया से भिन्न होती है, क्योंकि यह मूल्य प्रक्रिया से मगानित नहीं होती है। प्रायः योग्य ऋण ग्राहकों का चुनाव गैर मूल्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तथा इसी तरह कुल साख मात्रा का भी निर्धारण किया जाता है । इसके विपरीत विशुद्ध बाजारी प्रक्रिया में दोनों पक्षों में मूल्य ही प्रधान होता है । वे लोग जो बाजारी मूल्य अदा करने के इच्छुक होते हैं, वे योग्य ग्राहकों में आते हैं और अन्य को छोड़ दिया जाता है अर्थात् इसके अन्तर्गत उधार ग्राहकों को पूर्णतः उनकी माग वक्र पर पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है ।

एक दिये मूल्य पर जितनी साख की मात्रा उधार लेना चाहें, ले सकते हैं । दूसरे रूप में सस्थागत प्रक्रिया गैर मूल्य कारकों नियमों पर आधारित है और इसमें किसी मूल्य की मान्यता नहीं होती है । अधिक सपष्ट रूप में मूल्य स्वयं माग तथा पूर्ति के निर्धारक रूप में नहीं होती, बल्कि यह स्वयं माग तथा पूर्ति के बाजारी दशाओं के कुछ अन्य गैर बाजारी दशाओं से प्रभावित होती है । कार्यशील प्रक्रिया नियम तथा गैर कार्यशील प्रक्रिया यहाँ साख राशिनिग के लिये महत्वपूर्ण है । अतः साख निर्धारण में यहाँ इन प्रयोगों तथा गैर मूल्य कारकों को स्पष्ट करना आवश्यक होगा । यहाँ यह दिखाना आवश्यक होगा कि गैर मूल्य कारक किस तरह मूल्य कारक पर अधिक प्रभावी है । सस्थागत कारक को प्रभावित कारकों की दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1 वित्तीय

2 गैर वित्तीय

जहा तक सस्थागत साख के निर्धारण में वित्तीय कारकों का प्रश्न है, उनमें साख की अदायगी तथा शुद्ध प्रतिफल दर है । इन दो कारकों के साथ और बहुत से कारक हैं । यहा पर संक्षेप में इन दो कारकों का विश्लेषण किया जा रहा है । साथ ही साथ यहा पर ऋण तथा साख को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है । जहा तक प्रतिफल के शुद्ध दर का प्रश्न है, यह ऋण के ब्याज दर और ऋण के सेवा लागत के अंतर से प्राप्त होता है । प्राप्त सिद्धान्त के अनुसार ऋण ब्याज दर साख का अकेले नियंत्रक कारक है । वास्तविक जीवन में संस्थागत ऋण ब्याज दर को प्रशासनिक कीमते कहते हैं । यह दर जो महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह यह है कि इच्छुक ऋण ग्राहक और गैर ऋण ग्राहक को अलग करता है । जो लोग स्वतंत्र दिये गये ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें इसमें स्वतः निर्धारित कर लिया जाता है और सीमित अर्थ में यह ब्याज दर एक रशनिंग प्रक्रिया का कार्य करता है, किन्तु इच्छुक ऋण ग्राहकों में ब्याज दर के अलावा अन्य शक्तिया भी कार्य करती हैं और यही शक्तिया सस्थागत साख के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है । यहा ऋण सेवा लागत पर भी ध्यान दिया जा सकता है कि ऋण सेवाओं पर क्या लागत है । यहा पर यह पर्याप्त होगा कि मध्यम ऋणों की सेवा लागते बड़े सेवा लागतों से अधिक होती हैं और इसलिए यदि एक जैसा प्रतिफल दिया गया हो और अन्य बातें समान हों तो छोटे ऋणों पर शुद्ध प्रतिफल दर बड़े ऋणों के प्रतिफल दर से कम होती है । इससे सस्थागत ऋण दाताओं को छोटे ऋण देने में हतोत्साहित होना पडता है किसी भी दिये गये ऋण में दो तरह के अदा करने की प्रतिज्ञा निहित है । वह मात्रा, जो ऋण ग्राहक द्वारा ली गयी है, उसे अदा करने की तथा ऋण पर ब्याज दर अदा करने की प्रतिज्ञा । इन दोनों अदायगियों का सम्बन्ध भविष्य से हैं । अतः इसमें अनिश्चयता तथा जोखिम निहित है कि इसमें से ऋण ग्राहक एक को या दोनों को अदा न कर सके । सामान्यतया एक स्थायी राजनैतिक वातावरण में सरकारी ऋणों पर अदायगी का जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों से अदायगी के इसके अनेक अधिकार होते हैं, परन्तु व्यक्तिगत

क्षेत्रों के सभी ऋणों पर कुछ न कुछ जोखिम सम्बन्धित है । अतः ऋण दाता का सबसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध इस जोखिम का पता लगाना है और पर्याप्त उपयुक्त रूप से इसके सम्बन्ध में सुरक्षित होना है । यहाँ पर कुल मिला करके साख ग्राहकों की साख योग्यता का प्रश्न है । इस तरह के साख निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह से बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं है और वे मात्र माग और पूर्ति शक्तियों से निर्धारित नहीं होती और यह कई गैर बाजारी शक्तियों पर आधारित है तथा हर देश में अलग - अलग होती है ।

यहाँ पर साख अदायगी से सम्बन्धित जोखिम के दो स्रोतों में भेद करना महत्वपूर्ण होगा (1) व्यक्तिगत (नैतिक) जोखिम, (2) व्यापारिक जोखिम । पहला जोखिम उधार लेने वाले की इमानदारी से सम्बन्धित है, जो ऋण की अदायगी न कर सके और यह भी बाजारी शक्तियों पर आधारित नहीं है । इस पर मुख्य रूप से राजनैतिक प्रवाह भ्रष्टाचार, गैर इमानदारी आदि है, व्यापार जोखिम, उद्यमों के जोखिम पर निर्भर करता है । मोटे तौर पर यह उधार लेने वाले की अदायगी क्षमता पर आधारित है । यह ऋण ग्राहकों के वर्तमान और सम्भावित सम्पत्तियों तथा आय दशाओं पर निर्भर करता है । अतः ऋण देने के पूर्व ऋण दाताओं को ऋण ग्राहकों की पूरी वित्तीय स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए ।

अनुभव के आधार पर यह प्राप्त हुआ है कि भुगतान सामर्थ्यता भी ऋण दाता के लिये ऋण देने के लिये उत्साहित नहीं करता, क्योंकि वास्तविक साख क्षति की दशा में यह पर्याप्त नहीं है कि ऋण दाता ऋण और व्याज की वसूली कर सके । परिणाम स्वरूप ऋण दाता पर्याप्त मात्रा में ऋण के बदले प्रतिभूति रखने पर जोर देता है । इसी तरह प्रतिभूति के बदले दिये गये ऋण को सुरक्षित ऋण कहा जाता है और जो ऋण प्रतिभूतियों के आधार पर नहीं दिया जाता , उन्हें असुरक्षित ऋण कहा जाता है और उसे अल्पावधि के लिये विश्वसनीय ग्राहकों को दिया जाता है । ¹⁰ प्रतिभूति आधार पर ऋण देने का मुख्य आधार ऋण क्षति से सुरक्षित रखना है । तथा

10. State Bank of India, Manthly Review, June, 1988.

ये वस्तुओं, सेवाओं की मात्रा, मशीन, मोटर गाडिया, वास्तविक सम्पदा, सोना - चादी, अन्य जेवरात, वस्तुओं की रसीदें, बिल आदि तथा विनियम स्टॉक प्रतिभूतिया, जैसे जीवन बीमा निगम प्रतिभूतिया, सार्वधिक जमा रसीदें, बिल आदि हो सकते हैं । इन्हें बैंकिंग आदेय कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिभूतिया बैंको में स्वीकार होती है । किसी ऋण के बदले प्रतिभूति के रूप में आदेय का स्वीकार होना वाक्षनीय गुणों पर आधारित है अर्थात् वे स्थायी तथा अचल हैं और ऋण समयावधि में उनके मूल्य में गिरावट न हो और उन्हें आसानी से रखा जा सके और उनका मूल्य स्थिर हो, और इनका आर्थिक मूल्य पर्याप्त हो, जिससे ऋण तथा ब्याज की वसूली की जा सके । यहा यह समझ लेने की बात है कि जब किसी आदेय को एक प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, तो ओदर्यों पर ऋण दाता का अधिकार होना चाहिए और यह अधिकार सस्थागत है, न कि बाजारी प्रक्रिया । यह अधिकार व्यापारिक क्रिया तथा देश के नियम के अन्तर्गत होना चाहिये । उदाहरण के लिये अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऋण दाता को सम्पत्ति का अधिकार हस्तान्तरण कर दिया जाता है । इन सब बातों का महत्व अर्थशास्त्रियों के लिये दो दृष्टिकोणों से है । प्रथम तो यह कि ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में पर्याप्त सक्षम कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है और दूसरे इससे जुड़े हुये सेवा लागत है, जिसमें ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन स्वीकृत, बंटवारा, ऋणों की अदायगी, कानूनी कार्यवाही, आदेयों की बिक्री आदि सम्मिलित है ।

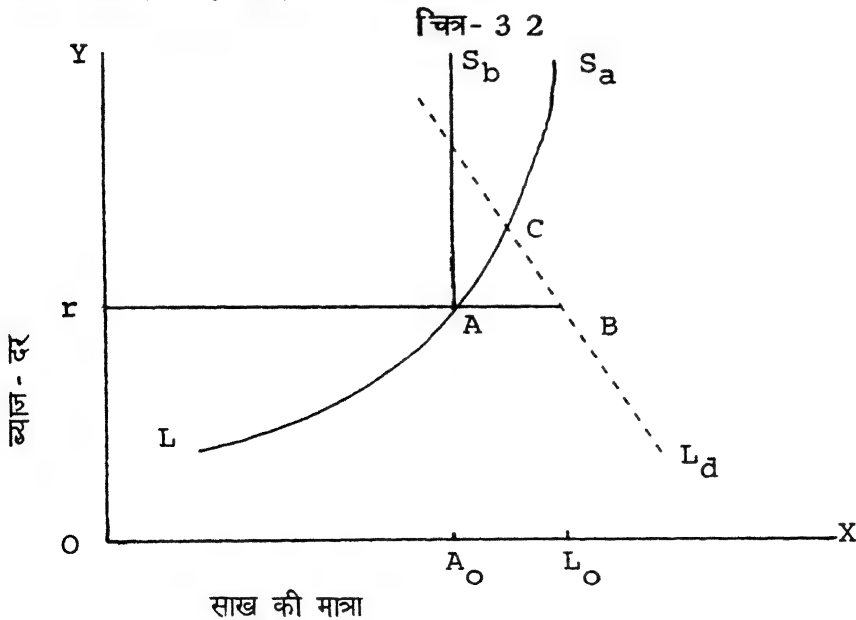
जब स्वीकृत प्रतिभूति प्रदत्त की गयी हो, उस दशा में ऋण ग्राहकों को कितना साख इसके बदले में दिया जाय, बैंक सामान्यतया बैंकिंग आदेयों के पूरे मूल्य के बराबर ऋण प्रदान नहीं करते, उसके एक प्रतिशत के रूप में ऋण के रूप में दिया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य और प्रतिशत ऋण के अन्तर को ऋण ग्राहक के उधार लेने की शक्ति को प्रदर्शित करता है । इस प्रतिशत ऋण व्यवस्था का मुख्य योगदान ऋण द्वारा वित्तीय व्यापारिक कार्यों में स्थिरता बनाये रखना है । यदि ऋण दाता प्रतिभूति के पूरे मूल्य के बराबर ऋण निर्गत कर देते हैं तो ऋण ग्राहक का व्यापारिक कार्यों में स्थिरता न बनी रह सकेगी और ऐसी स्थिति में भुगतान जोखिम अधिक

इसके आधार पर ऋण ग्राहक को पुनः ऋण लेने के लिये योग्य बनाना है। ऋण के बदले में दी जाने वाली ये प्रतिभूतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं - प्राथमिक प्रतिभूतियाँ तथा कोलेट्रल प्रतिभूतियाँ। प्राथमिक प्रतिभूतियाँ आदेयों की प्रतिभूतियाँ, जो ऋण फंड द्वारा सृजित या प्राप्त की जाती हैं तथा कोलेट्रल प्रतिभूतियाँ, प्राथमिक प्रतिभूतियों के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर होती हैं, ये प्रायः ऋण ग्राहक द्वारा स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, जो लिये गये ऋण की शर्तों या गारंटी रूप में होती हैं। प्रायः व्यक्ति ऋणों में इस तरह का अन्तर महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि ऋण दाता प्रायः स्वर्णाभूषणों या अचल सम्पत्तियों के आधार पर ऋण देते हैं, किन्तु उभयोन वस्तुओं के वित्तीयन में हायर परचेज वित्त कम्पनियाँ प्रायः प्राप्त कोलेट्रल प्रतिभूतियों की माग करती हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने वाला उन उपभोग वस्तुओं के स्वामित्व और उनके उपयोग को करता है। इसी तरह व्यवसायिक ऋण उत्पादक व्यवसायी आदेयों को सृजित करने या प्राप्त करने हेतु लिये जाते हैं, चाहे वे फैक्ट्री निर्माण, मशीन क्रय आदि को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ऋणदाता को देते हैं। इस तरह के प्रश्नों का सम्बन्ध साख निर्धारण से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। यह बात स्पष्ट है कि कोलेट्रल प्रतिभूतियों को कड़ाई से लागू करने में संस्थागत ऋणदाता जैसे बैंक को अपने आधारभूत कार्यों में अड़चने पड़ सकती है, जैसे उत्पादक साख देने में, क्योंकि सभी सम्भावनी ऋण ग्राहक इस स्थिति में नहीं होते कि बैंक द्वारा प्रदत्त साख अग्रिमों के बदले वे पर्याप्त कोलेट्रल प्रतिभूतियाँ दे सकें। इसी तरह यहाँ महत्वपूर्ण बात इस तथ्य से जुड़ा है कि बैंक साख को प्राप्त करने वाले निर्धन वर्ग इस तरह को प्राप्त करने वाले निर्धन वर्ग इस तरह की प्रतिभूतियों को कैसे अदा कर सकते हैं। बड़े ऋण ग्राहकों के सम्बन्ध में निदेशकों के व्यक्तिगत प्रतिभूतियाँ प्राप्त समझी जाती हैं, जिसके कारण यह प्रक्रिया बड़े एवं धनी ऋण ग्राहकों के लिये अनुकूल है, जब कि इससे नये और छोटे उद्यमी विपरीत रूप में प्रभावित होते हैं। अतः यह उपयुक्त होगा कि कोलेट्रल प्रतिभूतियों के रूप में अधिक जोर न दिया जाय और ऋण ग्राहक के भुगतान सामर्थ्यता को देखा जाय। अतः यहाँ ऋण ग्राहक के प्राथमिक प्रतिभूति से है, न कि कोलेट्रल प्रतिभूति से। अनेक प्रकार के आदेयों का प्रयोग प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है,

होगा । भारत के साथ अनेक देशों में केन्द्रीय बैंक ने इस सीमा प्रतिशत का प्रयोग चयनात्मक साख विधियों में किया है । इसका प्रयोग करने से विभिन्न व्यापारिक तथा आर्थिक क्रियाओं में ऋण का हतोत्साहित या उत्साहित किया जा सकता है । वास्तविक व्यवहार में साख जोखिम के सम्बन्ध में ये सभी सस्थागत सभावनाएँ हैं, विशिष्ट ऋण ग्राहकों द्वारा प्रतिवर्तित की जा सकती हैं, क्योंकि प्रतिभूतियों के मूल्यों को ऊँचा दिखाया जा सकता है । इस विवरण से स्पष्ट होता है कि सस्थागत वित्तों में ऋण ग्राहक के साथ योग्यता प्रशिक्षण में कई जटिल शक्तियाँ सम्बन्धित हैं । ये सारी समस्याओं का ध्यान एक साख निर्धारण के एक मानक सिद्धान्त में ध्यान नहीं दिया जाता, ऋण बाजार में ऋण दाता और ऋण ग्राहक का सम्बन्ध काफी समय के लिये बना रहता है और ऋण की अदायगी तक यह कायम रहती है । अतः साख निर्धारण सिद्धान्त में इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिये ।

ऋण दाता द्वारा ऋण ग्राहकों के सम्बन्ध में होने वाले जोखिम के इस विश्लेषण के साथ इन सारी बातों को एक साथ माग और पूर्ति विश्लेषण में रख सकते हैं और एक साख पूर्ति वक्र बनायी जा सकती है, जो साख की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है और इन कारकों पर आधारित हैं, जिस सीमा तक सम्भावी ऋण ग्राहक इन कारकों पर ध्यान देते हैं, उस सीमा तक उनकी साख माँग प्रभावित होती है । परंपरागत सिद्धान्त में किसी व्यक्तिगत ऋण ग्राहक की पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होती है और यह बाजारी निर्धारित ब्याजदर पर इस वक्र पर इन कारकों को ध्यान में रखते हुये कोई व्यक्तिगत ऋण ग्राहक जितना चाहे उधार नहीं ले सकता और इस तरह साख पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढाल लिये होती है । इस सम्बन्ध में साख पूर्ति वक्र या तो ऊपर की ओर सीधे ढाल लिये हो सकती है या एल (L) आकार में हो सकती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है । दोनों ही दिशाओं में यह आवश्यक है कि ऋण ग्राहक की साख योग्यता और ऋण ग्राहक की प्रकृति के आधार पर ऋण दाता द्वारा जोखिम का अनुपात अनुमानित किया जा सकता है । एक सीमा के बाद यह अनुमानित जोखिम इतना अधिक हो सकती है कि ऊँची ब्याज दर पर भी वह ऋण देने को तैयार न होगा । अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिकल्पना का समावेश किया जा सकता है, जो ऋण

देने की प्रतिज्ञा से सम्बन्धित है । सरल रूप में यह परिकल्पना यह निर्देश करती है कि ऋण ग्राहक की यदि शुद्ध क्षमता दिया गया है तो ऋण पर जोखिम, ऋण मात्रा का बढ़ता हुआ फलन है यह इसलिये है कि जोखिम अनिश्चयता कि ससार में किसी विनियोग परियोजना से संभावित प्रतिफल सफल न हो सके और उनमें हानि हो सकती है और ऋण ग्राहक ऋण का भुगतान करने में असफल हो सकता है, इसलिये यदि ऋण ग्राहक का इक्विटी दी हो तो जैसे जैसे ऋण मात्रा में वृद्धि होगी, वैसे-वैसे यह जोखिम बढ़ेगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अन्य बातें सामान्य हों तो जैसे-जैसे ऋण दिया जाता है, जोखिम बढ़ता जाता है । अतः वह ऋण ग्राहक को अधिक ऋण देने का तभी तैयार होगा, जब ब्याज की दर ऊँची हो । साख पूर्ति वक्र के दोनों रूपों को $L A S$ और $R A S_b$ के रूप में होगा । इन दोनों पूर्ति वक्रों का निर्माण इस मान्यता पर आधारित है कि ब्याज दर के अलावा अन्य कारक जो ऋण दाता को उधार देने के लिये प्रभावित करते हैं, वे स्थिर हैं । ये अन्य कारक LS वक्र पर स्थिति का निर्धारित करते हैं । LS_a वक्र यह दिखाता है कि L_o मात्रा तक ऊँचा ब्याज दर अधिक साख पूर्ति का है यहाँ L_o पर यह वक्र पूर्णतया औनुभौमिक हो जाती है, जो यह बात प्रदर्शित करती है कि एल ओ से अधिक साख की मात्रा पर ऋण दाता किसी भी ऊँचे नीचे ब्याज दर पर उसे ऋण जोखिम के बदले उसे ऋण देने के लिये उत्साहित नहीं करती।



साख पूर्ति का L स्वरूप वक्र RASB इस मान्यता पर खींचा गया है कि R ब्याज पर स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है, चाहे यह मौद्रिक अधिकारी अथवा बैंक संघ द्वारा निर्धारित हो। यही बात सस्थागत ऋणों और अग्रिमों के बाजारों में भी सत्य है। इस वक्र पर A बिन्दु पर तीव्र विकुचन होती है, जो LSA वक्र पर स्थित है। यह साख की न्यूनतम मात्रा (A_0) को दिखाती है, जो ब्याज दर पर प्रस्तावित किया जाता है। इस मॉडल में मान्यता के आधार पर कोई भी ऊँची साख की मात्रा तभी प्रस्तावित की जायेगी, जब ब्याज दर R से अधिक हो और इस तरह A बिन्दु LSA वक्र पर ऊपर की ओर बढ़ेगी, जहाँ तक साख की माग वक्र, जो नीचे की ओर गिरती हुयी LD रेखा द्वारा दिखायी गयी है, वह RA साख मात्रा से अधिक नहीं होती, तब तक कोई ऋण ग्राहक निर्धारित साख प्राप्त करता है, वह AB मात्रा के बराबर होता है। इस मॉडल में माग पक्ष का फलन यह निर्धारित करता है कि कोई ऋण ग्राहक साख की निर्धारित मात्रा को प्राप्त कर रहा है और यह मात्रा कितनी है। इस मॉडल में साख पूर्ति वक्र में यदि LD और LSA वक्र बाजारी माग और पूर्ति वक्र है तो साख बाजार में संस्थिति C बिन्दु पर होती है, जो संस्थित ब्याज दर और मागी जाने वाली संस्थिति साख माग और पूर्ति को दिखाती है।

उपयुक्त विश्लेषण को अब अन्तर ऋण दाता साख निर्धारण को दिये गये ब्याज दर विश्लेषण किया जा सकता है। पूर्व किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है कि परंपरागत प्रतिभूति उन्मुख साख पूर्ति के सम्बंध में जो कारक ऋण दाता के लिये महत्वपूर्ण है, वह ऋणग्राहक की इक्विटी या शुद्ध स्थिति है, जिससे उसकी वांछित प्रतिभूति द्वारा अदा करने की योग्यता तथा प्रतिशत ऋण को पूरा करने की स्थिति पता चलती है और कारक जैसे ब्याज दर तथा ऋण ग्राहक के विनियोग परियोजनाओं का जोखिम गैर महत्व के हैं। पुन साख की पूर्ति ऋण ग्राहक के इक्विटी का बढ़ता हुआ फलन है। जितनी अधिक ऋण ग्राहक की इक्विटी होगी, उतना अधिक उसे साख प्रदान किया जायेगा। इस तरह प्रतिभूति उन्मुख साख के निर्धारण का स्थान जिसके पास जितना

है उतना देना है, इस मॉडल में इस तरह पूर्ति वक्र का अभिप्राय होगा कि एक धनी ऋण ग्राहक एक निर्धन ऋण ग्राहक की तुलना में आगे की स्थिति में होगा । इसका अभिप्राय यह होगा कि मॉडल में क्षैतिज रेखा दाहिनी ओर बढ़ेगी, क्योंकि साख की मांग वक्र LD एक धनी ग्राहक के लिये दाहिनी ओर आगे की ओर स्थित होगी, एक निर्धन ग्राहक की तुलना में । अतः धनी ऋण ग्राहक को साख प्रदत्त की मात्रा निर्धन ऋण ग्राहक की तुलना में अधिक होगी । इस तरह ऋण ग्राहक में साख राशिनग का अनुपात अनुपातिक रूप से समान नहीं होगा । अधिक रूपों में यह ऋण ग्राहकों में अलग - अलग होगा और यह अन्तर अधिकांशतः पूर्ति पर होगी । यदि साख की मांग R ब्याज दर दिया हुआ मान लिया जाय । इससे साख सस्थाओं को कुछ ऋण दाताओं की तुलना में साख देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण कुछ लोगों को कई रूपों में सहायता की जा सकती है । जैसे, प्रतिभूति के मूल्य को ऊँचा करके, आसान आदेशों को स्वीकृत करके एक ही प्रतिभूति के बदले कई साख दे कर के, साख देने में सुविधा तथा कम समय ले कर आदि । सस्थागत साख निर्धारण में गैर वित्तीय कारकों का भी विश्लेषण किया जा सकता है । यदि सस्थागत साख का निर्धारण सस्थागत है और एक बाजारी प्रक्रिया नहीं है तो इसको गैर वित्तीय कारक भी उसी तरह प्रभावित करेंगे । ये मुख्य कारक सामाजिक और राजनैतिक हैं । जहाँ तक सामाजिक कारकों का प्रश्न है, वह वित्तीय सस्थाओं से उत्पन्न होते हैं । ये सामाजिक सम्बन्ध पारवारिक सम्बन्धों के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा, बैठकों आदि द्वारा होती हैं तथा साथ ही साथ सामाजिक विकास, भ्रष्टाचार आदि से प्रभावित है । इन सब का परिणाम बड़े उधार ऋण ग्राहकों के पक्ष में होता है । आधुनिक वित्तीय सस्थाओं का उदय वस्तुतः आधुनिक उद्योग और व्यापार के कारण हुआ है और इस तरह समयोपरि उनके सम्बन्धों में परिवर्तन हुये हैं, जैसे कि औद्योगिक और व्यापारिक ऋण ग्राहकों द्वारा वित्तीय प्रतिभूतियों को लेने, स्टॉक विनिमय के सगठनों, उनके वैधानिक संरचना, साख प्रदान करने की विधि आदि है । स्वाभाविक रूप से वित्तीय प्रबन्धक बड़े उधार ग्राहक को ऋण देने में सुविधा का अनुभव करते हैं और इस रूप में निर्धन ऋण ग्राहकों की उपेक्षा की जाती है । सामाजिक कारकों के साथ-साथ राजनैतिक कारक भी सस्थागत साख निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका

अदा करते हैं, परन्तु अधिकांश रूप में राजनैतिक प्रभावों का लाभ बड़े ऋण ग्राहकों को प्राप्त होता है । अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर बड़े ऋण ग्राहक राजनैतिक शक्ति को भी एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी आर्थिक शक्ति द्वारा राजनैतिक निर्णय कर्ताओं को भी भ्रष्ट करने में अधिक सफल हो जाते हैं । भ्रष्टाचार की प्रक्रिया पूर्णतया व्यापक और सर्वमान्य है । यद्यपि भ्रष्टाचार का साधारण अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किन्तु अधिकांश लोग इसको स्वीकार करते हैं । छोटे ऋण ग्राहक में भी यह भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति होती है, परन्तु उनके सगठन तुलनात्मक रूप से कमजोर और असंगठित होता है । और इसलिये यदि सिद्धांत रूप में भी छोटे ऋण ग्राहकों के पक्ष में नीति निर्धारण होते हैं, तो वे भी साख का वास्तविक क्रियान्वयन एवं योजनाएँ उनके पक्ष में नहीं होती । अतः इस बात की आवश्यकता है कि इन साख योजनाओं की आधारभूत दशाओं को स्पष्ट किया जाए तथा इन दशाओं को किस तरह से प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, इसका विश्लेषण होना चाहिए ।

मुद्रापूर्ति और साख पूर्ति की अवधारणा और सिद्धान्त के उपर्युक्त विश्लेषण हमारे वर्तमान मौद्रिक और साख विश्लेषण में नीति-निर्माण में बड़े महत्वपूर्ण हैं । मुद्रापूर्ति की अवधारणा, जिसमें करेन्सी तथा माग जमाएँ सम्मिलित हैं तथा उच्च अर्घ मुद्रापूर्ति, जिसमें करेन्सी तथा आरक्षित सम्मिलित हैं, यह स्पष्ट करती है कि किस तरह मौद्रिक नीति विशिष्ट मौद्रिक आरक्षितों का समायोजन करेगी । मुद्रा पूर्ति का विशुद्ध बैंकिंग सिद्धान्त मुद्रा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के विभिन्न स्रोतों को दिया गया है और अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट अवयव के नियंत्रण द्वारा मौद्रिक स्थायित्वता प्राप्त करने में सहयोगी है । भारत जैसी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग दशा तथा मुद्रा माग के विभिन्न अवयव मौद्रिक नियंत्रण हेतु बड़े महत्वपूर्ण हैं । इसी तरह मुद्रा पूर्ति स्टॉक में

भी मुद्रा पूर्ति के क्षेत्रवार नियंत्रण हेतु उपयोगी है । मुद्रा पूर्ति के इस अवधारणा और सिद्धान्त के साथ यह सम्भव है कि किसी एक विशेष मुद्रा पूर्ति स्टॉक अवयव को नियंत्रित किया जाय और अन्य अवयवों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित सकिया जाय ।¹¹ चूँकि यहां उच्च

11. R.B.I., Report of the Second Working Group 1977,
p.9.

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत

(MONETARY AND CREDIT POLICY OF RBI, DURING THE PLAN PERIOD)

मुद्रापूर्ति के विभिन्न सैद्धान्तिक विश्लेषणों के दिये गये विवरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रापूर्ति सम्बन्धी विश्लेषण के बाद यह महत्वपूर्ण होगा कि हम योजनावधि के अन्तर्गत विशेषकर 1961 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति तथा उसमें समय-समय पर हुए परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करें। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति का विश्लेषण विशेषकर 1961 के बाद से करने का प्रधान कारण यह रहा है कि 1961 के बाद देश के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा एवं साख का अत्यधिक विस्तार हुआ और कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु मौद्रिक तथा साख नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व के अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने हेतु मौद्रिक नीति में परिवर्तन का आधार लिया है, जिसमें ऊँचे स्तर के विनियोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने की प्राथमिकता दी गयी है। आर्थिक विकास के रूप में केन्द्रीय बैंक नीति के उद्देश्य के कारण मौद्रिक नीति के विकास में महत्वपूर्ण कदम लिये गये और इस तरह तीव्र आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक, जो देश का प्रधान मौद्रिक अधिकारी है, वह द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त तक नियन्त्रित रूप में कार्य किया और युद्ध के समाप्ति में इसके मौद्रिक नीति का प्रधान उद्देश्य युद्ध से हुये वित्तीय घाटे की व्यवस्था करने से था। इस तरह मौद्रिक नीति की तकनीक, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसरण किया उसकी इस रूप में पुष्टि प्रो० के०एन० राज ने भी की है।¹

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ आर्थिक विकास में नई दिशा तथा गति प्राप्त हुई और नियोजित अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास तथा क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप के साथ मौद्रिक

1. K.N. Raj, The Monetary Policy of the Reserve Bank of India, 1948, p. 160.

नीति के कार्यशीलता एवं क्षेत्र में विस्तार हुआ। इस तरह युद्ध सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था के स्थान पर मौद्रिक नीति का उद्देश्य अब बदल कर विकासात्मक योजनाओं के वित्तीयन से हो गया। यह अनिवार्य समझा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु सीधे अधिकार दिये जायें। फलतः बैंक नियंत्रण एक्ट 1949 पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत बैंकिंग व्यवस्था के नियंत्रण एवं निरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत अधिकार दिये गये और विकासात्मक योजनाओं में उद्देश्य के अनुसार, सामाजिक रूप से वांछित क्षेत्रों में तथा प्राथमिक क्षेत्रों में साख के प्रवाह को सुनिश्चित कर सके। इस तरह युद्धोपरात स्वतंत्र भारत में भारतीय रिजर्व बैंक देश के मौद्रिक एवं साख संरचना का संरक्षक एवं नियंत्रक के रूप में उभर कर सामने आया। मोटे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति अधिक प्रभावी ढंग से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उभर कर सामने आया।

4.1 प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मौद्रिक एवं साख नीति

(1950-51 — 1955-56 तथा 1956-57 — 1960-61)

भारत सरकार ने अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक सुदृढ़ मौद्रिक नीति के महत्व पर बल दिया है।² एक केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का योगदान विकासात्मक क्रियाओं में वित्तीय प्रवाह को सुनिश्चित करना हो गया। मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य को योजनापर्यन्त कायम रखा गया और ऐसे कदम उठाये गये, जिससे बचत प्रोत्साहित हो, विनियोग उत्प्रेरित हो सके तथा ऐसा वातावरण उत्पन्न हो सके कि योजना के अन्तर्गत उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस तरह मौद्रिक नीति का अब प्रधान उद्देश्य आर्थिक विकास को त्वरित करने के साथ-साथ उपयुक्त मूल्य स्थायित्वता को प्राप्त करना हो गया। इस तरह प्रथम पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक तथा साख नीति का मोटे तौर पर दो प्रमुख उद्देश्य थे- प्रथम आर्थिक विकास तथा उत्पादन हेतु बढ़ती हुई साख आवश्यकता को उपलब्ध कराना तथा दूसरे, समग्र मांग तथा पूर्ति के बीच सतुलन स्थापित करना। इस तरह उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई साख आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना ही इन नीतियों

का प्रधान उद्देश्य रहा है। इसी के साथ यह भी माना गया कि विकास के प्रारम्भिक चरणों में उत्पादन की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय में अधिक तीव्र वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोग तथा व्यय में वृद्धि के साथ स्फीतिकारी दशाएँ उत्पन्न हो सकती हैं और इससे अर्थव्यवस्था की वांछित समृद्धि प्रभावित हो सकती है। इस उद्देश्य हेतु मौद्रिक नीति को एक शक्तिशाली उपकरण समझा गया, जिससे साख नियंत्रण द्वारा स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस योजना में इस बात की सन्तुष्टि की गयी कि प्रभावकारी साख नियंत्रण विनियोग तथा व्यापारिक क्रियाओं के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण के रूप में बना रहना चाहिए।³

प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रादुर्भाव के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के कुछ नये उपागम प्रारम्भ किये और बैंक दर को नवम्बर 1951 में 3 से 3 5 प्रतिशत बढ़ा दिया। यह बैंकिंग व्यवस्था के लिए इस बात का संकेत था कि दृढ़ साख नीति का प्रादुर्भाव तथा सस्ती मुद्रा नीति का समापन होना है।⁴

प्रथम पंचवर्षीय योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था को विदेशी विनिमय आरक्षितों अथवा बाह्य ससाधनों से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट चेतावनी दी गयी कि घाटे की वित्त व्यवस्था को उसी दशा तथा मात्रा में किया जाय, जब उपभोग सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति शीघ्र सुनिश्चित की जा सके और घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा मुद्रा की पूर्ति में विस्तार न किया जाय, अपितु यह साख व्यवस्था से किया जाय।⁵

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी दबावों से पीड़ित थी, अतः भारतीय रिजर्व बैंक की साख-नीति को कुछ सीमा तक मद्धी और नियंत्रित रखी गयी। बैंक दर में

3. Planning Commission, Problem of Economic development First Five Year Plan, p. 37.
4. C.R. Basu, Central Banking in A Planned Economy, 1978, p. 27.
5. First Five Year Plan, Planning Commission, p. 61.

वृद्धि के साथ-साथ खुले बाजार की क्रियाओं में भी परिवर्तन किये गये। इनके परिणाम स्वरूप पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों में मुद्रा पूर्ति में महत्वपूर्ण कमी रु० 214 करोड़ की हुई। इसी के साथ सरकार को बैंक का साख भी शुद्ध रूप से घटा और साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्र में भी बैंक साख नियंत्रित रहा। इस योजना के बाद के वर्षों में पुनः मुद्रापूर्ति तथा स्फीतिकारी दबावों में तीव्र वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार को दिये जाने वाले साख के कारण हुई। इस योजना में थोक मूल्य, जो 1954-55 में घट कर 11.8 हो गये थे, वे बढ़कर पुनः 1955-56 में 11.6 हो गये। इस तरह समग्र रूप में इस योजनावधि में मुद्रा पूर्ति में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा थोक मूल्यों की स्थिति 13 प्रतिशत रही और यह स्थिति देश के राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर 19 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में और 22 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में होने के कारण हुई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास की समस्याओं के समाधान हेतु मौद्रिक एवं साख नीतियों पर विशेष बल दिया गया। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं साख नीति मोटे तौर पर दो उद्देश्यों से सम्बन्धित रहे अर्थात् अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्रदान करना तथा विकास के साथ स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करना। इन उद्देश्यों के परिणामस्वरूप 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में संशोधन किया गया और योजनाकाल में आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय ढाँचे को अपनाया गया। मोटे तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रिजर्व बैंक के मौद्रिक और साख नीति को 'नियंत्रित विस्तार' कहा जा सकता है, जिसका अभिप्राय विस्तार के साथ स्थायित्वता है। यद्यपि रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के विविधीकरण तथा तीव्र विकास हेतु साख एवं मुद्रा पूर्ति में विस्तार की आवश्यकता समझी गयी, परन्तु इस बात पर विशेष बल दिया गया कि अत्यधिक मुद्रा पूर्ति में वृद्धि स्फीतिकारी होगी और अतः अर्थ व्यवस्था के वित्तीय स्थायित्वता के लिए हानिकारक होगी। ऐसे संदर्भ में रिजर्व बैंक की साख नीति साख एवं मुद्रा पर सामान्य नियंत्रण रखते हुए आवश्यक उत्पादक क्षेत्रों के क्रियाओं एवं विकास कार्यक्रमों को बिना नुकसान पहुँचाये हुए होना चाहिए।⁶

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समायावधि में साख को नियंत्रित रखने हेतु 1957 में बैंक दर

6. Report of the Central Board of Directors, RBI, 1956-57, p.14.

का 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। इसी के साथ-साथ खुले बाजार की क्रियाओं का अधिकांशतः प्रयोग सरकार को उसके कर्ज लेने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिये किया गया। परिणामतः 1957-1960 के समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का एक मात्र विक्रेता बन गया और बाजार के तरल ससाधनों को प्राप्त करने एवं साख विस्तार को प्रतिबन्धित करने में सहायक रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जिसका प्रयोग साख नियंत्रण हेतु किया गया वह था, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं एवं प्रतिभूतियों पर अग्रिमों के लिये चयनात्मक विधि। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से इन वस्तुओं के मूल्यों में अव्यवस्थित परिवर्तन को रोकना तथा स्टॉक संचयन को रोकना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख विधि द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे, धान, गेहूँ, मूँगफली, तिलहन, जूट, चीनी तथा अन्य खाद्यान्नों पर दिये जाने वाले अग्रिमों को इस विधि द्वारा नियंत्रित किया।

इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने साख विस्तार के नियंत्रण हेतु व्यापारिक बैंकों द्वारा गैर आपेक्षित साख विस्तार को रोकने हेतु नैतिक दबाव का भी महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया। इसी के साथ-साथ 1960 में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले मजदूरी में भी परिवर्तन किया गया। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि न्यूनतम ऋण दर सभी तरह के अग्रिमों पर 5 प्रतिशत होगी।

उपर्युक्त मुद्रा एवं साख नियंत्रण सम्बन्धी नीति के परिणामस्वरूप उनका तत्कालिक प्रभाव यह पड़ा कि बैंक साख 1957-58 तथा 1958-59 में महत्वपूर्ण रूप से घट गये, परन्तु उसके बाद पुनः बैंक साख में विस्तार हुआ, जबकि इसके नियंत्रण के अनेक उपाय किये गये।

मोटे तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुद्रा पूर्ति का अत्यधिक विस्तार हुआ अर्थात् 32 प्रतिशत, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह केवल 10 प्रतिशत रही। यहीं पर वास्तविक उत्पादन मात्रा की वृद्धि मात्र 18 प्रतिशत रही। थोक मूल्य सूचकांक लगभग सदैव बढ़ता रहा और वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत रही।

इस योजना में मुद्रापूर्ति के अत्यधिक विस्तार का सबसे प्रमुख कारक सरकारी क्षेत्र में बैंक साख में महत्वपूर्ण वृद्धि रही, जो कि बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था से उत्पन्न हुयी। इस तरह इस योजना में मौद्रिक नीति अपने उद्देश्य अर्थात् स्थायित्वता को प्राप्त करने में सफल न हो

सकी। साथ ही साथ वित्तीय एवं अन्य नीतियों में मौद्रिक नीति का समन्वय न स्थापित किया जा सका। इसी तरह साख नीति जो नियंत्रित विस्तार के आधार पर अपनायी गयी, वह भी स्फीतिकारी ही रही। बैंक-दर में मात्र आधा प्रतिशत वृद्धि किया गया और इस तरह उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सका। प्रो० बी०के० मदान ने इस सन्दर्भ में यह अभिव्यक्त किया है कि मौद्रिक नीति के प्रधान उपकरण के रूप में बैंक दर भारत में न तो बार-बार और न ही महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है।⁷ इसी तरह यद्यपि रिजर्व बैंक के एक्ट सशोधनों के परिणामस्वरूप आरक्षित कोष तथा ऋण देने एवं लेने के दरों के नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार दिये गये थे किन्तु योजनावधि में अन्तिम वर्षों तक में इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सका था। इसी तरह इस योजना में चयनात्मक साख नियंत्रक विधि भी विशेष महत्व की नहीं रही। देश में अव्यवस्थित तथा वैकल्पिक वित्त के स्रोतों के कारण तथा सामान्य साख विस्तार की स्थिति में मौद्रिक एवं साख नीतियाँ प्रभावकारी सिद्ध न हो सकी।

4.2 तृतीय पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक और साख नीति [1961-62 से 1965-66]

देश के तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में केन्द्रीय बैंक के मौद्रिक एवं साख नीतियों के कई तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। लगभग पूरी योजनावधि में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को सामान्यतः चुस्त बनाया गया। यह इस बात से स्पष्ट है कि साख जमा अनुपात में वृद्धि हुई, किन्तु इस योजना के अन्तर्गत अपनायी गई मौद्रिक नीति नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास-आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक से अत्यधिक मात्रा में ऋण लेने की प्रक्रिया मौद्रिक नीति के उद्देश्यों एवं साधनों में विभेद उत्पन्न करने लगी। मौद्रिक नीति के अन्तर्गत 1965-66 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साख उपलब्धता को सुनिश्चित किया था-रक्षा, निर्यात तथा खाद्य पदार्थ। देश की औद्योगिक व्यवस्था में उद्योगों के विकास हेतु बैंक साख की मांग में वृद्धि हुई, जिससे व्यापारिक बैंकों ने बढ़ती हुई मांग दशाओं के कारण साख पूर्ति करने की कठिनाइयों को अनुभव किया। इस योजना में भी यह अनुभव किया गया कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप लोगों की मौद्रिक आयों में तीव्र वृद्धि होगी, अपेक्षाकृत वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से। इसके कारण पुनः मुद्रा स्फीति के दबावों सम्बन्धी भय को सोचा गया अतः मौद्रिक एवं साख नीति के साथ वित्तीय नीति के संचालन

को इस रूप में रखने का प्रयास किया गया कि स्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ न बन सकें। साथ ही साथ इस योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि घाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप रखें।

इसमें यह भी प्रस्तावित किया गया है कि सरकार के बजट सम्बन्धी क्रियाएँ तथा साख के सृजन दोनों को साथ-साथ दृष्टिगत करते हुए उनमें उपर्युक्त सीमा को निर्धारित करना चाहिए। जहाँ तक व्यापारिक बैंकों द्वारा साख प्रदान करने की बात है इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि व्यक्तिगत क्षेत्र का उत्पादन देश के मूलभूत विकास उद्देश्यों से दूर न जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति के सम्बन्ध में 1960-61 के अन्त तक जो महत्वपूर्ण उपाय अपनाये गये थे, उनमें 1961-62 की मौद्रिक और साख नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये गये थे, केवल इस बात को छोड़कर कि चयनात्मक साख नियंत्रण कुछ सीमा तक सरल कर दिये गये थे और साथ ही साथ प्रत्येक बैंक के लिए आधारभूत कोटा हेतु बैंक दर पर ऋण लेने को जनवरी, 1962 में बढ़ा दिया गया था, इसका उद्देश्य लघु उद्योगों तथा सहकारिता के वित्तीयन में सहयोग करना था, परन्तु 1962-63 के बाद लगातार मूल्य वृद्धि के दबाव के कारण साख नीति कुछ प्राथमिक क्षेत्रों में बढ़े हुए साख की मात्रा को छोड़कर मोटे तौर पर अधिक दृढ़ थी।

बैंक साख में यह दृढ़ता इस कारण से और भी महत्वपूर्ण थी कि व्यक्तिगत तथा व्यापारिक क्षेत्र में बैंक साख में तीव्र विस्तार हो रहा था। इस तरह तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में मौद्रिक और साख नीति में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नीचे स्पष्ट किया जा सकता है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनवरी, 1963 में बैंक दर को 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया तथा पुन सितम्बर, 1964 में इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत और फरवरी, 1965 में 6 प्रतिशत कर दिया गया। इन परिवर्तनों का उद्देश्य बढ़ते हुए बैंक साख प्रवृत्ति पर रोक लगाना था। इसी तरह के साख नीति के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को की जाने वाली पुनर्वित्तीयन की सुविधा धीरे धीरे कड़ी कर दी गयी। इस समयावधि में विदेशी विनिमय-दर को बिगड़ती हुयी स्थिति के सन्दर्भ में आयातों पर अग्रिम जमा योजना प्रारम्भ की गयी। यह योजना 1965 में समाप्त कर दी गयी। बैंक-दर तथा पुनर्वित्तीयन की लागत के बढ़ने के कारण बैंकों के

जमा तथा उधार दरों में वृद्धि हुई, 1963 में अनेक बैंकों ने अपना न्यूनतम ऋण 65 प्रतिशत रखा अर्थात् बैंक - दर से 2 प्रतिशत अधिक। साथ ही साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं ने भी अपने ऋण दरों में वृद्धि की। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों द्वारा उधार लेने के लिए एक सीमा निर्धारित की गयी। व्यक्तिगत वस्तुओं विशेष कर कृषि वस्तुओं पर दी जाने वाली अग्रिम सम्बन्धी चयनात्मक साख नियंत्रण उत्पादन तथा मूल्य प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में परिवर्तनशील रूप में रहा, पर अक्टूबर 1963 के बाद इसमें कड़ाई कर दी गयी। यद्यपि साख नीति को महत्वपूर्ण रूप से कड़ा कर दिया गया था, फिर भी जैसा कि सारणी 4.1 में प्रदर्शित है बैंक साख 1963-64 के व्यस्त मौसम में बड़ी तेजी से बढ़े, जैसा कि यहाँ भी स्पष्ट है कि मन्दी के मौसम में जो उतार हुआ, व्यस्त मौसम के विस्तार की तुलना में बहुत कम था।

सारणी 4.1

अनुसूचित बैंकों की साख तथा जमाओं में मौसमी प्रवृत्ति

(रुपये करोड़ में)

		अनुसूचित बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक	समग्र उत्तरदायित्व
		साख	बैंक से उधार	जमाएँ
1961 - 62	मन्दी	- 76	- 32	+ 44
	व्यस्त	+ 204	+ 6	+ 157
1962 - 63	मन्दी	- 42	- 3	+ 84
	व्यस्त	+ 203	+ 22	+ 36
1963 - 64	मन्दी	- 121	- 29	+ 143
	व्यस्त	+ 376	+ 44	+ 84
1964 - 65	मन्दी	- 139	- 43	+ 211
	व्यस्त	+ 407	+ 124	+ 106
1965 - 66	मन्दी	- 93	- 123	+ 178
	व्यस्त	+ 309	+ 28	+ 214

स्रोत - Report on Currency and Finance, 1965 - 66.

इन वर्षों में, साख विस्तार मोटे तौर पर जमाओं में तीव्र वृद्धि थी। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि 1964-65 के व्यस्त मौसम में बैंक साख विस्तार का वित्तीयन भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये उधार से था।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में मोटे तौर पर मौद्रिक नीति अत्यधिक स्फीतिकारी रही। योजनावधि में कुल मिलाकर मुद्रापूर्ति वृद्धि लगभग 58 प्रतिशत रही, जबकि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में यह क्रमशः 10 प्रतिशत और 33 प्रतिशत रही। इसी के साथ मौद्रिक विस्तार तथा अर्थव्यवस्था के वृद्धि में अन्तराल 13.7 प्रतिशत वास्तविक राष्ट्रीय आय के रूप में रही। ऐसी स्थिति में जब विकास दर बहुत कम हो और कुल उत्पादन में उतार चढ़ाव 2.7 प्रतिशत वार्षिक औसत दर हो, वहाँ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में अभाव और तंगी का होना स्वाभाविक है और इसके परिणामस्वरूप इस समयावधि में मूल्यों में और वृद्धि हुयी। इस योजना के अन्तिम तीन वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक बढ़ कर 29 प्रतिशत हो गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार को साख, जो मोटे तौर पर घाटे की वित्तव्यवस्था को दिखाता है तथा सकल बैंक साख में विस्तार में दो महत्वपूर्ण कारक थे, जिन से मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुद्रापूर्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा उसके प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण सारणी 4.2 प्रदर्शित है।

सारणी में यह स्पष्ट है कि विदेशी विनिमय आदेयों में शुद्ध कमी का एक सामान्य प्रभाव विस्तार को कम करने से था। गैर मौद्रिक दायित्वों में तीव्र विकास विशेषकर समय-जमाओं में अन्तिम दो वर्षों में हुई वृद्धि से मौद्रिक विस्तार प्रभावित हुआ। यद्यपि इस योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था को अत्यधिक न करने का प्रारूप किया गया था, परन्तु वस्तुतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ऊँची रही (रु० 1133 करोड़)। इसी के साथ-साथ विकास व्ययों को बनाये रखने के लिए, ताकि समृद्धि दर त्वरित किया जा सके, बड़े पैमाने पर गैर विकासात्मक व्यय हुये और जिनके पीछे अनेक कारण रहे, जैसे, अत्यधिक रक्षा-व्यय, अतिरिक्त महंगाई भत्ते का देना, मजदूरी में वृद्धि तथा

सारणी 4 2

मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक

(रूपये करोड़ में)

	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	योग तीसरी योजना में
मुद्रा पूर्ति	177	264	442	328	449	1560
	(6.1)	(8.6)	(23.3)	(8.7)	(10.6)	(57.8)
1 सरकारी क्षेत्र को शुद्ध बैंक साख जिसमे से शुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक साख	157	269	281	268	448	1563
	159	207	195	128	371	1060
2 निजी क्षेत्र को शुद्ध बैंक साख	-18	105	178	53	80	398
(ए) व्यक्तिगत क्षेत्र को सकल बैंक साख	140	218	259	247	286	1150
(बी) बैंको की अमौद्रिक दायित्व	103	46	42	133	186	510
3. शुद्ध विदेशी विनिमय आदेय	-57	-43	35	-19	-24	-108

कोष्ठक में अंक मुद्रा पूर्ति में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है ।

स्रोत - Report on Currency and Finance, 1965-66.

देवी - आपदाओं यथा, सूखा (1965 - 66) आदि में दिये गये सहायता व्ययों के कारण हुआ ।

इस पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक तथा साख नीति के सन्दर्भ में यह बात कही जा सकती है कि बड़े पैमाने पर घाटे की वित्त व्यवस्था ने मौद्रिक अधिकारियों के मौद्रिक विस्तार नियंत्रण को समिति कर दिया था, फिर भी साख नीति स्थायित्वता को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त रूप से सुधरी नहीं थी । साख नीति द्वारा साख नियंत्रण के दबाव के बावजूद भी तथा कड़े उपायों के अपनाने पर भी

सफल बैंक साख मे महत्वपूर्ण विस्तार विशेषकर, व्यक्तिगत क्षेत्र मे हुआ । कुछ सीमा तक यह स्थिति आर्थिक विकास के साथ स्थायित्वता प्राप्त करने मे ताल-मेल न हो सकने के कारण हुई । इस अवधि मे मुद्रा स्फीति के अनेक महत्वपूर्ण कारणों मे वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति मे अभाव के कारण रहा। अतः साख नीति सामान्य साख विस्तार के साथ-साथ उत्पादन क्षेत्रों की वृद्धि मे विशेष उन्मुख रही और औद्योगिक उत्पादन की साख की आवश्यकता को पूरा करने मे महत्वपूर्ण रही । साथ ही साथ साख नीति का उद्देश्य प्राथमिक एवं चयनित क्षेत्रों तथा कृषि लघु उद्योग, सहकारी क्षेत्र तथा निर्यात आदि की साख आवश्यकता को पूरा करना भी रही । इस तरह से इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों मे साख प्रभाव के उपर्युक्त प्रभावीकरण विधि के अभाव से व्यक्तिगत क्षेत्र में साख को नियंत्रित करना संभव न हो सका ।

इस योजना के अन्तिम वर्षों मे यद्यपि महंगी मुद्रा नीति को अपनाया गया, परन्तु यह भी अधिक नहीं रही । इसका प्रधान कारण कीमतों मे तीव्र वृद्धि का होना था, जिसके द्वारा साख लागत मे वृद्धि को प्रभावहीन कर देती है । जमा वृद्धि मे तीव्र विकास विशेषकर जमाओं पर बढ़े हुए ब्याज दर के कारण बैंकों की तरलता में वृद्धि कर के साख प्रसार किया ।

4.3 वार्षिक योजनाओं में मौद्रिक एवं साख नीति (1966-67 — 1968-69)

भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं मे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद तीन वार्षिक योजनाओं के समयावधि में मौद्रिक एवं साख नीति का मोटे तौर पर प्रमुख उद्देश्य साख - नियंत्रणों को सरलीकृत करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त पुनर्विक्रयित सुविधा का उदारीकरण करना था । इस समयावधि मे इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि निर्धारित प्राथमिक क्षेत्रों, कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात के क्षेत्र मे चयनात्मक आधार पर प्रोत्साहन तथा बढ़ी हुई एवं सस्ती साख सुविधा दी जाय । इस समयावधि में 1966 के अवमूल्यन के सदर्थ मे तथा 1966-67 में अच्छी कृषि उत्पाद की प्रत्याशा मे 1966 के व्यस्त काल मे साख नीति को शिथिल (लचीला) कर दिया गया था । बाद मे 1967-68 और 1968 - 69 मे कृषि उत्पाद स्तर मे अधिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में तथा औद्योगिक क्षेत्र में मंदी

की प्रवृत्ति के सदर्थ में औद्योगिक उत्पादन को तीव्र करने के दृष्टिकोण से साख नीति को पुनः और अधिक आसान कर दिया गया ।

वार्षिक योजना सम्बंधी उपर्युक्त मुद्रा और साख नीति के सदर्थ में कई महत्वपूर्ण कदम लिये गये । 1968 के अन्तिम मन्दी काल में बैंकों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत उधार लेने की छूट दी गयी तथा बड़े बैंकों को यह सुझाव दिया गया कि वे अपने साख में वृद्धि का 80 प्रतिशत उद्योग तथा निर्यात - आयात के बिलों के वित्तीयन में लगावे । मन्दी की दशा विद्यमान होने के कारण निर्यात वृद्धि हेतु कई उपाय किये गये और जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती दर (4.5 प्रतिशत) पर पुनर्वित्तीयन भी सम्मिलित है । यह सुविधा मुख्य रूप से इंजिनियरिंग तथा सम्बंधित उत्पादों पर विशेष रूप से दिया गया था । इसी के साथ - साथ नवम्बर, 1967 में राज्य सरकारों तथा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यानों की प्राप्ति, वितरण, भण्डारण, रसायनिक उर्वरक, तथा कीट - नाशक के वितरण हेतु पुनर्वित्तीयन में बैंक-दर पर सुविधा दी गयी । साथ ही साथ कुछ विशिष्ट बैंकों को औचित्य पूर्ण आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण व्यवस्था की गयी । जनवरी, 1968 के बाद से रियायती दर (4.5 प्रतिशत) को व्यापारिक बैंकों के पुनर्वित्तीयन में उनके कुल अग्रिमों में वृद्धि, जो प्राथमिक क्षेत्रों से सम्बन्धित थी, के संदर्भ में कर दिया गया । प्राथमिक क्षेत्रों को और अधिक सहयोग हेतु कृषि की परिभाषा को और अधिक विस्तृत करके उसके मध्य कालीन साख को विनियोग और उत्पादन उद्देश्यों हेतु किया गया । इस सम्यावधि में पिछले वर्षों की तुलना में बैंक दर को मार्च, 1968 में 6 प्रतिशत से घटा करके 5 प्रतिशत कर दिया गया था । व्यापारिक बैंकों के अग्रिमों पर निर्धारित अधिकतम दर को भी घटा कर के 10 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया था कि इस आधे प्रतिशत की कमी को 80 प्रतिशत बैंक अग्रिमों में प्रदान किया जायेगा । इसी के साथ - साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा भी इसके उदारीकरण के अलावा साख लागत को कम कर दिया गया था । 1968-69 की समयावधि में खाद्यानों, तिलहनों तथा कपास के संदर्भ में चयनात्मक साख नियंत्रण को सामान्यतया उदार कर दिया गया था और इसका प्रमुख कारण इसकी दशाओं में सुधार का होना था । वार्षिक

सारणी 4.3

अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के साख में मौसमी उतार - चढ़ाव

(रूपये करोड़ में)

	1966-67		1967-68		1968-69	
	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त
1. बैंक साख	-66	+426	-101	+509	-43	+ 427
2 भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	-30	+ 41	-36	+105	-82	+ 70
3 समग्र जमाए	+265	+169	+194	+219	+239	+325

स्रोत Report on Currency and Finance, Various Issues.

बैंक साख में यह वृद्धि अशत 1967-68 तथा 1968-69 में अच्छी फसल के कारण हुई तथा बाद के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण भी हुई। इसके साथ ही प्राथमिक क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण साख वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए 1968 में कृषि क्षेत्र में साख ₹ 45 करोड़ से बढ़कर 1969 में ₹ 188 करोड़ हो गया तथा इन्ही वर्षों में लघु उद्योगों के लिए यह साख ₹ 194 करोड़ से बढ़कर ₹ 294 करोड़ तथा निर्यात के क्षेत्र में यह साख ₹ 174 करोड़ से बढ़कर ₹ 255 करोड़ हो गया। मोटे तौर पर तीन वार्षिक योजनाओं की समयावधि ऐसे मौद्रिक एवं साख उपायों से सम्बन्धित है, जो सरलीकृत एवं उदारीकृत प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है तथा तुलनात्मक रूप में मौद्रिक विस्तार के नीचे दर से सम्बन्धित है। मुद्रा पूर्ति तथा इसके महत्वपूर्ण अवयवों के वृद्धि - प्रवृत्ति को सारणी 4.4 में प्रदर्शित की जा सकती है -

सारणी 4.4

मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति एवं महत्वपूर्ण घटक

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष भर में बढ़ोत्तरी		
	1966-67	1967-68	1968-69
मुद्रा पूर्ति	421 (+9 3)	400 (+8 1)	429 (+8 0)
1 सरकारी क्षेत्र को शुद्ध बैंक साख, जिसमें से सरकारी क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का साख	199 120	296 168	444 347
2 (अ) व्यापारिक बैंक को सकल बैंक साख	487	421	502
(ब) व्यापारिक क्षेत्र को शुद्ध बैंक साख	198	181	89
(स) बैंकों के गैर मौद्रिक दायित्व	262	244	917
3 बैंक क्षेत्र के शुद्ध विदेशी विनिमय आदेय	78	13	164

मुद्रापूर्ति में कम वृद्धि का प्रधान कारण विकास परिचर्यों के घटने तथा कम मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था का होना था, जैसा कि सरकारी क्षेत्र में रिजर्व बैंक के शुद्ध साख की स्थिति से स्पष्ट है । यद्यपि व्यक्तिगत क्षेत्र में बैंक साख में वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से ऊँची थी, पर यह काफी हद तक बैंकों के गैर मौद्रिक दायित्वों में वृद्धि से समायोजित हो गयी । सुधरी हुई भुगतान संतुलन की स्थिति के कारण विदेशी विनिमय आदेयों द्वारा भी मुद्रा पूर्ति में थोड़ी वृद्धि हुई । थोक मूल्यों में वृद्धि 1966-69 समयावधि में 25.7 प्रतिशत रही और इसमें भी 1966-67 में यह वृद्धि सर्वाधिक 16 प्रतिशत रही ।

4.4. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एवं साख नीति (1969-70 --- 1974-75)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य से स्फीतिकारी दबावों के प्रारम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास को स्थायित्वता को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया । इस पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक तथा साख नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से समग्र माग एवं पूर्ति में संतुलन कायम करना, नयी उभरती हुई स्थिति के संदर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा को निर्धारित करना तथा बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण (जुलाई, 1969) के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन के वित्तीयन के लिए अधिक ससाधन उपलब्ध कराना, प्राथमिक क्षेत्रों और विशेषकर उपेक्षित क्षेत्रों, कृषि, छोटे उद्योग आदि में साख प्रवाह निर्धारित करना तथा विकास के साथ-साथ निर्यातों एवं उद्योगों की आवश्यकता के लिए साख की पूर्ति करना था ।

इस समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य व्यापारिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र एवं उपेक्षित क्षेत्रों में सगत हेतु साख को नियमित रखना था । इस दिशा में अनेक मौद्रिक एवं साख उपकरणों को अपनाया गया, यथा बैंक दर में वृद्धि वैधानिक तरलता एवं शुद्ध तरलता अनुपात में परिवर्तन और नकद आरक्षित अनुपातों में परिवर्तन, व्यापारिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी पुनर्वित्तीयन सुविधाओं को सीमित करना, अग्रिमों तथा जमाओं में ब्याज दर में परिवर्तन करना तथा चयनात्मक साख नियंत्रण उपायों में सुधार करना था । इस समयावधि में प्रमुख

साख एव वित्तीय उपायों का विवरण इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी, 1971 में 6 प्रतिशत तथा पुन मई, 1973 में 7 प्रतिशत कर दिया गया। 1970 में सैवधानिक तरलता अनुपात को दो बार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 27 तथा 28 प्रतिशत कर दिया गया और पुन अगस्त, 1972 में इसे 30 प्रतिशत तथा 1973 में 32 प्रतिशत कर दिया गया। इसी के साथ-साथ आवश्यक शुद्ध तरलता अनुपात को भी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 1970 में 32 प्रतिशत, 1971 में 34 प्रतिशत तथा 1972 में 36 प्रतिशत कर दिया गया। इसे पुन मार्च, 1973 में 37 प्रतिशत तथा जून, 1973 में 39 प्रतिशत तथा सितम्बर, 1973 में 40 प्रतिशत कर दिया गया। 1973-74 के दो मन्दी काल में नकद आरक्षित अनुपात को भी क्रमशः बढ़ाकर 3 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्तीयन की सुविधा को क्रमशः अधिक कठोर कर दिया गया, जिससे इसे नियंत्रित किया जा सके। बैंकों के अग्रिमों पर ब्याज दरों को क्रमशः बढ़ा दिया गया। न्यूनतम उधार देय ब्याजदर को जून, 1973 में 10 प्रतिशत कर दिया गया। पुन इसे बढ़ाकर दिसम्बर, 1973 में 11 प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि इस समयावधि में मुद्रा एव साख नियंत्रण को अनेक विधियां व्यापारिक क्षेत्र में साख प्रसार को रोकने में असमर्थ रहें। अतः 1973-74 के व्यस्त काल में परिमाणात्मक साख विधियों को अपनाया गया। यह अनुमान किया गया कि 1973-74 के बीच कुल बैंक साख ₹0 400-450 करोड़ से अधिक नहीं होगा। अतः निर्यात साख को परिमाणात्मक विधियों से मुक्त रखा गया। कुछ महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं यथा, खाद्यान्न तिलहन, कपास, चीनी, वनस्पति तथा जूट एव सूती वस्त्रों पर दिये जाने वाले अग्रिमों में चयनात्मक साख नियंत्रण विधियों में समय-समय पर परिवर्तन किया गया। 1972-73 के व्यस्त काल में खाद्यान्नों, तिलहनों के संदर्भ में अग्रिमों हेतु साख नियंत्रण को कठोर कर दिया गया। पुन 1973-74 के व्यस्त काल में न्यूनतम उधार ऋण को कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के संदर्भ में एक प्रतिशत बढ़ा दिया गया।

न्यूनतम शुद्ध तरलता अनुपात में हुए परिवर्तनों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों पर ब्याज दरों को सारणी 4.5 में व्यक्त किया जा सकता है।

सारणी 4.5

शुद्ध तरलता अनुपात में परिवर्तन तथा उस पर ब्याज की दर

शुद्ध तरलता अनुपात	भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये उधार पर ब्याज की दर (प्रति वर्ष प्रतिशत)
39 और इससे अधिक	9
38 और इससे अधिक लेकिन 39 से कम	10
37 और इससे अधिक लेकिन 38 से कम	11
36 और इससे अधिक लेकिन 37 से कम	12
35 और इससे अधिक लेकिन 36 से कम	13
34 और इससे अधिक लेकिन 35 से कम	14
33 और इससे अधिक लेकिन 34 से कम	15
32 और इससे अधिक लेकिन 33 से कम	16
31 और इससे अधिक लेकिन 32 से कम	17
31 से कम	18

स्रोत :- C.R. Basu, Central Banking in a Planned Economy, 1978.

इस समयावधि में मौद्रिक एवं साख नीति सम्बंधी उपर्युक्त उपायों को लेने का अभिप्राय यह था कि चयनात्मक आधार पर साख प्रवाह को विनियोग, उत्पादन वृद्धि तथा बेहतर आवश्यक वस्तुओं के वितरण को बनाये रखा जाए। मौद्रिक विस्तार के नियंत्रण सम्बंधी लागू की गयी नीति का यह उद्देश्य था कि जमा वृद्धि दर पर इसका कुछ प्रभाव पड़े। तरलता आवश्यकताओं को ध्यान

मे रखते हुये बैंकों को अपने साख प्रवाह को इस रूप से नियोजित करना है कि वह पूर्वत चयनात्मक आधार पर हो और प्राथमिक क्षेत्रों के लिए हो और यथासम्भव अपने संसाधनों पर आधारित हो । इस बात पर प्रधान दृष्टि रखी जायेगी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दृढ़ किया जा सके । साथ ही साथ निर्यात क्षेत्र के विशेष मांगों को ऊँची प्राथमिकता जारी रहेगी । संक्षेप मे मुद्रा स्फीति के दबावों को अर्थव्यवस्था मे बने रहने से सामान्य रूप से मौद्रिक नीति को इसे नियंत्रित करने का प्रधान उद्देश्य बनाया गया । साख प्रसार को सीमित करके बैंको के निजी संसाधनों पर आधारित किया गया । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता को मोटे तौर पर नाममात्र के लिए तथा अस्थायी रखा गया । उपर्युक्त मौद्रिक एवं वित्तीय नीति सम्बन्धी उठाये गये कदमों के बावजूद भी व्यापारिक क्षेत्र मे साख की वृद्धि महत्वपूर्ण रही, विशेषकर 1972-73 तथा 1973-74 मे । 1972-73 तथा 1973-74 के व्यस्त काल मे बैंक साख मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई और बाद के वर्षों मे साख विस्तार अपने सर्वोच्च सीमा तक पहुच गया, यह साख विस्तार परिमाणात्मक साख विस्तार की नियंत्रणात्मक सीमा के बाद भी हुआ, जो भारत के मौद्रिक इतिहास में पहली बार हुआ । इस समयावधि मे व्यापारिक क्षेत्र मे व्यापारिक क्षेत्र में अनुसूचित व्यापारिक बैंको के साख मे मौसमी परिवर्तन को सारणी 4 6 मे प्रदर्शित किया जा सकता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समयावधि मे मुद्रापूर्ति बढ़कर 88 प्रतिशत हो गई, जो इसी समयावधि में वास्तविक उत्पादन वृद्धि 18.9 से बहुत अधिक ऊँची थी । मुद्रा पूर्ति मे तथा वास्तविक उत्पादन मे अन्तराल विशेष कर 1971-72 तथा 1972-73 में बहुत बढ़ गया । इससे न केवल समग्र मांग एवं पूर्ति असंतुलन बढ़ गया, अपितु मुद्रा - स्फीति दबावों के कारणों में यह महत्वपूर्ण कारण रहा । किन्तु विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि पूरे योजना के समयावधि मे थोक कीमतों के वार्षिक औसत वृद्धि दर मुद्रापूर्ति तथा वास्तविक आय के वास्तविक औसत आय के काफी सन्निकट था। इस स्थिति को सारणी 4 7 मे प्रदर्शित किया जा सकता है ।

	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त	मन्दी	व्यस्त
	1969	1969-70	1970	1970-71	1971	1971-72	1972	1972-73	1973	1973-74		
1. सकल बैंक साख बिल												
सहित (छूट के बाद)	31	563	226	394	163	352	57	916	361	1355		
(अ) खाद्य	-	-	34	70	156	-71	-1	6	-57	188		
(ब)अखाद्य पदार्थ	31	563	192	324	7	423	58	910	418	1167		
2. समग्र जमा	348	324	449	436	624	624	705	811	899	677		
3 साख जमा अनुपात												
मौसम के अत में												
(पुनर्छूट बिल को												
छोड़कर)	72 4	79 4	77 0	78 0	73 1	71 7	66 2	70 3	67 4	73 7		

स्रोत - Report on Currency and Finance Varuous Issues.

सारणी 4.7

मुद्रा पूर्ति, राष्ट्रीय आय तथा थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक उतार - चढ़ाव

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि		
	मुद्रापूर्ति	राष्ट्रीय आय (1960-61 के मूल्य आधार पर)	थोक मूल्य सूचकांक (1970-71 = 100)
1969-70	10.5	6.4	3.7
1970-71	11.8	6.0	5.5
1971-72	14.0	1.1	5.6
1972-73	15.7	1.3	10.0
1973-74	15.2	5.7	20.2
1969-74	13.4	3.5	8.9

(वार्षिक औसत)

स्रोत - Report on Currency and Finance Various Issues.

इसके बावजूद कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया था कि घाटे की कितनी उभरती हुई आर्थिक प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में निर्धारित किया जायेगा, पर वास्तविकता यह रही कि पाकिस्तान युद्ध तथा बंगला देश शरणार्थियों के परिणामस्वरूप रक्षा व्यय में वृद्धि के कारण यह काफी ऊँची हो गई। ऐसी परिस्थिति में साख नीति की प्रभावकारिता सामान्यतया सीमित हो गयी। मूलतः सरकार के वित्तीय क्रियान्वयन एवं व्यापारिक क्षेत्रों से सम्बन्धित साख नीति में उपयुक्त

समन्वय के अभाव में इस समयावधि में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों की मांग तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई। इस समयावधि में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की मात्रा जून, 1969 में ₹0 774 करोड़ से बढ़कर दिसम्बर, 1973 में ₹0 2466 करोड़ हो गयी अर्थात् पूरी समयावधि में कुल प्रदत्त साख 22.3 प्रतिशत से बढ़कर 36.7 प्रतिशत हो गयी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में मौद्रिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि बैंक साख में वृद्धि वास्तविक उत्पादन वृद्धि से काफी अधिक हो गयी। उदाहरण के लिए बृहद एवं मध्यम उद्योगों में साख वृद्धि 1972-73 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 1973-74 में 30 प्रतिशत हो गयी। जबकि औद्योगिक उत्पादन 1972-73 में 4 प्रतिशत तथा 1973-74 में मात्र 2 प्रतिशत ही रहा। इस समयावधि में एक महत्वपूर्ण कारक जो साख नियंत्रण उपकरणों की प्रभावकारिता को न केवल सीमित किया, अपितु बैंकिंग व्यवस्था का संचालन इस तरह किया कि उद्योग एवं व्यापार हेतु विस्तृत स्तर पर साख प्रदत्त किया जाय, वह उधार देय ससाधनों से सम्बन्धित था। इस योजना के प्रारम्भिक समय में बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बैंक क्षेत्रों में तीव्रगति से बैंक शाखाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप बैंक जमाओं की वृद्धि दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी। ऐसी परिस्थिति में मौद्रिक अधिकारियों द्वारा अपनाये गये उपाय महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सके। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश में गैर-लेखा जोखा कित्त के साथ स्फीतिकारी दशाएं विकसित हुयी और इनका पुनः प्रभाव मौद्रिक एवं साख नीतियों के प्रभावकारिता पर पड़ा।

4.5 पंचम पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एवं साख नीति (1974-75 --- 1979-80)

पाचवी पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में गैर स्फीतिकारी विकास को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इस योजना के पूर्व स्फीतिकारी प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो चुकी थी। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों में कोई भी घाटे की कित्त व्यवस्था नहीं की जायेगी और बाद के वर्षों में घाटे की कित्त व्यवस्था को उस न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा, जिससे

मुद्रा पूर्ति बढ़कर के स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न न कर सके । ⁸ इस योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों में उद्देश्य प्राप्त हेतु समन्वित सगति होनी चाहिए । इस योजना में इस बात पर पुन बल दिया गया कि सरकार के मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों में अधिक से अधिक निकटतम सगति उत्पन्न की जाये । ⁹ इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि विनियोग व्ययों के नियोजन के साथ उसी तरह से साख नियोजन भी होना चाहिए, जिससे इसका नियंत्रण अधिक सफलता पूर्वक उद्देश्य के अनुसार किया जा सके और जो बढ़ते हुए उत्पादन की आवश्यकता के अनुरूप हो ।

पाचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ इस विशेष बात से आरम्भ होता है कि 1974-75 में मुद्रा स्फीतिदर अत्यधिक ऊँची रही । जुलाई, 1974 में केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर स्फीतिकारी नीति उपायों को बड़े विस्तृत एवं कड़ाई के साथ प्रारम्भ किया गया । इस तरह इस . समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक एवं साख नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतियों को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है ।

इस योजना में मुद्रा प्रसार और स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने हेतु बैंक दर को महत्वपूर्ण ढग से 7 प्रतिशत से बढ़ाकर के 9 प्रतिशत कर दिया गया । इसी के साथ-साथ व्यापारिक बैंको के अग्रिमों सम्बन्धी न्यूनतम ऋण दरों को भी 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया और अधिकतम ऋण दरों को 9 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत कर दिया गया । उपभोग प्रवृत्ति को नियंत्रित करने तथा घरेलू बचतों की उगाही हेतु सावधि जमाओं तथा बैंक बचतों पर जमा दर में परिवर्तन 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के रूप में किया गया । इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक से बैंको द्वारा लिए जाने वाले उधार के अधिकतम दर को बढ़ा कर 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर

-
8. Planning Commission, Draft of Vth Five Year Plan, Part-I, 1974-79, p. 53.
 9. Planning Commission, Draft of Vth Five Year Plan, Part 1, 1974-79, p. 16.

दिया गया । इस योजना में विस्तृत निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित साख प्रयोग पर बल दिया गया । साथ-साथ बैंक साख में अत्यधिक वृद्धि को रोकने तथा उसके उपयुक्त प्रयोग हेतु व्यक्तिगत रूप से बैंको द्वारा साख बजट पर नियंत्रण किया गया । इस समयावधि में टण्डन समिति की रिपोर्ट और प्रस्तावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1974 में व्यापारिक बैंको के साख वितरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये ।

मौद्रिक एव साख सम्बन्धी उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1974-75 की समयावधि में मुद्रा पूर्ति तथा अन्य मौद्रिक कारकों में कमी होने के साथ - साथ थोक कीमतों का सूचकांक 1974-75 में गिरकर 7.1 प्रतिशत हो गया । 1975-76 की मौद्रिक एव साख नीति मोटे तौर पर 1974-75 में अपनायी गयी नीति को ही कुछ परिवर्तनों के साथ अपनायी गयी। इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक एव साख नीति सम्बन्धी पूरे वर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्घोषित उपायों में कहा गया कि सामान्य तथा चयनात्मक साख उपाय अधिक लचीले ढंग से प्रयोग किये जायेंगे । शुद्ध तरलता अनुपात की व्यवस्था, जो पिछले दस वर्षों से चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया । अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को सलाह दिया कि चयनित प्राथमिक क्षेत्रों में वित्तीयन हेतु वे मध्यकालीन वित्त प्रदान करने को प्राथमिकता दे ।

वर्ष 1976-77 की समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एव साख नीति सम्बन्धी परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकता है । इस समयावधि में वैधानिक नकद अवशेष अनुपात को 1976 में 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया और पुन उसी वर्ष 6 प्रतिशत कर दिया गया । जनवरी, 1977 में बैंकों के लिए यह पुन आवश्यक हो गया कि वे अपने बढ़े हुए मांग एवं समय जमाओं के 10 प्रतिशत भाग को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दें । बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह भी सुझाव दिया कि वे सीमित ससाधनों के आधार पर विवेकपूर्ण साख की मात्रा, दिशा तथा ब्याजदर को निश्चित करे, परन्तु इसके बावजूद भी वित्तीय वर्ष 1976-77 में व्यापारिक क्षेत्रों

मे समग्र बैंक साख बढ़कर के ₹0 2276 करोड़ हो गयी, जो 1975-76 मे ₹0 2108 करोड़ थी । इस तरह व्यापारिक क्षेत्रों मे बैंक साख मे उल्लेखनीय वृद्धि, मुद्रा पूर्ति मे वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रही और मुद्रा पूर्ति 1976-77 मे बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गयी । व्यापारिक क्षेत्रों को प्रदत्त समग्र बैंक साख के वितरण को सारणी 4.8 मे प्रदर्शित किया जा सकता है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि कुल साख वृद्धि का लगभग $1/3$ भाग वर्ष 1974 से 1977 के बीच खाद्यान्न प्राप्ति क्रियाकलापों से सम्बन्धित था । इस तरह प्राथमिक क्षेत्रों यथा कृषि, लघु उद्योग आदि मे समग्र साख का प्रसार 30 प्रतिशत से अधिक रहा ।

मुद्रापूर्ति विस्तार मे एक नया कारक जो वर्ष 1975-76 से विराजमान रहा, वह विदेशी विनियम आदेशों मे तीव्र वृद्धि का होना था, इसमे 1975-76 मे वृद्धि ₹0 711 करोड़ हुआ जो 1974-75 मे केवल ₹0 238 करोड़ था । मुद्रापूर्ति मे वृद्धि वस्तुतः इससे भी अधिक होती । किन्तु तुलनात्मक रूप से बैंकिंग क्षेत्र के गैर मौद्रिक दायित्वों मे तीव्र वृद्धि हुई । इस समयावधि मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो साख नीति अपनायी गई, वह प्रथम दो वर्षों मे नियंत्रणात्मक प्रवृत्ति के साथ सफल रही । इसी के साथ कुछ वृद्धि मूल्यों मे अत्यधिक वृद्धि होने के कारण हुई, जो सुस्ती की दशाओं के कारण अर्थव्यवस्था मे उत्पन्न हुई और जिसके लिए खाद्य पदार्थों में साख की पूर्ति की गयी । वर्ष 1975-76 मे गैर-खाद्य साख लगभग 14.4 प्रतिशत रहा । वस्तुतः उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र वृद्ध साख नीति से ग्रस्त थी ।

वर्ष 1976-77 मे साख नीति ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्णतया व्यवस्थित रूप मे नहीं थी, जैसा कि कुल उत्पाद मे वृद्धि तथा मूल्यों मे वृद्धि के दबाव के कारण आवश्यक थी । भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साख मे वृद्धि के अलावा जो खाद्य पदार्थों के उगाही तथा प्राथमिक क्षेत्रों से सम्बन्धित थी, साख मे वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग बढ़ते हुए औद्योगिक इकाइयों के वित्तीयन हेतु यथा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के वित्तीयन हेतु था ।¹⁰ इस समयावधि मे साख नीति

सारणी 4.8

सकल बैंक साख का क्षेत्रीय वितरण

(रुपये करोड़ में)

		वर्ष भर में उतार - चढ़ाव		
		अप्रैल अंत 1974	अप्रैल अंत 1975	अप्रैल अंत 1976
		से अप्रैल अंत 1975	से अप्रैल अंत 1976	से अप्रैल अंत 1977
1	खाद्यान्न साख	+140 (14 6)	+1047 (42 9)	+669 (29 4)
2	प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस क्षेत्र को निर्यात साख सहित)	+348 (36 4)	+688 (23 2)	+774 (34 0)
	(अ) लघु उद्योग	+116	+172	+215
	(ब) कृषि	+186	+282	+277
	(स) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र	+ 46	+234	+282
3	अन्य सभी क्षेत्र (इन क्षेत्रों को निर्यात साख सहित)	+469 (49 0)	+703 (28 8)	+833 (36.6)
4.	खाद्येत्तर साख	+817 (85 4)	+1391 (57 1)	+1607 (70.6)
	जिसमें से			
	निर्यात साख	- 85	+275 (11 3)	+219 (9.6)
5	सकल बैंक साख	+957	+2438	+2276

स्रोत :- (1) Reserve Bank of India, Annual Report, 1976-77.
(11) Report on Currency and Finance, 1976-77.

मे एक महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रीय साख बटवारे से सम्बन्धित था, जिससे अधिक आर्थिक और तार्किक रूप से बैंक संसाधनों का प्रयोग हो सके । इस समयावधि मे चयनात्मक साख नीति भी लागू रहे, जो सविदनशील वस्तुओं के सम्बन्ध मे साख - नियन्त्रण से सम्बन्धित थे ।

जहा तक वर्ष 1977-78 मे साख नीति का प्रश्न है, वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रत्याशित मुद्रा पूर्ति वृद्धि के सदर्थ मे तैयार की गयी थी तथा साथ ही साथ अत्यधिक मूल्य स्तर के वृद्धि के सदर्थ मे भी । इसमे इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मौद्रिक एव साख नीति को मौद्रिक विस्तार से जहा तक सम्भव हो रोका जाय । इसका उद्देश्य विनियोग को प्रोत्साहित करने, उत्पादन तथा निर्यात मे वृद्धि करने तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं एव औद्योगिक कच्चा माल की पूर्ति करने से था । बैंकिंग व्यवस्था और अत्यधिक तरलता को नियन्त्रित करने तथा बैंक साख विस्तार को रोकने के सम्बन्ध मे इस समयावधि मे अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।ये निम्नलिखित है -

पहला, बैंकों को यह सलाह दिया गया कि प्रत्येक बैंक साख नियोजन करें और साख वितरण पद्धति को राष्ट्रीय प्राथमिकता के उद्देश्य के समकक्ष ले आयें । उन्हें यह सलाह दिया गया कि प्राथमिक क्षेत्रों, समाज के गरीब तबके तथा खस तौर से गरीबी रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वालों के लिये अधिक साख निर्धारित करे ।

दूसरा, मौद्रिक नीति का एक बहुत बड़ा अंश, जो बैंकों के ब्याज दर संरचना के विवेकीकरण से सम्बन्धित है, उसे अपनाया गया । समय जमाओं पर ब्याज दर को 5 प्रतिशत से घटा कर के 3 प्रतिशत कर दिया गया । व्यापारिक बैंकों के सभी संगठित जमाओं पर ब्याज दर 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर के 6 प्रतिशत कर दिया गया।

तीसरे, दीर्घकालीन पूर्ण निवेशों को प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण से सावधि ऋणों पर ब्याज की सीमा, जो 3 वर्ष से कम हो, वह 14-15 प्रतिशत से घटा करके 12.5 प्रतिशत कर दिया गया । तेल तथा तिलहनों के लगातार बढ़ते हुए मूल्य दबाव के सदर्थ में बैंक सीमा को बढ़ा कर

के 10 प्रतिशत कर दिया गया ।

चौथे, जनवरी, 1977 से वर्धमान नकदी आरक्षित अनुपात को 10 प्रतिशत कर दिया गया।

वर्ष 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को यह सलाह दिया कि कृषि तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में साख को आवंटित करे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ऋण ₹0 2500 जो लघु कृषकों से सम्बन्धित था, उसे 11 प्रतिशत के ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया और ऐसे ऋणों को 50 प्रतिशत भाग पुनर्विक्रितीय के दृष्टिकोण से बैंक - दर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुन सलाह दिया गया कि उपेक्षित क्षेत्रों के समग्र साख का 33 प्रतिशत 1979 तक कर दिया जाना चाहिए ।

व्यापारिक क्षेत्रों में बैंक साख में निम्न वृद्धि के कारण मौद्रिक विस्तार की दर में कमी हुई, फिर भी 1977-78 में मुद्रा पूर्ति में जो 15.4 प्रतिशत वृद्धि हुई, वह राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी । इससे भी अधिक पिछले वर्ष मुद्रा पूर्ति में अप्रत्याशित वृद्धि 18.5 प्रतिशत से हुयी । इस समयावधि में मौद्रिक विस्तार के लिए दो प्रमुख कारक रहे । प्रथम, सरकारी क्षेत्र में शुद्ध बैंक साख में महत्वपूर्ण वृद्धि, जो पिछले वर्ष ₹0 908 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹0 1942 करोड़ हो गयी और दूसरा, लगातार तथा बड़े पैमाने पर विदेशी विनियम आदेशों में वृद्धि जो 1976-77 में ₹0 1463 करोड़ थी वह बढ़कर ₹0 1990 करोड़ हो गयी । इस समयावधि में एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि समय जमाओं में वृद्धि दर कम रही, जो 1976-77 में 27.7 प्रतिशत से गिरकर 1977-78 में 22.9 प्रतिशत हो गयी ।

1977 में केन्द्र में नई सरकार का गठन हुआ, जिसने पाचवीं योजना को एक वर्ष पूर्व ही 1977-78 में समाप्त कर दिया और छठी योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, जो 1983-84 तक चलती, किन्तु 1980 में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हो गया और उसने उपयुक्त छठी योजना को समाप्त करके नई छठी योजना को प्रस्तुत किया ।

4 6 छठी पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एवं साख नीति (1979-80 -- 1984-85)

मार्च, 1979 के पश्चात अत्यधिक स्फीतिकारी दबावों के विद्यमान रहने तथा इसके पूर्व पेट्रोलियम आदि उत्पादों की कीमतों में तीव्र वृद्धि आदि ने अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की सम्भावनाओं पर और इसके अतिरिक्त विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन भविष्य में बनाने की गुन्जाइश पर दुष्प्रभाव डाला। छठी योजना के पहले वर्ष में कीमत स्तर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु दृढ़ कीमत नियन्त्रण एवं मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का प्रयोग करके सरकार कीमतों पर काबू पाने में सफल हो गयी, बावजूद इसके कि इस दौरान भारी घाटे की वित्त व्यवस्था किया गया। छठी योजना के दौरान कीमत स्तर में 9.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि हुई और इसके नतीजे के तौर पर श्रम - वर्ग की वास्तविक मजदूरी में शोचनीय कटौती हुई।

छठी योजना के दौरान भारत सरकार की मौद्रिक नीति अनिवार्यतः अत्यधिक तरलता को रोकने की रही है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उत्पादक एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय। मुद्रा एवं उधार के विस्तार पर कड़ा नियंत्रण करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1981 में नकद आरक्षित अनुपात 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार एक ओर मांगप्रबन्ध द्वारा और दूसरी ओर पूर्ति प्रबन्ध द्वारा 1981 से 1983 के बीच कीमत - स्तर को स्थिर करने में मदद दी गयी। छठी योजना में चावल, गेहूँ, चीनी, गुड़ तथा अन्य जनोपयोग वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण का प्रयास किया गया। छठी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसका निर्माण दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में किया गया था। इसमें पन्द्रह वर्षीय एक दीर्घकालीन योजना तैयार की गयी, जिससे विकासगत समस्याओं का निदान हो सके। यह न केवल सफल राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, रोजगार, बचत एवं विनियोग जैसे परम्परागत तत्वों पर आधारित था, बल्कि इसका विकास गरीबी के प्रतिशत, सम्भावित आयु, खाद्यान्न, चीनी, कस्त्र आदि के उपभोग के सदर्भ में भी किया गया था। गरीब वर्ग के लिये अधिक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किया गया।¹¹

छठीं पयवर्षीय योजना के जून 1981 में अनुसूचित वणिज्य बैंको की शाखाओं की संख्या 35,548 थी तथा इनके द्वारा जुटायी गयी कुल जमा राशियाँ रुपये 40,413 करोड़ थी। इसी प्रकार बैंक ऋण बढ़कर रुपये 21,332 करोड़ हो गया। वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली वित्तीय सहायता का वितरण 1980-81 में रुपये 1,603 करोड़ था। 1980-81 में पूर्ववर्ती वृद्धिकारी नकद शेष को समाप्त कर दिया गया, फलस्वरूप इस अवधि में नकदी प्रारक्षित अनुपात 6 प्रतिशत रहा, लेकिन आगे के वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि बनी थी।

1981-82 में मौद्रिक एवं साख नीति एक नियंत्रणात्मक रूप में रही। जहाँ एक ओर मुद्रापूर्ति में कमी करने का प्रयास रहा, वहीं सावधि जमा को बढ़ाकर बचत उत्पन्न करना रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रापूर्ति एवं बैंक साख नियंत्रण वही रही, जो पिछले वर्षों में विश्लेषित किया गया है। इस समयावधि में एक महत्वपूर्ण विकास साख नीति में यह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक दिसम्बर 1980 में नकदी साख व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण रखी। व्यापारिक बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया। 1981-82 के बजट के साथ ब्याज दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया ताकि ब्याज दर और अधिक विवेकपूर्ण बनाया जा सके। ब्याज - दर बैंक जमाओं पर, जो सितम्बर 1979 में पुनर्संशोधित किया गया था, उनका समायोजन मार्च, 1980 में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। अधिकृत ब्याज - दर 10 प्रतिशत रखा गया।¹² सहकारी बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि सावधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दे। ब्याज दर के संरचनात्मक परिवर्तन के साथ उधार देय ब्याज व्यापारिक बैंकों के भी विवेकपूर्ण बनाये गये। इसका उद्देश्य वर्तमान में कई निर्दिष्ट दरों को कम करना था और बेहतर ब्याज दर विभिन्न वर्ग के ऋण ग्राहकों से वसूल करना था। इसका उद्देश्य साख वृद्धि को नियंत्रित करने से भी रहा। एक महत्वपूर्ण बात, जो नई उधार देय नीति में रही, वह उधार देयता में चार दशांशों से और विभिन्न वर्ग के ऋण ग्राहकों से सम्बन्धित रही। ऋणों, अग्रिमों, ओवर ड्राफ्ट आदि के न्यूनतम दर को उर्ध्वो संशोधन किया गया है। लगातार मुद्रा स्थिति की दशांशों के बने रहने के कारण भारतीय

रिजर्व बैंक ने 1981 में सामान्य निर्देश व्यापारिक बैंको को दिया कि बैर - खाद्य साख में प्रसार पूरे वित्तीय वर्ष में अत्यधिक विस्तार न हो। नकदी आरक्षित अनुपात को ऊँचा कर दिया गया। विवेकपूर्ण वित्तीयन तथा पुनर्भणना दर उर्ध्वमुखी सशोधित किये गये, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक पुनर्वित्तीयन कम कर सके। पुनर्वित्तीयन पर अधिकतम ब्याज दर 11 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया, परन्तु इसका प्रभाव बैंक द्वारा दिये गये ऋणों पर नहीं पड़ेगा। इसका अभिप्राय यह था कि व्यापारिक बैंको का पुनर्वित्तीयन केवल अल्पकालीन तथा विशिष्ट सन्दर्भों में होगा। इस समयावधि में बैंक दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर के 10 प्रतिशत कर दिया गया। बैंक दर में इस परिवर्तन के साथ खाद्य तथा निर्यात का पुनर्वित्तीयन भी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर के 10 प्रतिशत कर दिया गया।¹³

कुछ संवेदनशील वस्तुओं के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण समायोजन चयनात्मक साख नियंत्रण के द्वारा किया गया। गेहूँ, धान, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों को न्यूनतम मार्जिन को 10 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया गया, फिर भी चयनात्मक साख नियंत्रण चीनी से सम्बन्धित उत्पादन तथा स्टॉक की दृष्टिकोण से उसी रूप में समयोजित किया गया।

प्राथमिक क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को साख प्रवाह के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य निर्देश इन्हें और अधिक बढ़ाने के सन्दर्भ में किया। प्राथमिक क्षेत्रों में ये अग्रिम इस रूप में बढ़ाये जाये कि समग्र ग्रामीण ऋण का 40 प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत हो। पुन यह 40 प्रतिशत प्राथमिक एवं सम्बन्धित क्षेत्र को हो। प्राथमिक क्षेत्रों के अन्तर्गत, कृषि, लघु उद्योग तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में निर्धारित किया गया। विभेदात्मक ब्याज दर योजना को व्यक्तिगत क्षेत्र के बैंको को भी लेकर पुन विस्तृत की गयी, जिससे इसका क्षेत्र पूरे देश भर में फैल सके। यह परियोजना पुन सशोधित की गयी कि बैंक इस कार्य को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से कर सके इस समयावधि में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गयी। बैंको को यह निर्देश दिया गया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कमजोर वर्गों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करे। इस

समयावधि में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हर विकास खण्डों में प्रसारित किया गया ।

संस्थागत व्यवस्था, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की साख पूर्ति से सम्बन्धित है, उसे अधिक मजबूत बनाने के लिये सरकार ने एक नये बैंक नाबार्ड की स्थापना जुलाई, 1982 को किया, जो अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों हेतु व्यापारिक बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को पुनर्वित्तीयन करता है। नाबार्ड को यह भी अधिकार है कि वह अपने ससाधनों को सरकार तथा बाजार से उत्पन्न कर सके। यह भारतीय रिजर्व बैंक से भी अल्प समयावधि के लिये सहायता प्राप्त कर सकती है । नाबार्ड के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन आने अध्याय 6 में किया जायेगा ।

देश के विकास कार्यक्रमों में निर्यात के महत्व को मानते हुए सरकार ने जनवरी, 1982 में निर्यात - आयात बैंक की स्थापना किया । यह बैंक निर्यातको और आयातों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा तथा प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में अन्य वित्तीय संस्थाओं का, जो आयात - निर्यात से सम्बन्धित है, उनका संचालन करेगा । मोटे तौर पर इस बैंक के कार्य निर्यात एवं आयात का वित्तीयन भारत तथा अन्य देशों में करना, सहयोग के उद्यमों में बाहरी देशों का आयात - निर्यात में पुनर्वित्तीयन करना , भारतीय पक्ष के लोगों को ऋणप्रदान करना, जिससे वे विदेशों में अपने शेष पूँजी को सह उद्यमों में लगा सके। इस तरह यह बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी.आई) के अन्तर्गत राष्ट्रीय वित्त के कार्यों को स्वयं करेगा ।

इस प्रकार इस अवधि में मुद्रापूर्ति में EM_1 तथा EM_3 भी सीमित रही, प्राथमिक क्षेत्रों में साख - प्रवाह उँचा रहा और खाद्य पदार्थों में कुल बैंक साख अधिक रहा । चूँकि स्फीतिकारी प्रवृत्तियाँ बनी रही, इसलिये मौद्रिक एवं साख नीति को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया ।

1983-84 में मौद्रिक एवं साख नीति दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों से सम्बन्धित थी। अतिरिक्त तरलता का न उत्पन्न होना और स्फीतिकारी दबावों को फिर से न उभरने देना तथा साख को इस रूप में नियंत्रित करना कि उत्पादन बना रह सके। समग्र मौद्रिक संसाधन में प्रसार जनवरी, 1984

तक काफी तेज था, पिछले वर्ष की तुलना में । इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त तरलता की स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसे अवांछनीय साख प्रसार हुआ, इसको समाप्त करने के लिये और स्फीतिकारी दबावों पर नियंत्रण रखने के लिये नकदी आरक्षित अनुपात को बढ़ा दिया । साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि साख की पूर्ति उत्पादक क्षेत्रों में रुकावट न हो और चयनित क्षेत्रों में साख की उपलब्धता बनी रह सके। मौद्रिक नीति को 1982 - 83 में उदार रखा गया, 1981-82 की तुलना में । चूंकि स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सका, अतः मौद्रिक नीति को 1982-83 में चयनात्मक ढंग से उदारीकृत किया गया, परिणामस्वरूप एम₃ में वृद्धि, जो 1981-82 में 12.5 प्रतिशत पर रुक गया था, वह 1983-84 में 16.1 प्रतिशत हो गया। इसी के साथ साथ एम₁ में भी 1982-83 में विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गया। पूरे आरक्षित बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का योगदान रुपये 2508 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा। इस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक का साख केन्द्र और राज्य सरकारों में राज्य सरकारों को कम प्राप्त हुई । वर्ष 1982-83 में व्यापारिक क्षेत्रों को बैंक साख बढ़ाकर के रुपये 8247 करोड़ हो गया अर्थात् 19 प्रतिशत, जो पिछले वर्ष में केवल 18.6 प्रतिशत था। साख नीति 1982-83 में धीरे धीरे सरलीकृत कर दी गयी, परिणामस्वरूप साख की उपलब्धता कई उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ गयी । इन उपायों में नकदी आरक्षित अनुपात को कम करना तथा सौ प्रतिशत पुनर्विक्तियन करना था । निर्यात - आयात के क्षेत्र में पुनर्विक्तियन को सुधारा गया और निर्यात के क्षेत्र में साख के प्रसार का विस्तार किया गया ।

साख नीति 1983-84 में इस रूप में बनायी गयी कि अतिरिक्त तरलता को रोका जा सके और साथ ही साथ साख को चयनित उत्पादन क्षेत्रों में बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया और उधार देय ऋण दरों में कमी की गयी। इससे अधिकांश ऋण ग्राहकों में उत्साह उत्पन्न हुआ । व्याज दर में अल्पकालीन ऋणों के सन्दर्भ में कृषि, लघु क्षेत्र, निर्यात, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में महत्वपूर्ण कमी की गयी । साथ ही साथ साख नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया कि अप्रत्याशित जमा में वृद्धि बनाये रखा जाय । बैंकिंग क्षेत्र में अत्यधिक

तरलता विद्यमान थी, जिससे साख तरलता में महत्वपूर्ण अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी। इस सन्दर्भ में नकदी साख अनुपात का 7 प्रतिशत से बढ़ा करके 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। इन विभिन्न दशाओं में नकदी साख अनुपात को कम करने के बावजूद भी जमा में वृद्धि बनी रही और साख में वृद्धि भी बढ़ती रही। इस समयावधि में कुछ परिवर्तन खाद्य - साख वित्तीयन की सीमा से सम्बन्धित रहे। व्यापारिक बैंकों की वास्तविक वृद्धि 1983-84 के मध्य तक रुपये 4880 करोड़ थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित राशि से बहुत अधिक थी। प्राथमिक मुद्रा में भी वृद्धि इसी तरह रही।

अर्थव्यवस्था में पूँजीगत विनियोगों को और तेज करने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1984 में उदार ऋण नीति अपनाया गया। इस नीति के परिपेक्ष्य में रियायत दर 12.5 प्रतिशत पर सहायता दिया गया। विशेष दबाव इस बात पर दिया गया कि उत्पाद उच्च कोटि का हो तथा उनकी प्रक्रिया तकनीकी और औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित हो। ऐसी यूनिट जो शत प्रतिशत निर्यात करती है, उसे 1.5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गयी। मन्दी तथा व्यस्त मौसम में ऐसी नीतियों को बनाया गया, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार हो। यद्यपि उधार देय दर का सरचनात्मक परिवर्तन जो 1983 में था, उसे परिवर्तित नहीं किया गया, परन्तु कुछ समायोजन किये गये, जिससे साख नीति पर परिमाणात्मक प्रभाव पड़ सके। इनमें से उर्वरकों पर दिये गये अत्रिम्नों में कमी, दालों तथा तिलहनो की उगाही, कृषकों, व्यवसायियों तथा स्वरोजगार के लोगों पर रियायती दरे लागू रहें।

चयनात्मक साख नीति के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये, जिसमें चीनी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीनी के अबिक्रीत स्टॉक के कारण किया गया। आबकारी इयूटी कुछ परिवर्तनों के साथ कायम रहा। छठी पंचवर्षीय योजना के वित्तीय वर्ष 1983-84 में मौद्रिक एवं साख नीति मुख्य रूप से दो उद्देश्यों से सम्बन्धित रही। आर्थिक विकास में संवर्धन करना, विशेषकर चयनित क्षेत्रों में, जब कि इसी के साथ - साथ स्फीतिकारी दशाओं पर नियंत्रण रखना।

1983-84 में मौद्रिक विस्तार 1982-83 की तुलना में अधिक रहा और बैंको के पास अतिरिक्त तरलता विद्यमान रही। मौद्रिक नीति इस स्थिति का समाधान करने में रही और नकदी साख अनुपात को लगातार बढ़ाती रही, जब तक स्फीति कारी दबावों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण न प्राप्त कर लिया जायेगा इसकी प्रवृत्ति यही रहेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना बहुत ही जटिल परिस्थितियों में शुरू की गयी थी, परन्तु इसके बावजूद भी योजना के सम्यक क्रियान्वयन से छठी योजना के अधिकांश निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया था। इस योजना में विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य 5.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, जिसे योजना के अन्त में प्राप्त कर लिया गया। कृषि क्षेत्र के लिये निर्धारित विकास दर 3.8 प्रतिशत से भी अधिक 4.3 प्रतिशत प्राप्त किया गया। यह योजना पिछली तीन दशाब्दियों के मौद्रिक एवं साख नीति तथा अन्य नीतियों का मनन करके तैयार किया गया था। छठी योजना का वास्तविक व्यय ₹0 1,09,2917 करोड़ (89-90 कीमत से) है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय रुपये 97,500 करोड़ (79-80 की कीमत) है, इसमें औसत रूप से 12 प्रतिशत वृद्धि हो गई। छठी योजना सामान्यतः सफल रही है।

छठी योजना में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य रूप से लाभदायकता का अधिक सुदृढ़ करना, भूमि, सुधार कार्यक्रम को तीव्र गति से लागू करना, नवीन तकनीकी का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुँचाना तथा कृषि विकास को ग्रामीण क्षेत्र में आये तथा रोजगार में वृद्धि का साधन बनाना आदि था। इस योजना में घरेलू तथा निर्यात की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कृषि उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही साथ यह भी लक्ष्य रखा गया था कि इस योजना में 153.6 मिलियन टन अनाज का वार्षिक उत्पादन होगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा भू-क्षरण पर भी ध्यान दिया गया। इस योजना में कृषि क्षेत्र का परिव्यय रुपये 19,829 करोड़ था, जो कि कुल योजनागत व्यय का 18 प्रतिशत है। इस योजनावधि में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डों में

प्रारम्भ कर दिया गया। इस योजना में छोटे एवं सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के विकास के लिये कृषि एवं सहायक व्यवसायों के विकास हेतु विभिन्न प्रयास किये गये।

छठी योजना की समग्र अवधि में 1979-80 की कीमतों पर रुपये 1,58,710 करोड़ का कुल विनियोग (सकल पूँजी निर्माण) किया गया। इसमें रुपये 1,49,647 करोड़ का वित्त प्रबन्ध देशीय बचत द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी। छठी योजना में रोजगार वृद्धि हेतु कृषि, ग्राम विकास, ग्राम तथा लघु उद्योग आदि को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गयी। ग्रामीण मजदूरों जो मुख्यतः दैनिक मजदूरी पर निर्भर करता है, के पास मन्दी मौसम में आय का कोई स्रोत नहीं होता, इनके लिये राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव किया गया। छठी योजना में 1984-85 तक बचत दर के 24.5 प्रतिशत तक बढ़ जाने की प्रत्याशा थी, किन्तु वास्तविक बचत दर केवल 23.3 प्रतिशत तक पहुँच पायी। इसी तरह औसत वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत से कम थी।

छठी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण रूप से मौद्रिक विस्तार हुआ। बृहद मुद्रा पूर्ति (एम₃) में औसतन 16.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। प्रारक्षित मुद्रा में वार्षिक वृद्धि दर 16.5 प्रतिशत था। छठी पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण अवधि में मौद्रिक समुच्चयों में वृद्धि की औसत वार्षिक दर को सारणी 4.9 में देखा जा सकता है। सारिण में सातवीं योजना अवधि में भी मौद्रिक दर को प्रदर्शित किया गया है। छठी योजनावधि में मुद्रा गुणक लगभग 3.4 पर स्थिर था।

4.7 सातवीं पंचवर्षीय योजना में मौद्रिक एवं साख नीति (1984-85 -- 1989-90)

छठी पंचवर्षीय योजना अनेक जटिलताओं एवं प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी काफी सीमा तक सफल रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सातवीं योजना तैयार की गयी। सातवीं योजना दीर्घकालीन दृष्टि से तैयार की गयी थी, जिसका लक्ष्य अगले पन्द्रह वर्षों (1985 - 2000) तक स्वतः वित्त पोषित अर्थव्यवस्था का होना है। सातवीं योजना में विकास दर 5 प्रतिशत वार्षिक रखी गयी थी। कृषि क्षेत्र के लिये यह दर 4 प्रतिशत वार्षिक थी।

सारणी 4.9

मौद्रिक समुच्चयों में वृद्धि की औसत वार्षिक दर

(प्रतिशत)

पद	1980-81 से	1985-85 से
	1984-85 तक	1989-90 तक
1 एम ₃	16 7	17 6
(क) बैंको के पास माग जमा राशिया	14 3	15 4
(ख) बैंको के पास सावधि जमा राशिया	16 1	15 8
(ग) बैंको के पास सावधि जमा राशिया एम ₃ के साधन	18 1	18 9
(I) सरकार को निवल बैंक ऋण जिसमे से	20 5	18 4
केन्द्रीय सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	22 2	17 8
(II) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	18 3	16 5
(III) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा पर परिसम्पत्तिया	(-) 1 1	16 7
() सरकार की जनता के प्रति करेन्सी सम्बन्धी देयताये	5 6	15 2
() बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर -मौद्रिक देयताए	19 9	15 7
2 प्रारक्षित मुद्रा	16 5	17 2
3 मौद्रिक गुणक (मूल्य निरपेक्ष सख्या मे दिये गये है।)	3 44	3 41

Source : Economic Survey, 1980-81 to 1990-91.

सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुद्रापूर्ति की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रथम चार वर्षों में लगभग 17 प्रतिशत थी, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को अत्यधिक तरलता का सामना करना पड़ा और जिससे मुद्रा स्फीति का दबाव पूरे योजनावधि में बनी रही। योजना के अन्तिम वर्ष में मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर शिखर स्तर 19.7 प्रतिशत पर पहुँच गयी, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गयी।

चयनात्मक साख नियंत्रण के अन्तर्गत साख अधिकरण योजना के लिये अप्रैल, 1986 में उधार सीमा बढ़ाकर रुपये 6 करोड़ कर दिया गया। विनिर्माण इकाइयों और निर्यातकों के लिये यह सीमा रुपये 7 करोड़ रखी गयी। मार्च, 1986 के अन्त तक यह योजना 843 पार्टियों पर लागू की गयी। योजना के अधीन रुपये 21,670 करोड़ उधार की स्वीकृति दी गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण मौद्रिक विस्तार का अवधि थी।

भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार को दिया गया साख 1985-86 में रुपये 3,186 करोड़ और इसी अवधि में 1986-87 में रुपये 5048 करोड़ था। योजना के अगले वित्तीय वर्षों 1987-88 में रुपये 6761 करोड़, 1988-89 में रुपये 8457 करोड़ तथा 1989-90 में रुपये 14,056 करोड़ थे। इसी तरह क्षेत्रवार बैंक साख का वितरण मार्च, 1985 में 40.0 प्रतिशत, मार्च, 1986 में 40.8 प्रतिशत, तथा मार्च 1988 में 44.1 प्रतिशत हो गया। सातवीं योजना के मध्य में सुखमय चक्रवर्ती समिति के प्रस्तावों और सुझावों को क्रियान्वित किया गया। यह समिति नियोजित ढंग से समग्र मौद्रिक लक्ष्यों की आवश्यकता और उसके विकास द्वारा उपर्युक्त मौद्रिक समृद्धि को प्रस्तावित करती है।

इस समयावधि में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मात्र तरलता की समग्र मांग एवं पूर्ति से सम्बन्धित नहीं था, अपितु नियोजित प्राथमिकता के आधार पर स्थापित सामाजिक आर्थिक दशाओं के परिप्रेक्ष्य में तरलता के क्षेत्रीय बंटवारे से सम्बन्धित था। ये प्राथमिक क्षेत्र, कमजोर वर्ग के निर्यातकों, स्व रोजगार योजना के लोगों तथा ग्रामीण कलाकारों में विशेष महत्वपूर्ण साख का निर्धारण किया गया। जहाँ तक मौद्रिक एवं साख नीति के परिवर्तन तथा विकास का सम्बन्ध है, वह अर्थव्यवस्था में

सारणी 4.10

मुद्रा भण्डार में परिवर्तन के साधन

(रूपये करोड़)

		इन अवधियों में घट बढ़					
		1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
		31 मार्च से	31 मार्च से	31 मार्च से	31 मार्च से	31 मार्च से	31 मार्च से
		31 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक	31 मार्च तक
1	एम ₁ (जनता के पास उपलब्ध मुद्रा)	6517	4171	5310	7039	8231	19274
11	एम ₃ (कुल मौद्रिक साधन)	16268	16313	18578	22422	28959	37160
	(i) जनता के पास उपलब्ध करेंसी	3069	2378	1812	5177	4770	7971
	(ii) बैंको के पास मांग जमा राशियाँ	3144	2099	3 88	1774	3164	6399
	(iii) बैंको के पास सावधि जमा राशियाँ	9751	12142	13268	15383	20728	22866
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'अन्य जमा राशियाँ'	304	-304	10	88	297	-96
3	एम ₃ में परिवर्तन के साधन (1+2+3+4+5) -						
	1 सरकार को दिये गये निवल बैंक ऋण (क+ख)	9586	8093	11825	12350	12105	20676
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण (1 + ii)	7426	4442	5048	6402	6928	14068
	(i) केन्द्रीय सरकार को	6056	6468	5262	6559	6503	13813
	(ii) राज्य सरकार को	1370	-2026	- 214	- 157	425	255
	(ख) अन्य बैंको द्वारा सरकार को दिए गए ऋण	2160	3651	6777	5948	5177	6608
2	वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (क + ख)	10227	11850	7286	12786	20395	23822
	(क) वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए ऋण	327	300	365	395	1734	825
	(ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंको द्वारा दिए गए ऋण	9855	11550	6921	12390	18661	22997
3	बैंकिंग क्षेत्र को निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियाँ	1322	841	-47	805	1127	-133
4	सरकार को जनता के प्रति करेंसी संबंधी दायित्वियाँ	58	154	116	188	95	80
5	बैंकिंग क्षेत्र की सावधि जमा के अलावा निवल मुद्रा - भिन्न देनदारियाँ (क + ख)	9925	4625	602	3667	4784	7285
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा - भिन्न देनदारियाँ	3311	2085	1619	781	2711	600
	(ख) अन्य बैंक की निवल मुद्रा भिन्न देनदारियाँ (अवशेष)	1614	2540	-1017	2886	2052	6685

1989-90 में भी दर्ज की गयी। योजना के अन्य वर्षों में 1985-86 में 19.4 प्रतिशत, 1987-88 में 17.2 प्रतिशत, 1988-89 में 19.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

1988-89 में लेखा वर्ष को कैलेंडर वर्ष से बदल कर वित्तीय वर्ष कर दिया गया, जिससे बैंकों की राशियों और ऋण में वर्षान्तर में असामान्य वृद्धि आयी। बैंकों के वित्तीय वर्ष 1989-90 के अन्त में कुल जमा राशियों और ऋण में दोबारा तेज तथा असामान्य वृद्धि हुई, इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 मार्च से 6 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के पखवाड़े के दौरान बिना पूर्वानुमति लिए एक विवेकाधीन पुनर्वित्त प्राप्त करने का प्रयत्न किया।¹⁴

सातवीं योजना के पूरी योजनावधि में साधन पक्ष की ओर मुद्रा पूर्ति वृद्धि 1984-85 में 23.6 प्रतिशत, 1985-86 में 16.1 प्रतिशत, 1987-88 में 17.1 प्रतिशत, 1988-89 में 17.8 प्रतिशत और 1989-90 में 19.3 प्रतिशत के कारण काफी अधिक सीमा तक लगातार राजकोषीय असंतुलन रहा है।

1989-90 में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत सरकार को निवल बैंक ऋण रहा है। इसमें रुपये 20,137 करोड़ का विस्तार हुआ था। स्वर्ण पनमूल्याकन सहित बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में वित्तीय वर्ष 1989-90 में रुपये 212 करोड़ की कमी हुई थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रचालनों से सम्बन्धित आकड़े सारणी 4.11 में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि का एक मात्र प्रमुख स्रोत रहा है, जो 1989-90 में अधिक मौद्रिक विस्तार का मूल स्तम्भ है। 1989-90 में यह प्रारक्षित मुद्रा में हुई विस्तार का 96.1 प्रतिशत बैठता है, जबकि 1988-89 में यह 73.2 प्रतिशत और 1987-88 में 73.7 प्रतिशत था। इसके सषटकों में क्रमशः 1989-90, 1987-88 और 85-86 में सरकार को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण में वृद्धि का क्रमशः 93.9 प्रतिशत, 102.5 प्रतिशत और 101 प्रतिशत थी।

14. Economic Survey 1990 - 91, P. 125

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक चुने हुए निर्देशकों में घट - बढ़

(रूपये करोड़)

इन अवधियों में घट बढ़

		1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 °
		31 मार्च से 31 मार्च तक	31 मार्च से 31 मार्च तक	31 मार्च से 31 मार्च तक	31 मार्च से 31 मार्च तक	31 मार्च से 31 मार्च तक	31 मार्च से 31 मार्च तक
1	कुल जमा राशिया (क+ख)	11839	13133	16356	1315	21897	16809
	(क) माग जमा राशिया	2743	1756	2298	1040	2569	5514
	(ख) सावधि जमा राशिया	9096	11377	1258	14275	19328	2125
2	भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	469	-943	-620	847	1303	-1128
3	भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ वाकी और जमा वाकी	2759	864	1415	3348	3761	2291
	(क) रोकड़ बाकी	127	231	4	4	145	204
	(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशिया	2632	633	1447	3344	3616	2087
4	माग और अल्प सूचना पर देय राशिया	189	-67	367	-865	1499	-1172
5	बैंक ऋण (क + ख)	7148	7869	4999	7492	12470	16734
	(क) जनता को अनाज खरीदने के लिये ऋण	1489	293	-104	-2349	-1490	1237
	(ख) खाद्य भिन्न बैंक ऋण जिनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को	5659	7576	5103	9841	13960	15496
6	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	3732	5666	8606	8118	7674	9707
	(क) सरकारी प्रतिभूतिया	2087	349	6704	5815	4954	6477
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया	1645	2117	1902	2303	2720	3230
7	अन्य बैंकों के चालू खाते में जमा शेष राशि	248	418	-421	-266	180	247

प्रारक्षित मुद्रा में 1984-85 में 21.5 प्रतिशत, जब कि इसके अगले वर्ष 1985-86 में अत्यधिक कमी 8.3 प्रतिशत, 1987-88 में 19.4 प्रतिशत, 1988-89 में 17.7 प्रतिशत और 1989-90 में 23.2 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। 1989-90 में यदि रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में 2.1 प्रतिशत की कमी न हुई होती तो प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि और अनुवर्ती मौद्रिक विस्तार और अधिक हुआ होता, जब कि इसके विपरीत 1988-89 में इसमें 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सरकार को दिया गया निवल रिजर्व बैंक ऋण, जो कि प्रारक्षित मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें 1984-85 में अत्यधिक वृद्धि 27.7 प्रतिशत (रूपये 7426 करोड़) के मुकाबले 1985-86 में काफी कम 13.0 प्रतिशत (रूपये 4442 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गयी। 1987-88 और 1988-89 में यह लगभग स्थिर क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इसी तरह 1988-89 में दर्ज की गई 13.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1989-90 में 23.6 प्रतिशत को अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य और सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को 1989-90 में दिए गये ऋण वृद्धि 1988-89 में हुई 59.4 प्रतिशत तथा 45.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत काफी कम थी। 1989-90 में प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसके प्रमुख स्रोतों में से एक अर्थात् केन्द्रीय बैंक के निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण में कई पखवाडों की समाप्ति के बाद 31 मार्च, 1989 के स्तर की तुलना में 1989-90 के केन्द्रीय बजट में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 7,337 करोड़ रुपये की वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई। चूंकि केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा केन्द्रीय सरकार को दिए गए निवल रिजर्व बैंक ऋण में हुए विस्तार को प्रकट करने का एक प्रमुख उपादान है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति भी यही बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार 1989-90 की समाप्ति पर रूपये 10,624 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋण का क्षेत्रवार आवंटन सारणी 4.12 में दिया गया है। ये आकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विलयन के कारण

सारणी 4 12

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार आवंटन

(रूपये करो

	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	करोड़ रूपये	प्रतिशत	करोड़ रूपये	प्रतिशत	करोड़ रूपये	प्रतिशत	करोड़ रूपये	प्रतिशत
सकल बैंक ऋण	7356	13 3	7651	12 3	15468	22 0	16943	19 8
1 सरकारी खाद्य वसूली	-432	-7 8	-2914	-57 1	-1421	-64 9	1237	160 6
2 सकल खाद्य भिन्न ऋण (-क+ख+ग+घ)	7787	15 7	10605	18 5	16889	24 8	5706	18 5
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (1+2+3)	3484	16 2	4020	16 0	5149	17 7	6168	18 0
(1) कृषि	1512	16 7	1439	13 6	1941	16 2	2584	18 5
(2) लघु उद्योग	1292	16 5	1712	18 8	2315	21 4	2415	18 4
(3) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	680	14 5	869	16 2	893	14 3	1169	16 4
(ख) उद्योग (मध्यम और बड़े)	2934	15 9	3797	17 8	7032	28 0	6087	18 9
(ग) थोक व्यापार (अनाज की वसूली को छोड़कर) (1+2+3+4)	14	0 4	518	16 8	1169	32 5	705	14 8
(1) भारतीय कपास निगम	-51	-31 9	-18	-16 5	-54	-59 3	103	278 4
(2) भारतीय खाद्य निगम(उर्वरक)	8	5 7	22	14 8	31	18 1	28	13 9
(3) भारतीय जूट निगम	71	55 9	-56	-28 3	-44	-31 0	-44	-44 9
(4) अन्य व्यापार	-14	-0 5	570	21 7	1236	28 7	618	14.0
(घ) अन्य क्षेत्र	1355	20 5	2270	28 4	3 39	34 5	2746	19 9
निर्यात ऋण	73	30 6	771	24 5	2224	56 8	2104	34 3

Source : Economic Survey, 1986-87 to 1990-91.

मार्च, 1990 से 49) द्वारा नियोजित ऋण से संबंधित हैं, जो बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत बैठते हैं। 1989-90 के दौरान कुल मिलाकर सकल बैंक ऋण 1988-89 में 22 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि की निम्न दर 19 8 प्रतिशत दर्ज की गई, तथापि निरपेक्ष रूप से सकल बैंक ऋण में हुए 15,468 करोड़ रुपये विस्तार की अपेक्षा 1989-90 में हुये 16,943 करोड़ रुपये विस्तार काफी अधिक था। खाद्य ऋण में 1988-89 में हुई कमी के बावजूद 1989-90 में वृद्धि दर्ज की गई।¹⁵

जहां मार्च, 1986 के अन्त में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गये बैंक ऋण में 40 8 प्रतिशत (रुपये 3,157 करोड़) की वृद्धि हुयी, वहीं योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण में रुपये 6,168 करोड़ की काफी अधिक वृद्धि हुयी, जो मार्च 1990 के अन्त में निवल बैंक ऋण में वृद्धि का 42 4 प्रतिशत है। इसके पूर्व 1988-89 में इसमें 43 2 प्रतिशत वृद्धि हुयी थी। कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋण में 1985-86 में 44 3 प्रतिशत 1987-88 में 13 6 प्रतिशत (रुपये 1,439 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गयी। इसमें 1988-89 में रुपये 1,941 करोड़ (16 2 प्रतिशत) और 1989-90 में रुपये 2,584 करोड़ (18 5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी। लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों में 1985-86 में 38 1 प्रतिशत, 1987-88 में 18 8 प्रतिशत (रुपये 1,712 करोड़), 1988-89 में 18 4 प्रतिशत (रुपये 2,315 करोड़) तथा 1989-90 में 21 4 प्रतिशत (रुपये 2,415 करोड़) की वृद्धि हुई। बड़े और मझोले उद्योगों के अग्रिमों में 1984-85 में रुपये 1,318 करोड़ (9 0 प्रतिशत) वृद्धि हुयी, लेकिन इसके अगले वर्ष 1985-86 में अत्यधिक वृद्धि रुपये 3,231 करोड़ (20 3 प्रतिशत) वृद्धि हुयी। 1987-88 में रुपये 3,797 करोड़ (17 8 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी। 1988-89 में रुपये 7,032 करोड़ (28 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि की तुलना में रुपये 6,087 करोड़ (18 9 प्रतिशत) का अतिरिक्त बैंक ऋण प्राप्त हुआ। थोक व्यापार के अग्रिमों में, खाद्य वसूली के अतिरिक्त 1988-89 में रुपये 1,169 करोड़ (32 5 प्रतिशत) तथा 1989-90 में रुपये 705 करोड़ (14 8 प्रतिशत) की वृद्धि

दर्ज की गयी । निर्यात ऋण में भी 1988-89 में रुपये 2,224 करोड़ (56.8 प्रतिशत) तथा 1989-90 में रुपये 2,104 करोड़ (34.3 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी ।

1987-88 से 1989-90 की अवधि में सभी वित्तीय संस्थाओं की कुल स्वीकृतियों तथा सवितरणों में वृद्धिकारी प्रवृत्ति देखने में आई है । उनके द्वारा स्वीकृति कुल सहायता की राशि 1987-88 में रुपये 9,171.8 करोड़ से बढ़कर 1988-89 में रुपये 14,073.4 करोड़ हो गई तथा 1989-90 में यह बढ़कर रुपये 15,631.4 करोड़ हो गई । आकड़ों से सातवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों की अवधि में कुल स्वीकृति में 34 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि का पता चलता है । इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता राशि के सवितरण में इसी अवधि में 22 प्रतिशत की ऐसी ही वृद्धि का पता चलता है । यह 1987-88 में रुपये 6,788.4 करोड़ की तुलना में 1989-90 में रुपये 10,001.7 करोड़ थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने सातवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों में सभी वित्तीय (सावधि ऋण देने वाली) संस्थाओं द्वारा स्वीकृति की गई कुल सहायता की अपेक्षा अधिक राशि स्वीकृति की गयी थी। 1987-88 और 1989-90 के मध्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोजनवार प्रत्यक्ष सहायता अनुदान में नई परियोजनाओं के लिए 28 प्रतिशत, विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार/विविधीकरण के लिए 76 प्रतिशत तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापित परियोजनाओं के लिए 20 प्रतिशत और पूरक सहायता के लिए 33 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई । वर्ष 1989-90 के दौरान मियादी उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा सहायता की बहुत सी नई योजनाएं आरम्भ की गईं, जिनमें महिला उद्यम निधि योजना, महिला विकास निधि योजना, उपस्कर ऋण तथा खरीददार ऋण, परिसम्पत्ति ऋण योजना शामिल है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता प्रदान की है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम दोनों ने मिलकर 100 करोड़ रुपये की राशि से अपनी द्वितीय उद्यम पूंजी निधि (वीआईसीआईयूएसआई-)

द्वितीय) की स्थापना की है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भी पूजी बाजार के क्षेत्र में एक विकसित व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यू बम्बई में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट की स्थापना की है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सातवीं योजना के अंतिम से तीन वर्षों में कुछ विशेषज्ञता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं का संवर्धन किया है। दूसरी वित्तीय संस्थाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने 1987 में भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लिमिटेड का संवर्धन किया, जिसे नौवहन तथा मत्स्य पालन क्षेत्र की रूग्ण कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के साथ-साथ जहाजों और मत्स्य जलपोतों के अधिग्रहण के लिए सहायता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार दूसरी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इण्डिया के साथ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1989 में भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की, जो पर्यटन और इससे संबंधित कार्यों के क्षेत्र में उद्दमों को रूपया और विदेशी मुद्रा, दोनों में, सहायता प्रदान करेगा, शेयर ऋण पत्रों की जिम्मेदारों सभालेगा/सीधे ही अंशदान करेगा, पूर्तिकर्ताओं को ऋण की सुविधाएं प्रदान करेगा, उपस्कर पट्टे पर देगा/प्राप्त करायेगा। इसी प्रकार सात अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का प्रतिभूति संबंधी लेन - देन करने के लिये इन संस्थाओं द्वारा 1987 में भारतीयस्टाकधारिता लि० की स्थापना की गई थी। सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र की सभी वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस निगम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने की मजूरी दी है।¹⁶ दूसरी उल्लेखनीय घटना इन संस्थाओं का उद्यम पूंजी क्षेत्र में प्रवेश है। उद्यम पूंजी निधियां संसाधन जुटाने का वैकल्पिक तरीका प्रदान करती हैं। जो कि कंपनी की विशिष्ट जोखिम आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई०सी०आई०) और भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) द्वारा निर्मित उद्यम पूंजी के निर्मित होने से उद्यम पूंजी सहायता अब अधिक सुलभ है।

भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा पिछले अनेक वर्षों में किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा बाजार में और अधिक विविधता आई है । 182 दिवसीय राजकोषीय हुडियो, वाणिज्य हुडियो, वाणिज्यक दस्तावेजों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के कारोबार में काफी विस्तार हुआ है । सातवीं योजना के अंतिम वर्षों में, अन्तर-बैंक माग मुद्रा, अल्पावधि नोटिस मुद्रा और सावधि मुद्रा के लेनदेन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है । सातवीं योजना में केवल अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह को ही माग/नोटिस में ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को ऋणदाता के रूप में काम करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी । यह स्मरणीय है कि निवेशकर्ताओं को उनकी अल्पावधि निधियों के निवेश में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1989 में जमा पत्र शुरू किये गये थे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि माग मुद्रा दरों में काफी अस्थिरता रही है । मई, 1989 में माग मुद्रा दरों में छूट देने से अनेक बैंक ऋण देने और उधार लेने में परिवर्तन करते रहे हैं और इस प्रकार बाजार के एक तरफा होने में कमी लाने में सहयोग दे रहे हैं । इसके बावजूद यह देखा गया है कि माग राशि दरों में रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले सप्ताह में तेजी से वृद्धि होती है और जब बैंकों की नकदी प्रारक्षित अनुपात सबंध आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब दूसरे सप्ताह में गिरावट आ जाती है । 25 अप्रैल, 1988 से आरम्भ अपने मुद्रा बाजार प्रचालन के माध्यम से भारतीय बट्टा भुनान और वित्त गृह न केवल 182 दिवसीय राजकोषीय हुडियो को एक उच्च नकदी दस्तावेज के रूप में विकसित करने में, बल्कि इन हुडियो के लिए एक सहायक बाजार स्थापित करने में भी सफल रहा है । 1989-90 के दौरान इन हुडियो का समय कारोबार, 1988-89 के स्तर की तुलना में लगभग दुगुना हो गया और रुपये 21,953 करोड़ की राशि तक पहुंच गया ।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने प्रचालन जुलाई, 1988 से प्रारम्भ किए थे और यह देश के आवासीय वित्तपोषण के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा । यह न केवल इस प्रकार के

वित्तपोषण के लिए मजबूत सस्थागत ढांचे के संवर्धन का पक्षधर रहा है, बल्कि विशेष रूप से आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बचतों पर बल देते हुए वास्तविक संसाधनों अर्थात् जमीन और भवन निर्माण सामग्रियों की पूर्ति बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के सहयोग से घरेलू लोगों से संसाधन जुटाने की दृष्टि से, विशेषकर मकानों/फ्लैटों के निर्माण के लिए 1 जुलाई, 1989 को गृह ऋण खाता स्कीम शुरू की है।¹⁷

भारतीय बैंक ने पहली प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपादान सेवाएँ स्थापित करने के लिए उपाय करने और उपादान सेवाएँ पूरे स्तर पर आरम्भ करने के लिए कानूनी उपायों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उपादान को कारोबार के एक भाग के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें बैंक/बैंकों की सहायक संस्थाएँ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत कार्य कर सकती हैं। देश के सभी चारों क्षेत्रों अर्थात् पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी के लिए अनुसूचित बैंकों ने उपादान सेवाएँ शुरू करने के वास्ते आवेदन किया है और ये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। ये उपादान अभिकरण न केवल कार्यशील पूँजी की बाधाओं को हटाने में इकाइयों की सहायता करेगी, बल्कि ऋण प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करेगी और जोखिमों का जायजा लेने में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान कर इकाइयों को संरक्षण भी देगी। उपादानों को इसके बदले में लघु क्षेत्र से तत्काल उपलब्ध व्यापार का भी लाभ मिलेगा।

1987 से सरकारी क्षेत्र के कुछ वाणिज्य बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (1987), केनरा बैंक (1987), इंडियन बैंक (1989) पंजाब नेशनल बैंक (1990) और बैंक ऑफ इण्डिया (1990) ने भी अपनी व्यापारिक सहायक बैंकिंग कंपनियों के माध्यम से पारस्परिक निधियों की स्थापना की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी 1989 में अपनी पारस्परिक निधि शुरू की। इन पारस्परिक निधियों ने 1989-90 के दौरान 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें भारतीय बैंको ने हाल ही में प्रवेश किया है, वह अपतटीय निधियों का क्षेत्र है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने दो निधियों के क्षेत्र में शुरुआत की है। (क) लन्दन की मेरिल लिच के सहयोग से जुलाई, 1986 में आरम्भ की गई इंडिया फंड और (ख) अमरीका में एक निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत मेरिल लिच एंड नोमुर सिक्कुरिटीज इंटर नेशनल इन्व्हेस्टमेंट्स के सहयोग से अगस्त, 1989 में इंडिया ग्रोथ फंड। इन निधियों के लिए अनिवासी भारतीय और विदेशी लोगों ने अंशदान किया है और इनका कारोबार क्रमशः लन्दन तथा न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंजों में होता है। 1989-90 में भारतीय स्टेट बैंक ने भी इंडियन मैग्नम फंड (मिग्नम 1989) नामक अपतटीय निधियों के दो समुच्चय जारी किए हैं। यह निधि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत है और भारतीय स्टेट बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक संस्था द्वारा इसका प्रबन्ध किया जाता है। इसके अलावा यह सहायक संस्था, एशियाई विकास बैंक द्वारा जनवरी, 1990 में आरम्भ की गयी एशियाई परिवर्तनीय और आय निधि नामक बहुराष्ट्रीय अपतटीय निधि के भारतीय विभाग (20 प्रतिशत) की निवेश प्रबन्धक होगी। 18

4.8 मौद्रिक एवं साख नीति में नवीनतम परिवर्तन एवं विकास

1989-90 से मौद्रिक नीति को बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे तथा निरन्तर बनी रही अत्यधिक तरलता का सामना करना पड़ा, जिससे मुद्रास्फीति एक बार पुनः उभर कर सामने आयी। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त, भुगतान सन्तुलन की बिगड़ती हुई स्थिति भी थी, जो खाड़ी संकट के बाद विशेष रूप से बदतर हो गयी थी। अतः 1990-91 के उत्तरार्ध तथा 1991-92 के पूर्वार्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत कार्यों में सकल मांग को, विशेषकर आयात की मांग को सीमित रखना सर्वोपरि उद्देश्य बन गया। अल्पावधिक प्रबन्ध पर प्रमुख बल देने के बावजूद वित्तीय प्रणाली की परिचालनगत कुशलता को बढ़ाने तथा मुद्रा बाजार को विकसित करने के दीर्घ-कालीन उद्देश्यों का भी अनुसरण किया गया। इसके साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा जुलाई

1991 से आरम्भ किये गये व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और सरचनात्मक सुधार के उपायों के समन्वित कार्यक्रम को समर्थन दिया जाये। इस सम्बन्ध में वित्तीय प्रणाली पर श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मौद्रिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

1990-91 में मुद्रापूर्ति के सभी सघटकों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार की अत्यधिक और अनियोजित निकासी के कारण थी । सरकार के विस्तृत बजटीय घाटे के कारण सरकार को निवल बैंक ऋण और केन्द्रीय सरकार को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण दोनों में ही तीव्र वृद्धि हुयी । 1990-91 में भरपूर फसल के कारण खाद्य ऋण में तेजी से वृद्धि हुयी, जबकि खाद्य - भिन्न ऋण में कम वृद्धि हुयी । इस अवधि में विशेषकर वर्षान्त में भारतीय रिजर्व बैंक को आयातों के लिये बैंक वित्त पोषण को सीमित करने के लिये ऋण नीति सम्बंधी विशिष्ट तथा स्थायी उपाय किये, क्योंकि भुगतान सतुलन की स्थिति बिगड़ गयी थी, जिससे विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार में भारी कमी आ गयी थी ।

सामान्य ऋण नियंत्रण सम्बंधी उपायों में नकदी प्रारक्षित अनुपात को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी निवल मांग और सावधि देनदारियों के विद्यमान कानूनी 15 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी निवल मांग और सावधि देनदारियों की साविधिक नकदी अनुपात को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5 प्रतिशत कर दिया गया और इसे 22 सितम्बर, 1990 से प्रभावी बनाया गया, जो अनिवासी बाह्य खातों (रूपया) और पवदेशी मुद्रा अनिवासी खातों पर लागू नहीं किया गया। खातों की परवर्ती दो श्रेणियों के लिए साविधिक नकदी अनुपात को भी 28 जुलाई, 1990 को आरम्भ हुए पखवाड़े से 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। तिलहनो और खाद्य तेलों (वनस्पति को छोड़कर) के अग्रिमों के सम्बन्ध में 2 जुलाई, 1990 से चयनित ऋण नियंत्रणों को कठोर कर दिया गया, लेकिन गेहूँ के मामले में ऐसे नियंत्रणों को कम कर दिया गया । बाद में सुधरी हुई पूर्ति स्थिति को देखते हुए इन्हें समाप्त कर दिया गया । 10

अक्टूबर, 1990 से गेहूँ और दालों को छोड़कर धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन को भी एकदम 15 प्रतिशत बिन्दुओं तक नीचे लाया गया और 10 अक्टूबर, 1990 से पूर्व नियत स्तर पर उन्हें बनाए रखकर उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण 8 जनवरी, 1991 से बढ़ाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी, 1991 से निर्यात ऋण पुनर्वित्त को उदार बनाया गया। पुनर्वित्त 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर दिया गया।¹⁹

ब्याज दर ढाँचे को युक्ति युक्त बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब उसने 22 सितम्बर, 1990 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार दरों की एक नयी व्यवस्था लागू की और निर्यातों तथा विभेदक ब्याज दर योजना के अतिरिक्त अग्रिमों के लिये विशिष्ट, क्षेत्र-विशिष्ट और अचल विशिष्ट ब्याज दरों के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों की अग्रिमों के आकार से सम्बद्ध ब्याज दरों के रूप में बदल दिया गया। 1 जनवरी, 1991 से सम्बद्ध नकद ऋण ब्याज दर से अधिक 2 प्रतिशत बिन्दु पर ब्याज दर निर्धारित की गई है, ताकि हुडी प्रथा को प्रोत्साहन मिले।

1990-91 में सीमित मुद्रा (एम₁) में 22 मार्च, 1991 तक 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बृहत मुद्रा (एम₃) में भी सम्बद्ध अवधि में 15.1 प्रतिशत (रुपये 19,090 करोड़) की निम्न वृद्धि दर्ज की गयी, जो मुख्यतः 1990-91 में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंकों के ऋण में कम वृद्धि के कारण थी, और कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम के अन्तर्गत ऋणों की माफी के परिणाम स्वरूप थी। 1990-91 में माग जमा राशियों और मियादी जमा राशियों में भी महत्वपूर्ण कमी आयी। सरकार को निवल बैंक ऋण में 23 मार्च, 1991 तक रुपये 21,138 करोड़ का विस्तार दर्ज किया गया। 31 मार्च, 1990 से 22 मार्च, 1991 तक प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि की दर बहुत कम 6.0 प्रतिशत दर्ज की गयी। 1990-91 में सरकार को दिए गए निवल रिजर्व बैंक ऋण में रुपये 12,960 करोड़ (17.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए भारतीय रिजर्व

बैंक के ऋण में रुपये 837 करोड़ की अत्यधिक कमी आयी ।

बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के सम्बन्ध में अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 तक मझोले और बड़े उद्योगों को दिया जाने वाला अतिरिक्त ऋण रुपये 3841 करोड़ (100 प्रतिशत) था। इस अवधि में संचित अतिरिक्त सकल खाद्य-भिन्न ऋण रुपये 3,841 करोड़ (49 प्रतिशत) था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण में रुपये 1,716 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सरकारी खाद्य वसूली के लिये दिये गये ऋण में रुपये 2,532 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1990-91 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित ब्याज दरों के सम्बन्ध में उठाया गया अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार देने की दरों को युक्तिसंगत बनाना था। ब्याज की विभेदक दर कमजोर वर्गों के लिये 4 प्रतिशत तथा निर्यात ऋण के लिये दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये उधार दरों में संशोधन 22 सितम्बर, 1990 से लागू किया गया, जो कार्यशील पूँजी तथा अत्यधिक ऋण पर भी समान रूप से लागू होता है। वाणिज्यिक ब्याज दर रुपये दो लाख से ऊपर ऋण पर 16 प्रतिशत (न्यूनतम) बनाये रखी गयी, लेकिन रुपये 7,500 तक के लिये अग्रिमो पर न्यूनतम उधार की दर 10 प्रतिशत रखी गयी।²⁰ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 10 अक्टूबर, 1990 से ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू ब्याज दरों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति दी गयी - (1) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिये ऋण (2) व्यक्तियों को शेयरों और डिबेंचरों/बांडों के विरुद्ध ऋण (3) अन्य प्राथमिकता - भिन्न क्षेत्र के वैयक्तिक ऋण। इसके अलावा निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा निर्धारित करने का आधार वर्ष 25 अगस्त, 1990 से वित्तीय वर्ष 1988-89 कर दिया गया। मौद्रिक वृद्धि और निर्यात संवर्धन की सर्वोच्च आवश्यकता को देखते हुये। जनवरी, 1991 से पुनर्वित्त समानुपात को बढ़ा कर उपर्युक्त आधार की तुलना में निर्यात ऋण के स्तर में वृद्धि का 75 से 100 प्रतिशत कर दिया गया। इस वर्ष अपनाये गये सामान्य ऋण नियंत्रण के अन्य उपायों में, वृद्धिकारी खाद्य-भिन्न

ऋणजमा अनुपात को 60 प्रतिशत की व्यवस्था को जारी रखा गया । इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के ऋणकर्ताओं के लिए ऋण सीमाओं के अप्रयुक्त ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभार प्रारम्भ करना है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1990-91 में इसके ऋण प्रबन्ध में कीमत - संवेदनशील वस्तुओं के लिये बैंक ऋण के सबंध में चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों का उपयुक्त प्रयोग किया गया है। रूई तथा कपास पर बैंक अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन को 45 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया । 16 अप्रैल, 1990 से, ऋण की उच्चतम सीमा वाली वस्तुओं के सबंध में, उपर्युक्त 3 वर्षीय आधार अवधि 1986-87, 1987-88, 1988-89 (नवम्बर-अक्टूबर) को 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिये बढ़ा दिया गया, ताकि एक वस्तु विशिष्ट के विरुद्ध बैंक अग्रिमों के लिये ऋण की उच्चतम सीमा निर्धारित की जा सके । गेहूँ के विरुद्ध सभी बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन को कुल मिलाकर 15 प्रतिशत बिन्दु और कम कर दिया गया । रूई और कपास पर सभी अग्रिमों को 16 अप्रैल, 1990 से जुलाई, 1990 से लागू चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सभी प्रावधानों से छूट दे दी गयी । कड़े चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत तिलहन और वनस्पति सहित खाद्य तेलों के विरुद्ध बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 4 मई, 1990 और 2 जुलाई, 1990 से कुल मिलाकर लगातार दो बार 15 प्रतिशत बिन्दु बढ़ा दिया गया।

वर्ष 1990-91 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते हुये वित्त मंत्री द्वारा किसानों, दस्तकारों और बुनकरों के लिये ' ऋण राहत स्कीम ' के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गयी थी। घोषित निर्णय के अनुरूप भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 को अनुमोदित किया । 15 मई, 1990 से लागू ऋण राहत स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं - 21

(1) यह स्कीम बैंकों और सहकारी समितियों के सभी पात्र ऋणों के सबंध में लागू होगी ।

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के मामले में भारत सरकार उस ऋण राहत की राशि को वहन करेगी, जो इन सस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभग्राहियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) सहकारिताओं के सबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य सरकारों की स्कीमों के सबंध में व्यय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समान आधार पर वहन किया जायेगा।

(4) यह राहत ऐसे अनिच्छुक चूककर्ताओं को उपलब्ध होगी, जिन्होंने एक या अधिक बैंको से ऋण लिये थे, भले ही उधार ली गयी राशि की मात्रा कुछ भी क्यों न हो। लेकिन राहत की अधिकतम राशि प्रति पात्र लाभग्राही रुपये 10,000 पर सीमित होगी।

(5) लाभग्राही निर्धारित करने की तारीख 2 अक्टूबर, 1989 होगी। इस स्कीम के समाप्त होने की तारीख 31 मार्च, 1991 निर्धारित की गयी थी, किन्तु 30 जून, 1991 को समाप्त हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को समर्थन देने के लिये बैंको को विशेष रूप से अक्टूबर, 1990 में ठोस प्रयास करने की सलाह दी थी। अगस्त, 1990 से मियादी उधार देने वाली सस्थाओं द्वारा औद्योगिक वित्त के लिये ब्याज दर ढाँचे को और उदार बनाया गया, वित्तीय सस्थाओं को सावधि ऋण के लिये मूल ब्याज दर पहले जो 14 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी, इसमें संशोधन करके दो - स्तरीय ब्याज दर ढाँचा लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत पहले दो वर्षों के लिये अथवा परियोजना के पूरा होने तक (जो भी पहले हो) सावधि ऋणों पर ब्याज दर 14 प्रतिशत निर्धारित की गयी (स्तर प्रथम) और शेष अवधि के लिये मूल उधार दर 15 प्रतिशत होगी (स्तर द्वितीय)।²²

1990-91 में वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सस्थागत विकास, लघु उद्योगों के लिये शीर्ष बैंक के रूप में 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' की स्थापना रहा। इस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। इसने 2 अप्रैल, 1990 से रुपये 4,200 करोड़ के निवेश से अपना कामकाज प्रारम्भ किया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से लघु उद्योग विकास

निधि तथा राष्ट्रीय इक्विटी निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व सभाल लिया ।

वर्ष 1991-92 अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से स्थिर करने और मूलभूत सुधारों को लागू करने के लिये दृढ़ नीतिगत उपायों को प्रारम्भ करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवधि थी। इस अवधि के दौरान विशिष्ट साख नीतिगत उपायों के चार प्रमुख तत्व थे। उपायों के प्रथम समूह का लक्ष्य आयात को सीमित करना था । आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने के बजाय नकदी मार्जिन लागू करके (जो एक समय 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के दायरे में रहा) तथा 25 प्रतिशत ब्याज दर अधिभार लगाकर आयात वित्तपोषण की लागत में वृद्धि करने जैसे उपायों को आयात सीमित रखने का भेदभाव रहित तरीका माना गया। उपायों का दूसरा समूह, जो प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण की उपज है, भुगतान सतुलन में चालू लेखा खाते को सीमित रखने के लिए उठाया गया है । आय के किसी विशेष स्तर के लिए, व्यय में कटौती अथवा समावेशन का निश्चय ही यह अर्थ है कि व्यवस्था की समग्र मौद्रिक मांग साथ ही मुद्रास्फीति को भी कम किया जाए । लेकिन समग्र मांग तथा मुद्रा स्फीति में कटौती से ही भुगतान सतुलन की स्थिति में तुरत सुधार नहीं हो जाता है। उन्हें व्यवस्था की विभिन्न कड़ियों के माध्यम से कार्य करना होता है तथा उसे आय में से आयात के प्रति मामूली - से लगाव जैसे मानदण्डों पर निर्भर रहना पड़ता है । राजकोषीय घाटे को सीमित रखने के साथ - साथ मुद्रा और ऋण की तंगी का यह परिणाम भी होता है कि इससे मुद्रास्फीति के नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के अलावा ससाधनों के उपयोग में अधिक मितव्ययिता आती है । उपायों की तीसरा समूह विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में कुछ गिरावट के फलस्वरूप आया । उन उपायों में आयातों पर नकदी मार्जिन संबंधी शर्तों का हटाया जाना तथा बड़े उधारकर्ताओं के मामले में उधार पर ब्याज दरों को उसी प्रकार थोड़ा कम किया जाना शामिल है । उपायों का अन्तिम समूह सरकार द्वारा किये गये राजकीय समायोजन तथा व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण तथा सरचनात्मक समायोजन के मेल से उत्पन्न हुआ, जिसके सदर्थ में यह व्यवहार्य समझा गया कि नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात दोनों में सांविधिक

पूर्वक्रयाधिकार के स्तर को कम किया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र को सुधारने के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में वित्तीय प्रणाली पर गठित नरसिंहम समिति ने बैंकों के ससाधनों के पूर्वक्रयाधिकार में कटौती करने की सस्तुति की। इसके जवाब में सरकार अपनी उधार संबंधी जरूरतों को बैंकों के ससाधनों के पूर्वक्रय के बजाय, ज्यादा से ज्यादा बाजार से पूरा करने पर सहमत हो गयी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित करने के समग्र प्रयास के एक अंग के रूप में भारत सरकार ने दो नयी लिखते अर्थात् 364- दिवसीय खजाना बिल और 5 और 10 वर्षीय दिनकित प्रतिभूति दोनों नीलामी आधार पर जारी की, ये लिखते भी मौद्रिक नियंत्रण लागू करने के बेहतर साधन विकसित करने की दिशा में बढ़ने के लिए एक प्रमुख आधार प्रदान करेगी। उधार की ब्याज दरों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जाना तथा जमाराशि की परिपक्वता अवधि और जमाराशि पर ब्याज दर निर्धारित करने के संबंध में बैंकों को दी गयी पर्याप्त स्वतंत्रता भी उक्त सुधार कार्यक्रम के अंग हैं।

1991-92 के मौलिक लक्ष्यों को रेखांकित करने वाली व्यापक अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख परिकल्पनाएँ थीं- सकल देशी उत्पाद की वृद्धि 3 से 3.5 प्रतिशत तक, मुद्रास्फीति की दर 9 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा एम₃ के विस्तार में लगभग 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी। आयात संबंधी दबावों, ऋण सम्बन्धी तथा राजकोषीय समायोजन - उपायों का समग्र वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ा तथा इस स्थिति में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि 2.0 प्रतिशत से थोड़ी कम रह गयी और विशेषकर औद्योगिक उत्पादन में पूर्णतः अवरोध बना रहा। ऐसी स्थिति में भी 1991-92 में एम₃ का विस्तार 18.5 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिसके कारण थे - प्राथमिक चलनिधि में देशी विस्तार और प्रयोजित स्तर की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन। चूंकि विदेशी मुद्रा के आगम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी, अतः इन ससाधनों के आगम को रोकने वाले उपाय नहीं किये गये, ताकि कहीं ऐसा न हो कि इन उपायों से ऐसे आगमों में कमी आ जाए। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990-30 जून, 1991 को समाप्त हो गयी प्राप्त आकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा रुपये 7,917 करोड़ का ऋण राहत प्रदान किया गया, जिसमें से वर्णित बैंकों ने रुपये 2,962 करोड़, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने रुपये 808 करोड़ और सहकारी बैंकों ने रुपये 4,147 करोड़ प्रदान किये।

कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को पुनर्जीवित करने तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में मुद्रास्फीति नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1992-93 की प्रथम छमाही की मौद्रिक एवं साख नीति बनायी गयी । सकल राजकोषीय घाटे को 1991-92 में सकल देशी उत्पाद के 6.5 प्रतिशत से घटाकर 1992-93 में सकल देशी उत्पाद के 5 प्रतिशत पर लाने के सरकार के घोषित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति तैयार की गयी थी । समग्र नीति का उद्देश्य है मुद्रास्फीति की दर को कम करके 8 प्रतिशत तक लाना । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने बजट घाटे (और मुद्रीकृत घाटे) को कम करके उसे 1992-93 में रुपये 5,389 करोड़ तक लाने की योजना बनायी है । मुद्रीकृत घाटे में कटौती का पूरा असर मुद्रास्फीति के कम होने पर पड़े इसके लिए यह माना गया कि मुद्रीकृत घाटे को न केवल वित्त वर्ष के अंत में बल्कि पूरे वर्ष भर में कम रखा जाना चाहिए ।

आलोच्य अवधि के दौरान मौद्रिक और साख नीतिगत महत्वपूर्ण उपायों को तर्कधार नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

(1) बैंक दर मौद्रिक नीति के एक साधन के रूप में बैंक दर निष्क्रिय रही थी तथा जुलाई, 1981 से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । मुद्रास्फीतिकारी दबावों तथा रिजर्व बैंक की आधारभूत दर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए यह उपयुक्त समझा गया कि बैंक दर के (नियंत्रणकारी) साधन को सक्रिय किया जाये । तदनुसार 3 जुलाई, 1991 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर को 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत वार्षिक और 8 अक्टूबर 1991 को कारोबार की समाप्ति से इसे और अधिक बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया ।

आलोच्य अवधि में उधार पर ब्याज की दरों में चार बार संशोधन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दरों से अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित मुद्रास्फीति की झलक मिले और ब्याज दरों को धनात्मक बनाने की आवश्यकता थी । पहले यह मानते हुए कि मौजूदा अधिक मुद्रास्फीतिकारी दबावों के सदर्थ में कई उधार पर ब्याज की दरें वास्तविक रूप में नकारा हो गयी हैं,

अनुसूचित वाणिज्य बैंको के उधार पर ब्याज की दरों में 9 अक्टूबर 1991 से 15 प्रतिशत बिन्दुओं की एक समान वृद्धि कर दी गयी। तीसरे, चूंकि 2 लाख रुपये से अधिक की ऋणसीमा के लिए न्यूनतम उधार पर ब्याज की दर अप्रैल, 1991 और अक्टूबर, 1991 के बीच 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी थी, मुद्रास्फीति की दर में कुछ गिरावट को देखते हुए सावधानी पूर्वक 2 मार्च, 1992 से 2 लाख रुपये से अधिक ऋण सीमा वाले उधारकर्ताओं के लिए उधार पर ब्याज की दर में 1 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी कर दी गयी, अतः बैंको की उधार की ब्याज दर संरचना को क्रमिक रूप से युक्तियुक्त बनाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में 22 अप्रैल 1992 से उधार पर ब्याज की दरों की मौजूदा छ श्रेणियों को घटाकर चार कर दिया गया।²³

अनिवार्यतः बैंक जमा राशियों पर धनात्मक वास्तविक ब्याज दर उपलब्ध कराने हेतु आलोच्य अवधि में बैंको की जमा राशियों पर ब्याज दर संरचना में कुछ एक संशोधन हुए। पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंको ने अपने उधार कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था अपने निजी ससाधनों से की है तथा वैकल्पिक बचत साधनों की प्रतिस्पर्धा के लिए बैंको को तैयार करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंको की सावधि जमा राशि दरों में सभी स्तरों पर 4 जुलाई, 1991 से एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की गई है। एक वर्ष और अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम की जमा राशियों के लिए ब्याज दरें 12 प्रतिशत वार्षिक हो गयीं। 3 वर्ष और अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशियों की ब्याज दरें 13 प्रतिशत वार्षिक पर अपरिवर्तित बनी रही। अब बैंको को यह छूट है कि वे परिपक्वता अवधि तथा जमा राशियों पर ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक की एकल निर्धारण सीमा के अन्तर्गत निर्धारित कर लें। बचत जमा राशि पर ब्याज दरों को 4 अप्रैल, 1992 से एक प्रतिशत अंक बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। वर्ष 1991-92 के पूर्वार्द्ध तक, जब आयातों को सीमित रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, मुद्रा नीति संबंधी उपायों में क्रमिक रूप से सख्ती की गई। निर्यातों को बढ़ाने की महती आवश्यकता और बैंको को निर्यात ऋण देने के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण पुनर्वित्त फार्मूला को उदार बनाया गया और इस सुविधा के अन्तर्गत बैंको को निधियों की उपलब्धता भी बढ़ायी गई। भारत में प्रारक्षित राशि की अपेक्षाये चलनिधि नियन्त्रण के लिए एक प्रमुख साधन रही है। सांविधिक चलनिधि अनुपात,

जिसे यद्यपि मूलतः विवेक सम्मत उपाय के रूप में स्वीकार किया गया था, आंशिक रूप में सरकार को उधार की आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार आधारित दरो से कम दर पर करने का उद्देश्य पूरा करता रहा है । प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में लगातार वृद्धि के कारण यह साधन प्रति उत्पादक के रूप में उभर रहा था, क्योंकि इससे बैंकों की लाभप्रदता भी प्रभावित होती है । श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित वित्तीय प्रणाली पर समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सांविधिक चल-निधि अनुपात को चरणबद्ध तरीके से कम किये जाने की सिफारिश की थी । सरकार द्वारा किये गये राजकोषीय समायोजन और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के संदर्भ में यह व्यवहार्य समझा गया कि सांविधिक पूर्वक्रयाधिकार में वर्तमान स्तरों को तर्कसंगत बनाया जाये । नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की थी कि मौद्रिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात का प्रयोग जारी रखा जाए यद्यपि यह अनुभव किया गया कि इसका वर्तमान स्तर काफी ऊँचा है और इन्हें कम करने की आवश्यकता है । वर्ष 1991 के पूर्वार्ध की गम्भीर अवधि के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को मई, 1991 में लागू किया गया । यह अनुभव किया गया कि 15 प्रतिशत के औसत अनुपात के साथ-साथ 10 प्रतिशत वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात को जारी रखा जाना ज्यादा अवधि तक उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे उत्पादक क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में अवरोध होगा । बैंकों की लाभप्रदता को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से नकदी प्रारक्षित अनुपात बढ़ाया गया है और साथ ही नकदी शेष राशियों पर ब्याज भी बढ़ाया गया है । चूँकि नकदी शेष राशियों पर ब्याज की अदायगी से मौद्रिक नियंत्रण कम होता है, अतः नकदी प्रारक्षित निधि को और भी बढ़ाना पड़ा । यदि नकदी शेष राशियों पर ब्याज नहीं अदा किया गया होता, तो उसी स्तर पर मौद्रिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात को बहुत कम दर पर निर्धारित किया जा सकता था । वित्तीय वर्ष 1991-92 के पूर्वार्ध के लिए साख नीति के तौर पर बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि वर्ष 1991-92 में उनका वृद्धिशील निवल खाद्येतर ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक नहीं हो । समस्त बैंकिंग प्रणाली ने वर्ष 1991-92 से इन मानदण्डों को अपनाया और पहले जैसा वृद्धिशील निवल खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात के निर्धारण को जारी रखना 1992-93 के लिए आवश्यक नहीं माना

गया । तदनुसार अप्रैल, 1992 में वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात का निर्धारण वापस ले लिया गया । बैंको को यह सलाह दी गई कि वे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादक गतिविधियों को पुनर्चालू करने, विशेषकर छोटे किसानों लघु उद्योगों और निर्यातों की आवश्यकताओं के लिए समर्थन देने हेतु अपनी ऋण सुविधाओं को सामान्य करें । मुद्रास्फीति के तीन दबावों के संदर्भ में प्रारक्षित मुद्रा विस्तार को नियंत्रित करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9 अक्टूबर, 1991 से कुछ पुनर्वित्त सुविधाएँ वापस ले ली गई हैं । ये हैं - खाद्य वस्तुओं के लिए ऋण का पुनर्वित्त, वैकल्पिक पुनर्वित्त, 182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त और विवकाधीन पुनर्वित्त । इस प्रकार निर्यात ऋण पुनर्वित्त के अतिरिक्त कोई और पुनर्वित्त अब भारतीय रिजर्व बैंक से बैंको को उपलब्ध नहीं है । 9 अक्टूबर, 1991 से प्रणाली बैंको से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक को बकाया ऋणों में कोई वृद्धि नहीं हो ।

- (1) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण
- (2) अन्य गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तिगत-ऋण
- (3) शेयरों और डिबेंचरों/बांडों के एवज में व्यक्तियों की ऋण और
- (4) अचल सम्पत्ति पर ऋण ।

बैंकों के स्रोतों पर दबावों को कम करने एवं औद्योगिक उत्पादन की उगाही को सुविधाजन्य बनाने के संदर्भ में दिनांक 22 अप्रैल, 1992 से प्रथम दो श्रेणियों के ऋणों पर से प्रतिबंध हटा लिए गये, जबकि अन्य दो पर प्रतिबंध लागू रहे । इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे दिनांक 22 अप्रैल, 1992 से शेयर और डिबेंचरों/बांडों पर व्यक्तिगत ऋण पर 75 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन निर्धारित करें । इस वर्ष मुद्रा बाजार म्युचल फंड की एक नयी योजना प्रारम्भ की गयी । श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार को इस तरह पुनर्गठित किया जा रहा है, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों पर ऋण के लिए सरकार की निर्भरता कम हो । यह मुद्रा नियंत्रण के एक साधन के रूप में कार्य करेगा, जिसमें ब्याज दरों में लचीलापन, नयी लिखतों को प्रारम्भ किया जाना, खुले बाजार के क्रियाकलापों द्वारा चल-निधि विस्तार/सकुचन किया जायेगा ।

व्यापक मुद्रा (एम₃) तथा सकीर्ण मुद्रा (एम₁) दोनों में 1991-92 में काफी अधिक मौद्रिक विस्तार हुआ। एम₃ में पिछले वर्ष के रुपये 34,878 करोड़ (15.1 प्रतिशत) की तुलना में रुपये 49,256 करोड़ (18.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 1991-92 में एम₃ में हुई वृद्धि वर्ष के बृहद आर्थिक उद्देश्य तैयार करते समय निर्धारित 13 प्रतिशत की वांछित वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये निवल रिजर्व बैंक ऋण में भी पिछले वर्ष के रुपये 20,065 करोड़ (13.2 प्रतिशत) की तुलना में रुपये 19,296 करोड़ (11.2 प्रतिशत) की न्यूनतम वृद्धि हुई। प्रारक्षित मुद्रा में 1990-91 के रुपये 10,188 करोड़ (13.1 प्रतिशत) की तुलना में 1991-92 में रुपये 11,730 करोड़ (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की निवल देशी आस्तियों में पिछले वर्ष के रुपये 8,273 करोड़ (11.6 प्रतिशत) की तुलना में 1991-92 में रुपये 875 करोड़ (1.1 प्रतिशत) की अत्यंत कम वृद्धि हुई। 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार को एनडीए तथा निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण में वृद्धि करने के लक्ष्य पूर्णतः पूरे हो गये। सकल जमा राशियों का विस्तार 1990-91 के रुपये 25,583 करोड़ (15.3 प्रतिशत) के स्तर से बढ़कर रुपये 38,216 करोड़ (19.8 प्रतिशत) हो गया और वह 1991-92 की दूसरी छमाही की ऋण नीति में घोषित रुपये 28,500 करोड़ के सशोधित कार्यकारी अनुमान को पार कर गया। 1991-92 में बैंक जमा राशियों में तीव्र वृद्धि हुयी और 1992-93 की पहली तिमाही में भी जमा राशियों में वृद्धि की गति बनी थी। इस अवधि में बैंकिंग परिवर्ती दरों को सारणी 4.13 में स्पष्ट किया गया है।

इस अवधि में सकल जमा राशियों में तीव्र विस्तार के बावजूद कुल बैंक ऋण में विस्तार की गति उल्लेखनीय रूप से कम रही। वर्ष भर में खाद्यान्नों की वसूली में गिरावट तथा अधिक निकासी, जिसकी वजह से उनके स्टॉक के स्तरों में तीव्र गिरावट आयी, के कारण खाद्य ऋण का विस्तार 1990-91 के रुपये 2,500 करोड़ की तुलना में रुपये 164 करोड़ पर साधारण रहा। प्रतिबद्धात्मक ऋण नीतिगत उपाय और अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट तथा ऋण की बढ़ती हुई लागत से खाद्योत्तर ऋण में कम विस्तार हुआ और यह 1990-91 के रुपये 12,348 करोड़ (12.4

सारणी 4 13

बैंकिंग परिवर्ती वृद्धि दरें

(प्रतिशत में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अप्रैल-जून)
सकल जमाराशिया	14 9	18 7	19 1	15 3	19 8	4 5
माग जमाराशिया	5 3	15 3	24 6	15 0	35 8	0 4
सावधि जमाराशिया	17 1	19 4	18 2	15 4	16 5	5 6
बैंक ऋण	11 4	20 1	19 8	14 6	8 0	6 5
खाद्य ऋण	57 1	64 9	160 9	124 6	3 6	9 2
खोद्योत्तर ऋण	17 4	22 8	18 5	12 4	8 2	6 4
निवेश	20 5	17 5	17 8	16 6	20 2	4 5

Source - Reserve Bank of India, Annual Report, 1991-92.

प्रतिशत) तथा 1989-90 के रुपये 15,497 करोड (18 5 प्रतिशत) की तुलना में रुपये 9,127 करोड (8 2 प्रतिशत) रहा ।

जुलाई 1991 से प्राधिकारियों ने स्थिरीकरण और सरचनात्मक समायोजन दोनों के लिए तीव्र गति और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य किया । राजकोषीय स्थिति को ठीक करने, विनिमय दर के समायोजन और सुधार, मौद्रिक लक्ष्यों तथा मद्रा-स्फीति नियंत्रण आदि ने तुरत उपायों का रूप धारण किया, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता आ सके । इस प्रकार वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गयी सरचनात्मक समायोजन और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया को 1992-93 में समेकित किया गया। सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की जिस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया था, उससे अर्थव्यवस्था को गति

मिली है। यद्यपि एक वर्ग ऐसा भी है जो इन आर्थिक सुधारों का प्रभाव स्थिर या नकारात्मक मानता है, क्योंकि इन आर्थिक सुधारों के बाद भी औद्योगिक मन्दी बरकरार रही। इसका कारण यही था कि आर्थिक सुधार जिस गति से प्रभावी हो रहे थे, वित्तीय सुधार उस अनुपात में धीमे थे। वित्तीय सुधारों के बिना आर्थिक सुधारों का वांछित परिणाम संभव नहीं था। औद्योगिक मन्दी समाप्त करने के लिए वित्तीय सुधार भी आवश्यक था। इसी दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री सी० रंगराजन ने वित्तीय वर्ष 1993-94 की द्वितीय छमाही के लिए 11 अक्टूबर 1993 को नई मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा की।

घोषित नई नीति में वैधानिक तरलता अनुपात में कमी की गई है। यह कमी वर्तमान 37.25 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत घटाकर 34.75 प्रतिशत कर दिया गया है। वैधानिक तरलता की यह दर 16 अक्टूबर, 1993 से लागू होगी तथा यह घटी हुई दर 17 सितम्बर, 1993 तक की देनदारी के स्तर पर लागू मानी जायेगी। यदि 17 सितम्बर 1993 के बाद देनदारी में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो तरलता अनुपात 30 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत होगा। इससे बैंकों की व्यवसायिक पूँजी में रुपये 4150 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। 7 अप्रैल, 1993 को तरलता अनुपात में की गई कमी से घटी राशि को निकाल दिया जाय तो यह बढ़ोत्तरी रुपये 3050 करोड़ के बराबर बैठती है। सरकार ने 7 अप्रैल, 1993 को एक घोषणा के माध्यम से वैधानिक तरलता अनुपात को तीन वर्ष में घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने का निर्णय किया था। अप्रैल में घोषित मौद्रिक एवं साख नीति के तहत इसे चार चरणों में 37.75 प्रतिशत से घटाकर 36.75 प्रतिशत तक लाना था। इसके पहले और दूसरे चरण को पहले ही व्यवहार में लाया जा चुका है, किन्तु अब नये निर्णय से ये स्वतः स्थगित हो जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह की पहली कटौती जनवरी-मार्च, 1992 में की थी, तब तरलता अनुपात की दर बहुत ऊँची थी, लगभग 38.5 प्रतिशत। बैंकों को अपनी जमा पूँजी का इतना भाग रिजर्व बैंक में जमा रखना पड़ता था, किन्तु इस छूट से बैंकों को अपना घाटा पूरा करने में मदद मिल सकती है। नई नीति में दूसरा परिवर्तन प्राथमिक क्षेत्रों के सन्दर्भ में किया गया है। इन क्षेत्रों को कर्ज देने की नीति में बदलाव हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रों को मिलने वाले ऋण में से 18 प्रतिशत हिस्सा कृषि का होता है। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह की

कृषि शामिल है । नई व्यवस्था के तहत प्रावधान किया गया है कि परोक्ष कृषि को मिलने वाला ऋण कृषि क्षेत्र के कुल ऋण के 25 प्रतिशत से अधिक न हो । इस नीति में यह छूट दी गई है कि गेहूँ और कपास के लिए ऋण लेने वालों पर अब तक लागू कुछ नियन्त्रणों का कोई प्रावधान नहीं होगा। धान के लिए ऋण पर मार्जिन में 15 प्रतिशत की कमी की गई है और ऋण सीमा 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई है । तिलहन और बिनौले के लिए बैंक मार्जिन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लदान पूर्व निर्यात कर्ज के लिए विदेशी मुद्रा में ऋण उपलब्ध करने की सुविधा दी है । निर्यातकों को दी जाने वाली इस ऋण की सीमा 90 प्रतिशत तक होगी । पहले यह सीमा 100 प्रतिशत तक थी । इसके अतिरिक्त कम्पनियों को तीन महीने से एक साल में पूर्ण भुगतान के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति भी दी गई है, जिससे वे बैंक ऋणों पर ही निर्भर न रहे । प्रवासी भारतीयों के रूपया मुद्रा खातों पर ब्याज दर 1 प्रतिशत घटा दिया गया है । विदेशी मुद्रा खाता योजना के अन्तर्गत एक साल से अधिक और 2 साल से कम की अवधि में परिपक्वता गारन्टी के अन्तर्गत निकाली जाने वाली धनराशि को योजना को समाप्त कर दिया गया है । यह 12 अक्टूबर 1993 से प्रभावी हो गई ।

कृषि क्षेत्र को अधिक साख, ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 'नाबार्ड' की ऋण सीमा बढ़ा दी गई है । यह बढ़ोत्तरी रुपये 400 करोड़ की होगी अर्थात् वर्तमान रुपये 3300 करोड़ से बढ़कर यह धनराशि रुपये 3700 करोड़ हो गई है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि बैंक व्यापारिक कर्जों के लिए बहुत अधिक ब्याज दर न वसूले । बैंक रुपये दो लाख से अधिक कर्ज पर ब्याज - दर स्वयं तय करने के लिए स्तन्त्र हैं, किन्तु इस सन्दर्भ में तर्क सगत एवं सकारात्मक माप दण्ड अपनाए जाने की आवश्यकता है । यह बैंक प्रबन्धक का दायित्व है कि वे इस तरह व्यवस्था करें, जिससे ऋण स्वीकृत करने के अधिकारों का औचित्य पूर्ण उपयोग हो । बैंकों को कर्ज के लंबित प्रस्तावों और नवीकरण के लिए पड़े प्रस्तावों को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के भीतर निपटा देना चाहिए ।

इस तरह यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में मौद्रिक एवं साख नीति पूर्व घोषित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अनुरूप नरसिंहम् समिति की सत्तुतियों को दृष्टि में रखते निर्माण किया जा रहा है ।

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति

(MONETARY AND CREDIT POLICY OF RBI FOR AGRICULTURE
AND RURAL SECTOR)

प्रस्तुत अध्याय में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा एवं साख नीतियों का विवेचना किया जायेगा । यह आवश्यक होगा कि प्रारम्भ में हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति को स्पष्ट कर दें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों में साख नीति के निर्माण हेतु उपयोगी होगा । कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों का विवरण देना भी आवश्यक होगा, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु साख प्रदान करती है। इस विश्लेषण के साथ भारत में कृषि-साख व्यवस्था की विवेचना भी महत्वपूर्ण होगी । इन विश्लेषणों के साथ कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा एवं साख नीति की विवेचना कृषि साख हेतु की जायेगी ।

5 । ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा कृषि वित्त

भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या काफी लम्बे समय से चली आ रही है। ग्रामीणों एवं कृषिकों पर साहूकारों एवं जमींदारों द्वारा दिए गये ऋण का भारी बोझ है । यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, साथ ही साथ ब्याज भी बढ़ता रहता है। यह अनुत्पादक ऋण होता है। हेनरी वोलफ के अनुसार, यह देश महाजनों की मुट्ठी में है। यह कर्ज का बन्धन ही है कि कृषि का विकास रुकी हुई सी अवस्था में है । अधिकांश कृषक परिवारों के लिए आज भी ऋणग्रस्तता एक समस्या बनी हुई है । 1875 में डेकन रैयट्स कमीशन ने अनुमान लगाया था कि देश का एक तिहाई किसान ऋण ग्रस्त है और प्रति व्यक्ति औसतन ₹0 371 कर्ज है।¹ एडवर्ड मैकलेन ने सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए ग्रामीण ऋण का अनुमान ₹0 300 करोड़ लगाया था ।²

1. Deccan Ryots Commission Report, p. 29.

2. Bombay Banking Enquiry Committee Report, p. 58.

ग्रामीण ऋणग्रस्तता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसी रूप में बनी थी और आज भी यह समस्या भयावह रूप से विद्यमान है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 'ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे' में 1951-52 में अपनी एक जाच में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, जिसमें से मुख्य बातें हैं ³- पहला, ग्रामीण क्षेत्र में ऋणग्रस्त परिवारों का अनुपात 51.7 प्रतिशत है। दूसरा, ग्रामीण परिवारों का लगभग 63 प्रतिशत ऋणग्रस्त है और प्रति परिवार औसतन ₹ 283 का ऋण है। तीसरे, बड़े जोत के किसानों की तुलना में छोटी जोत के किसानों पर ऋण का भार बहुत अधिक है। चौथे, बिना चुकता कर्ज प्रति परिवार ₹ 29 से ₹ 1,200 के बीच है ।

'आल इण्डिया रूरल डेब्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्वे 1961-62' के अनुसार, सम्पूर्ण देश में प्रति परिवार औसतन ₹ 654 का कर्ज है । 30 जून, 1962 को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में ₹ 2,779 करोड़ ग्रामीण ऋण का अनुमान लगाया गया अर्थात् लगभग 75 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त थे । 1971 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव था, को छोड़ कर शेष भारत में लगभग 70 प्रतिशत किसान ऋणग्रस्त थे । 1971-72 में भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वे 'आल इण्डिया रूरल डेब्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट' के अनुसार लगभग 43 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त थे, जब कि 1961-62 में लगभग 63 प्रतिशत लोग ऋणग्रस्त थे, 1971-72 के सर्वे में दिखाया गया है कि जून 1971 में कुल ग्रामीण ऋण ₹ 3848 करोड़ था । यू0 एन0 आई0 के सर्वे (1975) यह प्रदर्शित करता है कि लगभग 65 से 70 प्रतिशत छोटे किसान, ग्रामीण हरिजन और आदिवासी ऋणग्रस्त हैं, और ग्रामीण साहूकारों, महाजनों द्वारा स्वतंत्र रूप से उनका शोषण किया जा रहा है इस सर्वे के अनुसार, प्रति परिवार औसतन ₹ 250 से ₹ 500 के बीच ऋण था ।

ग्रामीण क्षेत्र और विशेषकर किसानों में ऋणग्रस्तता की समस्या होने का मुख्य कारण है, कृषि उपज का स्तर और किसानों का आय स्तर नीचा है, जिससे वे अपने उपभोग सम्बंधी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाते । जब तक किसानों की आय में वृद्धि नहीं होगी, तब तक किसान ऋणग्रस्त ही रहेंगे । ऋणग्रस्तता एक ऐसा रोग है, जिसका प्रभाव सिर्फ

किसानों के आर्थिक जीवन पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उनके सामान्य तथा नैतिक जीवन पर भी पड़ता है। कृषक हमेशा ऋण के भार से दबे रहने के कारण मशीनों, अच्छे बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करने में अपने को असमर्थ पाता है, अर्थात् साधनों का अभाव रहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसकी उत्पादिता पर पड़ता है। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता के अनेक कारण हैं, जिनमें से अधिकांश कारण परंपरागत हैं। इनमें से मुख्य कारण निम्नलिखित हैं -

(1) **पैतृक ऋण** - ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण पैतृक ऋण है, जो उचित प्रतिबन्ध के अभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होता रहता है। उत्तराधिकारियों को ऋण तभी चुकाना पड़ता है, जब कि यह मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति भी लेता हो और वह भी ऋण सीमा या देन दारी प्राप्त सम्पत्ति के मूल्य तक ही सीमित रहता है।

(2) **कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन** - कृषि क्षेत्र के उपविभाजन तथा अपखंडन के कारण उनके जोतों का आकार पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे होते जा रहे हैं, जिसके कारण उससे प्राप्त उत्पादन उनके जीवन निर्वाह के लिए भी कम पड़ता है, ऐसे में कोई अतिरिक्त खर्च उन्हें कर्जदार बना देता है। डार्लिंग के अनुसार⁴ बिना ऋण लिए एक छोटे जोत द्वारा एक कृषक को अपने परिवार को पालने के लिए चतुराई परिश्रम एवं अल्पव्यय का सहारा लेना पड़ता है। अन्यथा वह ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाता है।

(3) **कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति** - दयनीय आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप कृषक नवीन तकनीक को अपना नहीं पाते और अल्प उत्पादिता पर ही उन्हें सतोष करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उपभोग ऋण कृषकों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे उत्पादन और उत्पादिता वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

4. Darling, M.L. - Peasantry in Prosperity and Debt
p. 262.

- (4) **कृषि पर जनसंख्या का अतिभार** - हमारे देश में जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वह सभी क्षेत्रों के लिए खतरनाक है, ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का भार और भी बढ़ता जा रहा है। जिससे प्रतिव्यक्ति आय में लगातार कमी होती जा रही है।
- (5) **सामाजिक रीति-रिवाज** - विवाह, धार्मिक उत्सव, जन्म, मृत्यु आदि ऐसे सामाजिक रीति-रिवाज हैं, जिन पर कृषक काफी अधिक धन अनावश्यक एवं अनुत्पादक व्यय करता है। इस अतिरिक्त खर्च के लिए एक गरीब किसान एवं खेतिहर मजदूर ऋण लेने के लिए विवश हो जाता है।
- (6) **कृषकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा** - अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। अशिक्षा किसानों की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है। अपनी अज्ञानता के कारण किसान बड़ी असानी से धूर्त एवं चतुर महाजनों के चंगुल में फस जाते हैं।
- (7) **कृषि का प्राकृतिक साधनों पर निर्भरता एवं दैविक प्रकोप** - भारत में अधिकांश कृषि अब भी वर्षा पर निर्भर रहती है। बाढ़, अग्नि, सूखा, तूफान, टिड्डी दल आदि के आक्रमण से बचाव के लिये एक गरीब कृषक कृत्रिम साधनों का उपयोग करने के लिए ऋण का सहारा लेता है। एक छोटे जोत का कृषक केवल तभी ऋण से मुक्त रह पाता है, जिस वर्ष कोई प्राकृतिक आपदा न हुई हो।⁵
- (8) **उच्च ब्याज दर के कारण** - ग्रामीण महाजनों की ब्याज की उंची दर भी कृषक को उधार लेने के लिए विवश करता है, क्योंकि वे ब्याज के भुगतान के लिए पुनः ऋण लेते हैं। यह ब्याज दर भी अलग - अलग स्थानों में अलग - अलग है और आवश्यकतानुसार तय होता है।

(9) **महाजनों के ऋण देने के मनमानी तरीके** - कृषि कृति की पूर्ति मुख्यतः ग्रामीण सेठ, महाजनों और साहूकारों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत से ग्रामीण कृषकों का महाजनों के यहाँ चालू खाता खुला रहता है। वे गरीब किसानों की सदैव वित्तीय मदद करते हैं, बदले में हमेशा के लिए महाजनों के चंगुल में फँस जाते हैं और महाजन उनका शोषण करते रहते हैं।

(10) **भूमि एवं सिंचाई पर उँचे कर** - सरकार की भूमि राजस्व नीति भी ऋणग्रस्तता के लिए जिम्मेदार है। किसान को अपने उत्पादन से इतनी आय नहीं प्राप्त होती कि उँचे कर का भुगतान कर सके। इस कर को भरने के लिए किसान को ऋण लेना पड़ता है।

(11) **पर्याप्त विपणन सुविधा का अभाव** - भारतीय किसानों के लिए अब भी ऐसा बाजार उपलब्ध नहीं है, जहाँ उनके उत्पादन का उचित मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके। उनसे साहूकार या बणिये बहुत ही निम्न दर पर उनके उत्पादन खरीद लेते हैं और अभाव या जरूरत के समय इन्हीं किसानों को वे उँचे दर पर बिक्री करते हैं।

उपर्युक्त के अलावा अन्य बहुत से क्षेत्रीय कारण भी होते हैं, जो एक कृषक को ऋणग्रस्त बना देते हैं। चूँकि ज्यादातर ये ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिये होते हैं अतः इनकी अदायगी समय से नहीं हो पाती है और न ही इनका आर्थिक विकास में कोई योगदान होता है। प्रो० पी० ए० वाडिया के अनुसार किसानों की आय का कोई अतिरिक्त स्रोत न होने के कारण वे हर मौसम में उधार लेते रहते हैं, इस प्रत्याशा से कि उनकी ऋणग्रस्तता कम हो जायेगी। भारतीय किसानों के बारे में यह कहा जाता है कि उनको महाजन उधार लेने के लिये, वकील झगडा करने के लिये और व्यापारी फिजूल खर्ची करने के लिये उकसाते हैं।

चूँकि कृषि हेतु साख आवश्यक है, अतः यह महत्वपूर्ण है कि साख सस्ता और सुरक्षित हो। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं का यह फर्ज हो जाता है कि वह उन सभी सावधानियों को बरतें, जिससे कृषि साख निर्धारित लक्ष्य तक सस्ते सुरक्षित और उत्पादक रूप में हों।

सामान्यतया कृषकों को साख की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है -

पहला, कृषकों को दीर्घकालीन विनियोग के लिए यथा, भूमि क्रय, भूमि में स्थायी सुधार करने, जल निकासी व्यवस्था करने, मेड-बंदी करने, नये पम्पसेट एवं अन्य सिंचाई सुविधाओं को प्राप्त करने तथा उन्हें अधिक उत्पादक बनाने हेतु एक निश्चित पूँजी की आवश्यकता हो सकती है ।

दूसरा, मध्य कालीन उपकरण साख पशुओं, उपकरणों, मशीनरी के क्रय करने तथा कुआ आदि खोदने, पम्पसेट लगाने, डेयरी, मुर्गी पालन, पौध-रोपड़ आदि के लिए आवश्यकता होती है ।

तीसरा, बीजों, खादों, उर्वरकों तथा उपकरणों के रखरखाव एवं भूमि के चालू खर्चों पर कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होती है । इस तरह का वित्त उत्पादन तथा उपभाग दोनों दृष्टि से हासिल नहीं है, क्योंकि कृषकों का अपने दैनिक जरूरतों को पूरी करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह इसके अतिरिक्त विपणन वित्त की आवश्यकता होती है , जिसे कृषक अनुकूल समय आने पर अपने उत्पाद का विक्रय कर सके । अन्ततः फसलों में क्षति हो जाने तथा अन्य राहत कार्यों के दृष्टिकोण से यथा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूमिक्षरण आदि के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है ।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धिशील प्रवृत्ति में उतार - चढ़ाव एक विशेषता है । अच्छे मानसून के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है, जब कि खराब मानसून के परिणामस्वरूप घटता है। 1970-71 के दौरान 108.4 मिलियन टन के उच्च उत्पादन स्तर की तुलना में 1972-73 के दौरान, जो सूखे का वर्ष था, खाद्यान्न उत्पादन में 11.4 मिलियन टन की कमी आयी । इसी प्रकार 1978-79 में हुए 131.9 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1979-80 में 22.2 और 1983-84 में हुये 152.4 मिलियन टन की तुलना में 1987-80 में 12.0 मिलियन टन की कमी आई । शताब्दी के भयंकर सूखे के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षाकृत न्यूनतम गिरावट यह दर्शाती है कि भारतीय कृषि में अन्तर्निहित लचीलापन है और इसमें समयावश्यक उत्पादन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की अच्छी क्षमता है । अतः विकास की नीति ऐसी होनी चाहिए कि वह उतारों को दीर्घावधि

मे कम करने की दिशा में बढ़ सके । सूखा पड़ने से कृषि पैदावार और आय में भारी कमी हो जाती है, जिससे काफी संख्या में कृषक बेरोजगार हो जाते हैं । इसका सबसे खराब असर ग्रामीण निर्धनों पर पड़ता है, जिनमें भूमिहीन मजदूर और लघु तथा सीमान्त कृषक शामिल हैं और ये ही सर्वाधिक असुरक्षित हैं । बार-बार सूखा पड़ने से कृषक - त्रणकर्ता और ऋण संस्थाएँ दोनों ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि इससे निधियों का पुनर्चक्रिकरण मुश्किल हो जाता है । अतः विकास एजेंसियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार प्रदान करने वाली कृषि इतर गतिविधियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 की स्थापना के साथ - साथ कृषि विकास हेतु इसका प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, परन्तु इसके राष्ट्रीयकरण के बाद इसका कार्य विशेष रूप से बढ़ गया । मोटे तौर पर कृषि शाखा के तीन पक्ष हैं अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त । इनमें से मध्यकालीन और दीर्घकालीन शाखा वित्त भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन है । जब कि अल्पकालीन शाखा में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों के साथ सहयोग देता है । भारतीय रिजर्व बैंक सीधे कृषि क्रियाओं का वित्तीय नहीं करता, किन्तु यह अपने कृषि विभाग एवं नाबार्ड द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करता है । इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में कृषि शाखा विभाग की स्थापना की गयी, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि शाखा की आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का अध्ययन दल तैयार करना है । केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सुझाव देना एवं सहकारी बैंकों का विशेष संचालन करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य एजेंसियों के साथ सहकारी बैंकों के कार्यों का निरीक्षण करना है । व्यापारिक बैंकों तथा उनके साथ सहकारी बैंकों में कृषि क्रियाओं के लिये समन्वय स्थापित करना है । यहाँ पर 'आल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी' का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा, जिसकी प्रमुख प्राप्ति इस रूप में रही कि अपने कार्यावधि के समय में भी सहकारी शाखा समितियाँ कृषि शाखा में बहुत कम योगदान कर रही हैं । दूसरे, कुल मिलाकर इससे बड़े किसान ही लाभान्वित हुये हैं। ऋण अब भी प्रतिभूतियों एवं आदेयों के आधार पर है, न कि उत्पादक आवश्यकताओं के आधार पर । इस समिति ने सह शाखा

संस्थाओं के पुनर्संरचना हेतु कुछ सुझाव भी दिये हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख के विवरण को जो सहकारी बैंक, स्टेट बैंक, तथा कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम को दिया गया, उसे सारणी 5 । में दिखाया जा सकता है ।

सारणी 5 ।

सहकारी समितियों, स्टेट बैंक और कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम को भारतीय रिजर्व बैंक का साख

(रुपये करोड में)		
वर्ष	अग्रिम	राशिया
1951 - 52	11 99	7 81
1955 - 56	23 80	12 98
1959 - 60	100 95	75 54
1960 - 61	146 66	89 40
1961 - 62	192 92	122 80
1962 - 63	220 28	134 22
1964 - 65	283 49	148 63
1965 - 66	150 10	172 17
1968 - 69	790 20	- -
1972 - 73	831 68	246 29
1973 - 74	744 37	367 19
1974 - 75	1105 80	533 56
1977 - 78	1052 00	814 00
1978 - 79	1125 00	780 00
1979 - 80	1199 00	819 00

सारणी से यह स्पष्ट है कि 1951-52 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी साख समितियों, स्टेट बैंक और कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम को दिये गये अग्रिम वर्ष 1974-75 तक लगातार बढ़ते रहे, जब कि 1977-78 से इन में कमी आने लगी। इसका प्रधान कारण यह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद व्यापारिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास हेतु साख प्रदान किया जाने लगा ।

जहा तक अल्पकालीन साख का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि साख के वित्तीयन हेतु प्रदान करता है और साथ ही साथ फसलों के विपणन क्रय तथा उर्वरकों के वितरण आदि हेतु वित्तीयन करता है। इस अल्पकालीन साख का प्रमुख रूप से दो उद्देश्य है - एक, जहा तक सम्भव हो सके कृषि साख आवश्यकताओं को पूरा करना और दूसरे सहकारी साख संरचना को तैयार करना, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा कर सके । इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की दो प्रमुख शर्तें एक तो गैर बकाया और दूसरा आवश्यक वातावरण का होना है। यहा यह उद्देश्य रखा गया कि अग्रिमों और बकाया में बहुत अन्तर नहीं होना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि सहकारी बैंक अधिक से अधिक अपने ससाधनों द्वारा कृषि ऋण पूरा करे और इसमें साख की सीमाओं का निर्धारण उधार लेने वाले सस्थाओं , उसके निजी वित्त, जमाओं तथा तरल ससाधनों को रखने एव ऋणों की वसूली आदि पर निर्भर करेगा। 1951 में इस तरह का अल्पकालीन साख ₹0 57 6 करोड़ का था, जो 1969-70 में बढ़कर ₹0 370 करोड़ हो गया और यह 1978 में बढ़कर ₹0 961 करोड़ और 1979 - 80 में ₹0 945 करोड़ हो गया । इस तरह स्वीकृति धनराशि और बकाये के विवरण को हम सारणी 5 2 में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

मध्यकालीन साख का वितरण राष्ट्रीय कृषि साख फंड द्वारा कृषि सुधार हेतु प्रदान किया जाता है । यथा, भूमि विकास हेतु निर्माण तथा सिंचाई ससाधनों के रख रखाव हेतु, मशीनों उपकरणों, यातायात साधनों तथा उर्वरकों को क्रय करने हेतु, कृषि फार्म भवनों आदि का निर्माण हेतु तथा पशुपालन एव मुर्गीपालन हेतु, जो आर्थिक रूप से कमजोर कृषक हैं, उनके लिए प्रदत्त किया जाता

सारणी 5 2

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को अल्पकालीन समायोजन

(रूपये करोड मे)

वर्ष	स्वीकृति राशिया	बकाया राशिया
1950 - 51	7 6	- -
1955 - 56	30 0	13.0
1960 - 61	112 0	101 0
1965 - 66	213 0	144 0
1969 - 70	370 0	214 0
1974 - 75	613 8	776 0
1977 - 78	845 0	325 0
1978 - 79	961 0	277 0
1979 - 80	945 0	222 0

स्रोत - Report on Currency and Finance, Various Issues.

है । इस तरह ऋणों को 15 माह से 5 वर्ष के समयावधि के लिए प्रदान किये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मध्यकालीन ऋणों के विवरण को सारणी 5 3 में दिखाया जा सकता है ।

सारणी से स्पष्ट है कि 1979-80 में मध्यकालीन साख की सीमा 149 करोड थी, जब कि यह 1978-79 में केवल 70 करोड ही थी और इसी तरह 1979-80 में आहरण तथा बकाया धनराशि क्रमशः 109 करोड तथा 158 करोड था ।

सारणी 5 3

मध्य कालीन ऋण

(रुपये करोड मे)

वर्ष	स्वीकृत	आहरण	वकाला राशिया
1954 - 55	0 27	-	-
1955 - 66	0 31	-	-
1960 - 61	5 00	4 00	9 00
1965 - 66	14 00	7 00	15 00
1967 - 68	16 00	9 00	16 00
1969 - 70	18 00	13 00	20 00
1970 - 71	17 54	10 19	-
1972 - 73	8 72	-	16 88
1973 - 74	11 77	6 03	19 91
1974 - 75	98 87	4 58	15 65
1876 - 77	66 00	103 00	97 00
1977 - 78	121 00	115 00	161 00
1978 - 79	70 00	48 00	119 00
1979 - 80	199 00	109 00	158 00

स्रोत - Report on Currency and Finance, Various Issues.

भारतीय रिजर्व बैंक अपने राष्ट्रीय कृषि साख फंड द्वारा मध्यकालीन ऋणों में अल्पकालीन ऋणों को परिवर्तित करके मध्यकालीन फसलों के उत्पादन हेतु देता है । अल्पकालीन ऋण को

सहकारी ग्रामीण ऋण एजेंसियों को निम्न ब्याज पर उधार देना और प्रतियागी दरों पर जमाराशिया जुटानी होंगी, तब तक उनके लिये अपने जमा संग्रहण और उधार के कार्यकलापों का विस्तारण करने में मददरूनी निरुत्साह रहेगा । ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये पर्याप्त जमाराशिया जुटाने में सहकारी ऋण समितियों के असमर्थ होने के फलस्वरूप नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्तीयन का अधिकतर आश्रय लेना आवश्यक हुआ है।⁶

सारणी 5 4

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं को दीर्घ कालीन साख

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृति सीमा	आहरण	बकाया राशिया
1972 - 73	46 29	48 69	100 05
1973 - 74	31 02	310 02	122 00
1974 - 75	48 37	48 37	156 20
1976 - 77	81 30	81 30	271 30
1977 - 78	86 00	86 00	328 00
1978 - 79	94 00	94 00	384 00
1979 - 80	105 00	100 00	439 00

स्रोत - Report on Currency and Finance, Various Issues.

6. Reserve Bank of India, Annual Report, 1991 - 92, pp. 95 - 96.

इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख को सहकारी साख सस्थाओं द्वारा दिये जाने के उद्देश्य को हम प्रोत्साहन तथा सलाहकार के रूप में, पुनर्वित्तीयन की सुविधा के रूप में तथा कार्यों की नियंत्रक के रूप में दे सकते हैं। अपने इस कार्य को सम्पादित करने में भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक उपायों को लिया है, जिसका उद्देश्य सहकारी साख सस्थाओं के क्रिया कलापों में सुधार लाने से है और उन्हें मजबूत वित्तीय आधार देने से है। इनका मुख्य उद्देश्य इस बात से है कि सहकारी साख सस्थाएँ अधिकतर साख का प्रवाह ग्रामीण जनसंख्या के कमजोर वर्गों में प्रवाहित करें और साख का क्षेत्र मजबूत हो। इसके साथ-साथ अन्य एजेंसियों यथा, कृषि सेवा समितियाँ बड़े एवं बहु उद्देश्यीय समितियाँ तथा कृषि साख सघन विकास कार्यक्रम हैं, जिन सभी को अन्ततः जिला साख नियोजन में सम्मिलित कर दिया गया है।

कृषि साख के वित्तीयन हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया था। 1951 के विकासात्मक नियोजन के प्रारम्भ तक भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि वित्तीयन बहुत ही अपर्याप्त तथा अप्रत्यक्ष था। इसमें यद्यपि अलग से कृषि साख विभाग था, किन्तु इसका मुख्य कार्य शोध था, न कि कृषि वित्तीयन। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कृषि प्रधान होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण रूप से कृषि साख सुविधाओं की उपलब्धता के विस्तार और उनकी आवश्यकताओं का अनुभव किया। अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष रूप से कृषि साख विभाग का निर्माण किया, जिसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं -

1. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के परामर्श में कृषि साख सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करना।

2. कृषि साख के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का समन्वय करना, विशेषकर राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य संस्थाओं के साथ, जो कृषि साख में योगदान करते हैं।

3 राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य ग्रामीण साख एजेन्सियों के माध्यम से कृषि फसलों और कृषि कार्यों का वित्तीयन करना । ⁷

इस सम्बन्ध में एम0 एल0 डार्लिंग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सहकारी साख की कुछ अनियमितताओं को स्पष्ट किया गया है और ग्रामीण महाजनों के उच्च व्याज दर और उनके अन्य व्यवसायिक कार्यों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में यह विचार रखा कि सहकारी आन्दोलन ही कृषि वित्त की महत्वपूर्ण एजेंसी हो सकती है । इस तरह से सहकारी साख संस्थाएँ ही सुधरे और परिवर्तित रूप में ग्रामीण साख सुविधाओं में उपर्युक्त योगदान कर सकती है। कृषि साख का विस्तृत स्वरूप 'ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे' में स्पष्ट किया गया है ।⁸ भारत सरकार ने एक लघु कृषक व्यापार संघ बनाने का निर्णय लिया है, जो विभिन्न प्रकार के कृषि व्यापारों की सहायता द्वारा ग्रामीण इलाकों में आयोपार्जन और रोजगार हेतु अभिनव विचारों को समर्थन देगा ।

5 2 कृषि एवं ग्रामीण साख हेतु वित्तीय एजेंसिया

देश की स्वतंत्रता के बाद नियोजित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में 'ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी' में यह पाया गया कि 1951-52 में साख के मुख्य रूप से दो स्रोत प्रधान थे पहला, महाजन और दूसरा, ऋण ग्राहक के सम्बन्धी, जो दोनों मिलाकर के कुल साख का लगभग 84 प्रतिशत

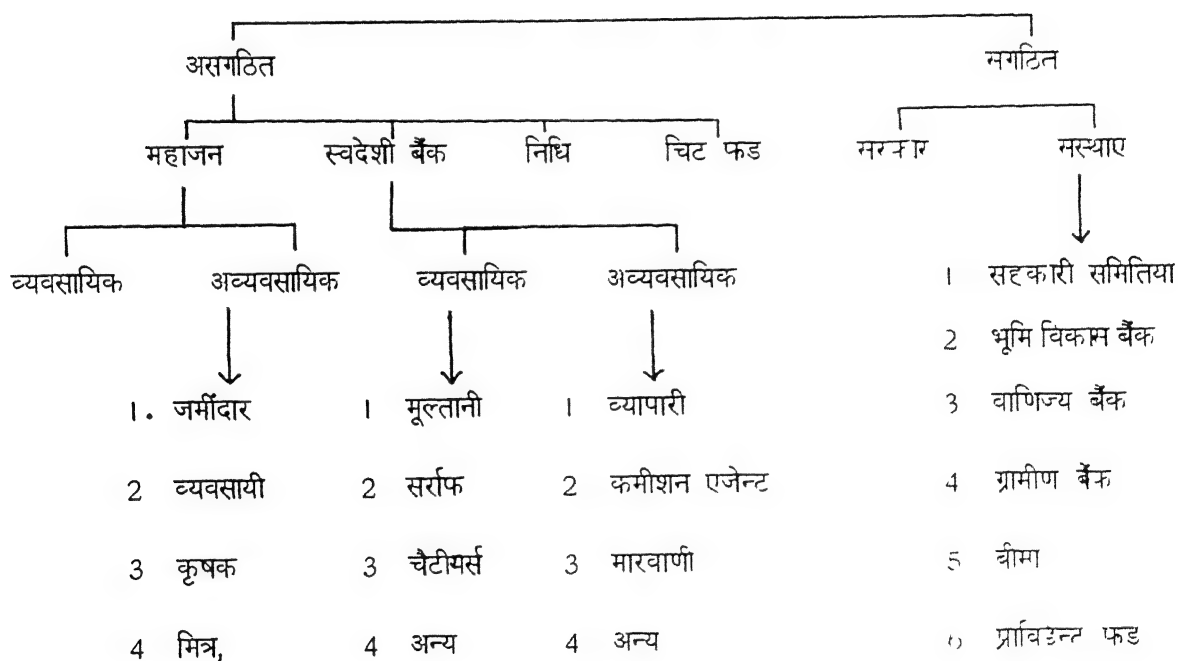
7. The RBI - Function and Working, Bombay - p 70.

8. "Today agricultural credit that is supplied falls short of the right quantity, is not of the right type, does not serve the right purpose and by the criterion of need (not overlooking the criterion of creditworthiness) often often fails to go to the right people." - C.R. Basu, Central Banking in a planned Economy - The Indian Experiment, 1978. p. 147.

प्रदत्त करते थे। सरकार, व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक केवल 76 प्रतिशत साख प्रदान करते थे। इस सम्बन्ध में प्राथमिक आधार पर भारत की ग्रामीण क्षेत्र में एजेंसियों का विवरण निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है -

चार्ट -5।

ग्रामीण क्षेत्र में वित्त एजेंसियां



जहा तक ग्रामीण एव कृषि क्षेत्र मे संगठित एजेन्सियों का प्रश्न है, वहा क्रमश 1961 के बाद से व्यापारिक बैंकों की स्थिति मे काफी सुधार हुआ है। कुल साख का जहा 1961 मे व्यापारिक बैंकों का भाग 0 3 प्रतिशत था, वह 1971 मे बढ़कर 2 4 प्रतिशत हो गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र मे महाजनों का प्रतिशत 1961 मे 84 प्रतिशत था, वह गिरकर 1971 मे केवल 23 प्रतिशत रह गया। इस सम्बन्ध मे 1961 से 1971 तक विभिन्न साख एजेन्सिया मे कृषि परिवार द्वारा प्राप्त ऋण का विवरण सारणी 5 5 मे दिया गया है।

सारणी 5 5

एजेन्सिया और कृषकों द्वारा लिये गये ऋण

		30 जून तक		
		प्रतिशत मे		
एजेन्सिया		1951	1961	1971
1	संस्थागत एजेन्सिया	7 6	18 4	31 3
(क)	सरकार	3 9	6 7	7 1
(ख)	सहकारी समितिया	3 7	11 4	22 0
(ग)	वाणिज्य बैंक	-	0 3	2 4
(घ)	बीमा	-	--	0 1
(ङ)	प्रॉविडेंट फण्ड	-	--	0 1
2	नैर संस्थागत एजेन्सिया	92 4	81 6	68 3
(क)	जमींदार	3 2	0 9	8 1
(ख)	कृषक महाजन	25 2	48 1	23 0
(ग)	व्यवसायिक महाजन	46 8	13 8	13 1
(घ)	व्यापारी	4 7	7 1	8 4
(ङ)	रिस्तेदार एव दोस्त	11 4	5 2	13 1
(च)	अन्य	1 1	6 5	2 6

इस तरह से 1951 से 1971 के बीच जो मुख्य सस्थागत साख एजेंसिया ग्रामीण कृषि साख पर अपना प्रभाव दिखाया है, वह सहकारी साख सस्थाए और व्यापारिक बैंक हैं । 1970 और उसके बाद सस्थागत साख एजेंसियों का योगदान एवं प्रवृत्ति, जो बढ़ते हुए ग्रामीण साख के रूप में देखा जा सकता है, उसे सारणी 5 6 में दिखाया जा सकता है । यहां पर व्यापारिक बैंकों का समृद्धि दर सहकारी साख सस्थाओं से अधिक था ।

सारणी 5 6
कृषि क्षेत्र की सीधे प्राप्त सस्थागत वित्त

(रूपय करोड़ में)

साख सस्थाए	30 जून को समाप्त वर्ष पर निर्गत ऋण एवं अग्रिम					
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7
सहकारी समितिया	1039	1187	1430	1444	1560	1744
सरकार	37	82	82	98	119	153
अनुसूचित वाणिज्य						
बैंक	274	405	508	569	800	1045
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	--	2	16	44	101	100
योग	1390	1675	203	2153	2580	3042

स्रोत :- Report of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development (CRAFICARD) 1981, p. 476.

इस तरह भारतीय ग्रामीण एव कृषि क्षेत्र में साख की अनिवार्यता का अनुभव करते हुए भारत सरकार ने अनेक समितियों को गठित किया है, जिससे ग्रामीण एव कृषि क्षेत्र में बैंकिंग और साख सुविधाएं प्रदान की जा सकें। जहां तक अल्पकालीन एव मध्यकालीन साख का प्रश्न है, गांडगिल समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सस्तुति की है कि एक कृषि साख निगम की प्रत्येक राज्य में स्थापना होनी चाहिए, केवल उन राज्यों को छोड़कर जहां सहकारी साख संस्थाएं अन्यधिक क्रियाशील हैं। यह कृषि साख निगम एव स्वायत्त संस्था के रूप में होगी और राज्यों का इस की पूर्णता का आधा हिस्सा देना होगा। इस निगम का कार्य होगा कि वह पूरे सम्बंधित क्षेत्र में वर्जनिमया एव शाखाओं को स्थापित करे एव हर तरह की साख की पूर्ति करे। इस तरह में यह सहकारी साख समितियों को वित्त प्रदान करेगी, जहां केन्द्रीय, वित्तीयन एजेन्सियां नहीं हैं और व्यक्तिगत कृषकों को भूमि अधिक ऋण सीधे प्रदान करेगी। इस समिति की सस्तुतियां यद्यपि पूरे क्षेत्र में मान्यता नहीं प्राप्त कर सकी, विशेषकर इस रूप में कि जिस तरह साख प्रक्रिया की बात की गयी है, वह राज्य एव केन्द्रीय बैंकों द्वारा स्वतः ही प्राप्त कर ली जाती है।

पूँजी निर्माण, कार्यकलाप-विशिष्ट मूलभूत सुविधाओं के सृजन और कृषि उत्पादकता का बढ़ाने के लिये फसल उत्पादन की नई तकनीकी अपनाने में संस्थागत ऋण की भूमिका का अब पूर्ण तरह मान्यता मिल चुकी है। वर्ष 1980 और 1987 के बीच कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी निर्माण में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसे ऋण के अनोपचारिक स्रोतों और संस्थागत ऋण के बढ़े प्रवाह के माध्यम से उपलब्ध कराये गये निजी क्षेत्र के पूँजी निर्माण द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसतुलित किया जा सकता है। वर्ष 1977 और 1990 के बीच निवेश ऋण में औसतन 15.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में उत्पादन ऋण में औसतन 13.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।⁹

5.3 भारत में कृषि साख व्यवस्था

अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण से कृषि साख व्यवस्था में निम्न बातें

9. NABARD, Annual Report, 1991-92, pp. 42-45.

होनी चाहिए -

- 1 कृषि साख काफी समय के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है उसे पूरा किया जा सके । यह साख पूर्ति में समानता की दृष्टिकोण अर्थात् अन्य सस्थाओं की तुलना में समान ब्याज दर रखना चाहिए ।
- 2 ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली साख पूर्णतः सुरक्षित होनी चाहिए, जिसमें मान्य सुविधाओं का दुरुपयोग न हो, परन्तु इसके लिए प्रतिभूति आवश्यक रूप में भीतक बनना न हो।
- 3 प्रदत्त कृषि साख और कृषि की औसत उत्पादकता तथा कृषकों की आय पर आधारित होनी चाहिए, विशेष कर उस परिस्थिति में जब कृषि में आर्थिक मंदी की अवस्था हो ।
- 4 कृषि साख को उपयुक्त बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों की जिम्मेदारी पर होनी चाहिए, जो बैंकिंग एवं अनुभवों तथा प्रशिक्षणों को प्राप्त कर चुके हों ।
- 5 कृषि साख हेतु प्रतिभूतियाँ यदि आवश्यक हों तो व्यक्तिगत स्तर पर ऋण ग्राहक के नैतिक स्थिति तथा कृषि योग्यता पर दी जानी चाहिए ।

'ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी' ने देश में कृषि साख व्यवस्था के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, जो कृषि क्षेत्र में साख नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं ।¹⁰ कृषि साख को राज्य की नीतियों के साथ जुड़ा होना चाहिए । साथ ही साथ यह साख की व्यक्तिगत एजेंसियों के विकल्प में होना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त ससाधन होने चाहिए तथा कुशल प्रबन्धक द्वारा संचालित होना चाहिए । वस्तुतः कृषि साख की प्रतिभूति भूमि के प्रतिभूति के रूप में नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रत्याशित कृषि उपज के आधार पर होना चाहिए । इसे इस प्रकार होना चाहिए कि गांव स्तर से ऊपर की ओर सहकारिता आधार पर विकसित होना चाहिए । प्रदत्त

साख को प्रभावी ढंग से निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जो ऋण ग्राहक की उचित आवश्यकता एवं हित को कायम रख सके । विभिन्न प्रकार के ऋणों की समयावधि एवं व्याजदर उन उद्देश्यों से सम्बन्धित होना चाहिए, जिसके लिए कृषि साख प्राप्त किये जाते हैं, यद्यपि पर्याप्त रूप में आवश्यक उपभोग वस्तुओं के लिए भी ऋण दिये जाने चाहिए, फिर भी इन ऋणों का प्रधान लक्ष्य उत्पादन का दृष्टिकोण से होना चाहिए ।¹¹

इस तरह उपर्युक्त बातों के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि कृषि साख व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऋण ग्राहक इस जिम्मेदारी को ले सके कि वह ऋण की अदायगी कर सकेगा, ऐसा वातावरण उत्पन्न होना चाहिए कि ऋण ग्राहक समयानुसार अपनी शर्तों का पूरा करके अपने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक उत्थान को कर सके । भारत की वर्तमान कृषि क्षेत्र में कृषि साख की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपर्युक्त बातों के अलावा कुछ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हैं, जो कृषि साख सुविधा की दृष्टिकोण पर आधारित हैं । कृषक साख व्यवस्था में दीर्घकालीन मध्यकालीन अल्पकालीन, तीनों प्रकार की साख सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए । जिन कृषि उद्देश्यों के लिए साख ऋण दिया जाता है वह पर्याप्त होना चाहिए अन्यथा कृषक का अन्य स्रोत में अपने स्तर पर ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । कृषि कार्यों के लिए इस तरह के ऋण कम अवधि के अन्तर्गत उपलब्ध होने चाहिए और विशेषकर बीज, खाद तथा अन्य चालू खर्चों के लिए । इसमें अधिक समय नहीं लगाना चाहिए । इन सब कार्यों के लिए कृषि साख को लाचशील होना चाहिए अर्थात् व्यस्त मौसमों में इसमें वृद्धि और मन्द मौसमों में इसमें कमी की सम्भावना होनी चाहिए । ऋणों की वसूली में ऋण न दे सकने की अवस्था में सम्पत्तियों के उचित मूल्य पर विक्रय की व्यवस्था होनी चाहिए । कृषि साख व्यवस्था में साख सस्थाओं की क्षमता एक बफर स्टॉक रूप में अथवा अनिश्चितताओं को वहन करने के रूप में होनी चाहिए । कृषि कार्यों हेतु प्रदत्त साख पूर्णतः निर्देशित तथा निरीक्षित साख होनी चाहिए । इसके लिए ऋण ग्राहक को प्रशिक्षित एवं निर्देशित करने की आवश्यकता है । ऋण ग्राहक के दृष्टिकोण से साख सुरक्षित होना चाहिए अर्थात् कृषकों

11. Report of the Rural Credit Committee Survey, 1954, Vol-II, p. 162.

के पहुँच सीमा के अन्तर्गत समयानुसार उचित मात्रा में प्रतिभूति के आधार पर साख उपलब्ध हो और वह भी सही उद्देश्य के लिए सामान्य दर पर । इस तरह ऋण इस प्रकार होना चाहिए कि ऋण ग्राहक को यह सहयोग करे और उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर, न कि उसके मादनादरों में डाले । जहाँ तक कृषि साख का ऋण दाता का दृष्टिकोण है, इस सम्बन्ध में प्रणाली का प्रयाप्त प्रतिभूति होनी चाहिए, साख का प्रवाह आसान एवं लगातार तक हो सकती है । जब ऋण दाता इस बात से सुनिश्चित है कि उसके ऋण और हर तरह के बकाये का भुगतान हो जायगा, हर तरह का अपवचन, देरी कम की जा सकती ।

उत्पादकता स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों के विश्लेषण में स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि राज्यों और फसलों में असमान निष्पादन, सुनिश्चित जल आपूर्ति, उर्वरक उपयोग स्तर अधिक उपजवाली किस्मों के बीज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विस्तार, सस्थागत कारकों आदि की उपलब्धता आदि की वजह से था । नाबार्ड, वाणिज्य बैंक और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किये गए मूल्यांकन अध्ययनों से भी निष्कर्ष रूप में यह बात प्रकट हुई है कि जहाँ कार्यकलाप विशिष्ट मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ ऋण की उत्पादकता कम थी । ऋण को केवल उस स्थिति में उत्पादक माना जा सकता है, जब कि सस्थागत ऋण एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराये गए पूँजी ससाधनों का वृद्धिशील उपयोग, वृद्धिशील शुद्ध आय उत्पन्न करे, जो ऋण की राशि (मूलधन तथा ब्याज) की चुकौती के लिये पर्याप्त हो तथा कृषक को भी खुशहाल दशा में रख सके । ऋण का मूल महत्व कृषकों / ऋणकर्ताओं को सहायता पहुँचाना है, ताकि वे ऐसी अनुपूरक निविष्टियाँ प्राप्त कर सकें, जिन्हें वे अपने ससाधनों से नहीं खरीद सकते । ऋण को और अधिक उत्पादक तथा और अधिक क्षमतावान बनाने के लिये यह जरूरी है कि कृषि ऋण प्रणाली एक एकीकृत ऋण प्रणाली के रूप में कार्य करे ।

भारत में कृषि साख की व्यवस्था की समीक्षा को भी प्रस्तुत किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में प्रशासनिक ब्याज दर की व्यवस्था कुछ चयनित क्षेत्रों एवं वर्गों की दृष्टिकोण से किया गया ।

चक्रवर्ती समिति ने ब्याजदर सरचना का परीक्षण किया और प्रशासनिक ब्याज दर की कमियों को दिखाया। प्रथमतः यह प्रभावी साख को सृष्टि करने में असफल रहा और ऐसी परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दरों को दिया गया, जिनकी स्थिति संदेहास्पद रही। दूसरे यह पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए कम लाभकारिता सिद्ध हुई।

पूरे देश की स्थिति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भारत में जो रियायती दर पर ब्याज की स्थिति है, वह कमजोर वर्गों की दृष्टिकोण से कायम रहनी चाहिए, परन्तु अन्य क्षेत्रों में ब्याजदर नियंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह में जहां तक कृषि ऋण का प्रश्न है इसमें दो वर्ग होने चाहिए पहला, सकीर्ण वर्ग, जो अलग में लघु एवं सीमान्त कृषकों को रियायती दर पर होना चाहिए और दूसरा, अन्य ऋण ग्राहक, जो ब्याज दर के नियंत्रण में स्वतन्त्र हो और जिन पर ऊँची ब्याज दर होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास के साख प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशेष रियायती ब्याज दर ऋण व्यवस्था से सम्बन्धित रहे और उनके सभी ऋण माट तौर पर लघु सीमान्त कृषकों तक सीमित रहा है, परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पायेगी। इस बात से इस बात की सन्तुष्टि की गयी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सम्बन्धित बैंकों के साथ मिला देना चाहिए, जो बैंक कमजोर वर्गों को किये गये वित्तीयन का पूरा कर सकने में समर्थ है।

कृषि क्षेत्र में कुल कृषि साख में नाबार्ड का योगदान सभी ऋण प्रदान करने वाला संस्थाओं के रूप में 1986 में 45 प्रतिशत रहा। नाबार्ड के पुनर्विर्जीवन में सहकारी समितियाँ का अंग घटा है, जब कि व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में यह बढ़ा है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर्गत उत्पादन और विपणन गतिविधियों को सहायता देने के लिये नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल 4192 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की, जिनमें से बैंकों ने 2998 करोड़ रूपयों का उपयोग किया।¹²

12. National Bank For Agriculture and Rural Development, Annual Report, 1991-92, pp. 7-9.

अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण जो बैंकों के लाभकरिता घटने में रहा है, वह है निर्देशानुसार साख अथवा निश्चित गूप लक्ष्य साख, जो सरकार के निर्देश के अनुसार किया जाता है, दूसरा कारण यह रहा है कि रियायती दर पर कमजोर वर्गों के लिए साख का विस्तार किया गया । इसका यह अभिप्राय नहीं कि साख व्यवस्था का विकासात्मक परियोजनाओं से दूर रखना चाहिए, इसके विपरीत बैंकों को क्रियाशील हो करके सरकार के विकासात्मक योजनाओं में भाग लेना चाहिए ताकि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, पर गैर तार्किक रूप में जिस तरह से आदेशानुसार साख का विस्तार हुआ है, वह चिन्ता का विषय है । उसकी स्थिति इस रूप में रही है कि बैंक अपने लाभकरिता को कायम रखने में असमर्थ रहे हैं । दूसरी बात यह रही है कि सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है । बैंकिंग प्रक्रिया में कमी करके स्थापित साख उद्देश्यों को समाप्त करके अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति से साख वितरण व्यवस्था कमजोर पड़ गयी है, और अपने उद्देश्य में पीछे हो गयी और विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रही है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि साख सस्थाओं पर बढ़ते हुए राजनैतिक दबाव बढ़ रहे हैं । सरकारी स्तर पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नामित बैंक प्रबन्धकों और सचालकों पर राजनैतिक स्थिति का विशेष प्रभाव है । यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारों का सहकारी साख समितियों के भुगतान में कोई रुचि नहीं है और राजनैतिक आधार पर सहकारी साख समितियों के बकाये को समाप्त करने के लिए वादे किये जाते हैं । इससे पूरे देश में ऋण न अदा करने का वातावरण उत्पन्न होता है । इसी तरह राजनैतिक आधार पर ऋण मेला भी बहुत सी दशाओं में बिना पर्याप्त प्रतिभूति या बिना किसी प्रार्थनापत्र आदि पर किये जाते हैं । इन सन्दर्भों में ऋण जो राजनैतिक उद्देश्यों की दृष्टिकोण से दिये जाते हैं, उनमें बैंक एवं ऋण ग्राहक में सम्बन्ध नहीं रहता और बैंकों का भुगतान पूरी तरह प्रभावित होता है ।

इसी तरह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण साख व्यवस्था के सन्दर्भ में नाबार्ड की क्रियाकलाप केन्द्रीय सरकार के दबावों, जो व्यापारिक बैंक के ऊपर होता है, वह प्राथमिक क्षेत्रों में विशेषकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए और राज्य सरकार का दबाव सहकारी साख

संस्थाओं पर होता है । यद्यपि सरकार और राजनैतिक हस्तक्षेप नाबार्ड के सदस्यों में कुछ अप्रत्यक्ष होता है, पर इन प्रभावों को रोका नहीं जा सकता। इस तरह सरकार का दबाव नाबार्ड की क्रियाकलापों व साख वितरण व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अकुशलताएँ और कमियाँ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पायी गयी हैं, जिनमें बैंक साख का दुर्पयोग हुआ है। यह बड़े गम्भीर विषय का प्रश्न है कि इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करना, जो गरीबी रेखा को पार कर गये हैं, वे पूरे देश के सन्दर्भ में 13 प्रतिशत है, जब कि कई राज्यों में इस औसत से कम स्थिति है । इन कमियों के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावकारी हो सकते हैं, यदि उपयुक्त परिवर्तन और सुझाव का पालन किया जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि गाव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर नियोजन किया जाय । इस तरह के जिला स्तर के योजनाओं के सन्दर्भ में साख का महत्व और योगदान परिवर्तित रूप में होना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि हो और जिससे इसका दुर्पयोग न हो ।

5.4 भारत के कृषि वित्त में मौद्रिक एवं साख नीति

देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा एवं साख का सदैव ही महत्व रहा है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले कृषि क्षेत्र में वित्तीयन हेतु ब्याज दर निर्धारण की समस्या महत्वपूर्ण हुई और केन्द्रीय बैंक के विकास के साथ इस बात का अनुमान किया जाने लगा कि ब्याज दर में कुछ सीमा तक परिवर्तन मौद्रिक अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है और इस तरह साख नीति एवं मौद्रिक नीति में बैंक दर तथा ब्याज दर का महत्व विशेष रूप से बढ़ा । केन्स ने इसी बैंक दर के आधार पर ब्याज दर के विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था के विनियोग तथा रोजगार स्तर के निर्धारण को समझाया । यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर गिरता है तो विनियोग का स्तर बढ़ेगा और इस तरह उसने इस आधार पर सस्ती मुद्रा नीति का समर्थन किया । इसका अभिप्राय यह था कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिये मुद्रा बाजार में पर्याप्त क्लृप्त उपलब्ध हो, ब्याज दर कम हो,

विनियोग उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि हो ।

जहाँ तक मौद्रिक एवं साख नीतियों का भारतीय कृषि से सम्बन्ध है, वहाँ तीन प्रमुख बातें उल्लेखनीय हैं । प्रथम एक गैर कुशल वित्तीय व्यवस्था, सस्ती साख व्यवस्था को करने में असमर्थ है । दूसरे, कृषि साख के लागत के सम्बन्ध की अनिश्चितता तथा हानि की सम्भावना विशेषकर भारतीय परिवेश में महत्वपूर्ण है, सामान्यतः भारतीय कृषक आर्थिक रूप से दिवालिया की स्थिति में रहता है और उसकी साख बहुत कम होती है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय कृषि को लाभकरिता का आधार दिया जाय, जिससे महत्वपूर्ण रूप से कृषि लागत को कम किया जा सके । तीसरे, भारतीय कृषि साख सन्दर्भ में लागत का अशुभ एकाधिकारिक स्थिति के रूप में ग्रामीण महाजन का होता है । यहाँ तक कि उन स्थानों में भी, जहाँ सहकारी साख समितियाँ विद्यमान हैं । इस तरह उसका एकाधिकारिक रूप ग्रामीण साख में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इस तरह सस्ती मुद्रा एवं साख की दशाएँ एक व्यवस्थित मुद्रा एवं साख बाजार में महत्वपूर्ण रूप से कृषि साख की लागतों को प्रभावित करने में उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती । इस तरह ग्रामीण साख एजेंसियों तथा व्यवस्थित मुद्रा एवं साख बाजार में पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिए, जिससे भारतीय कृषि साख व्यवस्था में महाजन की एकाधिकारिक स्थिति को कम किया जा सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि महाजन की सभी गतिविधियों को प्रत्यक्षतः भारतीय रिजर्व बैंक के परिवेश में लाया जाय, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक प्रभावी रूप में ग्रामीण क्षेत्र के मुद्रा एवं साख बाजार में कार्यशील हो और कृषकों को आवश्यक एवं पर्याप्त साख सुविधाएँ प्राप्त हों सके । इस तरह से व्यवस्थित बैंकिंग सुविधाएँ प्रदत्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में साख वित्त उपलब्ध कराया जाये । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ब्याज दर को सरलीकृत बनाया जाय जो कृषि क्षेत्र में साख सुविधाओं के लिए प्रभावी हो सके ।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन अनेक कृषि विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ हैं । अतः उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, जिससे भारतीय कृषि में सतुलित विकास संभव हो सके । इस तरह के आर्थिक विकास तथा विनियोग मांग को प्रोत्साहित करने के लिए जहाँ ब्याजदर में कमी

करना आवश्यक है, वहीं साख पूर्ति को विस्तृत करना आवश्यक है, क्योंकि यदि दशाएँ अनुकूल हों तो सस्ती मुद्रा एवं साख, विनियोग तथा आर्थिक क्रियाओं को तीव्र कर सकती है। कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करने में और भविष्य के विनियोगों के सम्बन्ध में देश की स्पष्ट साख नीति होनी चाहिए। इस तरह कृषि क्षेत्र में इन विकासवात्मक विनियोग एवं कार्यक्रमों के द्वारा अतिरिक्त आय, विनियोग एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक एवं साख नीति का संचालन बैंक साख विस्तार की मात्रा को उस सीमा तक नियंत्रित करती है, जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसी तरह साख प्रवाह की दिशा को पूरी आर्थिक प्राथमिकताओं की दृष्टिकोण से किया जाता है। मौद्रिक एवं साख नीति के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया जा सकता है।

पहला, बिना उत्पादन प्रभावित किये हुये स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण करना।

दूसरा, सामान्य उपयोग सम्बन्धी संवेदनशील वस्तुओं के सग्रह को हतोत्साहित करना।

तीसरा, वंक्षित क्षेत्रों में साख प्रभाव को प्रोत्साहित करना तथा बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा साख अंतराल को पूरा करना।

इन उपर्युक्त उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को परिवर्तित होने वाली दशाओं का ध्यान में रखते हुए साख नीति का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है। वस्तुतः प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951 से ही साख नीति का महत्व स्वीकार किया गया है। अर्थव्यवस्था में बटते हुए मौद्रिक दशाओं तथा स्फीतिकारी दशाओं तथा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलनों के बटने के कारण मुद्रा एवं साख क्षेत्र में सरकारी स्तर पर कमी का अनुभव किया गया। वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विनियोग में बहुत तीव्र वृद्धि हुई और इस समयावधि में व्यक्तिगत क्षेत्रों में साख में अत्यधिक वृद्धि हुई। परिणामतः साख नीति को कठोर बना दिया गया। साख नीति को एक दिये हुए मौद्रिक बाजार की संरचना की दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। भारत में साख नीति के सामने अनेक सीमाएँ हैं यथा, असंगठित बाजार, गैर मौद्रिक क्षेत्र, संस्थागत तथा क्षेत्रीय साख अंतराल आदि।

इसी के साथ मुद्रा बाजार में, साख सम्बन्ध में मौसम व अनुसार मात्रा की मांग भी महत्वपूर्ण है ।

मौद्रिक नीति की ही तरह साख नीति का भी क्रियान्वयन अनेक नीति, उपकरणों के द्वारा किया जाता है। परम्परागत रूपसे साख नियंत्रण, केन्द्रीय बैंक दर खुले बाजार की ख़ियाए तथा आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से किया जाता है । इसी के साथ - साथ अनेक चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियों और नैतिक दबाव भी है ।

मौद्रिक नीति के अनेक उपकरणों में से एक महत्वपूर्ण उपकरण साख नियोजन से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत साख बजट का निर्माण समष्टि एवं व्यष्टि दोनों स्तरों पर किया जाता है । यह साख का धनात्मक और विकासात्मक पक्ष है और यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अधिक प्रभावी हुआ है । वस्तुतः साख नियोजन को मुख्य रूप से मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । मोटेतौर पर मूल्य स्थायित्वता मौद्रिक नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है । अतः साख नियोजन को इस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी होना चाहिए । इसके साथ - साथ नियोजन निम्नलिखित विकासात्मक कार्यों को करता है ।

पहला, अर्थव्यवस्था में मौद्रिकृत क्षेत्र तथा बैंकिंग प्रवृत्तियों में विस्तार करना ।

दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र के मौसमी साख अन्तराल को कम करना ।

तीसरा, क्षेत्रीय तथा क्षेत्रवार साख अन्तरालों को पूरा करना,

चौथा, बैंक साख का अधिक से अधिक अनुकूलतम वितरण की व्यवस्था करना ।

क्रियान्वयन रूप में मोटेतौर पर साख नियोजन का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था के सीमित उधार देय ससाधनों के नियोजन एवं बजटीकरण से है, जिससे अनुकूलतम रूप में बैंक वित्त की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके और इसके लिए निम्न दशाओं पर नियोजन को आवश्यकता होगी

पहला, साख नियोजन की आवश्यकता प्रथमतः राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। देश की

प्राथमिक आवश्यकताओं तथा सामान्य आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार समष्टि स्तर पर साख का वितरण इस रूप में करती है कि मौद्रिक स्थायित्वता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके । साख नियोजन वार्षिक योजनाओं में वित्तीय ससाधनों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित है ।

दूसरा साख नियोजन का दूसरा स्तर सस्थागत स्तर है । इसके अन्तर्गत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्यानुसार व्यष्टि स्तर पर व्यक्तिगत बैंक साख नियोजन करते हैं । इसके अन्तर्गत लगातार विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित आर्थिक दशाओं के आधार पर समायोजन करने की आवश्यकता होती है । प्रत्येक बैंक को पहले से ही ससाधनों की उगाही तथा साख वितरण सम्बन्धी नियोजन करने पड़ते हैं । पूरी अर्थव्यवस्था के साख नियोजन के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक इन व्यक्तिगत बैंकों से परामर्श करती है ।

तीसरा, साख नियोजन का तीसरा स्तर उद्योग स्तर है । इसके अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योगों का संगठन ऐसी योजनाओं को बनाता है, जो भौतिक उत्पादन एवं वित्तीय आवश्यकता तथा भविष्य के बैंक ससाधनों से ऋण स्थिति को दिखाते हैं ।

चौथा, साख नियोजन का अंतिम स्तर इकाई स्तर है । इसके अन्तर्गत बैंक वित्त के प्रयोगकर्ता को भी कुछ वित्तीय नियोजन करने की आवश्यकता होती है । इस मदर्भ में बैंकों के द्वारा न केवल अत्यधिक वित्तीयन हुआ है, अपितु जिन उद्देश्यों के लिए वित्त लिए गए थे, उनमें भी हेर फेर हुआ है और गैर वांछित आर्थिक क्रियाओं में वे प्रवृत्त किये गये हैं । इस सम्बन्ध में औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा है कि इस तरह के साख एवं वित्त के नियोजन पर ध्यान दे

भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा कृषि साख

(RBI, NABARD AND AGRICULTURAL CREDIT)

6। नाबार्ड की स्थापना

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में साख सुविधा और पुनर्वित्तीयन हेतु एक राष्ट्रीय बैंक की लगातार आवश्यकता के सन्दर्भ में 12, जुलाई, 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास हेतु 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' की स्थापना की गई। इस बैंक को संक्षेप में 'नाबार्ड' या 'राष्ट्रीय बैंक' कहते हैं। संस्थागत वित्त एवं साख के सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना अपना विशेष महत्व रखती है। इस तरह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सर्वोच्च संगठन के रूप में रिजर्व बैंक के कृषि-साख विभाग के सारे महत्वपूर्ण कार्यों और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के समस्त दायित्व नाबार्ड के अधीन आ गया।¹ इस तरह से नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्तीयन, विकास तथा सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण आदि को अपने अधीन कर लिया। मोटे तौर पर नाबार्ड पुनर्वित्तीयन तथा ऋण अग्रिमों द्वारा मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य स्वीकृत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन, विपणन एवं विनियोग सम्बन्धी क्रियाओं हेतु कृषि, ग्रामीण विकास, लघु स्तरीय उद्योगों, विकेन्द्रीत एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों एवं दस्तकारी और अन्य ग्रामीण शिल्पकारी तथा अन्य सम्बन्धित ग्रामीण आर्थिक क्रियाओं हेतु वित्त प्रदान करता है। कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की तरह नाबार्ड भी अपने स्वीकृत योजनाओं के लिये दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था ऋणों और अग्रिमों से करता है। साथ ही साथ यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उद्देश्यानुसार नाबार्ड के कुल वित्तीयन का सहकारी वित्तीयन सहयोग लघु सिंचाई योजनाओं में गया है और अवशेष कृषि मशीनीकरण, भण्डारण, एवं विपणन केन्द्र, भूमि विकास, वृक्षारोपण, बागवानी, मत्स्य पालन, डेरी विकास तथा अन्य कार्यों में हुआ

1. S.B.Gupta, Monetary Economics, Institutions, Theory and policy, 1982, p.79.

है। इस तरह रिजर्व बैंक के एक सर्वोच्च संगठन के रूप में नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु उन वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्तीयन प्रदान करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त में सम्बन्धित हैं। इन संस्थाओं को दी गई पुनर्वित्तीयन 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच ही होती है और यह पुनर्वित्तीयन 6.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की व्याज दरसे होती है। इसी के साथ नाबार्ड द्वारा भारत का निर्यात-आयात ऋण भी पुनर्वित्तीयन प्राप्त करता है, जो निर्यातानुमुख लघु उद्योगों के वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है। यह न केवल पुनर्वित्तीयन सुविधा प्रदान करता है, अपितु कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं को नीति एवं दिशा निर्देश भी करती है। 1982-83 से 1987-88 तक नाबार्ड का लेखा वर्ष जुलाई-जून था, किन्तु 1988-89 में लेखा वर्ष अप्रैल-मार्च कर देने का निर्णय लिया गया और इसी के अनुसार वर्तमान में लेखा वर्ष अप्रैल-मार्च है। 1988-89 लेखा वर्ष 9 माह की अवधि अर्थात् जुलाई, 1988 से मार्च 1989 तक ही रहा है।²

6.2 नाबार्ड के कार्य एवं संगठनात्मक संरचना

जहाँ तक नाबार्ड के योगदान एवं संगठनात्मक संरचना का प्रश्न है, यह ग्रामीण साख व्यवस्था के केन्द्र रूप में स्थापित की गई है तथा साथ ही साथ ग्रामीण साख संस्थाएँ- व्यापारिक बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को सहायगी वित्त प्रदान करने हेतु स्थापित की गयी है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड की स्थापना का कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बँक अधिनियम 1981 में निर्दिष्ट इसके योगदान को उद्धृत किया जा सकता है-

"-----providing credit for the promotion of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promoting integrated rural development and securing prosperity of rural areas and for matters connected therewith or incidental thereto."

2. NABARD, Annual Report, 1988-89, p.5.

इस सन्दर्भित एक्ट के अनुसार नाबार्ड को बहुत विस्तृत और परिवर्तनशील महत्वपूर्ण निम्नलिखित कार्य दिये गये है -

- 1 सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अल्पकालीन, मध्य कालीन एवं दीर्घ कालीन पुनर्वित्तीयन करना,
- 2 कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण के पक्ष में व्यापारिक बैंकों का पुनर्वित्तीयन करना,
- 3 कुछ विशिष्ट दशाओं में प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना,
- 4 कृषि, सम्बन्धित क्रियाएँ, ग्रामीण कलाकारों एवं उद्योगों तथा अन्य ग्रामीण विकास के लिये साख हेतु विकास नीतियों, नियमों और क्रियान्वयन सम्बन्धी शर्तों पर नियंत्रण करना,
- 5 ग्रामीण विकास एवं कृषि साख हेतु प्रशिक्षण, शाख एवं परामर्श सम्बन्धी कार्यों का करना,
- 6 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण विकास क्रियाएँ के संवर्धन हेतु सभी कृषि एवं ग्रामीण ऋण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना,
- 7 राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों के परामर्श, सुझाव एवं निर्देशन हेतु सदैव तत्पर और उपलब्ध रहना।³

मोटे तौर पर इन गैर कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण एवं साख संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करना,
- 2 संस्थागत विकास को प्रोत्साहित करना अथवा नवीन संस्थाओं को लाना,
- 3 ग्राहक बैंकों का निर्माण निर्देशन एवं मूल्यांकन करना।

इस सन्दर्भित क्षेत्रों में सफलता या असफलता सम्बन्धी किसी निर्णय दान से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि अपने दायित्व की अवधि में नाबार्ड ने अपन सहकारी बैंकों का पुनर्वित्तीयन महत्वपूर्ण विस्तार किया है, ग्रामीण कार्यों के बढ़ते दर से गैर कृषि फार्म क्षेत्रों में विविधीकरण करने हेतु कदम उठाना, विशिष्ट उद्योग कार्यक्रमों तथा सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सहयोग देना

3. Report of the National Cultural Credit Review Committee, pp. 368-370.

रहा है। किन्तु समयान्तर में यह पाया गया कि इसके द्वारा पुनर्वित्तीयन क्रिया अधिक महत्वपूर्ण रही, जबकि अन्य दो क्रियाओं का महत्व, जो दूसरे स्थान पर रहे, नाबार्ड का विकासात्मक योगदान कम महत्व का है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि अधिक व्यापक नवपर्वतक तथा दूर दृष्टिगामी प्रेरकों के दृष्टिकोण से अपने ग्राहक बैंको, अन्य अगो, राज्य सरकारों तथा विकास खण्डों और ग्राम स्तरों को लिया जाय। यदि देश के ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड को नतुत्व का योगदान करना है तो कृषि परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्तीयन के अलावा अपनी क्रिया-कलापों का इन्हें विस्तृत करना होगा। जैसा कि नाबार्ड के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से स्पष्ट है कि इसका प्रधान महत्व और योगदान अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों हेतु वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करना है, जबकि शर्त निदिष्ट विनियोग साख का पुनर्वित्तीयन सभी ग्राहक बैंकों को उपलब्ध रहता है, परन्तु उत्पादन और विपणन हेतु अल्पकालीन ऋण तथा विनियोग हेतु मध्यकालीन ऋण केवल सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक ही सीमित है।⁴ पिछले वर्षों में हर तरह के ऋणों का समग्र बँटवारा सारणी-6 में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह का बँटवारा, जो इस सारणी के तीसरे कॉलम में है, यह नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों का सम्मिलित करता है।

सारणी-6 ।

वितरित पुनर्वित्तीयन की कुल मात्रा
(रूपये करोड़)

वर्ष (जुलाई - जून)	कुल वितरित अल्पावधि/ मध्यावधि/ दीर्घावधि	अल्पावधि/ मध्यावधि	दीर्घावधि - संवितरण मात्रा	योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1982-83	3,911	3208	703	4957
1983-84	3,882	2990	892	4961
1984-85	3,410	2349	1,061	5601
1985-86	3,788	2596	1,192	7964
1986-87	4,282	2948	1,334	10099
1987-88	5,402	3920	1,482	9995

Source-Report of the Agricultural Credit Review Committee,
Reserve Bank of India.

नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन कार्यों की सुविधा हेतु मोटे तौर पर दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। दीर्घकालीन विनियोग वित्त तथा अल्पकालीन उत्पादन एवं विपणन वित्त, जैसा कि सारणी -6 2 में स्पष्ट है कि दीर्घकालीन विनियोग वित्त, जो नाबार्ड के ग्राहक बैंकों द्वारा वितरित किया गया है, वह लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति को सूचित करता है।⁵

सारणी-6 2

दीर्घकालीन पुनर्वित्त सवितरण

(रुपये करोड़)

वर्ष (जुलाई-जून)	राज्य सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राज्य भूमि विकास बैंक	वाणिज्य बैंक	जोड़
1982-83	45	1 61	235	362	703
1983-84	41	1 87	314	450	892
1984-85	37	1140	314	570	1061
1985-86	36	1158	337	661	1192
1986-87	65	1208	433	628	1334
1987-88	64	1216	467	735	1482
(जुलाई-मार्च)					
1988-89	75	1212	381	602	1270
(अप्रैल-मार्च)					
1989-90	115	287	559	741	1702
1990-91	114	289	565	939	1902
1991-92	149	295	658	952	2054

स्रोत- नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 1982-83 से 1991-92

जहाँ तक इन पुनर्वित्तीयन दीर्घकालीन विनियोगों को स्रोतानुसार बँटवारे का प्रश्न है, उसमें वाणिज्य बैंक और भूमि विकास बैंक महत्वपूर्ण सस्थाएँ हैं। इनमें भी वाणिज्य बैंकों का योगदान विशेष रहा है। फलतः उनमें अतिदेय की समस्या के कारण पुनर्वित्तीयन योग्यता की घटती हुयी स्थिति उत्पन्न हो गयी। 1991-92 में कुल पुनर्वित्तीयन ₹2054 करोड़ रुपये का लगभग आधा भाग ₹46.3 प्रतिशत वाणिज्य बैंकों द्वारा था, जबकि भूमि विकास बैंकों का एक तिहाई से कम ₹32.0 प्रतिशत था और राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम था। यह क्रमशः 7.3 और 14.4 प्रतिशत था।⁶

नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्तीयन की व्यूह नीति प्रारम्भ से ही ऐसी क्रिया कलाओं के पुनर्वित्त से सम्बन्धित रही, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के ससाधनों और तकनीकी अवसरों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके। इस तरह से राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण सीमित ससाधन, भूमि की उत्पादकता और उसके सवर्धन पर प्राथमिकता दी गयी, चूँकि भारत कृषि जोत क्षेत्र प्रसार की अपनी अधिकतम सीमा पर पहुँच रहा है। अतः कृषि उत्पाद एवं उत्पादिता को मुख्य रूप से लघु सिंचाई योजनाओं, भूमिगत जल, भूमि को जल प्रयोग हेतु उपयुक्त बनाना, कृषि क्रियाओं में यन्त्रीकृत करना, भूमि प्रयोगों में विविधीकरण लाना तथा बागवानों पर विशेष जोर दिया गया। उद्देश्यानुसार नाबार्ड द्वारा दिये गये पुनर्वित्तीयन के विवरण को सारणी 6.3 में प्रस्तुत किया गया है। यह स्पष्ट है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ से ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इस तरह जल-प्रबन्ध की सुचारू व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। इसी तरह कई राज्यों में अपर्याप्त शक्ति और ऊर्जा के सम्बन्ध में नाबार्ड ने राज्य विद्युत परिषदों को पुनर्वित्तीयन सहयोग दिया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के कार्यों के सवर्धन हेतु।

नाबार्ड अपनी व्यूह नीति में सिंचित क्षेत्रों के वित्तीयन हेतु प्रायोगिक (प्रायलेट) आधार पर एक साख-पैकेज को चक्रीय साख के रूप में कृषि भूमि की उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भ किया है।⁷ इस सम्बन्ध में यदि साख पूर्ति इन क्षेत्रों में नयी तकनीकी क्षेत्रों के सन्दर्भ में की जाती है तो

6. NABARD, Annual Report, 1991-92, p. 118.

7. NABARD, Annual Report, 1988-89, p.17.

सारणी 6 3

दीर्घकालीन पुनर्वित्तीयन - नाबार्ड द्वारा प्रयोजनवार सवितरण

(करोड रूपये)

वर्ष (जुलाई - जून)	लघु सिंचाई	भूमि विकस	स मन्वित ग्रामीण विकस कार्यक्रम	कृषि मशीनी - करण	पशुपालन एव मत्स्य - पालन	बागवानी एव वानिकी	अन्य	योग
1982 - 83	224	21	185	147	-	31	75	103
1983 - 84	312	29	233	204	-	43	71	892
1984 - 85	335	43	354	170	-	49	110	1061
1985 - 86	385	27	376	200	13	73	118	1192
1986 - 87	460	26	379	192	18	77	182	1334
1987 - 88	473	25	448	200	20	94	222	1482
(जुलाई - मार्च)								
1988 - 89	387	18	403	158	27	76	201	127
(अप्रैल - मार्च)								
1989 - 90	498	11	549	225	31	114	274	1702
1990 - 91	496	16	602	338	33	108	309	1902
1991 - 92	502	14	647	381	44	121	345	2045

Source: NABARD, Annual Report 1982 - 83 to 1991-92.

बैंकों के लिये अपनी ऋण नीतियों में परिवर्तन करना अपरिहार्य हो जाता है। इसी के साथ-साथ नाबार्ड का ध्यान एक दूसरे क्षेत्र की ओर आकृष्ट किया है, वह है, गैर-कृषि-फार्म क्षेत्र। इस क्षेत्र में ऊँची आय और रोजगार सृजन शक्ति के कारण नाबार्ड ने इस क्षेत्र में साख को प्रोत्साहित करने में कई कदम उठाये हैं और इस सम्बन्ध में शत-प्रतिशत पुनर्वित्तीयन किया जाता है। सिंचित कृषि के अतिरिक्त नाबार्ड के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, वानिकी तथा बेकार भूमि का विकास महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अपनी पुनर्वित्तीयन का एक बहुत बड़ा भाग मध्यम, लघु और सीमान्त कृषकों, कमजोर वर्गों, कृषि श्रमिकों तथा अन्य ग्रामीण निर्धनों के लाभ हेतु प्रदान किया गया है और इस तरह सिंचित परियोजनाओं के अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड का पुनर्वित्तीयन द्वितीय स्थान का रहा है। इसी तरह क्षेत्रानुसार औसत रूप से नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन का 20 प्रतिशत उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, 15 प्रतिशत पश्चिमी और पूर्वी राज्यों (प्रत्येक को), 19 प्रतिशत उत्तरी राज्यों, 21 प्रतिशत केन्द्रीय राज्यों तथा 28 प्रतिशत दक्षिण राज्यों को हुआ है।

नाबार्ड का पुनर्वित्त व्यवस्था अल्पकालीन उत्पादन एवं विपणन मोटे तौर पर राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित रहा है। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण मौसमी कृषि कार्यों के लिये फसल-ऋण दिया गया। विभिन्न वर्षों में सहकारी बैंकों ने फसल ऋण को अपने ससाधनों तथा रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के पूरक प्रयासों से हुआ है। फसल ऋण के वितरण को सहकारी बैंकों और नाबार्ड से सहायता को सारणी- 6 4 में प्रदर्शित किया जा सकता है।

देश में, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम, समन्वित चावल विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम, विशेष जूट विकास कार्यक्रम तथा वर्षा सिंचित कृषि के लिए एक राष्ट्रीय वाटर शेड विकास कार्यक्रम जैसे अनेक विशिष्ट योजनाओं हेतु नाबार्ड ने विशेष और अतिरिक्त साख सुविधाओं को ग्राहक बैंकों के माध्यम से उदार आधारों पर वित्तीयन किया है।

आयोजना और अनुप्रवर्तन के माध्यम से ग्रामीण ऋण की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड ने 1987 में सभाव्यतायुक्त ऋण योजनाएँ तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये योजनाएँ,

सारणी 6 A

सहकारी बैंको तथा नाबार्ड सहयोग से वितरित फसल ऋण

(करोड रुपय)

वर्ष (जुलाई - जून)	वितरित फसल ऋण	नाबार्ड का सहयोग	नाबार्ड क पुनर्वित्तीयन का प्रतिशत
1982 - 83	1908	858	45
1983 - 84	2158	803	37
1984 - 85	2323	868	37
1985 - 86	2747	873	32
1986 - 87	2620	936	36

Source: Report of the Agricultural Credit Review
Committee, RBI

ससाधन सपदाओं और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को अधिक यथार्थ तरीक से प्रतिबिम्बित करती है और कृषि विकास के कार्य में लगी एजेंसियों से सहबद्धता स्थापित करती है। आधारभूत स्तर पर ऋण आयोजना की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिये नाबार्ड ने जिलों में जिला विकास प्रबन्धक कार्यालय खोले हैं, जो जिले के विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सस्थागत ऋणों की ऋण आयोजना, अनुप्रवर्तन और पर्यवेक्षण से संबंधित समस्त कार्यकलापों के लिये नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। अभी तक 150 जिला विकास प्रबन्धक कार्यालय खोले जा चुके हैं और आगामी दो से तीन वर्षों में देश के शेष जिलों में भी जिला विकास प्रबन्धक कार्यालय खोलने की नाबार्ड की योजना है।⁸

नाबार्ड के पुनर्विक्तीयन व्यवस्था के प्राविधान के अन्तर्गत यह अधिकृत सस्थाओं के पुनर्विक्तीयन के अलावा सीधे कित्त तथा ऋण प्रदान कर सकती है। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सस्थागत व्यवस्था कमजोर है। इस तरह नाबार्ड के प्रत्यक्ष ऋण एवं साख व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि विकास सस्थाओं के ग्रामीण साख व्यवस्था के कित्तीयन हेतु यह सीधे विस्तृत दृष्टिकोण और क्षेत्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में कर सकती है। इस सम्बन्ध में पूर्वी विकास निगम तथा उत्तरी-पूर्वी राज्य इस प्रत्यक्ष ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।⁹

यहां पर नाबार्ड के विभिन्न कार्यों का पुनर्जवलोकन महत्वपूर्ण होगा और इस सम्बन्ध में इसके सस्थागत विकास को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें ग्रामीण कृषि को सस्थागत करने का उद्देश्य रखा गया था, परन्तु यह बात स्पष्ट हुयी है कि बहुत से ऐसे कारक, जैसे ऋण के लक्ष्य, वर्ग, खराब ऋण वसूली, प्रशासनिक ऋण दरों आदि से ग्रामीण साख सस्थाओं की शक्ति में कमी किये हैं। इस सम्बन्ध में नाबार्ड के सस्थागत कार्यों के विकास के सम्बन्ध में स्पष्ट मात्रात्मक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए तथा समस्त कार्यों और कार्यक्रमों के समन्वय प्रक्रिया को सस्थागत संरचना में पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नाबार्ड तथा अन्य संगठनों के सम्बन्ध को मजबूत बनाने

8. NABARD, Annual Report, 1992-93, p.49.

9. Bank Finance for Rural Development (Ed.) L.K. Naidia, p. 249-255.

चाहिए। नाबार्ड को अपने सम्बन्धित बैंकों में प्रशिक्षण क्रियाओं का सम्प्राप्त विकास का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

जहाँ तक नाबार्ड के कार्यों में निरीक्षण कार्य सम्बन्धित है, उसके पुर्नविनायन में रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के समय-समय पर दिये गये निर्देशों एवं नीतियों का पालन सुनिश्चित करना चाहिये। इन सब का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को एक मजबूत आधार बैंक नियम एवं परिनियम के मन्दर्भ में देना है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड को प्रदत्त लाइसेंसों को देने तथा वापस लेने का अधिकार नहीं है। यह मात्र निरीक्षण किये हुये लाइसेन्सों का विवरण रिजर्व बैंक को मस्तुति कर सकता है। महकारी नगण सस्थाओं में उनकी केवल बैंकिंग तथा वित्तीय क्रियाएँ नाबार्ड के नियन्त्रण में आती हैं और इन सम्प्राप्तों का प्रबन्ध एवं व्यवस्था कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट एवं नियम में निर्धारित होती है। इस तरह नाबार्ड के निरीक्षण कार्य में कई बाधाएँ हैं और अपने कार्यों को सम्पादित कराने में रिजर्व बैंक या महकारी साख नीति के रजिस्ट्रार का माध्यम लेना पड़ता है। ऐसे निरीक्षण बैंकों के नियमानुसार कार्य सम्पादन को निर्देशित नहीं करते। निरीक्षण रिपोर्टों का प्रयोग नाबार्ड, बैंक एवं अन्य एजेन्सियाँ द्वारा बहुत कम प्रयोग किया जाता है और इस तरह नाबार्ड के कार्यों और निरीक्षण कार्यों में बहुत सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण होगा कि नाबार्ड अपने निरीक्षण के उद्देश्य को पुन स्पष्ट करे, जिससे नाबार्ड के अनेक कार्यों को पूरा किया जा सके और बैंकों के निष्पादन में सुधार किया जा सके। निरीक्षण रिपोर्टों के क्षेत्र और विषयवस्तु मस्तुति हेतु बैंकों को सही दिशा-निर्देश हेतु दी जानी चाहिये।

नाबार्ड के सगठनात्मक सरचना और इसमें आवश्यक परिवर्तन को स्पष्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सगठनात्मक सरचना का प्रश्न है वह मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के पारस्परिक सम्बन्ध से है और इन दोनों के स्पष्ट कार्य विभाजन तथा दायित्वों से है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर नाबार्ड के कार्यों के सहायता हेतु स्थापित करने की आवश्यकता है और इस तरह जिला स्तर पर ये कार्यालय प्रतिनिधित्व करेंगे और स्थानीय दशाओं के आवश्यकतानुसार नाबार्ड के कार्यों में सहयोग करेंगे। इसी तरह नाबार्ड के उच्च सगठनात्मक स्तर पर वरिष्ठ प्रबन्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर मोटे और आधारभूत नीतियों का दायित्व होना चाहिये और उन्हें अधिकार एवं

स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिये। इसी तरह नाबार्ड के आन्तरिक सगठनात्मक और विभिन्न क्षेत्रों तथा कार्य-परिषद समितियों के अधिकार और क्षेत्र में कार्यागत कमियों को दूर करना चाहिये। इसी तरह जहाँ तक नाबार्ड के सलाहकार परिषद का प्रश्न है, इसमें उच्च स्तरीय विशिष्ट सलाह और ज्ञान परिषद का गठन होना चाहिये और उसमें सदस्यों की विशेष योग्यता तथा क्षमता के आधार पर विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, सम्बन्धित बैंकों, सरकारी विभागों तथा अन्य जुड़ी संस्थाओं को होना चाहिये। इस सलाहकार समिति के इकाई रूप में स्थानीय सलाहकार समिति राज्य स्तर पर गठित की जानी चाहिये और राज्य एवं क्षेत्र स्तर के नीति-नियोजन से सम्बन्धित बातें नाबार्ड तक सन्तुष्टि की जानी चाहिये। इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य नाबार्ड के नीतियों को कार्यान्वित करने में व्यवहारी नीति सम्बन्धी परिवर्तनों और उनको प्रारम्भ करने से है और सभी कार्यागत सम्बन्धों में ग्राहक वर्गों में सेवा-मानकों को स्थापित करना तथा साथ ही साथ नाबार्ड के सगठनात्मक तथा व्यवस्थात्मक विकास में आवश्यक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने से है। इसी तरह नाबार्ड के नियंत्रणात्मक योगदान के स्थान पर विकास और सेवा प्रवृत्ति विकसित करने की है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड को प्रभावी क्षेत्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण की पूरी जानकारी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में नियुक्त लोगों की बढ़ी हुयी उत्प्रेरणा की आवश्यकता है और इसके लिये दायित्व-अधिकार और कार्य-निर्वाह विवेचना का स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस तरह नाबार्ड में एक अधिक खुला तथा भागदारी आधार पर व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे इन परिवर्तनों के साथ नाबार्ड का स्वरूप निखर सके और जिनमें नाबार्ड अपने अस्तित्व को एक सह-संस्था के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु स्थापित कर सके। इस तरह उपयुक्त श्रम-शक्ति, विकास प्रशिक्षण आदि द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है।

ग्रामीण साख के एक सह संस्था के रूप में नाबार्ड का यह एक प्रमुख कार्य है कि वह सूचनाओं को प्राप्त करे और उनको न केवल अपने लिये विश्लेषित करे, अपितु ग्राहक वर्गों तथा अन्य संस्थाओं की सुविधा और समन्वय हेतु विभिन्न स्तरों पर नीतियों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करे नाबार्ड के वर्तमान व्यवस्था के सूचना सम्बन्धी पुनर्विलोकन, दिशा-निर्देशन तथा अन्य कार्यों

मूल्यांकन एवं उनके कम्प्यूटरीकरण हेतु यह आवश्यक समझा गया कि एक नये सूचना एवं मूल्यांकन विभाग की स्थापना की जाए, जो मोटे तौर पर नाबार्ड के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के उच्च प्रबन्धकीय स्तर, क्षेत्रीय अधिकारियों, सदस्य संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं तक पहुँचाये। नाबार्ड के अलावा अन्य संस्थाओं से महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करे और नाबार्ड को इनसे अवगत कराये। इस तरह इस विभाग की स्थापना से नाबार्ड की प्रबन्धकीय व्यवस्था में पुनर्वित्तीयन, संस्थागत विकास, निरीक्षण, वित्त तथा प्रशासनिक क्रियाएँ अधिक सुनिश्चित हो जायेगी।

नाबार्ड ने अपने संगठनात्मक व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण हेतु कदम उठाये हैं और एक कम्प्यूटर सेवा अनुभाग स्थापित किया है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पर नाबार्ड कार्य-कलापों में कम्प्यूटरीकरण का प्रारंभ करना है। इस तरह नाबार्ड की कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था नीति उन आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये, जो नाबार्ड की क्रियाओं और उद्देश्यों का प्राप्त करने में सहयोगी हों। प्रमुख उद्देश्यों के सम्बन्ध में पुनर्वित्तीयन के मुख्य कार्य, संस्थागत कार्य और निरीक्षण क्रियाओं के क्षेत्रीयकरण तथा इनके विकास और प्रभावों के मूल्यांकन एवं दिशा-निर्देशन को प्रभावी बनाने तथा निर्णय प्रक्रिया में सहायता हेतु समयानुसार महत्वपूर्ण और तथ्य-परक सूचनाओं को प्रस्तुत करना है।

इसी तरह नाबार्ड की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य बातें, शोध एवं विकास फंड की स्थापना है, जिसके अन्तर्गत और व्यवहारिक शोध के द्वारा नाबार्ड की परियोजनाओं के मूल्यांकन आदि का सहयोग प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण होगा कि इस फंड का प्रयोग ग्रामीण विकास में नये तथा व्यवहारिक अभिरूचियों और कार्य-कलापों को प्रोत्साहित, विकसित, मूल्यांकित और स्थापित करने में किया जाना चाहिये। इस तरह इस फंड के प्रयोग हेतु कुछ व्यवस्था नीति कार्य-योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। व्यापक परियोजनाओं के निर्माण हेतु चयनित क्षेत्रों तथा फार्म क्षेत्रों तथा चयनित खंडों में गहन अध्ययन में वित्तीयन करना और प्रशासनिक एवं ग्राहक बैंकों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना और इस तरह अपने ग्राहक बैंकों के दिशा-निर्देशन, मूल्यांकन और निरीक्षण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना तथा कृषि साख क्षेत्र के लिये एक दीर्घकालीन कम्प्यूटर व्यवस्था नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीयन, निर्देशन एवं समन्वय स्थापित करना है।

वर्ष 1993-94 के बजट में कृषि ऋण प्रणाली का फिर से मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि यह पूँजी-निर्माण और कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का एक अधिक कारगर साधन बन सके। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने हेतु नवीन ऋण मुश्त उपाय सुझाया गया है।

बजट में बेको को नाबार्ड की निवेश पुनर्वितीयन सहायता 2500 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, जो पिछले वर्ष {1992-93} के लिये निर्धारित 2300 करोड़ रुपये में 22 प्रतिशत अतिरिक्त है। इसी प्रकार सस्थागत स्रोतों से ग्रामीण ऋण प्रवाह में 20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। करोड़ रुपये से बढ़कर 16,600 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। बैंक उधारों के नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण की दर को उत्तर-पूर्व राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत तक और कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों के शत-प्रतिशत निर्यातमुखी इकाइयों के निवेश के संबंध में इसकी वृद्धि करने का प्रावधान है। नाबार्ड 125 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच चुने जिलों में ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के लिये प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारंभ करेगा। नाबार्ड कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में नवीन निवेशों के सहायतार्थ 2 करोड़ रुपये के आरम्भिक संग्रहण से एक उद्यम पूँजी निधि और सहकारी बैंकों में प्रबंध प्रणालियाँ और दक्षताओं को सुधारने में सहायता देने के लिये 10 करोड़ रुपये के आरम्भिक संग्रहण से एक सहकारी विकास निधि की स्थापना करेगा।¹⁰ वित्तीय वर्ष 1993-94 की द्वितीय छमाही के लिये घोषित साख नीति के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को ओर अधिक ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये नाबार्ड की ऋण सीमा ₹ 400 करोड़ बढ़ा दी गयी। यह वर्तमान में ₹ 3300 करोड़ से बढ़कर ₹ 3700 करोड़ हो गयी है।

6.3 नाबार्ड संसाधन एवं लाभकारिता-कुछ प्रक्षेप

कृषि एवं ग्रामीण साख पूर्ति तथा आवश्यकता के निमित्त अनुमानों के आधार पर यह स्थापित किया गया कि 1994-95 तथा 1999-2000 में साख व्यवस्था में क्रमशः ₹ 5,487 करोड़

10 27 फरवरी, 1993 को संसद में वर्ष 1993-94 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के भाषण से उद्धृत।

रु० 21,426 करोड का समग्र घाटा होगा। अतः साख व्यवस्था में सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंक स्वभावतः इस घाटे को पूरा करने के निमित्त पुनर्वित्तीयन हेतु नाबार्ड की ओर उन्मुख होंगे तथा साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि नाबार्ड के ससाधन मात्र इन्हीं सीमाओं तक सीमित न होंगे, अपितु कई कारणों से इससे अधिक होंगे। प्रधानतः भूमि विकास बैंक, जिनका अपना कोई ससाधन नहीं है तथा अपने ऋण क्रियाओं में ससाधन हेतु पूरी तौर पर नाबार्ड पर आश्रित हैं और इसी तरह नाबार्ड का पुनर्वित्तीयन सहकारी बैंको और व्यापारिक बैंका दोनों का उपलब्ध है, जिसका नाम व्यापारिक बैंक उठाते हैं तथा नाबार्ड का पुनर्वित्तीयन सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का फसल ऋण हेतु पुनर्वित्तीयन हेतु उपलब्ध रहता है।

साख सम्बन्धी प्रक्षेपों में फसल ऋण हेतु मांग व्यापारिक और सहकारी बैंका दोनों द्वारा सन् 2000 तक रु० 53,534 करोड अनुमानित किया गया है ¹¹ और इसमें सहकारी बैंकों और व्यापारिक बैंको का योगदान दोनों 50 प्रतिशत अनुमानित किया गया, चूँकि व्यापारिक बैंका 4 पागल पर्याप्त ससाधन होंगे, अतः वे फसल ऋण हेतु नाबार्ड से पुनर्वित्तीयन कम प्राप्त करेंगे और वर्तमान समय में इस उद्देश्य हेतु नाबार्ड उन्हें पुनर्वित्तीयन अनुमोदित नहीं करता। यह ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न वर्षों के सन्दर्भ से सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीयन क्रमशः घट रहा है। यद्यपि 1980-87 87-88, 88-89 में यह तेजी से बढ़ा है। इस सम्बन्ध में यह प्रस्तावित किया गया है कि सहकारी बैंको की आश्रिता 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हानी चाहिये।

वर्ष 1993-94 में नाबार्ड ने पुनर्वित्तीयन का पिछले वर्ष 1992-93 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक रखा है। 1992-93 में पुनर्वित्तीयन सहायता 2200 करोड निर्धारित किया गया था। अपने सस्थापित वर्ष 1982-83 में रु० 703 करोड में बढ़कर यह 1993-94 में रु० 2800 करोड हो गया। इस सम्बन्ध में नाबार्ड अपने पुनर्वित्तीयन कार्यक्रम को लघु सिंचाई परियोजनाओं और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख अवयवों में जारी रखेगा। इसी तरह कृषि क्षेत्र में यन्त्रीकरण एवं ट्रैक्टर आदि हेतु पुनर्वित्तीयन नीति को जारी रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ ज

11. RBI, Report of the Agricultural Credit Review Committee, p. 397.

भराव तथा शुष्क कृषि, फार्म, वानिकी, अनुपयुक्त भूमि विकास परियोजनाओं आदि हेतु पुनर्वित्तीयन पर विशेष बल दिया जायेगा।¹²

'ए रिब्यू ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इन इण्डिया' में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1994-95 तथा 1999-2000 के लिये सावधि साख माग का अनुमान क्रमशः ₹0 29,450 करोड़ तथा ₹0 57,339 करोड़ अनुमानित किया है। इसमें वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों का योगदान क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत है।¹³ इसका विवरण सारणी-6 5 में दिया गया है -

सारणी-6 5

सावधि साख माग में वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों का योगदान
(भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वाणिज्य बैंक (65 प्रतिशत)	सहकारी बैंक (35 प्रतिशत)	योग
1994-95	19,143	10,307	29,450
1999-2000	37,270	20,069	57,339

स्रोत - ए रिब्यू ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इन इण्डिया

उपर्युक्त ऑकड़े अन्तिम ऋण ग्राहकों के स्तर पर होने वाले ऋण का प्रदर्शित करते हैं। सामान्यता नाबार्ड 75-90 प्रतिशत तक बैंकों को पुनर्वित्तीयन करता है और 10-25 प्रतिशत बैंकों द्वारा किया जाता है। 1985-86 के अंत तक नाबार्ड ने एमए ऋणों के 41 प्रतिशत अंश का किया था। इस तरह नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन का प्रक्षेप इन ऋणों के लिये 1994-95 तथा 1999-2000 के लिये क्रमशः ₹0 14,725 तथा ₹0 29,669 करोड़ अनुमानित है। नाबार्ड की सहायता की स्थिति में इन पुनर्वित्तीयन अनुमानों के लिए उत्पन्न की जायेगी, उसका विवरण नीचे दिया गया है। इन अनुमानों

12. National Bank News Review, Dec 1990 pp 21-23

13. R.K Narula, Agricultural & Rural Advances by Commercial Bank, 1984, pp 479-485

के अलावा नाबार्ड ने स्वयं अपने पुनर्वित्तीयन सहयोग हेतु आठवीं योजना अवधि के लिए कुछ समर्थन किये हैं। इस तरह नाबार्ड के वित्तीय प्रक्षेपों का नीच दिया जा सकता है।

सारणी-6 6

नाबार्ड के वित्तीय प्रक्षेप

(रुपये करोड़)

संसाधनों की मांग	1990-91 - 1994-95
नियमित किये जाने वाले ऋण एवं अग्रिम	18,531
पुनर्भगतान	750
योग	19,281
संसाधनों की पूर्ति	
ऋणों की वसूली	10,283
राशास्त्र (दी अप) निधि में	
भारतीय रिजर्व बैंक का योगदान	1,650
राशास्त्र (दी अप) निधि में	
नाबार्ड के लाभों में से योगदान	2,509
भारत सरकार से उधार	
योग	14,501
घाटा	4,780

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदर्शित घाटे का किस तरह पूरा किया जायेगा, किन्तु इस घाटे की पूर्ति बाजार या सरकार या अन्य विकल्पों से उधार लेकर किया जायेगा। यहाँ यह निदिष्ट किया जा सकता है कि यह अनुमान विन्त के प्रवाह का प्रदर्शित करना है न कि स्टॉक को। यहाँ आठवीं योजना के साथ-साथ नवीं योजना के भी अनुमानों का प्रस्तुत किया गया है और इस तरह नाबार्ड से पुनर्वित्तीयन का अनुमान 1994-95 तथा 1996-2000 तक क्रमशः ₹ 15,079 करोड़ तथा ₹ 26,389 करोड़ अनुमानित किया है और इस तरह वार्षिक प्रक्षेपों और उन आधारों को जिन पर वे अनुमानित किये गये हैं, सारणी-6 7 में प्रदर्शित किये गये हैं।

नाबार्ड के पुनर्वित्तीयन प्रक्षेप के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिये सावधि ऋण वितरण

सारणी 6 7

30, जून की स्थिति		1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1090-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-2000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तीयन													
1	सहकारी बैंक	1,807	2,181	2,421	2,688	3,825	4,440	5,157	5,991	6,999	8,247	9,801	17,152
2	सहकारी संस्थाएँ	1,526	1 719	2 040	2,386	2,059	2,391	2,777	3,226	3,769	4,441	5,278	9,237
3	योग	3,333	3,900	4,461	5,074	5,884	6,831	7,934	9,217	10,768	12,788	15,079	26,389
B कुल वितरित सावधि ऋण													
4	सहकारी बैंक	5 136	5,649	6,212	6,834	7,157	9,720	11,178	12,854	14,781	16,998	19,143	37,720
5	सहकारी संस्थाएँ	3 531	3 884	4 272	4 699	5 168	5,834	6,018	6,917	7,955	9,152	10,307	20,069
6	योग	8 667	9,533	10,485	11,538	12,685	14,954	17,196	19,771	22,736	26,150	29,450	57,339
प्रतिशत 4 1													
5 2		43 21	44 25	47 75	50 77	39 84	45 68	46 14	46 64	47 37	48 52	51 21	46 03
6 3		38 45	40 91	42 54	43 99	46 38	45 68	46 14	46 62	47 38	48 52	51 20	46 02

स्रोत - 1 नाबार्ड का विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट 1

जिन स्रोतों से नाबार्ड वांछित ससाधनों का प्राप्त कर सकता है, उस सरणी 6.8 में प्रदर्शित किया गया है ।

सारणी 6.8

नाबार्ड वांछित ससाधन

(रूपये करोड़)

सद का नाम	1994-95	1999 - 2000
1 भारतीय रिजर्व बैंक का अशदान रु० 400 करोड़ प्रति वर्ष आठवी योजना में, रु० 450 करोड़ प्रतिवर्ष नवी योजना में	2,000	2,250
2 नाबार्ड के लाभ	2,600	4,000
3 बाजार से उधार	800	1,300
4 5.5 प्रतिशत की दर से भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार से उधार	2,248	2,760
5 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के काण्ट्रि पार्ट फंड	600	1,000
6 योग	8,248	11,310

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्शित सारणी के तीसरे, चौथे एवं पाँचवे स्रोतों में ससाधन प्राप्त करने में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होगी और कुछ सीमा तक घाटा पूरा नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर इन ससाधनों के वित्तीयन को नाबार्ड के लाभकरिता पर आधारित किया गया है।

नाबार्ड की स्थापना से यह परिकल्पना थी कि कृषि एवं ग्रामीण साख चुनौतियों के लिये इसके पास पर्याप्त ससाधन होंगे। स्थापना के समय ही नाबार्ड का पूँजी अशदान रु० 100 करोड़ के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय कृषि निगम के फंडों की आदेयों और दायित्वों के रूप में रु० 1390 करोड़ थी। यह स्थान्तरित वित्त लागत रहित ससाधन होने के नाते इक्विटी के समकक्ष माने जा सकते हैं। इस तरह नाबार्ड की ऋण इक्विटी अनुपात बहुत ही अनुकूल रही है और वह लगातार नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के स्थानान्तरित लाभों के कारण सुधरता रहा। इसी तरह इक्विटी फंड के अतिरिक्त नाबार्ड ने ऋण वित्तीयन हेतु कई कदम उठाये हैं। इनका प्रधान स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक, जो हर तरह के अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है, नाबार्ड के तुलन-पत्र वर्ष 1982-83 से 1986-87 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय फंड के स्थानान्तरण होने के नाते नाबार्ड की ऋण इक्विटी अनुपात जो 1.35 से अनुकूलतम रूप में शुरू हुयी, वह और अधिक सुधर कर 1986-87 में 0.81 हो गयी। इस ऊँचे इक्विटी के कारण नाबार्ड ने बहुत ही लाभकरिता के आधार पर कार्य किया है और नाबार्ड के स्वयं के लाभ इसके महत्वपूर्ण फंड के रूप में उत्पन्न हुआ है। वर्ष 1986-87 में यह स्पष्ट होता है कि नाबार्ड को मध्यकालीन और दीर्घकालीन पुनर्वित्तीयन वितरण 6.5 प्रतिशत विभिन्न विकेन्द्रीकृत लघु कृषकों को हुआ है। यहाँ पर ब्याज दर नाबार्ड की लाभकरिता के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः कोई भी विकास कार्य, जो अधिकांशतः वर्तमान ब्याज-दर पर ऋणों के द्वारा वित्तीयन किया जा रहा हो, वह नाबार्ड के लाभकरिता को गिरायेगा। इसके पुनर्वित्तीयन शक्ति को कम करेगा। इस सम्बन्ध में लाभकरिता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित तीन बातें महत्वपूर्ण हैं।

1. नाबार्ड के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक वृद्धि दर 14 प्रतिशत होनी चाहिये और भारतीय रिजर्व बैंक की तरह फंड की कमी को बाजारी ऋणों द्वारा पूरा करना चाहिये। इस स्थिति को सारणी 6.9 में प्रस्तुत किया जा सकता है।

- 2 उपर्युक्त स्थिति के आधार पर उसी वार्षिक वृद्धि दर, बाजारी ऋणों की वृद्धि पर 10 वार्षिक अवरोध किया जाना चाहिये। इस स्थिति को सारणी-6 10 में प्रदर्शित किया जा सकता है।

सारणी- 6.10

वित्तीय स्थिति-मॉडल II

(रूपये करोड़)

तुलन पत्र	1995	2000
ऋण	16887	32514
निवेश	1650	2000
अन्य परिसंपत्तियाँ	929	1788
	19466	36302
पूँजी	100	100
प्रारक्षित निधियाँ *	4911	8642
दीअप तथा स्थिरीकरण निधियाँ**	5760	7635
	10771	16377
उधार भारत सरकार से	5660	15300
भारतीय रिजर्व बैंक	1656	2323
डिबेंचर से	1100	1765
जमाओं से	109	149
अन्य दायित्व	170	388
	19466	36302
निधि (फंड) के स्रोत तथा प्रयोग		
लाभ *	615	831
दी अप तथा स्वीकरण निधियाँ **	375	375
उधार भारत सरकार से	1010	2700
भारतीय रिजर्व बैंक से	108	152
डिबेंचर से	100	160
जमाओं से	7	9
अन्य दायित्व	23	60
	2338	4287
अग्रिम	2074	3993
निवेश	50	75
अन्य दायित्व	114	219
आय और व्यय		
प्राप्त योग्य ब्याज	1327	2381
देय योग्य ब्याज	577	1273
अन्य मद में व्यय	115	244
अनुसंधान और विकास के पूर्व शुद्ध लाभ	632	864
अनुसंधान और विकास पर व्यय	17	33
शुद्ध लाभ	615	831

* नाबार्ड के अपने लाभ में से दीर्घावधि परिचालन (दी अप) और स्थिरीकरण निधि को अंतरित जोड़कर

** भारतीय रिजर्व बैंक का अशदान मात्र

- 3 उपलब्ध फंड तथा बाजारी ऋणों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि स्वीकृत न करना और उसे 10 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ने देना। इस स्थिति को सारणी-6 II में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी-6 II

वित्तीय स्थिति-मॉडल III

(रूपये करोड़)।

तुलन पत्र	1995	2000
ऋण	14290	21660
निवेश	1650	1900
अन्य परिसंपत्तियाँ	785	1190
	16725	24750
पूँजी	100	100
प्रारक्षित निधियाँ*	4968	8954
दी अप तथा स्थयीकरण निधियाँ**	5760	7635
	10828	16689
उधार भारत सरकार से	2916	3666
भारतीय रिजर्व बैंक से	1656	2323
डिबेंचर से	1100	1765
जमाओं से	109	149
अन्य दायित्व	116	158
	16725	24750
निधि (फंड) के स्रोत तथा प्रयोग		
लाभ *	637	915
दी अप तथा स्थयीकरण निधियाँ**	375	375
उधार-भारत सरकार से	150	150
भारतीय रिजर्व बैंक से	108	152
डिबेंचर से	100	160
जमाओं से	7	9
अन्य दायित्व	8	9
	1385	1770
अग्रिम	1265	1630
निवेश	50	50
अन्य दायित्व	70	90
	1385	1770
आय और व्यय		
प्राप्त योग्य ब्याज	1162	1673
देय योग्य ब्याज	411	575
अन्य मद में व्यय	100	162
	511	737
अनुसंधान और विकास के पूर्व शुद्ध लाभ	651	936
अनुसंधान और विकास पर व्यय	14	21
शुद्ध लाभ	637	915

* नाबार्ड के अपने लाभ में से दीर्घावधि परिचालन (दी अप) और स्थयीकरण निधि को अंतरित को जोड़कर

** भारतीय रिजर्व बैंक का अशदान मात्र

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ऋण प्रसार के वित्तीयन को ऋणों द्वारा करने से नाबार्ड की लाभकारिता हतोत्साहित होती है। प्रथम रूप सारणी-6 8 में 1994 में लाभ गिरने लगते हैं और 2000 वर्ष तक नाबार्ड अपने कार्यगत ऋणों को प्रारम्भ कर देता है। इसी तरह सारणी-6 9 में भी स्पष्ट है कि कुछ रियायती दरों पर ऋण के बावजूद नाबार्ड 6 5 प्रतिशत ब्याज दर को देते हुये अन्ततः घाटे में जायेगा, किन्तु तीसरे विकल्प सारणी-6 10 में नाबार्ड की लाभकारिता निम्न वृद्धि दर और लागत के कारण अनुमानित की गयी है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड की लाभकारिता की दृष्टिकोण से सारणी-6 9 में ऋणों को 1994-95 और 1999-2000 के लिये उपयुक्त होगा। एक उदाहरण के दृष्टिकोण से सारणी-6 8 में प्रयुक्त समृद्धि और ब्याजदरों पर आधारित नाबार्ड के इक्विटी योगदान का अनुवर्णन किया गया है, जिसे 1993-94 से 1999-2000 के लिये सारणी-6 12 में दिखाया जा सकता है।

सारणी-6 12

नाबार्ड के इक्विटी योगदान

वर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
इक्विटी योगदान	30	145	285	480	680	905	1145

6 4 नाबार्ड - कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

नाबार्ड के कार्यों तथा सगठनात्मक संरचना को अधिक प्रभावी बनाने हेतु और सही माने में कृषि और ग्रामीण विकास का एक विकासात्मक बैंक स्थापित करने के लिये यहाँ कुछ सुझावों को दिया जा सकता है। यह पाया गया है कि विभिन्न क्रियाओं में समन्वय का अभाव तथा नाबार्ड के पुनर्वित्तीय क्रियाओं के निर्देशन और मूल्यांकन के अभाव के कारण पुनर्वित्तीयन का चक्रीय प्रवाह प्रभावी ढंग से कार्यशील नहीं है।¹² स्थानीय आवश्यकताओं के पुनर्वित्तीयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर

कार्यालयों को सम्बन्धित नहीं किया गया है और इस तरह नाबार्ड के पुनर्विर्त्तीयन क्रियाओं में उच्च स्तरीय नीति और नियोजन की प्रधानता रही है। इस तरह नाबार्ड के पुनर्विर्त्तीयन क्रियाओं के विश्लेषण पर आधारित इनकी कुछ कमियों को प्रकट किया गया है। इसमें विनियोग निर्धारक तत्व योजनाओं का वित्तीयन तथा इकाई लगातारों को दृढ़ रूपों में प्रयोग किया जाता है और परिवर्तनीय स्थायी दशाओं और स्थानों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी तरह फार्म तथा गैर फार्म साख नियोजन तथा अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घ कालीन के वित्तीयन में भी प्रभावी समन्वय का अभाव है और क्षेत्रीय कार्यालयों की जिम्मेदारियों बहुत ही सीमित हैं। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि नाबार्ड ने इन दिशाओं में कुछ कदम उठाये हैं, इनमें प्रधान कार्यालयों के अधिकार को क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप कर पुनर्विर्त्तीयन सम्बन्धी अनेक प्रार्थनापत्रों का निपटारा करना, जिला साख नियोजनों की गुणवत्ता वृद्धि विधियों का विकास करना, राज्य और क्षेत्रवार योजनाओं के वित्तीयन मॉडलों को विकसित करना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान करना। इस तरह इन विभिन्न कार्यों से जिला साख नियोजन व्यष्टि स्तरीय योजना हेतु वास्तविक भूमिका अदा करके उत्पादन साख-समर्थक विनियोग फार्म और गैर-फार्म के क्रियाओं में समन्वय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहयोगी होगा। अन्ततः यह आशा की जाती है कि सेवा क्षेत्र उपागम के अन्तर्गत गांव साख नियोजन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी जिला साख नियोजन से जुड़ सकेगा और इस तरह से व्यष्टि एवं समष्टि साख नियोजन और पूरी साख व्यवस्था में नियोजन स्थापित किया जा सकेगा। इसके भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को अन्य एजेंसियों के साथ प्रतिक्रिया और समन्वय के साथ कार्य करना होगा। इसी तरह नाबार्ड को अपने ग्राहक बैंकों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी, जिससे कि ये बैंक परियोजनाओं के लिये तकनीकी तथा वित्तीय आवश्यकता पूरी कर सकें और नाबार्ड को भी अपने निरीक्षण तथा सन्तुष्टि प्रक्रिया को सुधारने में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि पुनर्विर्त्तीयन का विवरण ग्राहक बैंकों के सुविधानुसार उपर्युक्त स्थान पर होना चाहिये। यद्यपि इस दिशा में नाबार्ड पहले से ही ऋणों के बँटवारे को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कर रहा है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इसमें और शीघ्रता की जाये।

नाबार्ड को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये यह भी सुझाव दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रयोजित बैंकों में मिला देना चाहिये और इस तरह से ससाधनों को महत्वपूर्ण

रूप से अन्य सर्वधनात्मक क्रियाओं में प्रयुक्त करना चाहिये। इस तरह से सारे सुझावों का अभिप्राय यह है कि हम सस्थागत ग्रामीण साख संरचना को स्वनिर्मित रूप में उत्पन्न कर सकें। इन सुझावों के साथ यह आशा की जा सकती है कि एक राष्ट्रीय बैंक के रूप में साख व्यवस्था के नेतृत्व में यह भविष्य में उभरेगा। परन्तु इन सबके लिये आवश्यक है कि नाबार्ड को अधिक से अधिक सहकारी साख व्यवस्था पर सक्रेन्दीत होना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बहुत सी वाणिज्य बैंक शाखाओं को भी साख को अधिक प्रभावी रूप से समायोजित करने के लिये मजबूत बनाना होगा। वस्तुतः यह कार्य नाबार्ड के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है, जिसके बिना साख प्रवाह तथा कसूली का चक्र पूरा नहीं होगा और व्यवस्था स्व निर्मित नहीं हो सकेगी। इसी तरह नाबार्ड को अपने फलनात्मक योग्यता, जो परियोजनाओं, प्रभावीकरण, मूल्यांकन, निर्देश आदि से सम्बन्धित है, को सुधार करना चाहिये, जिससे ग्राहक बैंक इन कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सके। अन्ततः नाबार्ड को अपने निरीक्षण कार्यों तथा विकास कार्यों में अधिक अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना पड़ेगा अर्थात् निरीक्षणों से प्राप्त स्थितियों का उपर्युक्त ढंग से ग्राहक संस्थाओं को मजबूत करने में किया जाना चाहिये। साथ ही साथ नाबार्ड को ऐसे क्षेत्र, जो बेकार भूमि, वानिकी कार्यक्रम, शिल्पकार वर्ग के वित्तीयन तथा कृषि आधारित उद्योगों में पुनर्वित्तीयन को विकसित करना चाहिये। इस तरह नाबार्ड को प्रत्येक जिला में एक अधिकारी की नियुक्ति के द्वारा जिला साख नियोजन के सहयोग तथा ग्राहक बैंकों के सहयोग हेतु होना चाहिये। इन सब महत्वपूर्ण आधारों पर यह समझा जाता है कि इन सभी कार्यों तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाबार्ड को कार्य करना पड़ेगा। परन्तु पहले की उपलब्धियों तथा महत्वपूर्ण कार्य परिवर्तनों के साथ अगले दशक तक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने की सम्भावना है। इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक को सारे शक्तियों, अधिकार नाबार्ड को नीति विषयों में दे देना चाहिए और सहकारी बैंकों को इस दिशा में सहयोग करना चाहिये, जिससे इनकी संरचना और कार्यों को ठोस आधार प्राप्त हो सके।

कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता

(NEED FOR MONETARY AND CREDIT PLANNING
FOR AGRICULTURAL SECTOR)

एक नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि विकास के सामने अनेक वित्तीय समस्याएँ आती हैं, जिनका समाधान मौद्रिक एवं वित्तीय-नीतियों द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। भारतीय कृषि क्षेत्र में साख वितरण एवं कृषि कार्यों के लिए अग्रिमों तथा ऋणों से यह प्राप्त हुआ है कि उनका उत्पादक एवं उत्पादिता में प्रयोग न होकर दुर्प्रयोग हुआ है, जिससे एक ओर मुद्रा एवं साख का विस्तार हुआ है तथा साथ ही साथ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो पा रही है। इन साख सुविधाओं का अनुत्पादक एवं अवाछनीय प्रयोग हुआ है। इससे एक ओर जहाँ अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई है, वहीं देश में मुद्रा स्थिति की प्रवृत्ति पर अधिक दबाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सरचनात्मक परिवर्तन लाने हेतु मुद्रा एवं साख प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए मौद्रिक एवं वित्तीय नीति के साथ-साथ नियोजित मुद्रा योजना तथा नियोजित साख की आवश्यकता है। प्रो० एस० चक्रवर्ती ने अपने रिपोर्ट 'ए रिव्यू ऑफ मॉनेट्री सिस्टम इन इण्डिया' में मौद्रिक लक्ष्यों द्वारा नियोजित मुद्रा एवं साख नियोजन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है।¹ इसी तरह डॉ० पी० डी० हजेला ने अपने ग्रन्थ 'फ़ाबलम्पस ऑफ मॉनेट्री पॉलिसी इन अण्डरडेवलप कन्ट्री' में नियोजित मुद्रा को आधार रख कर सस्ती मुद्रा नीति का विरोध किया है।² इसी क्रम में प्रो० सूरजभान गुप्त ने अपने ग्रन्थ 'मॉनेट्री प्लानिंग इन इण्डिया' में मुद्रा एवं साख नियोजन

-
1. S. Chakravarty, Report of the Committee to Review the Working of the Monetary System, 1985 pp.166-172.
 2. P.D. Hajela, The Problem of Monetary Policy in Underdeveloped Countries, 1966, pp.30-34.

पर अत्यधिक बल दिया है।³ यद्यपि जून 1991 में नरसिंहम कमेटी रिपोर्ट के बाद देश की मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था स्वतंत्र तथा उदारीकरण नीति के आधार पर बाजारी शक्तियों के निर्धारित पूँजीवादी प्रवृत्तियों से सम्बन्धित रही है, तथापि मुद्रापूर्ति एवं साख पूर्ति की नियोजन की आवश्यकता बनी रही है।

7.1 कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नीतियाँ

जहाँ तक कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नीतियों का प्रश्न है, इसका विस्तृत विवरण पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है, फिर भी देश के कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता के सन्दर्भ में अति संक्षेप में इन नीतियों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद विशेषकर से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नीतियाँ महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन एवं उत्पादिता हेतु प्रेरक रही हैं। 1961 के बाद से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख एवं मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हुआ और इनके विकास में मौद्रिक एवं साख नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। मौद्रिक एवं साख नीति में परिवर्तन मुख्य रूप से ऊँचे स्तर के विनियोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिये की गयी।

7.2 मौद्रिक एवं साख नीति की सीमाएँ

देश की कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु यद्यपि मौद्रिक एवं साख नीतियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं, परन्तु सही माने में उनका कृषि एवं ग्रामीण विकास पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहा है। इसका प्रधान कारण यह रहा है कि ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियोजित ढंग से विकासात्मक कार्यों हेतु इन सुविधाओं का प्रयोग नहीं हो पाया है और न ही उत्पादन एवं रोजगार सृजन हेतु इन्हें उपयुक्त बनाया गया है। यद्यपि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ तथा आरक्षित कोष अनुपात विधियों के साथ-साथ अनेक प्रकार के

चयनात्मक साख विधियों को अपनाया है, परन्तु मोटे तौर पर भारतीय मौद्रिक एव साख नीति सस्ती मुद्रा नीति के ही स्वरूप में बनी रही है। देश में अविकसित मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार के रहते हुए तथा सुसंगठित बाजारों के अभाव में सस्ती मुद्रा नीति अधिकांशतः हानिकारक एव स्फीतिकारी रही है। केन्स के मिश्रित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक क्षेत्र में मौद्रिक नीति की एक सीमा है, जिसे तरलता जाल कहते हैं और यहाँ पर मौद्रिक अधिकारी अर्थव्यवस्था को इस जाल से छुटकारा दिलाने के लिए मौद्रिक नीति की असमर्थता को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मौद्रिक नीति के स्थान पर वित्तीय नीति महत्वपूर्ण होती है, जो अर्थव्यवस्था को स्थिरावस्था से हटा कर विकासात्मक प्रवृत्तियों में ले जाती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय मौद्रिक नीति एव साख नीति में व्याज दर का विशेष महत्व नहीं है और मुद्रा पूर्ति एव साख पूर्ति में नियंत्रण तथा नियोजन की आवश्यकता है। यद्यपि कृषि क्षेत्रों की आगतों यथा खादों, रासायनिक उर्वरकों पर अब दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया जा रहा है या समाप्त कर दिया जा रहा है, परन्तु देश के आर्थिक विकास एव सामाजिक न्याय की दृष्टिकोण से, पिछड़े क्षेत्रों एव वर्गों की दृष्टिकोण से, देश के ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक तथा अन्य गरीब जनता तथा उनके लिए उपयुक्त रोजगार के अवसरों के न होते हुए अब भी इस बात की भारी गुंजाइश है कि प्रभावी ढंग से कृषि एव साख का प्रवाह उत्पादक कार्यों के लिए किया जाय।

कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र के साख वितरण के सम्बन्ध में जहाँ उत्पादन एव उत्पादिता का प्रश्न रहा है, वहीं साख, ऋणों की वसूली की भी समस्या रही है। देश के अधिकांश व्यापारिक बैंक एव विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हानि पर चल रहे हैं। वस्तुतः यह आश्चर्य की बात है कि देश में साख-मेला तथा ₹0 10,000 तक के बैंकों के कर्ज को समाप्त किया गया है। भारत जैसे एक निर्धन देश में पर्याप्त ससाधनों के अभाव में इस तरह की क्रियाएँ पूर्वाग्रह तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित रही हैं, जिससे ये बैंक लाभकारिता के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। मौद्रिक नीति से ही अधिक जटिल साख नीति है, जिसमें साख का बँटवारा प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान साख नीति की यह अव्यवस्था रही है कि वह निर्धारित तथा लक्षित उद्देश्यों तक साख सुविधाओं को नहीं पहुँचा पायी और इसका अधिकांश लाभ बड़े तथा शक्तिशाली लोगों द्वारा अनुत्पादक कार्यों के लिए किया गया है।

कृषि एव साख नीति की यह भी सीमा रही है कि मौद्रिक एव वित्तीय नीतियों के अलावा अन्य गैर-वित्तीय मध्यस्थ संस्थाएँ और उनके द्वारा कृषि कार्यों हेतु वित्तीयन पर सरकार तथा मौद्रिक अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं रहा। भारत में सहकारी समिति, अब तक की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में माना गया है, परन्तु उपयुक्त मौद्रिक एव साख नीति न होने के कारण सहकारी साख समितियाँ भ्रष्टाचार के केन्द्र बिन्दु बन गये।

अतः मौद्रिक एव साख नीति के क्रियान्वयन एवं प्रभावी उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि देश की मौद्रिक एव साख नीति, मजदूरी नीति, आय नीति, उपभोग नीति तथा अन्य नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाय।

कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव वित्तीय नीति की असफलता इस दृष्टिकोण से भी रही है कि देश में मुद्रा बाजार, पूँजी बाजार, तथा स्टॉक एक्सचेंज में सम्बन्ध नहीं है और ये असंगठित तथा अविकसित हैं। यही कारण है कि देश में व्याज-दर नीति द्वारा आर्थिक-विकास एवं कृषि-विकास को अत्यधिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। केन्स की मौद्रिक नीति, जो व्याजदर नीति से सम्बन्धित है, वह भारत जैसे अल्पविकसित देश में लागू नहीं होती और इस तरह भारतीय कृषि क्षेत्र में सस्ती मुद्रा नीति अधिक उपयुक्त नहीं है।

7.3 कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नियोजन की प्रकृति तथा क्षेत्र

पिछले अध्यायों से यह स्पष्ट होता है कि देश के कृषि विकास हेतु मौद्रिक एव साख नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। जहाँ तक साख नियोजन का प्रश्न है, वह मौद्रिक नियोजन से अधिक जटिल है। मौद्रिक नियोजन का तात्पर्य समग्र मुद्रापूर्ति एवं साख के नियंत्रण से है, वहीं साख नियोजन का तात्पर्य मुद्रा की मात्रा एवं साख की मात्रा नियंत्रित करने से नहीं है। साख नीति की प्रकृति क्षेत्रवार एवं दिशावार आवंटन करने की है, जो साख के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के बीच की जाती है। जहाँ तक साख के आवंटन का प्रश्न है, वह निम्नलिखित तीन कारणों से महत्वपूर्ण है

1. साख का बटवारा सरकार तथा व्यापारिक क्षेत्रों से है।

- 2 व्यापारिक क्षेत्र के अन्तर्गत साख का आवटन प्राथमिकता के आधार पर यथा, कृषि निर्माण तथा व्यापारिक क्रियाओं से सम्बन्धित है।
- 3 आर्थिक स्तर या आय स्तरों के आधार पर व्यक्तिगत ऋण ग्राहकों के बीच साख का आवटन करना है।

उपर्युक्त साख आवटन के अतिरिक्त कुछ अन्य आधार भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए निर्माण उद्योगों में लघु स्तरीय उद्योग वृहद उद्योगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। इसी तरह व्यापार में आन्तरिक व्यापारियों तथा विदेशी व्यापारियों एवं थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों में अन्तर किया जाता है। इस तरह कुछ चयनित वस्तुओं के सन्दर्भ में साख का नियोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक दूसरे वर्गीकरण के आधार पर साख का आवटन करती है, अर्थात् प्राथमिकता के आधार या अन्य आधार पर। यहाँ पर क्षेत्रीय साख का बँटवारा एवं शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में साख का बँटवारा महत्वपूर्ण है।⁴

उपर्युक्त विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हमारा विश्लेषण किसी प्राप्त निष्कर्ष को देने से सम्बन्धित नहीं है, अपितु उन कदमों को लेने से है, जिससे नीति, उपाय व्यवहारिक रूप से प्रभावी हो सके। भारतीय सन्दर्भ में मौद्रिक एवं साख नियोजन मात्र नीति निर्माण स्तर पर निर्धारित करने से नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से कुल बैंक साख तथा इसके आवटन तथा प्रयोगकर्ताओं के बीच निर्धारण करने से है। इसी के साथ-साथ इन नियोजनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं सरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिससे वांछित रूप में साख का बँटवारा हो सके, क्योंकि बिना इसके सम्पूर्ण मौद्रिक एवं साख नियोजन केवल कागजी कार्यवाही होगी।

साख के निर्धारण के सभी प्रश्नों का प्रारम्भ सम्पूर्ण बैंक साख की मात्रा तथा नियोजित समयावधि (वार्षिक) से है। एक वर्ष के अन्तर्गत कितना साख एवं कितना मुद्रा की मात्रा नियोजित है, यह महत्वपूर्ण है। इन दोनों नियोजनों का उद्देश्य एक ही उद्देश्य से सम्बन्धित है। यहाँ पर हम उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा उपकरणों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका विवरण पहले ही दिया जा चुका है। जो हम मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के बारे में कह चुके हैं, वही बात साख नियंत्रण के बारे में

भी लागू है।

इसके पहले कि हम साख नियोजन एव मौद्रिक नियोजन में साख की मात्रा का क्षेत्रवार आवंटन एव निर्धारण करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अकित साख तथा वास्तविक साख में भेद स्पष्ट कर दें। मौद्रिक नियोजन तथा साख नियोजन में अकित साख तथा वास्तविक साख का महत्व विशेष अर्थ में अपना महत्व रखता है। अकित साख का अभिप्राय वर्तमान द्रव्य के मूल्य से है, जबकि वास्तविक साख स्थायी मूल्य द्रव्य से है। इनके अन्तर में जो महत्वपूर्ण बात है वह समयोपरि मूल्य परिवर्तन से सम्बन्धित है। यदि मूल्यस्तर स्थिर रहे तो अकित साख एव वास्तविक साख में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं होगा। परन्तु यदि कीमतें समयोपरि बदलती रहती हैं तो अकित साख वास्तविक साख से भिन्न होगा। स्फीतिकारी दशाओं के सन्दर्भ में अकित साख अधिक होगा, वास्तविक साख से। नीति निर्माण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक अधिकारी अधिकतम सीमा तक अकित साख मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह अकित साख से भिन्न है। यदि स्थायी व्यवहार सम्बन्धी आदेशों की प्राथमिकता ऐसी वस्तुओं के लिए करेंसी जमा अनुपात तथा समय जमा अनुपात दिये हो तो यह अकित साख समग्र पूर्ति का निर्धारक होता है। चूँकि अर्घ मुद्रा स्टॉक का नियंत्रण मौद्रिक अधिकारियों द्वारा होता है, अतः यह निश्चित करना कि उच्च अर्घ मुद्रा में वृद्धि तथा अकित साख मुद्रा में वृद्धि कितना हो, निर्धारित करना आसान है। यहाँ पर यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किस कारण से साख की अधिक पूर्ति ऋण ग्राहकों को किया जाता है, जो बैंक के शर्तों के आधार पर ऋण प्राप्त करते हैं। ये भी मौद्रिक सिद्धान्त के अन्दर जानने वाली बातें हैं और वे भी नवक्लासिकल परंपरा में।

कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नियोजन की प्रकृति, स्वरूप तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण होगा कि हम साख के आवंटन के आधार का विवरण प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में कम से कम दो नीतिपरक बातें निश्चित हो जानी चाहिए, इसके पहले कि कोई साख आवंटन का नियोजन किया जाय। प्रथमतः समष्टि स्तर पर यह स्पष्ट रूप से जाना जाय कि साख नीति का पूरा दृष्टिकोण साख आवंटन पर आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रानुसार है अथवा साख आवंटन आय सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणकर्ता के आधार पर है। दूसरा यह कि समष्टि स्तर पर यह जानना आवश्यक है कि क्या साख का प्राथमिक आधार—व्यक्तिगत ऋण-ग्राहक के भौतिक प्रतिभूति पर आधारित है। इन दोनों

बातों को स्पष्ट कर देना यहा महत्वपूर्ण होगा। इन बातों का स्पष्टीकरण मोटे तौर पर सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर होगा। प्रथमतः आर्थिक क्रिया के अनुसार क्षेत्रवार इनका निर्धारण होता है। इस तरह हम व्यक्तिगत साख, कृषि साख, निर्यात साख, खाद्यान्न साख तथा अन्य के रूप में देखते हैं। यदि पूरा उद्देश्य उत्पादन और विनियोग को प्रोत्साहित करना है और वह भी निर्धारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो क्षेत्रीय उपागम को न्यायोचित माना जा सकता है। इस तरह से वही बातें कृषि यथा, खाद्यान्न एवं आवश्यक कच्चे माल से सम्बन्धित हैं। इस पर सब्सिडी विचार-धारा के दृष्टिकोण से साख का आवंटन व्यापारिक बैंकों तथा मौद्रिक अधिकारियों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में किया जाता है। बहुत से अध्ययनों में यह दिखाया गया है कि कृषि साख का एक महत्वपूर्ण भाग बड़े कृषकों द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और क्षेत्रवार साख का वितरण इस समस्या का कोई हल नहीं ढूँढ़ पाता। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण होगा कि हम सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से यथा, गरीबी, बेरोजगारी निवारण तथा क्षेत्रीय असमानताओं तथा असंतुलन को दूर नहीं कर सकते। कृषि क्षेत्र में अनेक ऐसे शोध-अध्ययन हुए हैं, जिसमें अनुकूल दशाओं के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर उत्पादन छोटे फार्मों पर बड़े फार्मों की तुलना में अधिक हुए हैं। यह अनुमान किया गया है कि उत्पादन वृद्धि 100 से 200 प्रतिशत वर्तमान स्तर से अधिक हो सकती है। 'एग्रीकल्चर रिफाइनंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन' ने यह पाया है कि लघु सिचाई पर विनियोग का प्रतिफल भूमि विकास, डेयरी तथा अन्य क्षेत्रों में 20 से 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उपयुक्त साख नियोजन द्वारा छोटे उत्पादक महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन को बढ़ाने में कार्य कर सकते हैं।

समान महत्व के रूप में गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या साख नियोजन की दृष्टिकोण से उपयुक्त है, उस सीमा तक जहाँ बेरोजगारी गरीबी का कारण है। वहाँ दो बातें एक जैसे हो जाती हैं, परन्तु बहुत सख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी गरीब हैं। इस तरह से ये दो समस्याएँ गरीबी तथा बेरोजगारी कितनी शीघ्रता से दूर की जा सके, यह साख तथा मुद्रा नियोजन का मुख्य विषय रहा। पिछले 30 वर्षों में नियोजन तथा विकास पर दबाव बड़े उद्योगों को विकसित करने में रहा, जिससे इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। इनका सही समाधान लघु स्तरीय उत्पादकों को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में बढ़ावा देने से है, मुख्य रूप से कृषि उद्योग तथा व्यापार सेवाओं में। यहाँ पर हम इस समस्या का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और निष्कर्षात्मक रूप में यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कृषि एवं

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लघु उत्पादन कार्यों हेतु साख नियोजन¹ एवं नीति की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए।⁵

7.4 कृषि क्षेत्र में मौद्रिक लक्ष्य तथा नियोजित मुद्रा एवं साख पूर्ति

इसके अन्तर्गत हम मुख्य रूप से चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट एवं उनकी सस्तुतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। यह समिति 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश⁶ के मौद्रिक व्यवस्था तथा कार्यशीलता की समीक्षा हेतु नियुक्त की गयी थी। समिति के सुझावों का उद्देश्य मौद्रिक नियंत्रणों को सुधारना रहा है, जिससे मूल्य स्थायित्वता प्राप्त की जा सके। समिति के अध्ययन में यह उल्लेखनीय रहा कि मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए देश में स्थायित्वता प्राप्त की जाय। मौद्रिक नियंत्रण को मोटे तौर पर तीन रूपों में विभाजित किया गया -

1. मौद्रिक लक्ष्यों के आधार पर नियंत्रित मुद्रापूर्ति में वृद्धि करना।
2. साख बजटीकरण, जिसके अन्तर्गत व्यापारिक क्षेत्र में उपयुक्त बैंक साख की मात्रा तथा इस तरह के साख का सामाजिक कार्यों में आवंटन का विस्तृत रूप सम्मिलित है।
3. उपरोक्त दो के लिए समिति ने व्यवस्थित क्षेत्र में उपकरणों पर विशेष जोर दिया और प्रशासनिक ब्याज दर को उपयुक्त माना। इस तरह से मौद्रिक लक्ष्य तथा साख बजटीकरण अनुपेक्षित क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

उपर्युक्त तीनों सस्तुतिया अर्थात् मौद्रिक लक्ष्य, साख बजटीकरण तथा नियंत्रित परिवर्तनशील प्रशासनिक ब्याज दर अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र के सरचनात्मक परिवर्तन की रीढ़ है।

इनके अलावा भी समिति ने व्यक्ति स्तर पर तथा व्यक्तिगत ऋण ग्राहक में पुर्नसरचना और ऋण व्यवस्था पर भी अपने सुझाव दिये हैं। इसी के साथ-साथ वित्तीय व्यवस्था के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथमतः, मुद्रा बाजार के एक उपकरण से रूप में ट्रेजरी बिल को विकसित करना। दूसरे, कॉल मुद्रा बाजार को विस्तृत करके गैर - बैंकों के अल्पकाल वित्त को

सम्मिलित करना। तीसरा, बिल बाजार को प्रोत्साहित करना। चौथा, कैश क्रेडिट सिस्टम के स्थान पर धीरे-धीरे ऋणों एवं बिल वित्तों द्वारा करना। इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है।

जहां तक मौद्रिक लक्ष्यों का तात्पर्य है, वह मुद्रापूर्ति के वार्षिक वृद्धि दर को निश्चित करने से है। इसका उद्देश्य पूर्व परिभाषित नीति उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मौद्रिक सिद्धान्त तथा मौद्रिक अनुभवों के आधार पर समिति ने सही माने में मुद्रापूर्ति की समृद्धि को निर्धारित करने का सुझाव दिया है, जिससे यह नियंत्रित हो कर नियोजित उत्पादनस्तर पर मूल्य स्थायित्वता प्राप्त कर सके, यद्यपि इसके बावजूद भी कि मूल्य अन्य गैर-शक्तियों से प्रभावित है। इस सम्बन्ध में समिति ने 4 प्रतिशत थोक कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। इस मात्रा का प्रभाव दो कारणों से कमजोर पड़ता है। पहला, यह स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था अनुभवों के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में रही है, और दूसरा, इसे अधिक मुद्रास्फीति के रूप में मानता है, जो तुलनात्मक मूल्यों में परिलक्षित होता है।

मुद्रापूर्ति के निर्धारित लक्ष्यों के निर्धारण का आधार वही है, जिसका विश्लेषण हम कर चुके हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अनुकूलतम् रूप में मुद्रापूर्ति में वृद्धिदर अपनाना चाहिए, जो प्रत्याशित मुद्रा-माग वृद्धि के अनुरूप हो और प्रत्याशित वास्तविक आय स्थिर मूल्यों पर वृद्धि के अनुरूप हो। इस तरह से मुद्रापूर्ति वृद्धि का लक्ष्य का आधार आसानी से प्राप्त हो जाता है। यदि वास्तविक उत्पादन वृद्धि का दर 5 प्रतिशत हो तो अगले वर्ष में मुद्रापूर्ति की वृद्धि दर लक्ष्य भी 5 प्रतिशत होनी चाहिए।

चक्रवर्ती समिति में मुद्रापूर्ति के लक्षित दायरा को नहीं दिखाया गया है। इसमें मौद्रिक नीति के लचीलेपन हेतु, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार को विवेचनात्मक अधिकार हों, समिति ने यह स्पष्ट किया है कि यहां तक कि मुद्रापूर्ति का लक्षित दायरा, जो पहले उद्घोषित कर दिया गया है, उसे उच्च या निम्न रूप में उत्पादन तथा प्रवृत्तियों के आधार पर किया जा सकता है।⁶ भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभवगम्य लक्ष्यों जिसमें मुद्रा, मूल्य एवं उत्पादन का सम्बन्ध है, जो समिति के रिपोर्ट में प्रस्तावित की गयी है, वह यह दर्शाती है कि इनमें पारस्परिक सम्बन्ध वार्षिक

6. Report of the Committee to Review the Working of the Monetary System, S. Chakravarty 1985, pp. 25-30.

आकड़ों के आधार पर सम्भव नहीं है। इन सब कारणों से मौद्रिक समीक्षा, अल्पकालीन उतार-चढ़ाव सम्बन्धी उत्पादन तथा मूल्य में वांछित नहीं है। दूसरे शब्दों में, अत्यधिक अल्पकालीन मौद्रिक व्यवस्था का संचालन नहीं होना चाहिए और इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि दीर्घकालीन मौद्रिक स्थायित्वता सुनिश्चित की जा सके।⁷ इस सम्बन्ध में उपर्युक्त आधार पर मौद्रिक नीति एवं नियोजन की मुख्य दो बातें महत्वपूर्ण हैं पहला, समिति ने मुद्रा पूर्ति के लिए $एम_1$ की तुलना में $एम_3$ को अधिक महत्व दिया, यद्यपि समिति ने ऐसा करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया। दूसरा, समिति ने उच्च अर्ध मुद्रा अथवा मुद्रागुणक को मुद्रापूर्ति के रूप में माना और मुद्रागुणक को भारत में अत्यधिक स्थिरांक के रूप में देखा।

समिति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन मौद्रिक संरचनात्मक परिवर्तन साख बजटीकरण रहा। साख बजट के मुख्य रूप से दो रूप हैं। प्रथमतः व्यापारिक क्षेत्र में यथा सम्भव बैंक साख को निर्धारित करना तथा दूसरा क्षेत्रवार साख वितरण का विस्तृत लेखा-जोखा रखना।

समिति का तीसरा महत्वपूर्ण प्रतिवेदन अवयवों था जो वर्तमान मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन से अलग और प्रशासनिक ब्याजदर व्यवस्था से सम्बन्धित है। समिति ने वर्तमान मौद्रिक नीति के संचालन में कई कमियों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है, जिसे हम मौद्रिक एवं साख नीति के सीमाओं में दिखा चुके हैं। सामान्य रूप में समिति साख के मूल्यों के निम्न होने का विरोध करती है - चाहे यह सरकारी क्षेत्र में हो या व्यापारिक क्षेत्र में। इसके कई कारण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा अत्यधिक ऋण देने को प्रोत्साहन तथा सरकारी ऋणों का मौद्रिकीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों के पुनर्वित्तीयन हेतु कम मुद्रा छोड़ना। सरकार तथा अन्य द्वारा प्रभावी साख प्रयोग को हतोत्साहित करना। वित्तीय बजटों को हतोत्साहित करना। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की लाभकरिता को कम करना। अतः समिति ने अधिकतर दशाओं में अनेक ब्याज दरों को ऊँचे दरों में करने की सत्सुति की है। विश्लेषणात्मक सुविधा की दृष्टिकोण से समिति के अनेक सत्सुतियों को निम्न तीन रूपों में देखा जा सकता है -

पहला, ब्याजदर तथा प्रत्याशित मुद्रा स्फीति-दर,

दूसरा, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर,

तीसरा, बैंकों के जमा और ऋण पर ब्याज दर।

साराश रूप में चक्रवर्ती समिति की उपर्युक्त सस्तुतियों तथा अन्य सस्तुतियों को हम दे सकते हैं। ये सारी सस्तुतियां मोटे तौर पर मुद्रापूर्ति में वृद्धि को लक्ष्य करके दी गयी हैं। मौद्रिक लक्ष्य के अन्तर्गत यदि मुद्रा-माग की आय लोच दो के बराबर मान लिया जाय तो इसका परिणाम मुद्रापूर्ति में अत्यधिक समृद्धि से है और इस तरह यदि वास्तविक उत्पादन की तीव्र दर पाच प्रतिशत वार्षिक है तो यह लोच अकेले ही मुद्रापूर्ति में पाच प्रतिशत वृद्धि करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समिति में उल्लेखनीय है वह चार प्रतिशत सामान्य मुद्रा-स्फीति की दर से है। समिति ने अधिकतम वार्षिक मुद्रापूर्ति के एक दायरे की सस्तुति की है, न कि लक्ष्य का। इस तरह से मुद्रापूर्ति में अत्यधिक वृद्धि का दर बना रहेगा। समिति ने मुद्रापूर्ति के वृद्धि सम्बन्धी दायरे को और भी लोचशील बनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि मौद्रिक लक्ष्य को अर्थव्यवस्था के अनुभवों एवं समस्याओं के सन्दर्भ में ऊपर नीचे किया जा सकता है और तरह निर्धारित मौद्रिक लक्ष्य मुद्रापूर्ति पर नियंत्रण करने में असमर्थ होगा। साख बजटीकरण के अन्तर्गत यह सस्तुति कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अतिरिक्त पुनर्वितीयन करे, जब आवश्यक साख के अनुमान की पूर्ति न हो सके। ऐसी दशा में मौद्रिक लक्ष्यों के आधार पर मौद्रिक ससाधनों को उत्पन्न किया जा सकता है, इससे मुद्रापूर्ति के बढ़ने का दूसरा रास्ता खुल जाता है। अतः प्रशासनिक ब्याज दरों के सम्बन्ध में मुद्रा स्फीति की दर को चार प्रतिशत वार्षिक रखा गया है। यह दर वर्तमान प्रशासनिक ब्याज दरों हेतु वांछित है।

7 5 2000 ए0डी0 तक मौद्रिक एवं साख प्रक्षेप

एक नियोजित अर्थव्यवस्था में भविष्य की प्रक्षेपों तथा आवश्यकताओं का सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों के विनियोग हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिशा में कृषि क्षेत्र में कई प्रयास किये गये हैं, जो उत्पादन तथा आवश्यक आगतों का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से साख सुविधा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रूप से की गयी है और कुछ प्रयास भविष्य की साख आवश्यकताओं के सन्दर्भ में किये गये हैं। भविष्य के आवश्यकता तथा प्रक्षेपों हेतु अभी अनुमान विधियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पायी हैं।

पूरे देश के रूप में कृषि साख की आवश्यकता हेतु एक वर्किंग ग्रुप कृषि उत्पादन बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1965 में नियुक्त किया गया था, वह विशिष्ट रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में थी। बैकटरमैया समिति ने अल्पकालीन साख आवश्यकता 1973-74 के लिए ₹ 2000 करोड़ अनुमानित किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालीन साख आवश्यकता का अनुमान ₹ 1500 करोड़ और मध्यकालीन साख का अनुमान 500 करोड़ किया गया था। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, अल्प-कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख आवश्यकता को वर्ष 1985 के लिए किया था। आयोग ने लघु कृषक, सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों एवं गैर लघु कृषकों का अलग-अलग अनुमान किया था। साख की अल्पकालीन अनुमान कृषि सम्बन्धित-उत्पादनों यथा दूध, सुअरपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, तथा मत्स्य पालन हेतु अलग-अलग किया गया था और कुल साख आवश्यकताओं का अनुमान ₹ 16149 करोड़ किया था।

'नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर' की अनुमान विधि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं की अलग-अलग सींचित एवं गैर सींचित फसलों के लिए तथा कृषि सम्बन्धी अन्य क्रियाओं के लिए किया गया था। अल्पकालीन साख आवश्यकताओं के निर्धारण में यह माना गया था कि प्रति हेक्टेयर ₹ 600 सींचित क्षेत्र के लिए तथा ₹ 400 असींचित क्षेत्रों के लिए होगा। कुल साख फसलों के लिए सीमान्त एवं लघु कृषकों के बीच, पूरे देश के स्तर पर प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था। इसी तरह चारागाह कार्यक्रमों के लिए साख का अनुमान अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था।

यहां पर हम कृषि क्षेत्र में साख का अनुमान एवं प्रक्षेप वर्ष 1990, 1995 तथा 2000 वर्ष के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अल्पकालीन साख आवश्यकता के सम्बन्ध में हमने यह मान्यता मान ली है कि उत्पादन, मूल्य तथा नकदी एवं वस्तुरूप में व्यय के बीच सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध एक फसल से दूसरे फसल में तथा एक ही फसल में एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित होता रहता है। इस सम्बन्ध के आधार पर फसल उत्पादन की द्वितीय आवश्यकता को प्राप्त किया गया है। नकदी तथा वस्तुरूप में वित्त की आवश्यकता की भी इस सम्बन्ध पर आधारित किया गया है। फसल ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत यह सामान्यतया मान लिया जाता है कि परंपरागत कृषि में नकदी साख का अनुपात प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन का $1/3$ भाग से अधिक नहीं होगा। प्रयुक्त मॉडल में

अल्पकालीन साख आवश्यकता राज्यवार एव फसलवार के आधार पर किया गया है।

राज्यवार एव फसलवार वार्षिक अनुमान वर्तमान और स्थिर मूल्यों ₹1970-71 पर महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में 1970-71 से 1980-81 के सन्दर्भ में सी0एस0ओ0, भारत सरकार, 1985 के आधार पर 1981-82 से 1984-85 तक किया गया है। भौतिक उत्पाद तथा मूल्यों के आकड़े कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किये गये हैं। राज्यवार तथा फसलवार उत्पादन मूल्यों को इन चार वर्षों में कुल उत्पादन को उत्पादन मूल्य से गुणा करने से प्राप्त हुआ है। इसी तरह फसलवार उत्पादन के मूल्य के आकड़े वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर पूरे देश स्तर पर सी0एस0ओ0, भारत सरकार 1987 से प्राप्त हुये। राज्यवार एव फसलवार आकड़े फसल मूल्यों के आधार पर प्राप्त किये गये, जो 1970-71 से 1984-85 तक सम्बन्धित थे।

यहां पर फसलों के उत्पादन सम्बन्धी समृद्धि दर का विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा इस तरह का समृद्धि दर प्रक्षेप 1984-85 से 1990-91 तथा 1995-96 से 2000 वर्ष तक अनुमान प्रमुख उत्पादक राज्यों के सम्बन्ध में दिया गया है। इस तरह समृद्धि दर के अनुमान को हम सिचाई सुविधाओं तथा अन्य सुधारों के सम्बन्ध में फसल उत्पादन की मांग तथा व्यापार सम्भावनाओं के दृष्टिकोण से किये हैं। भविष्य के समृद्धि दरों के लिये हम कृषकों के सम्बन्ध में सर्वेक्षणों के प्राप्ति्यों का भी सहारा लिये हैं, जिसमें तकनीक हस्तारण, फसल उत्पाद, उर्वरक का प्रयोग तथा अन्य सुधरी हुई कृषि प्रक्रिया सम्मिलित हैं।

यहां पर विभिन्न वर्ग परिवारों के द्वारा कृषि क्षेत्र का अनुपात देना उपयुक्त होगा। मॉडल के अनुसार साख की आवश्यकता, जबकि क्तितीय आवश्यकता का राज्यवार एव फसलवार अनुमानित कर लिया गया हो, कृषि जोत परिवारों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इन आकड़ों के आधार पर वर्ष 1990 का अनुपात अनुमानित किया गया है और वर्ष 1995 तथा 2000 वर्ष तक का अनुमान किया गया है। सम्पूर्ण देश के स्तर पर आकड़े इस बात को ईंगित करते हैं कि भारतीय कृषि में सीमान्त कृषक अधिक होते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न वर्ग परिवारों का अनुपात पूरे देश के स्तर पर सारणी 7 । में दिया जा सकता है ।

सारणी 7 ।

भारत में विभिन्न वर्ष के कृषकों के जोतों का वर्गीकरण

वर्ष	लघु तथा सीमान्त कृषक		मझले कृषक		बड़े कृषक	
	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र
1970-71	69 89	29 87	26 21	48 25	3 90	30 88
1976-77	72 64	23 52	24 37	50 24	2 99	26 24
1980-81	74 54	26 27	23 05	50 92	2 41	22 81
1990	-	28 96	-	52 03	-	19 01

Source: National Bank News Review, March, 89

अल्प समयावधि के लिए वित्तीय आवश्यकता 1984-85 में ₹0 29500 करोड़ होगी और 2000 वर्ष तक यह बढ़कर ₹0 49000 करोड़ होगी । इन वित्तीय आवश्यकताओं को जोत - परिवार के आधार पर विभाजित कर दिया गया है, जिसका विवरण सारणी 7 2 में प्रदर्शित किया गया है। क्रियान्वित क्षेत्र के आकड़ा 1984-85 के वास्तविक आकड़ों पर आधारित है, जब कि अन्य वर्षों का अनुमान लगाया गया है । वित्तीय आवश्यकता के इन अनुमानों तक पहुंचने के लिए कृषि परिवार जोतों का आकार हम वही मान लिये हैं, जो अन्य शोधकर्ताओं ने माना है और इस तरह कृषि - फार्म से आय को वर्ष 2000 तक दिया गया है ।

सारणी 7 2

अखिल भारतीय स्तर पर जोतों के आकार के अनुसार वित्तीय आवश्यकता

वर्ष				(रूपये करोड़)
	लघु तथा सीमान्त जोतें	मध्यम जोतें	बड़े जोतें	योग
1984-85	7740	115003	6721	29464
1990	9892	117771	6493	34156
1995	11748	121107	7712	40567
2000	14293	125680	9383	49356

लघु एव सीमान्त कृषकों का वांछित वित्तीय माग 1984-85 में ₹0 60740 करोड़ से बढ़कर 2000 वर्ष में ₹0 14993 करोड़ हो जायेगा, जबकि बड़े कृषक वर्ग का यह वित्तीय आवश्यकता कम हो करके 1984-85 में ₹0 6721 करोड़ हुआ और 1990 के आधार पर यह बढ़कर ₹0 9383 करोड़ हो गया। 1990 की तुलना में 1984-85 में इस साख आवश्यकता को गिरने का कारण कृषि-जोत आकार में कमी का होना रहा।

फसलवार तथा राज्यवार वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान के बाद साख आवश्यकताओं के चार नीति विकल्पों के रूप में माना गया है। इसे सारणी 7 3 में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें साख आवश्यकता जो 1984-85 में ₹0 24783 करोड़ था, बढ़कर 2000 वर्ष तक ₹0 44964 करोड़ हो गया। कुल साख आवश्यकताओं को कृषि जोत आकार के अनुसार विभाजित कर दिया गया है। प्रथम विकल्प में लघु एव सीमान्त कृषकों के लिये अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक साख आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बड़े कृषकों की साख माग कम दिखाई गई है। विकल्प 2 में सबसे कम साख आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है। नीति निर्धारकों ने लघु तथा सीमान्त कृषकों पर अधिक प्रधानता दिया है, इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की

गयी है, जो इन कृषकों की साख माँग को पूरा कर सके। कृषि परिवार जोत आकार के आधार पर साख आवश्यकता का विवरण सारणी 7 3 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी 7 3

विभिन्न विकल्पों के अनुसार साख की आवश्यकता

(रूपये करोड़)							
वर्ष	योग	लघु एव सीमान्त	जोतें	मध्यम जोतें		बड़े जोतें	
विकल्प 1							
1984-85	27,824	9,450	(34,00)	15,003	(53,92)	3,361	(12,08)
1990	33,108	12,090	(36,52)	17,771	(53,68)	3,247	(9,80)
1995	39,322	14,359	(36,52)	21,107	(53,68)	3,856	(9,80)
2000	47,842	17,470	(36,52)	25,680	(53 68)	4,592	(9 80)
विकल्प 2							
1984-85	25,783	6,773	(26 27)	13,129	(50 92)	5,881	(22 81)
1990	30,101	8,717	(28 96)	15,662	(52 03)	5,722	(19 01)
1995	36,196	10,082	(28 96)	18,833	(52 03)	6,881	(19 01)
2000	44,968	13,023	(28 96)	23,397	(52 03)	8,548	(19 01)
विकल्प 3							
1984-85	29,464	7,740	(26 27)	15,003	(50 92)	6,721	(22 81)
1990	34,156	9,492	(27 79)	18,071	(52 91)	6,593	(19 30)
1995	40,567	11,748	(28 96)	21,287	(52 03)	7,712	(19 01)
2000	49,356	14,293	(28 96)	25,680	(52 03)	9,383	(19 01)

विकल्प 4

1984-85	36,011	9,460	(26 27)	18,337	(50 92)	8,214	(22 81)
1990	41,747	12,090	(28 96)	21,721	(52 03)	7,936	(19 01)
1995	49,582	14,359	(28 96)	25,798	(52 03)	9,426	(19 01)
2000	60,324	17,470	(28 96)	31,386	(52 03)	11,468	(19 01)

नोट. कोष्ठक में दिये गये अंक प्रत्येक वर्ष के योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

अब हम साख आवश्यकता को 1984-85 से 2000 वर्ष तक फसलवार दिखा सकते हैं। यह फसलवार विश्लेषण अल्पकालीन साख आवश्यकताओं पर आधारित है। प्रथम विकल्प के आधार पर हमने साख आवश्यकता को विभिन्न फसलों के दृष्टिकोण से सारणी 7.4 में प्रदर्शित किया है, पुन हमने फसलवार साख आवश्यकता को मुख्य फसलों के रूप में विभाजित किया है। हमने विभिन्न फसलों के प्रतिशत वर्गों के रूप में दी हुई कीमतें वर्ष 1978-79 से 1980-81 के आधार पर रखा है। इस तरह 1984-85 से 1990-95 के आधार पर प्रस्तुत विश्लेषण दिया जा रहा है।

सारणी 7.4

विकल्प I के अनुसार फसल साख की आवश्यकता

(रूपये करोड़)

फसल वर्ष	1984-85		1990		1995		2000	
चावल	7,274	(26)	3,441	(25)	10,270	(26)	13,107	(27)
गेहूँ	3,098	(11)	4,055	(12)	5,425	(14)	7,433	(16)
अन्य खाद्य पदार्थ	1,958	(7)	2,169	(7)	2,395	(6)	2,777	(6)
चना	781	(3)	887	(3)	1,028	(3)	1,251	(3)
अन्य दालें	1,101	(4)	1,252	(4)	1,451	(4)	1,765	(4)
गन्ना	1,619	(6)	1,922	(6)	2,283	(6)	2,777	(6)

मूँगफली	1,694	(6)	1,964	(6)	2,333	(6)	2,907	(6)
अन्य तिलहनें	1,424	(5)	1,843	(6)	2,431	(6)	3,253	(7)
कपास	1,139	(4)	1,421	(4)	1,814	(5)	2,426	(5)
जूट और	321	(1)	382	(1)	453	(1)	552	(1)
आलू	391	(1)	487	(1)	621	(2)	831	(2)
अन्य फसलें	2,027	(26)	8,286	(25)	8,819	(21)	8,762	(17)
योग	27,827	(100)	33,109	(100)	39,323	(100)	47,841	(100)

नोट कोष्ठक में दिये गये अंक योग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

1990 से 1995 तथा 2000 वर्ष तक साख आवश्यकता की मात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आदर्श विश्लेषणों के अलावा जो मुख्य समस्या थी वह पर्याप्त तथा समय से कृषि में साख देने की थी। सारी रूकावटें, जो शीघ्र साख देने में आती हैं, उन सब का निराकरण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं -

- 1 कृषि क्षेत्र में साख आवश्यकता केवल साख आवश्यकता तक सीमित नहीं होना चाहिए अपितु पूरी कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित होना चाहिए।
- 2 इस सम्बन्ध में साख आवश्यकता आगत वितरण के रूप में होना चाहिए और थोक तथा फुटकर आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में साख आगत वितरण हेतु सहकारी समितियों पर विशेष जोर देना चाहिए। फिर भी यदि आगत का वितरण व्यक्तिगत क्षेत्र से होता है तो वही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो इस समय कृषि क्षेत्र में प्रदान की जा रही है।
- 3 कृषि आधारित उद्योगों को, जो अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है, वे कृषि साख के अग होने चाहिए और वही प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वर्तमान समय में कृषि आवश्यकता हेतु दी जा रही है।

- 4 जहा तक अल्पकालीन साख आवटनों तथा साख कार्यक्रमों का प्रश्न है, कृषि उत्पादन मे उप विभाग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- 5 हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अल्पकालीन साख हेतु उपलब्ध साधनो को बढ़ाया जा सके।
- 6 ग्रामीण क्षेत्रों से उपलब्ध जमाओं का पूरा प्रयोग अल्पकालीन साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगाना चाहिए।
- 7 इन ससाधनों का प्रयोग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र मे नहीं लगाना चाहिए।
- 8 यदि आवश्यकता हो तो कृषि के प्राथमिक क्षेत्रों मे वर्तमान 17 प्रतिशत से बढ़कर के 25 प्रतिशत अंश लगाना चाहिए। कृषि उत्पादन के उपक्षेत्र मे विशेष अंश निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 9 चूंकि भविष्य मे अल्पकालीन साख की मात्रा कम होने की सम्भावना है, अत इसका वितरण उत्पादिता तथा विवेकपूर्ण ऋण भुगतान से सम्बन्धित होनी चाहिए।
- 10 वर्तमान समय मे अल्पकालीन साख का वितरण जो विभिन्न परिवार जोत के आधार पर है, उसमे विशेष ध्यान देना चाहिए।
- 11 यदि साख का वितरण विभिन्न जोत आकारों के आधार पर हो तो वर्तमान समय मे बडे और लघु तथा सीमान्त कृषक से साख परिवर्तित करके अधिकांश साख मध्यम कृषको को देना चाहिए।
- 12 उपर्युक्त साख आवश्यकता के आधार पर अल्पकालीन साख का क्षेत्रवार वितरण होना चाहिए। इसका विवरण सारणी 7 5 मे प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 7.5

फसल उत्पादन हेतु साख आवश्यकता का अल्पकालीन साख आपूर्ति सम्बन्धी व्यूह नीति
(रूपये करोड़)

व्यूहनीति	1984-85 धनराशि	वृद्धि दर (प्रति०)	1990 धनराशि	वृद्धिदर (प्रति०)	1995 धनराशि	वृद्धि दर (प्रति०)	2000 धनराशि
व्यूहनीति I	3219		16554		29491		35889
वृद्धि दर 1984-85 तथा 1990 के मध्य		38 75					
वृद्धि दर 1990 तथा 1995 के मध्य				12 24			
वृद्धि दर 1995 तथा 2000 ए डी						4.01	
यूह नीति II	3214		9741		29491		35889
वृद्धि दर 1984-85 तथा 1990 के मध्य		24 79					
वृद्धिदर 1990 तथा 1995 के मध्य				24 79			
वृद्धि दर 1995 तथा 2000 ए०डी०						4 01	
यूह नीति III	3219		7957		19661		35889
वृद्धि दर 1984-85 तथा 1995 के मध्य				19 84			
वृद्धि दर 1995 तथा 2000 ए०डी०						12.79	
यूहनीति IV	3219		7192		16065		35889
वृद्धि दर 1984-85 तथा 2000 ए.डी. के मध्य		17 44		17 44		17 44	

कृषि हेतु सस्थागत स्रोतों से अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन कुल साख का अनुमान 1999-2000 तक के लिये किया गया है। साख माग के प्रक्षेपों को अनुमानित करने हेतु ऋणों एवं अग्रिमों का भुगतान तथा बकाया वर्ष के अंत तक का लगाया गया है न कि प्रत्याशित दर से। यह प्रक्रिया पूर्णरूप से साख माग के तुलनात्मक दृष्टिकोण से लगायी गयी है, जिसमें कृषि तथा सम्बन्धित क्रियाओं में इसका अनुमान किया गया है। अल्पकालीन सावधि फसल उत्पादनों में यह प्रधान मान्यता रही है कि फसलों के उत्पादन मूल्य में तथा उन फसलों के उत्पादन लागत में सम्बन्ध है। ऐसा सम्बन्ध फसल-फसल में तथा एक ही फसल में परिवर्तित होता रहता है। इसी तरह मौसम-मौसम में, राज्य-राज्य में और राज्य के अन्तर्गत भी परिवर्तित होता रहता है जो कृषि जलवायु दशाओं पर आधारित है।

7.6 कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन की आवश्यकता

भारतीय कृषि क्षेत्र में एक सतुलित विकास के दृष्टिकोण से तथा साख का क्षेत्रवार आवंटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मौद्रिक एवं साख नियोजन की इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि देश में सम्पूर्ण मौद्रिक एवं साख ससाधनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता, प्रयोग की क्षमता और पूरे विकास के दृष्टिकोण से आवंटन किया जाय। साख नियोजन के दो पक्ष हैं-समष्टि पक्ष एवं व्यष्टि पक्ष। समष्टि पक्ष में साख नियोजन क्षेत्रवार और लक्ष्य के अनुसार साख का आवंटन होता है और व्यष्टि स्तर पर यह बैंकों के द्वारा विभिन्न बैंक सस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

साख नियोजन के पूर्व दो नीति सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथमतः, व्यापक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है कि क्या पूरे साख का ध्यान अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार साख आवंटन पर है कि नहीं। दूसरे, यह कि व्यापक रूप से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत ऋण ग्राहकों को दिये जाने वाले ब्याज का आधार वास्तविक सम्पत्ति के द्वारा प्राप्त होगी अथवा उनके भुगतान सामर्थ्यता अथवा दोनों के सहयोग के आधार पर। इन प्रश्नों का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार से चुने गये हैं और उनका क्या क्रम है। परंपरागत स्थिति के अनुसार पहले प्रश्न का उत्तर अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं के अनुसार साख

आवटन से है। इस तरह से हम औद्योगिक साख, कृषि साख, निर्यात साख, मध्य साख तथा अन्य साख की बात कर सकते हैं। यदि पूरा उद्देश्य उत्पादन को और विनियोग को बढ़ाने से है और अन्य सामाजिक कारकों यथा बेरोजगारी, गरीबी तथा समाज में आय तथा सम्पत्ति का बँटवारा और इस तरह से क्षेत्रीय उपागम को औचित्यपूर्ण देखा जा सकता है।

सफलता के दृष्टिकोण से साख-नियोजन जमायोजनाओं से सम्बंधित होनी चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण साख का आवटन बैंको की कुल जमा पर निर्धारित होता है इस तरह का साख नियोजन विकासशील भारत देश में अपना विशेष महत्व रखता है, ताकि सीमित बैंक ससाधनों का उत्पादकता के दृष्टिकोण से उपयोग हो सके और जिससे सामाजिक दृष्टिकोण से साख का आयोजन निर्धारित किया जा सके। इस तरह साख नियोजन बैंकिंग व्यवस्था के निर्धारित उद्देश्यों को सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देश की प्रगति में विशेष महत्वपूर्ण है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास उपलब्ध आर्थिक ससाधनों का प्रयोग राष्ट्रीय नियोजन की प्राथमिकता के आधार पर करता है। इस प्रकार का प्रावृत्तिक, आर्थिक ससाधनों का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नीति प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। चूँकि व्यापारिक बैंको को साख सीमित मात्रा में है, इसलिए इसका प्रयोग अच्छे ढंग से नियोजित होना चाहिए, जिससे कि इसका प्रयोग अधिकतम हो सके और आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक विकास अधिकतम किया जा सके। इस तरह इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य भारत में साख नियोजन को देश के नियोजित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से करना है, जहाँ मूल्य स्थायित्व तथा अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में व्यापारिक बैंको को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख समझा जा रहा है।⁸

साख नियोजन का उद्देश्य उपलब्ध साख ससाधनों का अधिकतम उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रयोग हो सके और पूरे समाज को देखते हुए। इसका अभिप्राय यह है कि यह सम्भव है कि सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साख मात्रा को निर्धारित किया जाय। इस तरह साख नियोजन का उद्देश्य साख प्रवाह को उन दिशाओं में प्रवाहित करने की आवश्यकता है,

8. S. Subrahmanya- Trends and Progress of Banking in India p. 273.

जो परम्परागत क्षेत्रों से हट कर व्यापारिक क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

पूरे देश में साख की मात्रा इसकी आवश्यकता से कम है। इसलिए साख की मात्रा को विवेकपूर्ण होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में इसे वितरित किया जा सके। एक पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत गैर-नियोजित तथा परंपरागत बैंक व्यवस्था के अन्तर्गत साख नियोजन साख के मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि साख के माग की तुलना साख पूर्ति में कमी होने के कारण स्वभावतः बाजारी ब्याजदर ऊँचा होगा, जिससे व्यापारिक वर्ग में ऋण ग्राहकों में साख की माग में कमी होगी और वे पूर्व के बराबर हो जायेगा। इस तरह साख की माग इसकी पूर्ति की तुलना में ब्याजदर को घटाने का काम करेगी और अपने प्रभाव में सीमान्त कृषकों की साख माग को बढ़ायेगी। मूल्य व्यवस्था इस तरह से यदि स्वतंत्र क्रियान्वयन में छोड़ दी जाय तो अतिरिक्त साख की माग एवं पूर्ति को कम करेगा और साख बाजार में संस्थिति उत्पन्न करेगा।

फिर भी इस तरह सीमित साख का बँटवारा विभिन्न प्रतिस्पर्धी लोगों में मूल्य व्यवस्था द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुकूलतम होगा और बड़े ऋण ग्राहकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं उद्योग को उचित साख न मिल पायेगा। पूरे समाज के दृष्टिकोण से साख उत्पादक बनाने के लिये और अर्थव्यवस्था के सम्भव अधिकतम विकास के लिए साख का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करना चाहिए, न कि उनके ऊँचे ब्याजदर को अदा करने की योग्यता के अनुसार, अपितु उनके आर्थिक एवं सामाजिक महत्व के अनुसार दिया जाना चाहिए। साख नियोजन उत्पादन, रोजगार सृजन, मूल्य स्थायित्वता को सुनिश्चित करने तथा आर्थिक लाभों को समानता के आधार पर विकसित करने के आधार पर किया जाना चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले, जब बैंक शेयर ग्राहकों से सम्बन्धित थे, उस समय लाभकारिता बैंकों का मुख्य उद्देश्य था और उस समय ये बैंक सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते थे, वर्तमान समय में ये एक दूसरे तरफ, जबकि राष्ट्रीकृत बैंक पूर्णतया सामाजिक लोगों द्वारा नियंत्रित है, समाज के प्रति उत्तरदायी है, न कि व्यक्तिगत शेयर ग्राहकों के। अब ये न केवल

सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, अपितु अपने उद्देश्यों के प्रमुख रूप में साख क्रियाओं को रखते हैं। अब बैंकों का संचालन इस बात से नहीं देखा जाता कि ये वास्तविक रूप में कितना लाभ करते हैं, अपितु उनकी सफलता इस बात में देखी जाती है कि देश के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितने सफल रहे। यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता

है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा धीरे-धीरे सामाजिक उद्देश्यों को अपनाने के कारण क्षेत्रवार साख का विकास महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से देश के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ेगा। देश की बैंकिंग व्यवस्था के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों एवं देश में समृद्धि का एक उपकरण माना जाता है। अतः देश के व्यापारिक बैंकों को अपने कार्यान्वयन में ऐसे साख नियोजन में लाना चाहिए, जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके। इस तरह के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में साख नीति को विस्तृत साख नीतियों और जमा नीतियों से जुड़ना चाहिए।

विकासशील भारत देश में एक केन्द्रीय बैंक सुरक्षित मुद्रापूर्ति को कायम रख सकता है और इस सन्दर्भ में साख नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक साख नीति या मौद्रिक बजट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, जिससे मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तुओं का उत्पादन वृद्धि बराबर हो सके। इस तरह से समष्टि स्तर पर साख का नियोजन अर्थव्यवस्था के मुद्रापूर्ति वृद्धि के अनुपात में उत्पादन क्षमता और उपलब्ध बाजारी अतिरेक के रूप में होना चाहिए, किन्तु व्यष्टि स्तर पर साख नियोजन एक सतुलित आधार रखता है, जिससे क्षेत्रीय स्थायित्व तथा बेरोजगारी का वितरण अनिश्चित न हो सके। जहाँ भी उत्पादन में कमी होगी, विशेषकर कृषि उत्पादन की दृष्टिकोण से वहाँ मुद्रापूर्ति की सुरक्षित मात्रा में कमी होगी, परन्तु मुद्रा पूर्ति में इस तरह के गिरावट औद्योगिक उत्पादकों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुस्ती ला सकता है। अतः एक सामान्य उपायों के साथ-साथ एक सतुलित क्षेत्रवार उपाय ही अधिकतम क्षमता वाले समृद्धि और मूल्य स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह साख नियोजन को इस तरह करे कि मौद्रिक बजट का क्रियान्वयन व्यष्टि स्तर पर साख-बजट का स्वरूप ले लें। इसका उद्देश्य मौद्रिक बजट द्वारा मुद्रापूर्ति के विकास-दर को सुनिश्चित करना है। मुद्रापूर्ति सरकार को दी जाने वाली शुद्ध साख का फलन है तथा व्यापारिक क्षेत्रों को दी जाने वाली शुद्ध साख तथा विदेशों में दी जाने वाली साख पर

आधारित है।

इस तरह समष्टि स्तर पर साख का सम्बन्ध व्यष्टि स्तर पर साख नियोजन से होना चाहिए। व्यापारिक बैंको की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने साख का आवंटन अपने सम्बन्धित शाखाओं द्वारा करें। व्यक्तिगत बैंक अपने शाख का वितरण सबसे गरीब तबके के लोगों से लेकर विभिन्न ऋण ग्राहकों तक वितरित करें, विशेषकर कृषि और प्राथमिक क्षेत्रों में इस तरह का साख आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

साख वितरण की प्रवृत्ति की समीक्षा 1968 से सारणी 7 6 में दी गयी है। इस सारणी से स्पष्ट है कि साख वितरण में कुल मिलाकर जो परिवर्तन हुआ है, वह नीति उद्देश्यों के सगत से गुजरी है। इस तरह से कुल साख में कृषि साख का क्षेत्र लगभग सत्रह प्रतिशत गया है, जो 1968 में केवल एक प्रतिशत था। इसी तरह लघु स्तरीय उद्योगों में कुल साख का बारह प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों से ले करके अर्थात् कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यापारी, स्वरोजगार आदि कुल साख का 1/4 हिस्सा प्राप्त करते हैं, जो पहले केवल सात प्रतिशत था। साख नियोजन जो बैंकों द्वारा किये गये हैं, वे पूर्ण सफल नहीं हो सके हैं, ऐसे अध्ययन जो साख अन्तराल से सम्बन्धित हैं वे स्पष्ट करते हैं कि लीड-बैंक स्कीम अभी भी वास्तविकता का रूप नहीं ले पाये हैं। अब भी साख नियोजन में इस बात की आवश्यकता है कि साख वितरण में समयावधिक को कम किया जा सके और विशेषकर लघु और ग्रामीण क्षेत्रों में उधार लेने वालों के सम्बन्ध में। जहां तक क्षेत्रीय असंतुलों का प्रश्न है वहाँ बैंक कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर पाये हैं। इस तरह कृषि उद्योग, व्यक्तिगत क्षेत्र तथा व्यापार एवं अन्य के सम्बन्ध में साख में इनके अनुपात को दिखाया जा सकता है।

सारणी-7 6
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साख का हिस्सा

		सम्पूर्ण अग्रिमों का प्रतिशत	
		जून, 1972	मार्च, 1968
I	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएँ	6 8	2 2
	(अ) कृषि	4 0	0 2
	(ब) वृक्षारोपण	2 2	1 8
	(स) सम्बन्धित क्रियाएँ	0 6	0 2

II	उद्योग	57 6	67 5	°
	॥अ॥ बड़े एवं मध्यम	45 5	60 6	
	॥ब॥ लघु	12 1	6 9	
	बड़े उद्योग			
	॥1॥ चीनी	1 9	5 3	
	॥2॥ खाद्य-तेल	0 6	1 4	
	॥3॥ सूती वस्त्र	7 5	10 3	
	॥4॥ जूट वस्त्र	1 5	3 1	
	॥5॥ रसायन एवं रसायनिक उत्पाद	5 4	3 6	
	जिसमें से उर्वरक	0 6	1 2	
	॥6॥ इस्पात एवं स्टील	2 8	3 7	
	॥7॥ इंजीनियरिंग	15 8	16 4	
	॥8॥ विद्युत, गैस, जल एवं सफाई सेवाएं	1 5	1 0	
III	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	1 8	-	
	॥अ॥ सड़क एवं जल परिवहन क्रियाएं	1 2	-	
	॥ब॥ लघु व्यापार	0 2	-	
	॥स॥ व्यवसायिक एवं स्व-रोजगार	0 3	-	
	॥द॥ शिक्षा	0.1	-	
IV	व्यापार एवं अन्य	33 8	30 3	
योग		100 0	100.0	

Source- S.L.N. Simha and A Raman (Ed.), Credit Planning and Policy.

सारांश, निष्कर्ष एवं नीतिपरक सुझाव

(SUMMARY, CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATIONS)

प्रस्तुत अध्याय में शोध विषय के सन्दर्भ में कुछ नीतिपरक सुझावों को प्रस्तुत किया गया है, जो भविष्य में अल्पविकसित भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सन्दर्भ में मौद्रिक एवं साख नीति के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इन सुझावों के पूर्व सम्पूर्ण शोध-साहित्य का सारांश एवं निष्कर्ष अध्यायवार दिया जायेगा। भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के पूर्व से ही मौद्रिक एवं साख नीति के महत्व को स्वीकार किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन देखने में यह आया है कि राष्ट्रीय आय में कृषि तथा इस पर आधारित व्यवसायों यथा, पशुपालन, वानिकी आदि की भागीदारीता लगातार कम होती गयी है। राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा आज मात्र 33 प्रतिशत (1988 - 89) है, जबकि 1950-51 में यह 59 प्रतिशत, 1960-61 में 52 प्रतिशत और 1983-84 में 37 प्रतिशत था।

शोध-प्रबन्ध का प्रथम अध्याय प्रस्तावना से सम्बन्धित है, जिसमें अध्ययन का स्वरूप, औचित्य और अन्य प्रमुख बातों को प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः मौद्रिक नीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण से है। मौद्रिक एवं साख नीति किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है,। साख नीति के उचित संचालन से देश के मौद्रिक क्षेत्रों की वृद्धि, मुद्रापूर्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तथा मुद्रा एवं मूल्य वृद्धि के सन्दर्भ में मूल्य स्थायित्वता की प्राप्ति आदि महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हैं। सैद्धान्तिक अनुभवगम्य विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी देश के आर्थिक क्रियाओं में और विशेषकर विकास प्रक्रिया में मुद्रापूर्ति, मौद्रिक शक्तियों और इससे सम्बन्धित अन्य कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। मौद्रिक एवं साख नीति किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों आदि द्वारा निर्धारित होती है। अल्पविकसित देशों के सन्दर्भ में आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का योगदान तभी अधिकतम कहा जायेगा, जब यह पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर ले और इसके साथ ही साथ मूल्य को एक निश्चित सीमा से आगे न बढ़ने दे।

शोध - प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में मौद्रिक नीति के सिद्धान्त को स्पष्ट किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व केन्स के योगदानों से स्पष्ट होता है। इसके पूर्व क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा-पूर्ति पर बहुत महत्व नहीं दिया था। केन्स ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक मौद्रिक अर्थव्यवस्था मूल रूप से एक बारटर अर्थव्यवस्था से भिन्न है। केन्स ने अपने मौद्रिक विश्लेषणों और ब्याजदर सिद्धान्त द्वारा यह स्पष्ट किया है कि किस तरह ब्याजदर में परिवर्तन का प्रभाव विनियोग और अन्य आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है। केन्स के पूर्व मौद्रिक सिद्धान्त मुख्य रूप से मूल्य स्तर का सिद्धान्त था और सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित था। केन्सोपरान्त मौद्रिक सिद्धान्त में डॉन पेटिन्किन, फ्रीडमैन, गर्ले-शॉ आदि अर्थशास्त्रियों का योगदान विशेष रूप से रहा है। डॉन पेटिन्किन ने अपने वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धान्त द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर केम्ब्रिज मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में निहित अनुपातिका नियम को पुनः स्थापित किया और मुख्य रूप से मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार के अंतः प्रक्रिया द्वारा केन्सीय ब्याज सिद्धान्त के निष्कर्षों के विपरीत इस बात को स्थापित किया कि मुद्रा तटस्थ है और इसके परिवर्तन के परिणामस्वरूप ब्याजदर एवं विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मिल्टन फ्रीडमैन समस्त स्तर पर रोजगार तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिये मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि आवश्यक मानते हैं और अपने विश्लेषण से स्थापित किया है कि केन्सीय आय गुणक की तुलना में आय प्रचलन वेग अधिक स्थायी है। उन्होंने समग्र मुद्रा मांग को बढ़ाने में मौद्रिक नीतिको प्रमुख आधार माना है। इसके बाद गर्ले-शॉने इस बात को स्थापित किया कि व्यापक अर्थ में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को पूरी बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के क्रियाओं को भी नियंत्रित करना चाहिए।

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुख्यतः तीन अवयव होते हैं - पहला मुद्रा की मात्रा, दूसरा, साख की मात्रा और तीसरा, ब्याजदर। केन्द्रीय बैंक, बैंक दर में परिवर्तन करके ब्याज दर और ब्याज संरचना में परिवर्तन करता है, जिससे मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा नियंत्रित होती है। इसी तरह मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिये खुले बाजार की क्रियाएँ और आरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन करके नियंत्रण किया जाता है। केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के अन्तर्गत परिमाणात्मक और चयनात्मक (गुणात्मक) मुद्रा और साख नियंत्रण निधियों का सहारा लेता है।

सामान्यतः मौद्रिक नीति और साख नीति समान है । समान अधिकारी के रूप में केन्द्रीय बैंक दोनों नीतियों का निगमन करता है । समस्त स्तर पर दोनों के उपकरण समान हैं । बावजूद इस समानता के, मौद्रिक नीति कई कारणों से साख नीति से भिन्न है। मौद्रिक नीति जहाँ मात्र समग्र पूर्ति से सम्बन्धित है, वहीं साख नीति विभिन्न क्षेत्रों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच उसके निर्धारण से सम्बन्धित है। इसी तरह साख के स्रोतों में भी भिन्नता है, इसमें सस्थागत तथा गैर सस्थागत स्रोत हैं । मात्रा के अलावा साख के अन्य पहलू जैसे, इसकी लागत, इसकी शर्तें एवं दशाएं, अवधि, पुनर्करण, जोखिम आदि उधार लेने-देने वालों के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि साख नीति का क्षेत्र अधिक व्यापक है । मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति में आमतौर पर कोई स्पष्ट अन्तर तथा विभाजन करना संभव नहीं है। मौद्रिक नीति अपने फलनात्मक क्रिया के द्वारा कभी - कभी वित्तीय नीति का रूप ले लेती है और इसी तरह वित्तीय नीति भी कभी - कभी मौद्रिक नीति में परिवर्तित हो जाती है । उदाहरणार्थ, यदि अर्थव्यवस्था में घाटे के बजट को पूरा करने के लिये कर, सार्वजनिक ऋण तथा अन्य साधनों का सहारा लिया जाता है तो यह वित्तीय नीति के अन्तर्गत आयेगा, लेकिन यदि यही इस घाटे को पूरा करने के लिये अतिरिक्त मुद्रा को छाप कर घाटे की वित्त - व्यवस्था का सहारा लिया जाता है तो यह मौद्रिक नीति के अन्तर्गत आयेगा । इसी तरह मौद्रिक नीति, बैंकिंग नीति से भी बहुत समान है । इनमें सम्बन्ध और समानता इतना अधिक है कि प्रायः मौद्रिक नीति और बैंकिंग नीति एक ही मान लिया जाता है और उनमें अन्तर करना कठिन हो जाता है ।

मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि वह अर्थव्यवस्था के अधिकतम आर्थिक विकास की प्राप्ति में सहयोग दे । यद्यपि आर्थिक विकास को अधिकतम करने से सम्बन्धित मौद्रिक नीति के उद्देश्य में बहुत विवाद रहा है, किन्तु अब यह सर्वमान्य विचार है कि अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का प्रमुख योगदान है। उपयुक्त दशाओं में सस्ती और महंगी मुद्रा नीतियों पर प्रसारणपूर्ण तथा सकुचित मौद्रिक दशाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक सृष्टि को बढ़ाया जा सकता है । मौद्रिक नीति का दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह है यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में सहायक हो । पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के रूप में मौद्रिक नीति

अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, आय तथा रोजगार के वृद्धि में सहायक होती है। मौद्रिक नीति का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य आन्तरिक मूल्य का स्थिरीकरण करना है। आजकल आर्थिक विकास के साथ स्थायित्वता को प्राप्त करना, आर्थिक नीति का प्रधान लक्ष्य होता जा रहा है। मूल्य - स्तर में अप्रत्याशित उतार - चढ़ाव समाज के विभिन्न वर्गों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था का सामान्य आर्थिक विकास खतरे में पड़े जाता है और उत्पादन, वितरण आय तथा रोजगार स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः मौद्रिक नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा मूल्य में स्थायित्वता हो। मौद्रिक नीति विनिमय - दर के स्थायित्व के द्वारा भुगतान सन्तुलन के घाटे तथा पूँजी प्रवाह की समस्या का समाधान कर सकती है। अर्थव्यवस्था के आन्तरिक व बाह्य स्थिरता के लिये यह आवश्यक है कि मौद्रिक नीति विनिमय दर को स्थायी बनाये। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य मुद्रा को तटस्थ रखना भी है तटस्थ मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों पर मुद्रा की मात्रा से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों तथा परिवर्तनों को दूर करना है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय के महत्व के कारण यह आवश्यक हो गया है कि मौद्रिक नीति ऐसी हो, जिससे आय की असमानता दूर हो और वितरण की उचित व्यवस्था स्थापित हो। मौद्रिक नीति के उपयुक्त प्रमुख उद्देश्यों के अलावा प्राकृतिक साधनों का संचयन, अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, अधिक प्रभावपूर्ण विदेशी नीति तथा साधनों को अधिक गतिशील बनाने सम्बन्धी उद्देश्य में मौद्रिक नीति का सहयोग अपेक्षित है।

मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में कई सरचनात्मक अवरोध उत्पन्न होते हैं। ऐसे अवरोधों का एक समूह स्थिर स्फीतिकारी दशा से सम्बन्धित है और दूसरा लागत वृद्धि शक्तियों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। किसी भी अर्थव्यवस्था में यह कठिन कार्य होता है कि मौद्रिक नीति के सभी उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर एक समय में केवल कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करे और किसी दूसरे समय दूसरे उद्देश्य को। अल्प विकसित देशों में एक बड़े गैर-मौद्रिक क्षेत्र की स्थिति के कारण मौद्रिक नीति सीमित हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई क्षेत्र गैर-मौद्रिकृत है। यहाँ कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग बाजारी स्थिति का न हो कर जीवन

निर्वाह हेतु है । मौद्रिक एव साख नीति पाच अन्तरपरस्परीय कारको पर आधारित है । ये कारक निम्नलिखित है -

1 साख की उपलब्धता 2 मुद्रा की मात्रा, 3 ऋण की लागत पूजी, 4 आदेयो की कीमतें तथा 5 अर्थव्यवस्था की समान्य तरलता । भारत में मौद्रिक नीति का सम्बन्ध नियन्त्रणात्मक पक्ष से है । मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता मुद्रा एव साख नियन्त्रण के उपकरणो पर आधारित है । मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, आरक्षित अनुपात कोष में परिवर्तन, घाटे की वित्त व्यवस्था, रिजर्व बैंक की बैंको को दिये गये साख की उपलब्धता तथा लागत में परिवर्तन, बैंको की वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि हैं । जहा तक मौद्रिक नियन्त्रण की सरकार उपकरण का प्रश्न है, वह घाटे की वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित है । मौद्रिक एव साख नियन्त्रण के लिये बैंक दर का प्रयोग जब एक उपकरण के रूप किया जाता है तो इससे विनियोग एव साहसोद्यमियों के प्रत्याशाओं और लाभकारिता तथा नये विनियोग हेतु साख की माग पर प्रभाव पडता है। इस तरह यह वित्तीय सस्थाओ के साख राशिनिग नीति को प्रभावित करती है। बैंक दर का प्रभाव सरकारी बाँड दरो तथा प्रतिभूतियो के विक्रय पर भी पडता है । बैंक दर की प्रभावकारिता के सम्बन्ध में बहुत विवाद रहा है, किन्तु भारत मे, जहा नियोजित व्यवस्था मे सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, वहा विनियोग को प्रभावित करने मे यह शक्तिशाली उपकरण सिद्ध हुआ है । इसलिये रिजर्व बैंक ने बैंक दर नीति का बारम्बार प्रयोग किया है, जैसा कि सारणी 8 । मे स्पष्ट है ।

मौद्रिक नीति का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ हैं। इस का अभिप्राय रिजर्व बैंक द्वारा लोगों तथा अन्य बैंको से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एव विक्रय से है। रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार मे प्रतिभूतियो के क्रय से मुद्रा पूर्ति तथा उच्च अर्ध मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। और प्रतिभूतियों के विक्रय से यह मात्रा घट जाती है। किन्तु भारत मे रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाएँ मौद्रिक नियन्त्रण का एक शक्तिशाली उपकरण नहीं रहा है। तीसरे उपकरण के रूप मे केन्द्रीय बैंक आरक्षितो की दरो मे परिवर्तन करके मुद्रा प्रसार एव सकुचन की

सारणी 8 ।

भारत में बैंक दर में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

माह	वर्ष	बैंक दर
प्रथम योजना के पूर्व		3 0
नवम्बर,	1951	3 5
मई,	1957	4 0
जनवरी,	1963	4 5
सितम्बर,	1964	5 0
फरवरी,	1965	6 0
मार्च,	1968	5 0
मई,	1971	6 0
जुलाई,	1973	7 0
जुलाई,	1974	9 0
जुलाई,	1981	10 0
जुलाई,	1991	11 0
अक्टूबर,	1991	12 0

Source - Various Issues of Economic Survey.

स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस तरह नकद आरक्षित अनुपात में कमी के द्वारा मुद्रापूर्ति में वृद्धि और इसकी वृद्धि के द्वारा मुद्रापूर्ति में कमी लायी जा सकती है। खुले बाजार की क्रिया की तुलना में आरक्षित अनुपात उपकरण कम प्रभावी है। उपर्युक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक बैंको तथा विकास बैंको को साख की उपलब्धता तथा लागत में परिवर्तन, को मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में प्रयोग

करता है। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में संवैधानिक तरलता अनुपात महत्वपूर्ण हो गया है। इस विधि का प्रमुख योगदान व्यापारिक क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के बीच साख के आवंटन से है। इस विधि में सरकारी प्रतिभूतियों तथा ऋणों को प्रभावित करके उच्च अर्ध मुद्रा को प्रभावित किया जाता है, जिससे मुद्रा पूर्ति भी प्रभावित होता है। भारत में संवैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन मौद्रिक नीति का एक परिवर्तनशील उपकरण नहीं रहा है।

उपरोक्त मौद्रिक नीति के परिणामात्मक उपकरणों के साथ-साथ कुछ चयनात्मक उपकरण भी हैं। ये चयनात्मक विधियाँ सामान्यतः प्रतिभूति उन्मुख होती हैं। भारत में प्रथमतः 1956 में इन विधियों का प्रयोग किया गया था। वर्तमान समय में खाद्यान्न, तिलहन, खाद्य तेल, सूत एवं कपास, चीनी, गुड़ एवं खाडसारी, सूती वस्त्र आदि वस्तुएँ इन विधियों से सम्बन्धित हैं।

केन्स के सामान्य सिद्धान्त के बाद विश्व के अधिकांश देशों द्वारा महंगी मुद्रा के स्थान पर सस्ती मुद्रा नीति को अपनाया गया। सस्ती मुद्रा नीति के लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार पूर्णतया संगठित और विकसित हो। इसकी एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि पूँजी की सीमान्त दक्षता गिर रही हो, अर्थात् अर्थव्यवस्था में विनियोग, रोजगार तथा आय का स्तर बढ़ रहा हो और भविष्य की प्रत्याशा और तकनीकी ज्ञान का स्तर अपरिवर्तित हो। विनियोग की मांग और ब्याज लोचशील हो। एक अल्प विकसित देश में सस्ती मुद्रा नीति की मान्यता स्वीकार करना सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ मजदूरी जीवन निर्वाह के इतने सन्निकट है कि इसमें किसी भी तरह की कटौती लोगों को स्वीकार न होगी।

मौद्रिक नीति का अभिप्राय ऋण की मात्रा में वृद्धि और सरकार के नगद शेषों में कमी है, जिसका परिणाम मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने से है। जहाँ तक इन ऋणों को केन्द्रीय बैंक से लिया जाता है, अर्थव्यवस्था के चलन में सीधे करेन्सी की मात्रा बढ़ जाती है। यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और मूल्य स्थायित्वता के सन्दर्भ में घाटे की वित्त - व्यवस्था की अहम भूमिका है।

मौद्रिक नीति के सन्दर्भ में रेडक्लिफ कमेटी पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। रेडक्लिफ कमेटी को मौद्रिक नीति और उसके क्रियान्वयन के परीक्षण का एकमात्र दायित्व सौंपा गया था।

इस समिति ने ब्रिटिश मौद्रिक नीति के सैद्धान्तिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। फिर भी इस समिति की रिपोर्ट बिट्रेन के मौद्रिक विकास का सम्यक विश्लेषण नहीं प्रस्तुत कर सका। इस समिति ने यह स्वीकार किया है कि मौद्रिक उपायों के सन्दर्भ में कोई सरल सन्तुति सम्भव नहीं हो सकी और मौद्रिक समस्याओं का कोई समाधान विधि नहीं सम्भव है। इस समिति का मौद्रिक नीति के प्रभावकारिता पर भी बहुत कम विश्वास था।

मौद्रिक नीति की कुछ सीमाएँ हैं तथा कुछ निर्धारित कार्य क्षेत्र है। जहाँ तक मौद्रिक नीति के लिये सम्भव कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र, जो यह कर सकती है, वह है मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के द्वारा देश में अस्थायित्वता उत्पन्न करने वाले कारकों को नियंत्रित करना। इसके अतिरिक्त यह अर्थव्यवस्था को एक स्थायी पूँष्ठभूमि दे सकता है। स्फीतिकारी और घाटे के बजट की स्थिति में अल्पकालीन ब्याज दर में वृद्धि के द्वारा मौद्रिक नीति सहयोग कर सकती है। मौद्रिक नीति के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य स्तर का नियंत्रण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौद्रिक अधिकारियों को मौद्रिक नीति में तीव्र उतार चढ़ाव से बचना चाहिये। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो मौद्रिक नीति की सीमा से बाहर हैं। मौद्रिक नीति की प्रथम सीमा यह है कि दीर्घ अवधि तक ब्याज दर को स्थिर नहीं रख सकती है। केन्द्रीय बैंक द्वारा लोगों से प्रतिभूतियाँ खरीदने पर अन्ततः ब्याज दर गिर जाती है और इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में व्ययों पर पड़ने वाले दबाव के कारण कुल व्यय बढ़ जाते हैं, परिणामस्वरूप ब्याज दर बढ़ जाती है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यह बेरोजगारी दर को भी बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकती है। मौद्रिक मानों के आधार पर वास्तविक ब्याज दर, बेरोजगारी दर, वास्तविक राष्ट्रीय आय स्तर, वास्तविक मुद्रा पूर्ति तथा मात्रा वृद्धि दर को स्थिर नहीं बनाया जा सकता।

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध का तीसरा अध्याय मुद्रा पूर्ति के सिद्धान्त से सम्बन्धित दैर्घ्यमान समय में मुद्रा पूर्ति के चार स्वतंत्र मान $एम_1$, $एम_2$, $एम_3$, $एम_4$ के रूप में हैं। मुद्रापूर्ति का यह नया विश्लेषण भारतीय मौद्रिक आकड़ों का सशोधन दो क्षेत्रों में करेगा। प्रथमतः तरलता परिवर्तन के आधार पर यह नया उपागम मौद्रिक योगों के लिए अधिक विस्तृत अर्थ प्रस्तुत करता है। दूसरे, नया

उपागम अपने विस्तार वृद्धि के साथ मौद्रिक आकड़ों को वास्तविकता के और अधिक निकट लायेगा। मुद्रा पूर्ति के एक अन्य विश्लेषण बैंकिंग सर्वसमिका सिद्धान्त में यह दर्शाया गया है कि बैंकिंग व्यवस्था का कुल दायित्व उसके कुल आदेयों के बराबर होता है। यहाँ कुल दायित्व में मौद्रिक दायित्व तथा गैर मौद्रिक दायित्व सम्मिलित हैं। इसी तरह कुल आदेयों में वित्तीय आदेय तथा गैर वित्तीय आदेय सम्मिलित हैं। किन्तु मुद्रा पूर्ति का यह विश्लेषण एक अव्यवहारिक, सीमित और सकीर्ण विश्लेषण है। इस कारण से अधिक व्यवहारिक तथा मौद्रिक नियोजन की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से मुद्रा या साख गुणक का सिद्धान्त दिया जाता है। मुद्रा या साख गुणक सिद्धान्त के अनुसार मुद्रापूर्ति, करेन्सी तथा माग जमाओं के योग के बराबर होती है तथा मौद्रिक आधार, वास्तविक बैंक संचितों तथा करेन्सी के योग के बराबर है। इसके अलावा मुद्रापूर्ति तथा मौद्रिक आधार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, जबकि आरक्षित कोष अनुपात से विलोम सम्बन्ध है। मुद्रा पूर्ति का एक और अन्य विश्लेषण उच्च अर्ध मुद्रा (एच) सिद्धान्त है। साधारण मुद्रा के विपरीत उच्च अर्ध मुद्रा (एच) वह मुद्रा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा निर्गमित तथा जो लोगों एवं बैंक के पास है भारतीय रिजर्व बैंक इस मुद्रा को आरक्षित मुद्रा मानती है। मुद्रापूर्ति के 'एच' सिद्धान्त को मुद्रा गुणक का सिद्धान्त भी कहते हैं। मुद्रा पूर्ति के 'एच' सिद्धान्त की यह मान्यता है कि प्रचलित ब्याज-दर के सन्निकट लाभ अर्जित करने वाले आदेयों की पूर्ति अत्यधिक लोचदार होती है और सामान्यतया बैंक अपने अवाक्षित अतिरिक्त आरक्षितों के द्वारा इन लाभ अर्जित आदेयों की ओर उन्मुख नहीं होते। इस तरह 'एच' सिद्धान्त की यह महत्वपूर्ण मान्यता है कि बैंक अपने आरक्षित जमाओं में संस्थिति प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि 'एच' का निर्धारण नीतिगत है, लेकिन वास्तविक व्यवहार में यह इतना आसान नहीं है। एक और सिद्धान्त मुद्रा पूर्ति का लेखा-जोखा विश्लेषण भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के संचयित लेखा-जोखा चार्ट से प्राप्त किया जाता है। इसको इसके वित्तीय आदेयों को क्षेत्रवार विभाजित करके बनाया जाता है। इसमें व्याख्यात्मक गुण नहीं हैं, क्योंकि यह विशुद्ध लेखा-जोखा विश्लेषण है। यह अनेक नीतियों और गैर-नीतियों में होने वाले परिवर्तन के कारण उनके मुद्रा पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है। यह मुद्रापूर्ति का लेखा - जोखा विश्लेषण 'एच' और 'एम' के अवयवों के योग को प्रस्तुत करता है और इसमें 'एच' पर 'एम' के आश्रित होने का ध्यान नहीं दिया जाता।

साख की पूर्ति और इसके निर्धारण के सम्बन्ध में साख निर्माण के सामान्य प्रश्न पर मानक सिद्धान्त अत्यन्त सरल है । यहाँ पर एक समरूप साख बाजार की मान्यता है, जिसमें ऋण ग्राहकों के सभी साख अदाओं को साख देने की एक जैसी बात कही जाती है । साथ ही साथ यह भी मान्यता है कि बाजार के दोनों पक्षों में पूर्ण प्रतियोगिता कार्यशील है, जिससे कुल माग, कुल पूर्ति के आधार पर एक ही समरूप ब्याज दर का निर्धारण होता है । विशेष बात यहाँ यह है कि प्रत्येक ऋण ग्राहक जितनी भी मात्रा में ऋण लेना चाहे, वह प्रचलित ब्याज दर पर ले सकता है, अर्थात् व्यवस्था में कोई भी साख राशिनिग नहीं है। इस तरह के साख बाजार का फलन पूर्णतः अवास्तविक है, क्योंकि एक तो साख बाजार पूर्णतः समरूप नहीं होते हैं और दूसरे इन बाजारों में सदैव पूर्ण प्रतियोगिता नहीं रहती है, प्रायः योग्य ऋण ग्राहकों का चुनाव गैर मूल्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इसी तरह कुल साख की मात्रा का भी निर्धारण किया जाता है। यहाँ यह दिखाना आवश्यक होगा कि गैर मूल्य कारक किस तरह मूल्य कारक पर अधिक प्रभावी है । सस्थागत कारक के प्रभावित कारकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - वित्तीय तथा गैर-वित्तीय। जहाँ तक सस्थागत साख के निर्धारण में वित्तीय कारकों का प्रश्न है, उसमें साख की अदायगी तथा शुद्ध प्रतिफल दर हैं। इन दो मुख्य कारकों के साथ और बहुत से अन्य कारक भी हैं, उन्हें इसमें स्वतः निर्धारण कर लिया जाता है और सीमित अर्थ में यह ब्याज दर एक राशिनिग प्रक्रिया का कार्य करता है, किन्तु इच्छुक ऋण ग्राहकों में ब्याज दर के अलावा अन्य शक्तियाँ भी कार्य करती हैं और यही शक्तियाँ सस्थागत साख के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं । इससे सस्थागत ऋण दाताओं को छोटे ऋण देने में हतोत्साहित होना पड़ता है । सामान्यतया एक स्थायी राजनैतिक वातावरण में सरकारी ऋणों पर अदायगी का जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों से अदायगी के इसके अनेक अधिकार होते हैं, परन्तु व्यक्तिगत क्षेत्रों के सभी ऋणों पर कुछ न कुछ जोखिम रहता ही है । अतः ऋण दाता का सबसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध इस जोखिम का पता लगाना है और पर्याप्त रूप से सुरक्षित होना है। इस तरह के साख निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह से न तो बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और न ही वे मात्र माग और पूर्ति शक्तियों से निर्धारित होती है । यह कई गैर-बाजारी शक्तियों पर भी आधारित है और हर देश में अलग - अलग कारक होते हैं । यहाँ पर

साख अदायगी से सम्बन्धित जोखिम के दो स्रोतों को बता देना महत्वपूर्ण होगा । (1) व्यक्तिगत (नैतिक) जोखिम, (2) व्यापारिक जोखिम । अनुभव के आधार पर यह प्राप्त हुआ है कि भुगतान सामर्थ्यता भी ऋण दाता के लिए ऋण देने के लिए उत्साहित नहीं करता, क्योंकि वास्तविक साख क्षति की दशा में यह पर्याप्त नहीं है कि ऋण दाता ऋण और ब्याज की वसूली कर सके । परिणाम स्वरूप ऋण दाता पर्याप्त मात्रा में ऋण के बदले प्रतिभूति रखने पर जोर देता है। ऋण के बदले में दी जाने वाली प्रतिभूतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं - प्राथमिक प्रतिभूतियाँ और कोलेटरल प्रतिभूतियाँ । बैंक सामान्यतया बैंकिंग आदेशों के पूरे मूल्य के बराबर ऋण प्रदान नहीं करते, बल्कि उसके एक प्रतिशत के रूप में ऋण दिया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य और प्रतिशत ऋण के अन्तर को ऋण ग्राहक के उधार लेने की शक्ति को प्रदर्शित करता है ।

परंपरागत सिद्धान्त में किसी व्यक्तिगत ऋण ग्राहक की पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार होती है और निर्धारित बाजारी ब्याज दर पर इस वक्र पर इन कारकों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्तिगत ऋण ग्राहक जितना चाहे उधार नहीं ले सकता । इस तरह साख पूर्ति वक्र ऊपर की ओर ढाल लिए होती है । अतः धनी ऋण ग्राहक को साख प्रदत्त की मात्रा निर्धन ऋण ग्राहक की तुलना में अधिक होगी । इस तरह ऋण ग्राहकों में साख राशिनिग का अनुपात अनुपातिक रूपसे समान नहीं होगी । यदि सस्थागत साख का निर्धारण सस्थागत है और एक बाजारी प्रक्रिया नहीं है तो इसको गैर-वित्तीय कारक भी उसी तरह प्रभावित करेंगे । यह मुख्य कारक सामाजिक और राजनैतिक हैं । मुद्रापूर्ति का विशुद्ध बैंकिंग सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के विभिन्न स्रोतों को दिखाता है और अर्थव्यवस्था में किसी विशिष्ट अवयव के नियंत्रण द्वारा मौद्रिक स्थायित्वता प्राप्त करने में सहयोगी है । भारत जैसी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग दशा तथा मुद्रा मांग के विभिन्न अवयव मौद्रिक नियंत्रण हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

चौथे अध्याय में पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति का क्रमबद्ध अध्ययन है । भारत सरकार ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं में एक सुदृढ़ मौद्रिक एवं साख

नीति के महत्व पर बल दिया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में यद्यपि मौद्रिक नीति के निश्चित तथा स्पष्ट उद्देश्य सामने नहीं थे, फिर भी प्रारम्भ में समस्या अल्पकालिक सन्स्थिति को प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि आर्थिक विकास लाने की थी। इस योजना में मौद्रिक नीति के महत्व को देखते हुये साख सृजन पर विशेष बल दिया गया । कृषि की अशांति उत्पादन के कारण योजनावधि में मूल्य स्तर में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी, जैसा कि आगे की योजनाओं में देखी गयी । योजना प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद बैंक दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 5 प्रतिशत कर दी गयी । खुले बाजार की क्रियाओं का भी योजना में प्रयोग किया गया । प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में मौद्रिक नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि पूरी योजनावधि में चयनात्मक साख नियन्त्रण का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। इस योजनावधि में वास्तविक राष्ट्रीय आय में 14 4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी तथा मुद्रा पूर्ति में 10 5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी । बैंकिंग क्षेत्र से सरकार द्वारा ऋण की मात्रा में कुल वृद्धि रुपये 2974 करोड़ थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में हुये मुद्रा प्रसार को विरस्त में लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ । जून 1955 से मार्च 1956 के बीच खाद्यान्नों के मूल्य में 30 प्रतिशत तथा सामान्य कीमत निर्देशांक में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुयी । योजनावधि में वित्तीय व्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था । वास्तविक राष्ट्रीय आय में 21 7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी तथा मुद्रा पूर्ति में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुयी, तदनुसार मुद्रा पूर्ति रुपये 2184 करोड़ से बढ़ कर रुपये 2902 करोड़ हो गयी । द्वितीय योजनावधि में मुद्रा की पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में स्फीतिक वृद्धि हुयी । मुद्रा प्रसार मागजन्य प्रकार का था, क्योंकि इस योजना में वस्तुओं की पूर्ति की अपेक्षा व्यय की मात्रा बहुत अधिक रही। इन व्ययों को पूरा करने के लिये घाटे की वित्त व्यवस्था को प्रमुखता दी गयी । अर्थव्यवस्था में साख नियन्त्रण के लिये रिजर्व बैंक में दोनो ही परिमाणात्मक तथा चयनात्मक विधियों का सहारा लिया । परिमाणात्मक साख नियन्त्रण के अन्तर्गत पूरी योजनावधि में बैंक दर केवल एक बार मई 1957 में 3 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया । बिल बाजार के अन्तर्गत ब्याज दर में कई बार वृद्धि की गयी, अन्तिम बार अक्टूबर 1960 में किया गया । 1956 में बैंक द्वारा नियन्त्रित प्रसार तथा विभेदात्मक समर्थन की नीति को अपनाया गया । मई 1960 तथा जनवरी 1961 में बीच

परिवर्तनशील नकद अनुपात विधि का प्रयोग भी किया गया । योजनाकाल में पहली बार चयनात्मक साख नियंत्रण का प्रयोग किया गया । इस योजनाविधि में छ खाद्यान्नों से सम्बन्धित तथा एक सूती वस्त्र से सम्बन्धित इस प्रकार कुल सात आदेश जारी किये गये। इन आदेशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने वह अधिकतम सीमा निर्धारित की, जो इन वस्तुओं के आधार पर किसी एक ऋण लेने वाले को दी जा सकती थी । रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति को नियंत्रित सीमा में रखने का भरसक प्रयास किया, किन्तु वह इसमें असफल रही ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना एक अव्यवस्थित अवस्था में प्रारम्भ हुयी, क्योंकि दूसरी योजना के अन्त में मुद्रा स्फीति की स्थिति काफी निराशाजनक थी । लगभग पूरी योजनाविधि में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को सामान्यतः चुस्त बनाया गया । घाटे की वित्त व्यवस्था, जिसका अनुमान 7.3 प्रतिशत था, बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गयी । मुद्रा प्रसारीय सरकारी वित्त व्यवस्था तथा बैंक साख के लिये बढ़ती हुयी मांग के फलस्वरूप मुद्रा पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुयी । यह वृद्धि 58 प्रतिशत तक रही । 1960-61 के मूल्य पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि लगभग 15 प्रतिशत हुयी । इसके साथ ही मूल्य स्तर में भी वृद्धि हुयी । योजनाविधि में थोक मूल्य निर्देशांक में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। नियंत्रित मौद्रिक नीति के बावजूद भी व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्गत ऋण में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। परिमाणात्मक साख-नियंत्रण के अन्तर्गत बैंक दर में वृद्धि कई स्तरों पर किया गया । जनवरी 1963 में 4 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत, सितम्बर 1964 में 5 प्रतिशत और फरवरी 1965 में 6 प्रतिशत बैंक दर कर दिया गया। परिवर्तनशील नकद अनुपात का प्रयोग नहीं किया गया । चयनात्मक साख नियंत्रण के सन्दर्भ में 1960 से 1963 के बीच इन नीतियों में कुछ उदारता कर दी गयी । 1963 में साख के प्रवाह के नियंत्रण हेतु गेहूँ, चावल, धान, चीनी आदि के सम्बन्ध में पुनः आदेश जारी किये गये । तीसरी योजनाविधि में देश में मौद्रिक विस्तार बहुत अधिक हुआ । तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने पर रिजर्व बैंक की नीति की प्रभावपूर्णता इस बात में भी झलकती है कि बैंक साख की बहुत अधिक मात्रा ग्रामीण कुटीर उद्योग धर्मों तथा सहकारी क्षेत्रों को मिली है । इतना ही नहीं बैंक ने व्याज दर के ढाँचे में उर्ध्वमुखी परिवर्तन का भी प्रयास किया, जिससे बैंक द्वारा दी जाने वाली साख की लागत बढ़ जाये तथा स्फीतिक वृद्धि के

नियन्त्रण में यह सहायक हो सके । पिछली योजना की ही तरह इस योजना में भी मूल्य में तीव्र वृद्धि बनी रही । इसके बाद वार्षिक योजनावधि में सबसे विचित्र स्थिति यह रही कि मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर में कमी के बावजूद भी मूल्य स्तर में वृद्धि देखी गयी । थोक मूल्यों के सामान्य निर्देशांक में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई । असामान्य स्थिति के कारण सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में बैंक साख के प्रसार में कमी दिखाई पड़ी। रिजर्व बैंक ने बैंको के तरलता अनुपात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाने की प्रवृत्ति रखी। इस वार्षिक योजनावधि में मौद्रिक नीति की सबसे प्रमुख घटना मार्च 1968 में घटी, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार बैंक दर को 6 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया । फरवरी 1969 में पुनर्वित्त प्रणाली में अनेक सुधार लाये गये । अल्पकालीन तथा कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों के सम्बन्ध में एक समान दर 4 5 प्रतिशत निश्चित की गयी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य से स्फीतिकारी दबावों प्रारम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास को स्थायित्वता की दशा को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया । इस योजना के मौद्रिक एवं साख नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप समग्र मांग एवं पूर्ति में सतुलन कायम करना, नयी उभरती हुई स्थिति के सन्दर्भ में घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा को निर्धारित करना तथा 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण (जुलाई 1969) के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन के वित्तीयन के लिए अधिक ससाधन उपलब्ध कराना, प्राथमिक क्षेत्रों और विशेषकर उपेक्षित क्षेत्रों, कृषि छोटे उद्योग आदि में साख प्रवाह को निर्धारित करना, विकास के साथ - साथ निर्यातों एवं उद्योगों की आवश्यकता के लिए साख की पूर्ति करना था । बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर जनवरी 1971 में 6 प्रतिशत तथा पुन मई 1973 में 7 प्रतिशत कर दिया गया । 1970 में सवैधानिक तरलता अनुपात को दो बार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 27 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत कर दिया गया और पुन अगस्त 1972 में इसे 30 प्रतिशत तथा 1973 में 32 प्रतिशत कर दिया गया । इसी के साथ-साथ आवश्यक शुद्ध तरलता अनुपात को भी 1973 में 40 प्रतिशत कर दिया गया, 1973-74 के दो मन्दी काल में नकद आरक्षित अनुपात को भी क्रमशः बढ़ाकर 3 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत कर दिया गया । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्तीयन की सुविधा को क्रमशः

अधिक कड़ा कर दिया गया । बैंको के अग्रिमो पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया । 1973-74 के व्यस्त काल में परिमाणात्मक साख विधियों को अपनाया गया । 1972-73 तथा 1973-74 के व्यस्त काल में बैंक साख में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और बाद के वर्षों में साख विस्तार अपने शिखर स्तर तक पहुँच गया, यह साख विस्तार परिमाणात्मक साख विस्तार की नियंत्रणात्मक सीमा के बाद भी हुआ । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समयावधि में मुद्रापूर्ति बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया, जो इसी समयावधि में वास्तविक उत्पादन वृद्धि 18.9 से बहुत अधिक ऊँची थी । पूरी समयावधि में कुल प्रदत्त साख 22.3 प्रतिशत से बढ़कर 36.7 प्रतिशत हो गयी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में मौद्रिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि बैंक साख में वृद्धि वास्तविक उत्पादन वृद्धि से काफी अधिक हो गयी । इस समयावधि में एक महत्वपूर्ण कारक जो साख नियंत्रण उपकरणोंकी प्रभावकारिता को सीमित किया, वह उधार देय ससाधनों से सम्बन्धित था । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश में गैर-लेखा जोखा वित्त के साथ स्फीतिकारी दशाएँ विकसित हुईं और इनका पुनः प्रभाव मौद्रिक एवं साख नीतियों के प्रभावकारिता पर पड़ा ।

पाचवी पंचवर्षीय योजना में गैर स्फीतिकारी विकास को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इस योजना के पूर्व स्फीतिकारी प्रवृत्ति बहुत अधिक सुदृढ़ हो चुकी थी । इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों में कोई भी घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं की जायेगी। इस योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि वित्तीय एवं मौद्रिक नीतियों में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित सगति होनी चाहिए । इस योजना में मुद्रा प्रसार और स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने हेतु बैंक दर को महत्वपूर्ण ढग से 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। इसी के साथ साथ व्यापारिक बैंको के अग्रिमो सम्बन्धी न्यूनतम ऋण दरों को भी 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया और अधिकतम ऋण दरों को 9 प्रतिशत से 10.5 प्रतिशत कर दिया गया । इस योजना में विस्तृत निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित साख प्रयोग पर बल दिया गया । इस समयावधि में टण्डन समिति की रिपोर्ट और प्रस्तावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1974 में व्यापारिक बैंको के साख वितरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश निर्गत किये । थोक कीमतों का सूचकांक 1974-75 में गिरकर 7.1 प्रतिशत हो गया । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्घोषित

उपायों में सामान्य तथा चयनात्मक साख उपाय अधिक लचीले ढंग से प्रयोग किये गये। शुद्ध तरलता अनुपात की व्यवस्था, जो पिछले दस वर्षों से चली आ रही थी, उसे समाप्त कर दिया गया। वैधानिक नकद अवशेष को 1976 में 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया और पुन उसी वर्ष 6 प्रतिशत कर दिया गया। व्यापारिक क्षेत्रों में बैंक साख में महत्वपूर्ण वृद्धि मुद्रापूर्ति में वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रही और मुद्रापूर्ति 1976-77 में बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गयी। मुद्रापूर्ति विस्तार में एक नया कारक जो वर्ष 1975-76 से विराजमान रहा, वह विदेशी विनिमय आदियों में तीव्र वृद्धि का होना था। इसमें 1975-76 में वृद्धि रुपये 711 करोड़ हुआ। इस समयावधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो साख नीति अपनाई गयी, वह प्रथम दो वर्षों में नियंत्रणात्मक प्रवृत्ति के साथ सफल रही। इस समयावधि में साख नीति में महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रीय साख बटवारे से सम्बन्धित था, जिससे अधिक आर्थिक और तार्किक रूप से बैंक ससाधनों का प्रयोग हो सके। बैंकिंग व्यवस्था और अत्यधिक तरलता को नियंत्रित करने तथा बैंक साख विस्तार को रोकने के सम्बन्ध में इस समयावधि में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। वर्ष 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को यह सलाह दिया कि कृषि और लघु उद्योगों के क्षेत्र में साख को आवंटित करने में प्राथमिकता दें। फिर भी 1977-78 में मुद्रा पूर्ति में जो 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वह राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक थी।

छठी पंच वर्षीय योजना के पहले वर्ष में यद्यपि कीमत स्तर में अत्यधिक वृद्धि 17 प्रतिशत हुयी थी, परन्तु दृढ़ कीमत नियंत्रण और मौद्रिक उपायों को सफलता पूर्वक प्रयोग करके सरकार कीमतों पर नियंत्रण पाने में सफल रही थी, लेकिन सरकार को इसके लिए भारी घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पडा। छठी योजना के दौरान मौद्रिक नीति सामान्यतः अत्यधिक तरलता को रोकने की थी, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। इस योजना में उत्पादक एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की मूल आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया। सितम्बर 1981 में नकद आरक्षित अनुपात 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे मुद्रा एवं उधार को नियंत्रित किया जा सके। इस योजना में चावल, गेहूँ, चीनी, गुड़ आदि वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास किया गया। 1981 में नकदी आरक्षित अनुपात को ऊँचा कर दिया गया। विवेकपूर्ण

वित्तीयन तथा पुर्नगणना दर में उर्ध्वमुखी सशोधन किया गया । पुनर्वित्तीयन पर ब्याज की अधिकतम दर को 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया । 1981 में ही बैंक दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया । साथ ही खाद्य तथा निर्यात सम्बन्धी पुनर्वित्तीयन भी 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया ।

कुछ संवेदनशील वस्तुओं को चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा नियंत्रित किया गया। गेहूं, धान, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की न्यूनतम मार्जिन 10 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दिया गया। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने में प्राथमिकता दी गयी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ कर दिया गया । जनवरी 1982 में निर्यात को समर्थन देने के लिये निर्यात - आयात ऐक की स्थापना किया गया । जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नये बैंक, जिसका नाम नाबार्ड रखा गया प्रारम्भ किया गया । 1984 में अर्थव्यवस्था में पूजीगत विनियोगों को और तेज करने की दृष्टिकोण से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण नीति को और उदार कर दिया गया । फलस्वरूप 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिया गया । छठी पंचवर्षीय योजना में अत्यधिक मौद्रिक विस्तार हुआ । एक ओर जहाँ बृहत् मुद्रा (एम₃) में औसतन 16.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुयी, वहीं प्रारक्षित मुद्रा में 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गयी ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी महत्वपूर्ण मौद्रिक विस्तार हुआ । बृहत् मुद्रा पूर्ति (एम₃) में औसतन 17.6 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुयी । सकीर्ण मुद्रा पूर्ति (एम₁) में औसतन 16.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुयी । चयनात्मक साख नियंत्रण के अन्तर्गत अप्रैल, 1986 में साख अधिकरण योजना के लिये उधार सीमा बढ़ाकर रुपये 6 करोड़ कर दिया गया । सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण जहाँ 1985-86 में मात्र रुपये 3,186 करोड़ था, वहीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 में बढ़कर रुपये 14,056 करोड़ हो गया था । भारतीय रिजर्व बैंक ने 1987 में चक्रवर्ती कमेटी की सत्तुतियों को लागू किया, जो नियोजित ढंग से समग्र मौद्रिक लक्ष्यों की आवश्यकता और विकास

द्वारा उपर्युक्त मौद्रिक समृद्धि प्राप्त करने से सम्बन्धित थी । सातवीं योजना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्ग के निर्यातको, स्व रोजगार योजना के उद्यमियों तथा ग्रामीण कलाकारों को विशेष रूप से साख उपलब्ध कराया गया । पूरी योजनावधि में मौद्रिक एवं साख नीति का उद्देश्य तरलता में वृद्धि को नियंत्रित करने से रहा है। क्षेत्रीय साख व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रधान उपकरण चयनात्मक साख नियंत्रण था । इसके अतिरिक्त एक अन्य उपकरण साख अधिकरण परियोजना को भी महत्वपूर्ण माना गया । 1988-89 में लेखा वर्ष को कैलेंडर वर्ष से बदल कर वित्तीय वर्ष कर दिया, जिससे बैंको की जमा राशियों और ऋणों में वर्ष के अन्त में असामान्य वृद्धि आयी । सातवीं योजना की पूरी योजनावधि में साधन पक्ष की ओर मुद्रा पूर्ति वृद्धि में लगातार बढ़ोत्तरी के कारण काफी अधिक सीमा तक लगातार राजकोषीय असन्तुलन बना रहा । सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि का प्रमुख स्रोत रहा । सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 के दौरान मियादी उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा सहायता की बहुत सी नई योजनाएँ प्रारम्भ गईं । एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, अपतटीय निधि के क्षेत्र में भी भारतीय बैंको ने सातवीं योजना के दौरान प्रवेश किया है। इन निधियों के लिये अनिवासी भारतीय और विदेशी लोगों के सहयोग से इनका कारोबार लन्दन और न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंजों में होता है ।

सातवीं योजना के अन्त से अत्यधिक तरलता के विद्यमान रहने से मुद्रा स्फीति की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । अतः आगे के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत कार्यों में सकल माग और विशेषकर आयात माग को सीमित रखना सर्वोपरि उद्देश्य बन गया । इसके बाद सरकार ने जुलाई, 1991 में नई उदार आर्थिक नीति की घोषणा की और वर्तमान समय तक उदारीकृत आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में नीति निर्माण हो रहा है । 1990-91 में सरकार ने विस्तृत बजट घाटा प्रस्तुत किया, जिससे सरकार को निवल बैंक ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक ऋण दोनों में ही तीव्र वृद्धि हुयी। इस वर्ष अच्छी फसल के कारण खाद्य ऋण में तज वृद्धि देखने में आयी, जबकि खाद्य भिन्न ऋण में अपेक्षाकृत काफी कम वृद्धि हुयी । सामान्य ऋण नियंत्रण अनुसूचित वाणिज्य बैंको के सन्दर्भ में अपरिवर्तित रहा । सितम्बर, 1990 से सांविधिक नकदी अनुपात को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.5

प्रतिशत कर दिया गया । जुलाई, 1990 स तिलहनो और खाद्य तेलों के अग्रिमो के सन्दर्भ में चयनित ऋण नियंत्रण को कठोर कर दिया गया है । गहू को इस नियंत्रण से मुक्त रखा गया । जनवरी, 1991 से निर्यात ऋण को उदारीकृत कर दिया गया । भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1990 से अनुसूचित वाणिज्य बैंको के लिये उधार दरो को नय सिरे से व्यवस्थित किया । हुडी प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिये जनवरी, 1991 से सम्बद्ध नरुद ऋण ब्याज दर से अधिक 2 प्रतिशत बिन्दु पर ब्याज दर निर्धारित किया गया । सितम्बर, 1990 स रूपये 7,500 तक के अग्रिमो पर वाणिज्यक ब्याज दर 10 प्रतिशत रखी गयी । अक्टूबर, 1990 स अनुसूचित वाणिज्य बैंको की कुछ श्रेणियो पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतन्त्रता दे दी गयी । वित्तीय वर्ष 1990-91 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कीमत संवेदनशील वस्तुओ के लिये बैंक ऋण के सबध मे चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋण के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मई, 1990 में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 लागू किया गया, जो 30 जून 1991 को समाप्त हुयी । योजना के अन्तर्गत रूपये 7,962 करोड का ऋण राहत प्रदान किया गया । अप्रैल, 1990 में एक नये बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किया गया ।

अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एव साख क्षेत्र मे उठाये गये कदमो के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, वार्षिक मुद्रा स्फीति दर, जो अगस्त 1991 मे 17 प्रतिशत था, वह घटकर मई 1993 मे 6 प्रतिशत हो गयी । सामान्य आर्थिक सवृद्धि दर, जो 1991-92 मे केवल 1.2 प्रतिशत थी, वह 1992-93 मे बढ़कर 4 प्रतिशत हो गयी । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य हानि पर चल रहे बैंको के साख वितरण तथा अग्रिमो पर अनेक नियंत्रणात्मक उपाय क्रिये गये । मौद्रिक क्षेत्र के उपायो के सम्बन्ध मे विनियम दर नीतियों मे परिवर्तन किया गया । केन्द्रीय सरकार का वित्तीय घाटा वर्ष 1990-91 मे सकल घरेलू उत्पाद को 8.4 प्रतिशत से कम करके 1991-92 में 6.5 प्रतिशत तथा पुन 1992-93 मे 5 प्रतिशत कर दिया गया । इन आर्थिक सुधारो, उपलब्धियों तथा कार्यक्रमो के आलोचनात्मक मूल्यांकन के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मुद्रा स्फीति की दर मई 1993 मे घट कर 6 प्रतिशत हो गयी, किन्तु वास्तविक स्थिति मे आवश्यक वस्तुओ के मूल्य में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आयी है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 1993-94 की अन्तिम छमाही हेतु 11 अक्टूबर 1993 को नयी नीति की घोषणा की। घोषणा के अनुसार वैधानिक तरलता अनुपात 16 अक्टूबर से 37 25 के स्थान पर 34 75 प्रतिशत होगी। यह घटी हुई दर 17 सितम्बर तक की देनदारी के स्तर पर लागू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नयी नीति का उद्देश्य उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त बैंक समर्थन सुनिश्चित करना है। लदान पूर्व निर्यात कर्ज के लिए विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डालर) में ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। कम्पनियों को तीन माह से एक साल में पूर्ण भुगतान के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी गयी है। प्रवासी भारतीयों के रूपया मुद्रा खाता पर ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी कर दी गयी। नाबार्ड की ऋण सीमा में 400 रुपये की बढ़ोतरी किया गया बैंको द्वारा ऋण सीमा रुपये 5 करोड से बढ़ाकर रुपये 50 करोड करने को कहा गया है। गेहूँ और कपास के लिए ऋण लेने वालों पर ऋण नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्तियन में कमी करके 90 प्रतिशत कर दिया गया।

पाचवे अध्याय में भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नीति को स्पष्ट किया गया है। 1971 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव था, को छोड़कर शेष भारत में लगभग 70 प्रतिशत किसान ऋण ग्रस्त थे। एक सर्वे के अनुसार जून, 1971 में कुल ग्रामीण ऋण रुपये 3,848 करोड था। यू एन आई की 1975 का सर्वे यह प्रदर्शित करता है कि लगभग 65 से 70 प्रतिशत छोटे किसान, ग्रामीण हरिजन और आदिवासी ऋणग्रस्त हैं और ग्रामीण साहूकारों, महाजनो द्वारा स्वतन्त्र रूप से उनका शोषण किया जा रहा है। किसानों और ग्रामीण के इतनी बड़ी मात्रा में ऋणग्रस्त होने का प्रमुख कारण है, कृषि उपज का अत्यन्त निम्न स्तर। फलस्वरूप किसानों का आय स्तर नीचा है, जिससे वे अपनी उपभोग एवं उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाते और यह अनुत्पादक ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण ग्रस्तता के मुख्य कारण हैं - पैतृक ऋण, कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन, कृषकों की दयनीय आर्थिक स्थिति, खर्चीले सामाजिक रीति रिवाज, कृषि पर जसख्वा का अतिभार, कृषकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा आदि।

मोटे तौर पर कृषि साख के तीन पक्ष हैं- दीर्घकालीन, मध्य कालीन तथा अल्प कालीन । सामान्यतया कृषको को साख की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है । पहला, कृषको को दीर्घकालीन विनियोग के लिए साख दूसरा, मध्य कालीन उपकरण साख की । तीसरा, बीजों, खादों, उर्वरकों तथा उपकरणों आदि के रख रखाव एवं भूमि के चालू खर्चों पर कार्यशील पूँजी की ।

भारतीय रिजर्व बैंक सीधे कृषि क्रियाओं का वित्तीयन नहीं करता, किन्तु यह अपने कृषि विभाग एवं नाबार्ड द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्तीयन करता है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में कृषि साख विभाग की अलग से स्थापना की गयी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का अध्ययन दल तैयार करना है। जहाँ तक अल्पकालीन साख का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि साख के वित्तीयन हेतु प्रदान करता है और साथ ही साथ फसलों के विपणन, क्रय तथा उर्वरकों के वितरण आदि हेतु वित्तीयन करता है। मध्यकालीन साख का वितरण राष्ट्रीय कृषि साख फंड द्वारा कृषि सुधार हेतु प्रदान किया जाता है। इस तरह के ऋणों को 15 माह से 5 वर्ष के समयावधि के लिए प्रदान किये जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जहाँ तक दीर्घकालीन साख का प्रश्न है, वह राष्ट्रीय कृषि फंड (दीर्घ कालीन क्रियाओं हेतु) के माध्यम से दी जाती है। इस वित्त का प्रयोग राज्य सरकारों को अग्रिमों को देने से है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी साख समितियों के माध्यम से वितरण करते हैं । सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण 5 वर्ष से 20 वर्ष अवधि के लिये दिये जाते हैं। 1951-52 में साख के मुख्य रूप से दो स्रोत प्रधान थे, पहला, महाजन और दूसरा, ऋण ग्राहक के सम्बन्धी, दोनों मिलाकर के लगभग 84 प्रतिशत कुल साख को प्रदत्त करते थे । सरकार व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक केवल 7.6 प्रतिशत साख प्रदान करते थे । किन्तु 1970 और उसके बाद संस्थागत साख एजेंसियों का योगदान एवं प्रवृत्ति को बढ़ते हुए ग्रामीण साख के रूप में देखा जा सकता है। भारत में कृषि साख व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये जा सकते हैं । जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

1. कृषि साख काफी समय के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य के

लिए लिया गया हो, वह पूरा सके ।

2 ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली साख पूर्णतः सुरक्षित ढाँची चाहिए, जिससे साख सुविधाओं का दुरुपयोग न होने पाये ।

3 कृषि साख को उपयुक्त बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों की जिम्मेदारी पर ढाँची चाहिए, जो बैंकिंग एवं कृषि अनुभवों तथा प्रशिक्षणों को प्राप्त कर चुके हैं ।

4 कृषि साख को राज्य की नीतियों के साथ जुड़ा होना चाहिए ।

5 कृषि साख व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऋण ग्राहक इस जिम्मेदारी को न सके कि वह ऋण अदायगी कर सकेगा ।

6 जिन कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण दिया जाता है, वह पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा कृषकों को अन्य स्रोतों से अपने स्तर पर ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

7 ऋण इस प्रकार होना चाहिए कि ऋण ग्राहक को यह सहयोग करे और उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करे, न कि उसको कठिनाइयों में डाले

इसी सन्दर्भ में चक्रवर्ती समिति ने ब्याज दर की कमियों को दिखवाया है। प्रथमतः यह प्रभावी साख को सृष्टि करने में असफल रहा । दूसरे, यह पूरी बैंकिंग व्यवस्था के लिए कम लाभकारिता सिद्ध हुई । इस तरह से जहाँ तक कृषि ऋण का प्रश्न है, इसमें दो वर्ग होने चाहिए । पहला, सकीर्ण वर्ग, जो अलग से लघु एवं सीमान्त कृषकों को रियायती दर पर होना चाहिए और दूसरा, अन्य ऋण ग्राहक, जो ब्याज दर के नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिन पर ऊँची ब्याज दर होनी चाहिए । हाल के वर्षों में कृषि साख के क्षेत्र में यह भी देखने में आया कि साख संस्थाओं पर राजनैतिक दबाव बढ़ रहे हैं । यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारों का सहकारी साख समितियों के भुगतान में कोई रुचि नहीं है और राजनैतिक आधार पर सहकारी साख समितियों के बकायों को समाप्त करने के लिए वादे किये जाते हैं, इससे पूरे देश में ऋण न अदा करने का

वातावरण उत्पन्न होता है ।

जहाँ तक मौद्रिक एवं साख नीतियों का भारतीय कृषि से सम्बन्ध है, वहाँ तीन प्रमुख बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम एक गैर कुशल वित्तीय व्यवस्था, सस्ती साख व्यवस्था का करने में असमर्थ हैं । दूसरे, कृषि साख के लागत के सम्बन्ध की अनिश्चितता तथा नाना ताल सम्भावना विशेषकर भारतीय परिवेश में महत्वपूर्ण है, सामान्यतः भारतीय कृषक आर्थिक रूप से दिगम्बित की स्थिति में रहता है और उसकी साख बहुत कम होती है। तीसरे, भारतीय कृषि साख सन्दर्भ में लागत का अशुभ एकाधिकारिक स्थिति के रूप में ग्रामीण महाजन का होता है इस स्थिति में निम्नलिखित के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन, जो अनेक कृषि विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ हैं, उनका पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए । कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करने में और संपन्न के विनियोगों के सम्बन्ध में देश की स्पष्ट साख नीति होनी चाहिए ।

छठे अध्याय में नाबार्ड के क्रिया कलापो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। संस्थागत वित्त एवं साख के सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना अपना विशेष महत्व रखती है । मोटे तौर पर नाबार्ड पुनर्वित्तीयन तथा ऋण अग्रिमों द्वारा मुख्य रूप से राज्य सहकारी बैंको, भूमि विकास बैंको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य स्वीकृत वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन, विपणन एवं विनियोग सम्बन्धी क्रियाएँ हेतु कृषि, ग्रामीण विकास, लघु स्तरीय उद्योगों विकन्द्रीत एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों, ग्रामीण तथा कृषि उद्योगों एवं दस्तकारी और अन्य ग्रामीण शिल्पकारी तथा अन्य सम्बन्धित ग्रामीण आर्थिक क्रियाएँ हेतु वित्त प्रदान करता है। उद्देश्यनुसार नाबार्ड के कुल वित्तीयन का सहकारी वित्तीय माध्यम लघु निचोई योजनाओं में अधिक गया है और अवशेष कृषि मशीनीकरण, भण्डारण एवं विपणन तथा भूमि विकास, वृक्षारोपण, बागवानी, मत्स्य पालन, डेरी विकास तथा अन्य कार्यों में हुआ है । नाबार्ड द्वारा भारत का निर्यात आयात बैंक भी पुनर्वित्तीयन प्राप्त करता है, जो निर्यातानुगुण रूप से वित्त की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है । मोटे तौर पर नाबार्ड के सारे कार्यों का निर्वहन में विभाजित किया जा सकता है -

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं साख सस्थाओं को पुनर्विर्त्तीयन करना ।
- 2 सस्थागत विकास को सर्वाधिक करना और नवीन सस्थाओं को विकसित करना ।
- 3 ग्राहक बैंको का निरीक्षण, निर्देशन एवं मूल्यांकन करना तथा सुझाव देना ।

यदि देश के ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नाबार्ड को नेतृत्व का योगदान करना है तो कृषि परियोजनाओं हेतु पुनर्विर्त्तीयन के अलावा अपनी क्रिया - कलापों को इसे विस्तृत करना होगा । नाबार्ड के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से स्पष्ट है कि इसका प्रधान महत्व और योगदान अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों हेतु वित्तीय सस्थाओं का पुनर्विर्त्तीयन करना है । यह स्पष्ट है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्रारम्भ से ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान दी गयी है और इस तरह जल प्रबन्ध की सुचारु व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। कई राज्यों में अपर्याप्त शक्ति और ऊर्जा के सम्बन्ध में नाबार्ड ने राज्य विद्युत परिषदों को पुनर्विर्त्तीयन सहयोग दिया है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण के कार्यों के सर्वधन हेतु । सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत नाबार्ड का पुनर्विर्त्तीयन द्वितीय स्थान का रहा है। इसी तरह क्षेत्रानुसार औसत रूप से नाबार्ड के पुनर्विर्त्तीयन का 28 प्रतिशत उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, 15 प्रतिशत पश्चिमी और पूर्वी राज्यों, 19 प्रतिशत उत्तरी राज्यों, 21 प्रतिशत केन्द्रीय राज्यों तथा 28 प्रतिशत दक्षिण राज्यों को हुआ है । नाबार्ड के पुनर्विर्त्तीयन व्यवस्था के प्राविधान के अन्तर्गत यह अधिकृत सस्थाओं के पुनर्विर्त्तीयन के अलावा सीधे वित्त तथा ऋण प्रदान कर सकती है, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ सस्थागत व्यवस्था कमजोर है। यह बात स्पष्ट हुई है कि बहुत से ऐसे कारक जैसे, ऋण के लक्ष्य, वर्ग, खराब ऋण वसूली, प्रशासित ऋण दरों आदि से ग्रामीण साख संस्थाओं की क्षमता में कमी हुयी है। इस सम्बन्ध में नाबार्ड के सस्थागत कार्यों के विकास के सम्बन्ध में स्पष्ट मात्रात्मक उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए तथा समस्त कार्यों और कार्यक्रमों के समन्वय प्रक्रिया को संस्थागत संरचना में पूरा किया जाना चाहिए, साथ-साथ नाबार्ड तथा अन्य संगठनों के सम्बन्ध को मजबूत बनाना चाहिए । नाबार्ड को संस्थागत विकास को अपने सम्बन्धित बैंको में प्रशिक्षण क्रियाओं का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए । यह महत्वपूर्ण होगा कि

नाबार्ड अपने निरीक्षण के उद्देश्य को पुन स्पष्ट करे, जिससे नाबार्ड के अनेक कार्यों को पूरा किया जा सके और बैंको के निष्पादन में सुधार किया जा सके । निरीक्षण रिपोर्ट के क्षेत्र और विषय वस्तु सन्तुष्टि हेतु बैंको को सही दिशा - निर्देश हेतु दी जानी चाहिए । नाबार्ड के आन्तरिक संगठनात्मक और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों का विभाजन स्पष्ट होना चाहिए । इसी तरह जहाँ तक नाबार्ड के सलाहकार परिषद् का प्रश्न है, इसमें उच्च स्तरीय विशिष्ट सलाह और ज्ञान परिषद का गठन होना चाहिए । इसी तरह नाबार्ड के नियंत्रणात्मक योगदान के स्थान पर विकास और सेवा प्रवृत्ति विकसित किया जाना चाहिए । नाबार्ड में एक अधिक खुला तथा भागीदारी आधार पर व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे इन परिवर्तनों के साथ नाबार्ड का स्वरूप निखर सके और जिससे नाबार्ड अपने अस्तित्व को एक सह-संस्था के रूप में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु स्थापित कर सके और भारतीय रिजर्व बैंक की साख नीति को सफल बनाने में सक्रिय योगदान कर सके ।

सातवें अध्याय में कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एवं साख नियोजन को दिया गया है। भारतीय कृषि क्षेत्र में साख वितरण एवं कृषि कार्यों के लिए अग्रिमों तथा ऋणों के अध्ययन से यह प्राप्त हुआ है कि उनका उत्पादन एवं उत्पादितों में प्रयोग न होकर दुर्प्रयोग हुआ है। इससे एक ओर जहाँ अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई है, वहीं देश में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर अधिक दबाव पड़ा है। मोटे तौर पर भारतीय मौद्रिक एवं साख नीति सस्ती मुद्रा नीति के ही स्वरूप में बनी रही है । देश में अविकसित मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार के रहते हुए तथा सुसंगठित बाजारों के अभाव में सस्ती मुद्रा नीति अधिकांशतः हानिकारक एवं स्फीतिकारी रही है । भारतीय मौद्रिक एवं साख नीति में व्याज दर का विशेष महत्व नहीं है, बल्कि मुद्रा पूर्ति एवं साख पूर्ति में नियंत्रण तथा नियोजन की आवश्यकता है । यद्यपि कृषि क्षेत्रों तथा आगतों तथा खाद रासायनिक उर्वरकों पर अब दी जाने वाली सहाय्य (सब्सिडी) को कम या समाप्त कर दिया जा रहा है, परन्तु देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय और पिछड़े क्षेत्रों एवं वर्गों की दृष्टिकोण से, देश के ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक तथा अन्य गरीब जनता लिए उपयुक्त रोजगार के अवसरों के न होते हुए अब भी इस बात की भारी गुंजाइश है कि प्रभावी ढंग से कृषि एवं साख का प्रवाह उत्पादक कार्यों के

लिए किया जाय । कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के साख वितरण के सम्बन्ध में जहा उत्पादन एवं उत्पादिता का प्रश्न रहा है, वहीं साख ऋणों की वसूली की भी समस्या रही है । भारतीय सन्दर्भ में मौद्रिक एवं साख नियोजन मात्र नीति निर्माण स्तर पर निर्धारित करने से नहीं है, अपितु सामाजिक दृष्टिकोण से कुल बैंक साख तथा उसके आवटन और प्रयोगकर्ताओं के बीच निर्धारण करने से है। इसी के साथ साथ इन नियोजनों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं सरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिससे वांछित रूप में साख का बटवारा हो सके, क्योंकि बिना इसके सारा मौद्रिक एवं साख नियोजन केवल कागजी कार्यवाही होगी । 'एग्रीकल्चरल रिफाइनंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन' ने यह पाया है कि लघु सिंचाई पर विनियोग का प्रतिफल भूमि विकास, डेयरी तथा अन्य क्षेत्रों में 20 से 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उपर्युक्त साख नियोजन द्वारा छोटे उत्पादक महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं । दो मुख्य समस्याएँ गरीबी तथा बेरोजगारी कितनी शीघ्रता से दूर की जा सके, यह साख तथा मुद्रा नियोजन का मुख्य विषय होना चाहिए।

जहा तक मौद्रिक लक्ष्यों का तात्पर्य है वह मुद्रा पूर्ति के वार्षिक वृद्धि दर को निश्चित करने से हैं । चक्रवर्ती समिति में मुद्रापूर्ति के लक्षित दायरे को नहीं दिखाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुभवगम्य लक्ष्यों, जिसमें मुद्रा, मूल्य एवं उत्पादन का सम्बन्ध है, जो समिति के रिपोर्ट में प्रस्तावित की गयी है, वह यह दर्शाती है कि इनमें पारस्परिक सम्बन्ध वार्षिक आकड़ों के आधार पर सम्भव नहीं है। ये सारी सस्तुतियाँ मोटे तौर पर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि को लक्ष्य करके दी गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समिति में उल्लेखनीय है, वह चार प्रतिशत सामान्य मुद्रा स्फीति की दर से है। समिति ने अधिकतम वार्षिक मुद्रापूर्ति का एक दायरे को सस्तुति की है, न कि लक्ष्य का । सम्पूर्ण देश के स्तर पर आकड़े इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय कृषि में सीमान्त कृषक अधिक होते जा रहे हैं और इनमें साख की माग बढ़ती जा रही है । अतः सारी रुकावटें जो शीघ्र साख देने में आती हैं, उन सब का निराकरण होना चाहिए । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं। -

- 1 कृषि क्षेत्र में साख आवश्यकता केवल साख आवश्यकता तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु पूरी कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित होना चाहिए ।
- 2 इस क्षेत्र में साख आवश्यकता आगत वितरण के रूप में होना चाहिए और थोक तथा फुटकर आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में साख लागत वितरण हेतु सहकारी समितियों पर विशेष जोर देना चाहिए ।
- 3 कृषि आधारित उद्योगों को, जो अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है, वे कृषि साख के अग होने चाहिए ।
- 4 जहां तक अल्पकालीन साख आवंटन तथा साख कार्यक्रमों का प्रश्न है, कृषि उत्पादन में उपविभाग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
- 5 हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अल्पकालीन साख हेतु उपलब्ध साधनों को बढ़ाया जा सके ।
- 6 वर्तमान समय में अल्पकालीन साख का वितरण, जो विभिन्न परिवार जोत के आधार पर है, उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

मौद्रिक एवं साख नियोजन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि देश में सम्पूर्ण मौद्रिक एवं साख साधनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता, प्रयोग की क्षमता और पूरे विकास के दृष्टिकोण से आवंटन किया जाय । सफलता की दृष्टि कोण से साख नियोजन जमा योजनाओं से सम्बन्धित होना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण साख का आवंटन बैंकों की कुल जमा पर निर्धारित होता है। इस तरह का साख नियोजन एक विकासशील भारत देश में अपना विशेष महत्व रखता है, ताकि सीमित बैंक साधनों का उत्पादकता के दृष्टिकोण से उपयोग हो सके । पूरे देश में साख की मात्रा इसकी आवश्यकता से कम है । इसलिए साख की मात्रा को विवेकपूर्ण होना चाहिए, ताकि विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में इसे समान रूप से वितरित किया जा सके । पूरे समाज के

साख को विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित करना चाहिए, न कि उनके ऊँचे ब्याज दर को अदा करने की योग्यता के अनुसार । यह भारतीय रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह साख नियोजन इस तरह करे कि मौद्रिक बजट का क्रियान्वयन व्यष्टि स्तर पर साख बजट का स्वरूप ले ले । इसका उद्देश्य मौद्रिक बजट द्वारा मुद्रा पूर्ति के विकास दर को सुनिश्चित करना है। इस तरह समष्टि स्तर पर साख का सम्बन्ध व्यष्टि स्तर पर साख नियोजन से होगा । व्यापारिक बैंको की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने साख का आवंटन अपने सम्बन्धित शाखाओं द्वारा करें । व्यक्तिगत बैंक अपने साख का वितरण सबसे गरीब तबके के लोगों से लेकर विभिन्न ऋण ग्राहकों तक वितरित करें, विशेषकर कृषि और प्राथमिक क्षेत्रों में इस तरह का साख आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब तक जो साख नियोजन बैंको द्वारा किये गये हैं, वे पूर्णतः सफल नहीं हो सके हैं । ऐसे अध्ययन जो साख अन्तराल से सम्बन्धित हैं, वे स्पष्ट करते हैं कि लीड- बैंक स्कीम अभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाये हैं । अब भी साख नियोजन में इस बात की आवश्यकता है कि साख वितरण में समय अन्तराल को कम किया जाय और विशेषकर लघु ग्रामीण क्षेत्रों में उधार लेने वालों के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायों में सम्बन्धित क्षेत्र के सन्दर्भ में कुछ सुझावों को दिया गया है । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नीतिपरक सुझावों को हम यहाँ दे रहे हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं साख नीति के अन्तर्गत सक्रिय खुले बाजार की क्रियाओं सबधी नीति को मौद्रिक नियंत्रण के साधन के रूप में आरक्षित निधि की मूल नीति में बदलाव की आवश्यकता को सहर्ष स्वीकार किया गया है, लेकिन वास्तव में मुख्य मुद्दा इस सुधार में तेजी लाने का है । यह माना जाता है कि बैंको को सांविधिक अपेक्षाएँ इस उँचाई तक पहुँच गयी हैं कि वे प्रति उत्पादक होती जा रही हैं तथा यह मध्यस्थहीनता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रही हैं। चूँकि समायोजन की अत्यधिक, प्राथमिक चलनिधि की समस्या को काफी बदतर बना सकती है, आरक्षित निधि में कटौती की गति का निर्धारण सावधानीपूर्वक करना चाहिए । इस प्रकार आरक्षित

नकदी निधि अनुपात में और अधिक यथार्थवादी स्तर तभी संभव है, जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव के स्थायी रूप से टिके रहने के स्पष्ट चिन्ह दिखायी पड़ते हों । नरसिंहम समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में इतना लचीलापन होना चाहिए कि वह अपनी मौद्रिक नीतिगत प्रयोजनों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात के साधन का उपयोग कर सके । आरक्षित नकदी निधि अनुपात व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण, नकदी शेष पर ब्याज का अनुपात है। ऊँचे ब्याज के साथ ऊँचे आरक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करना बेहतर है। दुविधा यह है कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात समायोजन बैंकों की अस्तित्वों को बदल देता है, जब कि ब्याज में कटौती बैंकों की आय को प्रभावित करती है। इस प्रकार आरक्षित नकदी निधि अनुपात के और नकदी शेष पर ब्याज दर के स्तर को अतः अनुकूल बनाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र बैंक लाभप्रदता प्रभावित न हो । इसके अलावा, पुनर्वित्तीयन और आरक्षित नकदी निधि अनुपात के बीच व्यापार बढ़ी है। शायद उच्च आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा उच्च पुनर्वित्तीयन की अपेक्षा निम्न आरक्षित नकदी निधि अनुपात और निम्न पुनर्वित्तीयन की प्रणाली को अपनाना बेहतर होगा । आदर्शतः आरक्षित नकदी निधि अनुपात का सामान्य स्तर ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी प्रकार के ब्याज की अदायगी नहीं होती है तब भी बैंकिंग प्रणाली व्यवहार्य हो तथा ज्यों ही मौद्रिक विस्तार अत्यधिक होता है आरक्षित नकदी निधि अनुपात को बढ़ाया जाये, जब मौद्रिक वृद्धि अपेक्षित स्तर पर वापस आ जाती है, निम्नगामी गतिविधियों को तेज किया जाना चाहिए । नरसिंहम समिति ने यह सिफारिश है कि पांच वर्षों की अवधि के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात को कम कर के 25 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए । कार्य की दिशा में यह उपयुक्त लक्ष्य है । तथापि सांविधिक चलनिधि को कम कर के 25 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए । कार्य की दिशा में यह उपयुक्त लक्ष्य है । तथापि सांविधिक चलनिधि अनुपात समायोजन की चरणबद्धता को बाजार उधार कार्यक्रम से सामंजस्य रखना चाहिए । सांविधिक चलनिधि अनुपात में भारी कटौती अप्रैल, 1992 से लागू की गयी है। भविष्य में, सांविधिक चलनिधि अनुपात में समायोजन की गति राजकोषीय समायोजन, मौद्रिक विस्तार तथा मुद्रास्फीति दर की गति पर निर्भर करेगी । मुद्रा बाजार दर, उधार और जमा राशि दर

तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों के रूप में ब्याज दर सुधार की प्रक्रिया काफी हद तक पहले ही प्रारम्भ हो गयी है। एक ओर इन उपायों को बनाये रखने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर प्रणाली में सभी दरों के अति तेजी से अपविनियमन की ओर सर्तर्कतापूर्वक बढ़ने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में अत्यन्त सबल अन्तर्निहित मुद्रा स्फीतिकारी सम्भावना का बना रहना रिजर्व बैंक के लिए चिन्ता का विषय है। सकल माग को सीमित करने के लिए, राकोषीय और मोद्रिक नीतियों को समन्वित करने का दृढ़ प्रयास किया गया है तथा इन नीतियों को विनियम दर, व्यापार और औद्योगिक नीति की पुनर्रचना के साथ परिचालित करने की कोशिश की गयी है। केवल माग प्रबन्ध उपायों से, खासकर कम अवधि में, मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण नहीं पाया जा सकता। जहाँ तक देश में सामान्य मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि पण्य बाजार को स्पष्ट सकेत दिया जाये कि माग पर सरकार आवश्यक उपभोक्ता सामग्री विशेषकर, अनाज और दालों के मामलों में, देशी आपूर्ति को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों के एक अंश को खर्च करेगी।

साख नीति के सन्दर्भ में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है। उत्पादन और रोजगार से संबंधित इन खंडों के अंश में किसी भी परिवर्तन के परिणामों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा, क्योंकि भारत की आर्थिक संरचना अत्यंत भिन्न-भिन्न है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के दो पहलू हैं, जिनकी रूप रेखा स्पष्टतः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पहला, यह कि बैंकिंग प्रणाली से कम ब्याज दरों के रूप में आर्थिक सहायता वहन करने की आशा नहीं की जा सकती और रियायत देने की बात को ऋण के आकार के साथ संबद्ध करके बड़ी सीमा तक इस विषय का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरे, यह तर्क दिया जा सकता है कि वित्त व्यवस्था में विकास के इस चरण पर, जहाँ कि आज भारत है, कमजोर वर्गों को ऋण का न्यायसंगत वितरण न केवल उत्पादन को बढ़ाने में योगदान करेगा, बल्कि इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।

वर्तमान समय में एक मूलभूत प्रथम आवश्यकता यह है कि ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को पुनः ठीक कर दिया जाए और एक सक्षम संस्थागत संरचना अस्तित्व में लायी जाए। जबकि

ग्रामीण ऋण सरचना को सुधरी अर्थक्षमता प्रदान करने के प्रश्न ने विभिन्न समितियों का ध्यान आकर्षित किया है, एक सक्षम सरचना विकसित करना अभी भी अपेक्षित है। भारत सरकार एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रश्न पर तुरत ध्यान देना आवश्यक है कि क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक ही राष्ट्रीय स्तर के बैंक के रूप में विलयित किया जाए अथवा चार या पांच आचलिक बैंकों के रूप में बैंकों की ग्रामीण सहायक सस्थाओं के रूप में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलयित करने के लिए नरसिंहम समिति द्वारा सुझाये गये विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। एक ऐसी ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली तैयार करना अनिवार्य है, जिसके लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता न हो। इस सदर्थ में व्याज दरों के बेहतर रूप में समनुरूप बनाने एवं लक्षित और लक्ष्येत्तर उधार के मिश्रण पर ध्यान देना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएँ गभीर हैं, इनके लिए एक बहुविध दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित होगा। जिस किसी क्षेत्र में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली सतोषजनक है, वहा मौजूदा सस्थाओं और वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण सहायक सस्थाओं जैसी नयी सस्थाओं को उनके अपने बल पर विकास करने की अनुमति देना उपयुक्त होगा। ऐसे क्षेत्र जहा ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली असतोषजनक है, वहा यह अनिवार्य है कि ऋण वितरण प्रणाली में सक्षमता युक्त सुधार लाने हेतु शीघ्र उपाय किये जायें। व्यापक आर्थिक परिदृश्य जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि पैदावार में कमी के कारण आपूर्ति में कमी होने की सभावनाएँ और उनकी मुद्रा स्फीति की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये मौद्रिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता अपनाने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के लिये विकासकी कार्यनीति देश के कृषि उत्पादन में सीमान्त तथा छोटे खेतों, जो कुल जोतों का 76 प्रतिशत है, के योगदान को स्पष्ट रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। छोटे खेतों की विकासात्मक कार्यनीति इस तरह तैयार की जानी चाहिए, जिससे उन्हें अधिक गहन कृषि विधियाँ अपनाने तथा सीमित ससाधनों का और अधिक दक्षता पूर्वक उपयोग करने में मदद मिल सके। छोटी जोत भूमि की उत्पादन समभाव्यताओं को पर्याप्त रूप से आकर्षण बनाया जाना चाहिए, ताकि वे

कृषि विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी से प्रवृत्त हो सकें। छोटे फार्मों हेतु विकास कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किये जाने चाहिये, ताकि उन्हें उपलब्ध ससाधनों का सबसे सही उपयोग करने के लिये प्रशिक्षण और मदद मिल सके। नाबार्ड द्वारा वर्ष 1983 में प्रारम्भ किया गया, ऋण द्वारा विकास पर आधारित विकास वालियन्टर वाहिनी कार्यक्रम, इस दिशा में एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है।

ग्रामीण जनसंख्या को कृषि के स्थान पर उससे सम्बद्ध अन्य कार्यकलापों तथा गैर कृषि क्षेत्र के कार्यकलापों की ओर मोड़ कर, कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम किया जाना चाहिए। इसके लिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता लाना जरूरी है, जिसमें कृषि से सम्बद्ध कार्यकलापों को प्रोत्साहन देना तथा कृषि अभिस्करण और गैर कृषि क्षेत्र के कार्यकलापों का विस्तार करना शामिल है। पशुधन उत्पादन, डेयरी तथा वानिकी में बढ़े हुए श्रम की खपत हेतु काफी सभाव्यताएँ हैं। इससे ग्रामीण श्रमिकों का कस्बों और शहरों की ओर पलायन रुकेगा।

कृषि अभिस्करण और विपणन संबंधी मूलभूत सुविधाओं सहित कृषि और गैर - कृषि क्षेत्र के समन्वित विकास का महत्त्व इस तथ्य को देखते हुए काफी बढ़ गया है कि पिछले वर्षों के दौरान सिंचाई, पशुपालन, फार्म मशीनीकरण और मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु काफी राशि निवेशित करने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में लगातार गिरावट आई है। परिचालनात्मक जोत भूमि के लगातार उप खण्डों में विभक्त किये जाने और कृषि के सीमान्तीकरण ने ऋण बाजार की समस्याओं को बढ़ा दिया है, विशेष रूप से ग्रामीण गैर कृषि कार्यकलापों में लगे ऐसे व्यक्तियों को वित्तपोषित करने के मामले में, जिनके पास ऋण एजेंसियों के पास प्रतिभूति के रूप में रखने के लिये ससाधन सीमित हैं। वर्तमान व्यापक आर्थिक परिदृश्य में समग्र रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि एक चिन्ताजनक पहलू है। मौसमी रोजगार की समस्या का निवारण करने के लिये गैर कृषि कार्यकलापों का विकास किया जाना जरूरी है। इसके अलावा, ग्रामीण कृष्येत्तर क्षेत्र का वित्तपोषण अपेक्षाकृत ज्यादा लाभकारी है और इससे बैंकों को, कृषि क्षेत्र में दिए गये ऋणों से हुए घाटे को कुछ सीमा तक पूरा करने में मदद मिलेगी।

यद्यपि सरकारी ऋण लिखतों को बाजार आधारित ब्याज दरों से जोड़ने के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति को उचित तौर पर अपनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है तथापि, जब तक कि कुल बाजार की गतिवधियाँ मौद्रिक नीति का एक प्रभावी साधन नहीं बन जाती, तब तक इस बारे में कोई भी कार्यवाई करना जल्दबाजी होगी। तब तक इसे ऐसा ही चलते देना चाहिए।

वर्तमान मौद्रिक नीति में चलनिधि को नियंत्रण में रखने के उपायों की अत्यंत कमी है। मुद्रा स्फीति की वर्तमान प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में ब्याज-दर सम्बन्धी उपाय का प्रयोग लचीलेपन के साथ करना होगा। मौद्रिक नीति गत उपायों पर जोर दिये जाने के कारण, यह आवश्यक है कि मौद्रिक प्रसार को नियंत्रित करने के लिये ब्याज दर नीति का प्रभावी तौर पर उपयोग किया जाए।

इस तरह से प्रस्तुत शोध अध्ययन एक दीर्घकालीन, स्थायी और उपर्युक्त मौद्रिक एवं साख नीति का निर्माण कर सकता है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र और दिशा में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, लाभकारी तथा साथ-साथ हानिकारक प्रभाव भी पड़े हैं। सस्ती मुद्रा एवं साख नीति के स्थान पर महंगी मुद्रा नीति द्वारा यदि नियोजित ढंग से मौद्रिक और साख नीतियों का पालन किया जायेगा तो निश्चित ही देश के कृषि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। इस दशा में यह सम्भव हो सकता है कि यदि ये नीतियाँ उपर्युक्त एवं प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता के आधार पर संचालित की जायेगी तो एक अभावपूर्ण भारत देश समृद्धि शाली देश हो सकता है और हमारे राष्ट्र का अस्तित्व विश्व के अन्य देशों के समान स्थापित किया जा सकेगा।

BIBLIOGRAPHY

Adiseshiah, M S	Seventh Plan Perspectives, Lancer International, New Delhi, 1985
Agrawal, A N , Verma H O & Gupta, R C	India - Economic Information Year Book, 1987-88, National Publishing House, New Delhi, 1987
Andey, K K	Money Foreign Exchange and Banking, Atma Ram & Sons, Delhi, 1963
Banerjee, B N	Industry, Agriculture and Rural development, B R Publishing Corporation, Delhi, 1987
Basu, C R	Central Banking in a Planned Economy - The Indian Experiment Tata Mc Graw - Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1978
Basu, S k	Central Banking in Emerging Countries, Asia Publishing House, Bombay, 1968
Basu, S K	A Review of Current Banking Theory and Practice, Mac Millan, Calcutta, 1971
Bulshiw, W	Provision of Credit with special Reference to Agriculture, Heffer and sons, Cambridge 1931
Bhattacharya, K N	India's Fourth Plan - Test in Growthmanship, Asia Publishing House, Bombay, 1966
Bhattacharya, P C	Role of Central Bank in a Developing Economy, Publishers Bombay, 1968
Brahmananda, P R	Growthless Inflation by Means of stockless Money Supply Himalaya Pub Bombay, 1985
Bright Singh, D	Inflationary Price trend in India Since 1939, 2nd rev edn, Asia Publishing House, Bombay, 1961
Catanach, I J	Land Development Banking in India, Oxford University Press Bombay, 1970
Chacko, K C	The Monetary and Fiscal Policy of India, Bombay, 1957
Chakravarty, S	Working of Monetary system in India, 1985
Choubey, B N	Agricultural Banking in India, National

- Di, V Balmohan, Rao,
J V , Prabhakara and
Rao, P Hrushikesava Rural Banks and Rural Credit, Discovery
Publishing House, New Delhi, 1991
- Das, Tushkar, K Rural Banking, National Institute of Bank
Management, Bombay
- Datey, C D Cooperative Bank and Agricultural Credit,
Vora & Co , Bombay
- Deb, K Rural Development in India since
Independence, 1986
- De Prano, M E Self - Correcting Problems in Money, Banking
and Monetary Theory, Allyn and Bacon,
Boston, 1966
- Desai, B M and
D K Farm Production Credit in Changing Desai,
Agriculture, I I M , Ahmedabad, 1979
- Desai, S S M Rural Banking in India, Himalaya Publishing
House Bombay, 1982
- Deshmukh, C D The Balance Between Monetary Policy and other
Instrument of Economic Policy in A Modern
Society, 1965
- Franks, Sir Oliver Some Reflections on Monetary Policy in the
Light of the Radcliffe Report, Asia
Publishing House, Bombay, 1961
- Friedman, Milton (Ed) Studies in the Quantity Theory of Money 1956
- Ghosh, A Control Techniques In Indian Monetary
Management, World Press Pvt ltd Calcutta,
1971
- Ghosh, B B Problems of Rural Credit in India, Calcutta
- Ghosh, O P Financial Institutions Economic Growth of
India, Light and life Publishers,
New Delhi, 1979
- Ghoshal, S N Agricultural Financing in India, Asia
Publishing House, Bombay, 1966
- Ghoshal, S N Agricultural Finance in India with special
Reference to Land Mortgage Banks, Asia
Publishing House, Bombay, 1968
- Gupta, R D Keynes and Post Keynesian Economics

- Cupla, S B Monetary Economics Institutions, theory and Policy, S Chand Company Ltd New Delhi, 1992
- Gurley, J G and Shaw, E S Money In A Theory of Finance, 1960
- Hajela, P D The Problems of Monetary Policy In Underdeveloped Countries, New Delhi, 1966
- Heller, W Monetary Policy Vs, Fiscal Policy A Dialogue, (Ed) by Milton Friedman and Walter Hellen, 1969
- Jagannathan, S Reserve Bank of India - Functions and Working, RBI Bombay, 1970
- Jain, M K Rural Banks and Rural Poor, 1989
- Jain, S C Management in Agricultural Finance S Chand & Co , Delhi, 1970
- Jha, K K Agricultural finance in Nepal, Heritage Publisher's, New Delhi, 1978
- Jha, M Lead Bank Scheme and Regional Development, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1988
- Johnson, H G Essays In Monetary Economics, London, 1967
- Joshi, P L Institutional Financing in India, Deep and Deep Publications New Delhi, 1985.
- Joshi, N C Indian Banking, Ashish Publishing House, New Delhi, 1979
- Kahlon, A S and Singh, K Managing Agricultural Finance Theory and Practice, Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1984
- Kotesar, I (Ed) Agricultural Credit in India, An Appraisal WAIM, Farmer's Welfare Trust, New Delhi 1974
- Krishna Murty, V Monetary Equilibrium and Economic Development, Popular Prakashan, Bombay, 1977
- Kumar, K Institutional Financing of Indian Agriculture, 1987
- Kumar, S Regional Rural Bank and Rural Development, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1990

- Kutty, G K Money and Banking, Concept Publishing House, New Delhi, 1979
- Laud, G M Cooperative Banking in India, Bombay, 1956
- Madan, B K Role of Monetary Policy in A Developing Economy, Chandigarh, 1963
- Mahajan, V S Studies in Indian Agriculture and Rural Development Deep and Deep publications, New Delhi, 1986
- Mamoria, C B Agricultural Problems of India, Kitab Mahal, Allahabad, 1982
- Mamoria, C B Rural Credit and Agricultural Co-operation in India, Kitab Mahal, Allahabad, 1983
- Mathur, B I (Ed) Indian Banking in Rural Development, RBSA Publishers, Jaipur, 1990
- Mathur, B S Land Development Banking in India, National Publishing House, Delhi, 1977
- Mehrotra, S R Institutional Credit and Agricultural Growth, Printwell Pub New Delhi
- Mehta, P and Prasher, R S Credit in Agriculture, B R Publishing Corporation, Delhi, 1987
- Mehta, P and Singh P R Credit in Agriculture, 1987
- Mellor, J W , Weaver, T F , Lele, U J and Simon, S R Developing Rural India, Plan and practice Cornell University Press Ithaca, New York , 1968
- Mittra, S A New Horizons of Central Banking, Bombay, 1967
- Mody, R J New Dimensions of Monetary Management, The Macmillan Company of India Ltd Delhi, 1974
- Mongia J N (Ed) India's Economic Policies, Allied Publishers Private Ltd , New Delhi, 1984
- Mongia, J N (Ed) India's Economic Development strategies 1951-2000 A D Allied Publishers Private Limited, New Delhi, 1986

- Nagpal, C S Monetary Policy and Inflation In India, Delhi, 1982
- Naidu, L K (Ed) Bank Finance for Rural Development, 1986
- Naidu, L K Bank Finance for Rural Artisans, Ashish Publishing House, New Delhi, 1988
- Naidu, T V Farm Credit and Cooperatives in India, Vora and Co Bombay, 1968
- Nanavati, M B and Anjaria, J J Indian Rural Problem, Indian Society of Agricultural Economics Bombay, 1976
- Narula, R K Agriculture and Rural Advance by Commercial Banks, U D H PUBLISHERS Delhi, 1984
- Nayan, K Commercial Banks in India Performance Evaluation, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1985
- Nigam, B M L Banking and Economic Growth, Vora and Co Publishers Bombay, 1967
- Padhy, K C Commercial Banks and Rural Development, Asian Publication Services, New Delhi, 1980
- Panda, R K Agricultural Indebtness and Institutional Finance, Ashish Publishing House, New Delhi, 1985
- Pannaddikar, P A and Mehta, N C (Ed) Rural Banking, National Institute of Bank Management, Bombay, 1970
- Pandey, K L Development of Banking in India, Scientific Book Agency, Calcutta, 1968
- Pandeya, P C Agricultural Planning in a Backward Economy, Chugh Publications, Allahabad
- Panikar, P G K Rural Savings in India Sommalaya, Banks, 1970
- Pany, R K Institutional Credit for Agriculture in India, Ashish Publishing House, New Delhi
- Patnaik, K M Monetary Policy and Economic Development in India, S Chand and Co , Delhi, 1967
- Raj, K N Monetary Policy of Reserve Bank of India, 1948

- Ramachandran, H and
De Campos Guimarães U P Integrated Rural Development in Asia, Concept
Publishing Company, New Delhi, 1991
- Rao, B R Current Trends in Indian Banking Criterion
Publications, New Delhi, 1984
- Rao, V G and
Malya, P Agricultural Finance by Commercial Banks,
Ashish Publishing House, New Delhi
- Rao, V L Progress of Development Bank in India, Chugh
Publication Allahabad, 1986
- Reddy, C R Co-operative Agricultural Finance Chugh
Publication, Allahabad
- Reddy, J M , Reddy, M Y Seventh Five Year Plan, Performance and
Úpadhyay, K S & Perspectives, Sterling Publishers (P)
Raghuram, Ch (Ed) Ltd New Delhi, 1989
- Rama Rau, B Evolution of Central Banking in India, Vora
and Co Bombay, 1960
- Sarma, B P The role of Commercial Banks in India's
Developing Economy, S Chand and Co
New Delhi, 1974
- Sarma, K R Financial Institutions and Regional
Development in India, Chugh Publications,
Allahabad, 1986
- Sen, S N The Monetary Policy of the Reserve Bank of
India, Popular Prakashan Bombay, 1964
- Sethi, J D Problems of Monetary Policy in an
underdeveloped Country, Asia Publishing
House, Bombay, 1961
- Shah, M Role of Reserve Bank of India in India's
Economic Development
- Sharma, K K Reserve Bank of India and Rural Credit,
Premier Publishing Co , Delhi, 1946
- Sharma, K K Role of Monetary Policy in Planned Economy,
Meerut 1965
- Sharma, K K Indian Monetary Policy, Meerut, 1968
- Sharma, R D P. Financing of Indian Five Year Plan, Capital
Publishing House, Delhi, 1968

- Simha S L N and Raman, A (Ed) Credit Planning and Policy, Vora and Co Publisher's Pvt Ltd , Bombay, 1974
- Simha, S L N and Raman, A Credit Planning Objectives and Techniques, Institute for Financial Management and Research, Madras, 1976
- Singh, A Rural Development and Banking in India, Deep and Deep Publication, New Delhi, 1985
- Singh, A B P Lead Bank Scheme, Capita Publishing House, Delhi, 1987
- Singh, J P Role of Institutional Finance in Agriculture, Ashish Publishing House, New Delhi, 1986
- Srivastava, R B Institutional Financing of Agriculture in India, Vohra Publishers and Distributors, Allahabad, 1987
- Subramanya, K N Modern Banking in India, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1985
- Subrahmanys, S Trends and Progress of Banking in India, Deep and Deep Publications New Delhi, 1986
- Subramanya, S (Ed) Trends and progress of Banking in India, Deep and Deep Publications New Delhi, 1986
- Thakur, D Indian Banking and Money Market, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1993
- Thirupala, N Agricultural Finance and Development, Chugh Publication, Allahabad, 1988
- Tomar, J S Farm Credit Planning Guide, Sagar Publication, New Delhi, 1974
- Tomar J S Farm Credit and Finance, Varma Bros , New Delhi, 1978
- Iripathi, B K Developments In the Quantity Theory of Money and their Policy Implications, Saraswati Prakashan, Allahabad 1989
- Vaish, M C Monetary Theory, Vikas Publishing House, Pvt Ltd , New Delhi, 1981
- Varma, V K Promotional Aspects of Monetary Management in India, Somaiya Publication Pvt Ltd , Madras 1978

REPORTS

A R D C	Report of the Committee on Integration of Co-operative Credit Institutions, 1976
Dantwala, M L	Report of the Committee on Regulation of Rural Banks
Desai, G	Report of the Expert Group on Agricultural schemes of the Commercial Banks, R B I 1978
Kimat	Report of the Working Group on Multi-Agency Approach to Agricultural Credit, R B I 1977
Gadgil, D R	Report of the Agricultural Finance Sub-Committee, Bombay, 1945
Gadgil, D R	Reports of the Committee to study Institutional Arrangement for Agricultural Credit in the Context of Social Objectives, R B I , 1969
Gorwala, A D	All-India Rural Credit Survey Committee, R B I Bombay, 1953
Gorwala, A D	Report of the Rural Banking Enquiry Committee, R B I , 1953
Government of India	Report of the Banking Commission, Publication Division, Government of India, New Delhi, Jan 1972
Government of India	Economic Survey, Ministry of Finance (Economic Division) Government of India (Various Issues)
Government of India	Five Year Plan from (I-VII) Planning Commission

ARTICLES

Bhende, M J	Credit Markets in Rural South India Economic and Political Weekly, Vol XXI Sept 22-27, 1986
Dandekar, M N	Fram Credit in India, Feb , 1988

Dandekar, V M	An Analysis of Inflation in India, Indian Economic Review, Oct , 1989
Datta, Bhattachosh	Monetary Reform, Economic and Political Weekly, Vol XVI Jan , 11, 1986
Dhondiyal, S P	A Note on Impact of Credit on Farm Growth I J A I , 67 (226), 1977
Dr Brahmananda, P R	What is Wrong with the Indian Monetary Policy, And How to Correct it / Dec , 1983
Friedman, Milton	The role of Monetary Policy, American Economic Review, Vol C L VII March, 1968
Johnson, H G	Monetary Theory and Policy, The American Economic Review, Vol L II No 3, June 1962
Mody, R J	Government Borrowing and the Monetary system, Economic and Political Weekly, Vol XVI Aug 9, 1986
Patil, R H	Monetary Reforms, Some Unresolved Issues, Economic and Political Weekly No , Vol XVI Jan 25, 1986
Pande, K P	Report of the Working Group on Co-ordination of short, Medium and long term Loans, 1964
Pal, T A and Narsimham	Report of the Working of the Group on Regional Rural Banks, 1975
Reserve Bank of India	Report of the Working Group Analysis on Money Supply, R B I Bulletin, July and August 1961
Reserve Bank of India	Report of the Informal Group on Institutional Arrangement for Agricultural Credit, 1964
Reserve Bank of India	Manual on short-term and long-term Loans for Agricultural Purposes, 1966
R serve Bank of India	Report of the All India Rural Credit Review Committee, 1969
Reserve Bank of India	Special Credit Schemes, 1970
Reserve Bank of India	Studies in Agricultural Credit, 1970.
Reserve Bank of India	The Reserve Bank of India, Functions and Working, R B I Bombay, 1970

Reserve Bank of India	Compilation and Analysis of Money Supply in India 1976
Reserve Bank of India	Report of the studies Group to Fram Guidelines for Follow-up of Bank Credit (Tandon Committee), 1975
Reserve Bank of India	Report of the Working Group to Review the system of Cash Credit (Chore Committee) 1979
Reserve Bank of India	Money Supply in India Concepts, Compilation and Analysis, (Report of the Second Working Group) Reprinted, 1979
Reserve Bank of India	Report of the Expert Group on state Enactments having a Bearing on Commercial Bank leading to Agriculture, (Tandon Committee), R B I , 1980
Reserve Bank of India	Report of the Committee of Review arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development (CRFICARD), 1981
Reserve Bank of India	Report of the Working Group and the Role of Banks in Implementation of New 20-Point programme (Ghosh Committee), 1982
Reserve Bank of India	Report of the Committee to Review the Working of the Credit Authorization Scheme (Marathe Committee), 1983
Reserve Bank of India	Report on the trend and progress of Banking in India, 1983-84
Reserve Bank of India	Report of the Committee to Review the Working of the Monetary system (Chakravarty Committee), 1985
Reserve Bank of India	Report of the Agricultural Credit Review Committee
Rangarajan C	Monetary Policy Price Stability and Interest Rate Regulation, Economic Times
Shah, V C	Monetary Analysis in India, 1948-49 to 1958-59, Indian Economic Journal, Vol 9, No 3, Jan 1962